राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 78

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 27 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

बुमराह ने फिर किया साबित–उनके जैसा नहीं कोई >> 14

सरोकार

सदियों पुरानी कुरीति पर दो वर्षों में लगाई लगाम

झाबुआ : मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ क्षेत्र में वधूमूल्य प्रथा का चलन जोरों पर था। वर पक्ष लड़की के पिता को नियत राशि देता और लड़की का पिता राशि के लालच में कम उम्र में ही बेटी की शादी कर देता। कलेक्टर आशीष सक्सेना को इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने का श्रेय दिया जा रहा है। (पेज-11)

जागरण विशेष

उप्र में गढ़ी जा रही 'सबसे ऊंची' गणेश प्रतिमा

चंदौसी : उप्र के चंदौसी में 135 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनाने का काम बीते वर्षों से चल रहा है। हालांकि भक्तों को एक वर्ष और इंतजार करना होगा क्योंकि कंक्रीट की यह प्रतिमा 2020 तक बनकर तैयार होगी। गिनीज बुक में कीर्तिमान दर्ज कराने के लिए दावा भेजा जा चुका है। (पेज-11)

अहम मुलाकात ▸ अमेरिकी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की दो टूक–तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते

मोदी के सामने मध्यस्थता राग से पीछे हटे ट्रंप

भारत–पाक के बीच कई मुद्दे हैं, जिनका द्विपक्षीय समाधान ढूंढ़ा जा सकता है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर मामले में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं होने की हामी भरवा पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप की मौजूदगी में मोदी ने कश्मीर मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की दूर-दूर तक की संभावना को खारिज कर दिया। मोदी ने साफ कहा कि दोनों देश आपसी बातचीत से सारे मसलों का हल निकालेंगे और हम किसी तीसरे देश को इस मामले में कष्ट नहीं देना चाहते। मोदी की बात से सहमति जताते हुए ट्रंप ने भी मान लिया कि भारत-पाकिस्तान आपसी बातचीत के जरिये कश्मीर समेत सभी मसलों का समाधान निकालेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने सार्वजनिक रूप से कश्मीर पर मध्यस्थता की गुंजाइश को खारिज कर मोदी ने ट्रंप को अपनी पिछली विवादित टिप्पणियों से पीछे हटने को बाध्य कर दिया। फ्रांस के शहर बायरिट्ज में जी-7 सम्मेलन से इतर मोदी और ट्रंप की सोमवार को हुई बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने बिना लाग-लपेट अमेरिकी राष्ट्रपति को कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की पेशकश नहीं करने का दो टूक संदेश भी दे दिया। गौरतलब है कि ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से हुई अपनी मुलाकात के दौरान पहली बार कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद के हालातों का हवाला देते हुए ट्रंप ने दूसरी बार मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था। ट्रंप के इन बयानों के बाद मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान उछल रहा था।

बायरिट्ज में मोदी-ट्रंप की बैठक में दोनों नेताओं के मीडिया से रूबरू होने के दौरान कश्मीर पर मध्यस्थता का सवाल मोदी से पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मसले द्विपक्षीय हैं और हम किसी तीसरे देश को इसका कष्ट नहीं देते। हम इन मसलों पर आपसी वार्ता कर इसका हल निकाल सकते हैं।'

इमरान की बौखलाहट पर नमक छिड़कते हुए मोदी ने कहा कि 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे और उन्हें विश्वास है कि दोनों पड़ोसी मुल्क अपनी समस्याओं पर आपस में चर्चा कर इनका समाधान निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं ट्रंप के सामने ही परोक्ष रूप से पाकिस्तान के आर्थिक दिवालियापन के कगार पर होने की ओर इशारा करते हुए मोदी ने इमरान को दोनों देशों की जनता से जुड़े अहम मुद्दों का हल निकालने की नसीहत दी। मोदी ने कहा, 'चुनाव के बाद मैंने प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर हुई चर्चा में कहा था कि भारत-पाकिस्तान दोनों को गरीबी, अशिक्षा और बीमारी से लड़ना है। मैंने उनसे कहा कि हमें अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना है।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी से बातचीत का ब्योरा देते हुए कहा, 'हमने बीती रात कश्मीर पर चर्चा की और प्रधानमंत्री का साफ मानना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वह पाकिस्तान से बातचीत करेंगे और आश्वस्त हैं कि वह कुछ ऐसा करेंगे। यह बहुत अच्छा होगा।' ट्रंप ने कहा कि मोदी और इमरान दोनों से उनके अच्छे रिश्ते हैं और वह उम्मीद करते हैं कि दोनों आपसी वार्ता से मसलों का समाधान निकालेंगे।

ट्रंप ने दिए अहम संकेत : अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बयान के जरिये यह संकेत जरूर दिया कि अनुच्छेद-370 हटाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को कम करने के लिए भारत-पाक के बीच बातचीत की संभावना जल्द बन सकती है। ट्रंप का यह संदेश जहां भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के लिए कश्मीर की मौजूदा हकीकत को स्वीकार कर किसी भी विवाद का हल निकालने की नसीहत भी है।

फ्रांस के बायरिट्ज में जी–7 बैठक से इतर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। मोदी ने ट्रंप से जम्मू–कश्मीर मामले में दो टूक कहा कि हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते। एएनआइ

दोनों नेताओं ने बातचीत को सफल और सकारात्मक बताया

मोदी और ट्रंप दोनों ने मुलाकात के बाद ट्वीट के जरिये इस बैठक को बेहद सकारात्मक और सफल बताया। ट्रंप ने अपने प्रशासन की उपलब्धियों में पीएम के साथ संबंधों को उल्लेख करते हुए कहा, 'मोदी की अगुआई में हम भारत के साथ व्यापार को बढ़ा रहे हैं।' वहीं मोदी ने कहा कि ट्रंप के साथ बैठक बेहद शानदार रही, जिसमें द्विपक्षीय मसलों पर उपयोगी चर्चा हुई और सहमति बनी कि दोनों देश व्यापार के मुद्दों को दोनों के हित में हल करेंगे। मोदी–ट्रंप की बैठक के बाद विदेश सचिव विजय गोखले ने पत्रकारों से कहा कि गर्मजोशी और सकारात्मक माहौल में दोनों नेताओं की बैठक 40 मिनट चली और मोदी–ट्रंप की मई से यह तीसरी मुलाकात है। जम्मू–कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली से जुड़े सवाल पर गोखले ने कहा कि कुछ पाबंदियां अभी कानून व्यवस्था के मद्देनजर लागू रहेंगी।

बैंक घोटाले में शरद और अजीत पवार के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई, आइएएनएस : मुंबई पुलिस ने सोमवार को एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे व राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत कई लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। बांबे हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को इस मामले में एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था। दक्षिणी मुंबई के एमआरए मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस मामले की जांच करेगी।

बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस एसके शिंदे की पीठ ने पिछले हफ्ते कहा था कि आरोपितों के खिलाफ विश्वसनीय सुबूत हैं। पीठ ने ईओडब्ल्यू से उचित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच करने को कहा था। पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता सुरिंदर एम अरोड़ा द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया था।

एफआइआर में शरद और अजीत पवार के अलावा दूसरे दलों के बड़े नेताओं के नाम भी हैं। इनमें राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, पूर्व उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटिल, शिवसेना के आनंदराव वी. अडसुल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 30 जिला सहकारी बैंकों के पूर्व निदेशकों, नाबार्ड, सरकारी और बैंक अधिकारियों के नाम भी एफआइआर में शामिल हैं। इन सभी लोगों को 2007 से 2011 के बीच धोखाधड़ी कर राज्य के सबसे बड़े सहकारी बैंक को एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के लिए आरोपित किया गया है।

न्यूज गैलरी

राज–नीति ▸ पृष्ठ 3

निर्मोही अखाड़े से पूछा, आप रामलला के पक्ष में या विरोध में

नई दिल्ली : राम जन्मभूमि के एक तिहाई हिस्से के मालिक निर्मोही अखाड़ा ने जब सोमवार को रामलला विराजमान की ओर से दाखिल मुकदमे का विरोध जारी रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़ा की पैरवी कर रहे वकील सुशील जैन से पूछा कि वह रामलाल के मुकदमे के समर्थन में हैं या विरोध में।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 7

डिप्लोमाधारी डॉक्टर भी अब बनेंगे सीनियर रेजीडेंट

कानपुर : डिप्लोमाधारी डॉक्टर भी देशभर के चिकित्सा विश्वविद्यालयों, चिकित्सकीय संस्थानों राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजीडेंट बन सकेंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 16 अगस्त को इस आशय का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

फिक्की ने लगाया करीब सात फीसद ग्रोथ रेट का अनुमान

नई दिल्ली : इकोनॉमिक ग्रोथ के कई अनुमान आने के बाद अब इंडस्ट्री चैंबर फिक्की ने भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कम से कम 6.9 फीसद जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान लगाया है। लेकिन पहले आए कई अनुमानों से फिक्की के अनुमान में अंतर यह है कि इसमें माना गया है कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन ही जीडीपी को इस ऊंचाई तक पहुंचेगा।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

पाकिस्तान को काली सूची से बचाने में जुटे इमरान खान

इस्लामाबाद : आतंकी फंडिंग पर पाकिस्तान को काली सूची में डाले जाने के मंडरा रहे खतरे ने प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वह इस खतरे से बचने के प्रयास में जी जान से जुट गए हैं। इसी के तहत उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के सभी 27 बिंदुओं पर अमल करने के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है।

सीबीआइ मामले में याचिका खारिज, ईडी के गिरफ्तार करने पर रोक जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ हिरासत में होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ मामले में अग्रिम जमानत याचिका महत्वहीन बताकर खारिज की

▸ सीबीआइ रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, ईडी के मामले में आज भी जारी रहेगी बहस

आइएनएक्स मीडिया मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार का दिन थोड़ी खुशी थोड़े गम का रहा। कोर्ट ने सीबीआइ के मामले में दाखिल चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका महत्वहीन बताते हुए खारिज कर दी, हालांकि मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत चल रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी रहने के कारण गिरफ्तारी से फिलहाल संरक्षण जारी रखा है। ईडी मामले में बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी। चिदंबरम को एक झटका यह भी लगा कि कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बावजूद सीबीआइ रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए नहीं लगी। अब इस याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई होगी।

चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की हैं। दो में सीबीआइ और मनी लांड्रिंग मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। तीसरी याचिका में चिदंबरम ने सीबीआइ हिरासत में भेज जाने के आदेश को चुनौती दी है।

सोमवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस की शुरुआत करते हुए चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि वह प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया, उन्हें सुने जाने का अधिकार है। लेकिन पीठ ने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद याचिका महत्वहीन हो गई है। कोर्ट ने चिदंबरम से कहा कि वह मामले में नियमित जमानत याचिका दाखिल करें। इसके बाद सिब्बल ने ईडी मामले में अग्रिम जमानत पर बहस की और कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई का उन्हें मौका मिलना चाहिए। उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जब ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था उस समय ये बातें नहीं पूछी थीं जिनके अब आरोप लगाए जा रहे हैं। ईडी कह रहा है कि चिदंबरम की 11 संपत्तियां और 17 बैंक खाते विदेश में हैं जबकि चिदंबरम की न तो कोई संपत्ति और न ही कोई खाता विदेश में है। सिब्बल की ओर से सोमवार को बहस पूरी हो गई। उन्होंने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कोर्ट से मंगलवार तक का समय मांग लिया। मंगलवार को ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे। ईडी ने सोमवार को हलफनामा दाखिल कर चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध किया। हलफनामे में कहा कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट की सूचना के मुताबिक चिदंबरम और सहयोगी साजिशकर्ता अभियुक्तों की संपत्तियां और बैंक खाते विभिन्न देशों में हैं। ये संपत्तियां अर्जेंटीना, आस्ट्रिया, ब्रिटिश वर्जिनिया आइलैंड, फ्रांस, ग्रीस, मलेशिया, मोनक्को, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और श्रीलंका में हैं।

पी चिदंबरम को सोमवार को सीबीआइ कोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया मामले में 30 अगस्त तक के लिए और सीबीआइ की रिमांड में भेज दिया। प्रेट्र

चिदंबरम की सीबीआइ रिमांड की अवधि चार दिन और बढ़ी पेज>>3

आम्रपाली मामले की ऑडिट रिपोर्ट ईडी व पुलिस को देने के निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : घर खरीददारों के पैसे में से 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी करने वाले आम्रपाली के निदेशकों और ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली पुलिस और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) को देने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को आम्रपाली द्वारा जमा कराई गई धनराशि में 7.16 करोड़ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को जारी करने के निर्देश भी दिए ताकि ग्रुप की रुकी हुई परियोजनाओं का काम पूरा किया जा सके। पीठ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकारियों को निर्देश दिए कि घर खरीददारों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नोडल सेल स्थापित करें। साथ ही प्राधिकारियों को आम्रपाली के मामलों से निपटने में कोर्ट रिसीवर और वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमानी के साथ समन्वय के लिए एक ऐसे अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश भी दिया जो उपप्रबंधक से निचले स्तर का नहीं हो। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

आरबीआइ पौने दो लाख करोड़ देने पर राजी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ आरबीआइ के बोर्ड ने स्वीकार की जालान कमेटी की सिफारिशें

आरबीआइ ने जालान कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इसमें से रिकॉर्ड 1,23,414 करोड़ रुपये सरप्लस के रूप में होंगे, जो आरबीआइ चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार को ट्रांसफर करेगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आरबीआइ से लगभग एक लाख करोड़ रुपये सरप्लस मिलने की उम्मीद जताई थी। ऐसे में जालान कमेटी की सिफारिश के आधार पर आरबीआइ से बड़ी रकम मिलने के बाद सरकार के लिए फिस्कल डेफिसिट को काबू रखना आसान हो जाएगा। आरबीआइ से सरप्लस मनी के लिए सरकार लंबे समय से मांग करती रही है।

आरबीआइ ने सोमवार शाम को एक बयान जारी कर कहा कि बैंक के बोर्ड ने सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का निर्णय किया है। इसमें 1,23,414 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरप्लस के रूप में हैं, जबकि 52,637 करोड़ रुपये संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत अतिरिक्त प्रावधान के हैं। आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई आरबीआइ के बोर्ड की 578वीं बैठक में रियलाइज्ड इक्विटी के स्तर को बैलेंस शीट के 5.5 परसेंट पर बनाकर रखने का फैसला किया गया जबकि फिलहाल यह 6.8 परसेंट है। रियलाइज्ड इक्विटी के स्तर को घटाने का ही नतीजा है कि सरकार को 52,637 करोड़ रुपये सरप्लस से अतिरिक्त मिलेंगे। बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि 30 जून 2019 को आरबीआइ वित्तीय मजबूती की दृष्टि से ग्लोबल स्तर पर अच्छी स्थिति में है। यही वजह है कि इस राशि के ट्रांसफर करने का निर्णय किया गया है।

बहरहाल चालू वित्त वर्ष में आरबीआइ सरकार को कुल 1,23,414 करोड़ रुपये सरप्लस देगा, जिसमें से 28,000 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। सरकार ने आरबीआइ के सरप्लस से कुछ राशि लेने के नजरिये से जालान समिति का गठन किया था। यही वजह है कि मोदी सरकार जब दोबारा सत्ता में आई, तो पांच जुलाई को पेश आम बजट में उसने आरबीआइ और सरकारी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से 1,06,041 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में मिलने की उम्मीद जताई। हालांकि पहली फरवरी को पेश अंतरिम बजट में उसने इस मद से 82,911 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद जताई थी। वैसे, चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार को रिकॉर्ड सरप्लस रिजर्व बैंक से प्राप्त होगा। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये सरप्लस ट्रांसफर किया था।

शक्तिकांत दास — फाइल फोटो

आरबीआइ ने कब–कब दिया कितना सरप्लस (रुपये करोड़ में)

वर्ष	सरप्लस
2013–14	52,679
2014–15	65,896
2015–16	65,876
2016–17	30,659
2017–18	50,000
2018–19	1,23,414

फैसले से राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में मिलेगी मदद पेज>>12

भ्रष्टाचार के आरोपित 22 टैक्स अधिकारी जबरन रिटायर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार की बड़ी कार्रवाई

▸ सीबीआइसी ने 22 सुपरिटेंडेंट व एओ स्तर के अधिकारियों को हटाया

▸ मोदी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में जून से अब तक लगभग 50 टैक्स अधिकारियों की कर चुकी है छुट्टी

कारोबारियों को तंग करने वाले और भ्रष्टाचार के आरोपित टैक्स अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए मोदी सरकार ने सीबीआइसी में सुपरिटेंडेंट और एओ स्तर के 22 वरिष्ठ अधिकारियों को नौकरी से जबरन रिटायर कर दिया। इनमें से कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जबकि कुछ को सीबीआइ ने पकड़ा है। इस साल जून के बाद यह तीसरा मौका है जब सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से निकाला है। इसके जरिये सरकार ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार और अक्षमता के खिलाफ उसकी कार्रवाई जारी रहेगी।

सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) ने फंडामेंटल रूल 56 (जे) का इस्तेमाल करते हुए जिन अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है उनमें सीजीएसटी जोन नागपुर, भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मेरठ और मुंबई तथा कस्टम के जोन बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ के अधिकारी शामिल हैं।

सीबीआइसी ने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद उठाया है। पीएम ने कहा था कि टैक्स प्रशासन को कलंकित करने वाले कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने हो सकता है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ईमानदार टैक्सपेयर्स को तंग किया हो। सरकार ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए हाल में कई ऐसे अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया है। उल्लेखनीय है कि सीबीआइसी के इस कदम से पूर्व सरकार ने फंडामेंटल रूल 56 (जे) का इस्तेमाल करते हुए 27 आइआरएस अधिकारियों को जबरन रिटायर किया था जिसमें 12 अधिकारी सीबीडीटी के थे।

सूत्रों ने कहा कि सीबीआइसी ने जिन अफसरों को जबरन रिटायर किया है उसमें 11 अधिकारी नागपुर और भोपाल जोन के हैं। उन पर नियमों का उल्लंघन करते हुए इंदौर की एक सिगरेट कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा एक-एक अधिकारी चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मेरठ और चंडीगढ़ जोन के जबकि दो-दो अधिकारी मुंबई, जयपुर और बेंगलुरु जोन के हैं।

कर्मचारियों की सेवा की समीक्षा कर सकती है सरकार : सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 56 (जे) के तहत सरकार कर्मचारियों की सेवा की समीक्षा कर सकती है और यह देख सकती है कि उनको जनहित में सरकारी नौकरी में बनाए रखा जाए या नहीं। सरकारी नियमों के अनुसार कर्मचारियों के 50-55 की उम्र पर पहुंचने और 30 साल की सेवा पूरी होने के छह महीने पहले अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जा सकती है।

गर्मजोशी

फ्रांस के खूबसूरत शहर बायरिट्ज में हुई दोनों वैश्विक नेताओं की मुलाकात, इस मुलाकात ने बदलकर रख दिए सब समीकरण

दोस्तों की तरह नजर आए ट्रंप–मोदी, बेफिक्री के साथ लगाए ठहाके

जेएनएन, नई दिल्ली

'इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात करना ही नहीं चाहते...' एक दोस्त के इतना कहते ही दूसरा दोस्त जोर से हंस पड़ा। दोनों ने एक-दूसरे के हाथों को गर्मजोशी से पकड़ लिया। एक ने दूसरे के हाथों पर दोस्ती में रची-बसी हल्की सी चपत भी लगा दी और कुछ देर तक हंसी गूंजती रही। एक दोस्त दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री और दूसरा सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका का राष्ट्रपति।

फ्रांस के खूबसूरत शहर बायरिट्ज में सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। मेजबान फ्रांस के विशेष आमंत्रण पर जी-7 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे मोदी ने यहां कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप और मोदी की मुलाकात का इंतजार सबको था। यह मुलाकात इसलिए भी अहम हो गई थी, क्योंकि पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान कश्मीर मसले पर ट्रंप के बयान से हालात कुछ तल्ख हो गए थे। लेकिन जैसे ही फ्रांस में मोदी और ट्रंप की मुलाकात आगे बढ़ी, ट्रंप को लेकर पिछले कुछ दिनों में बनी अविश्वास की छवि भी साफ होती दिखी। मुलाकात में दोनों नेताओं की सहजता से ऐसा लगा मानो पुराने दोस्त कई दिन बाद मिले हों।

दिख रहा था फर्क : मोदी-ट्रंप की बेफिक्र और खिलाखिलाहट भरी बातचीत के बाद ट्रंप-इमरान की मुलाकात से इसकी तुलना भी स्वाभाविक है। एक ओर ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे इमरान पूरी बातचीत में नर्वस दिखाई दिए थे तो दूसरी ओर मोदी आत्मविश्वास से भरे मजबूत नेता के तौर पर दिखे। ट्रंप से मुलाकात के दौरान इमरान कई बार अपनी शेरवानी ठीक करते रहे थे। मुलाकात में दोनों नेताओं का रवैया भी काफी हद तक औपचारिक ही दिखा था। वहीं मोदी-ट्रंप की बातचीत में गंभीरता थी, हंसी थी, ठहाका था, मजाक था और एक-दूसरे के लिए सम्मान की झलक भी। दो अलग-अलग देश के नेताओं के बीच ऐसी गर्मजोशी और बेतकल्लुफी कम ही देखने को मिलती है। दोनों नेताओं की बातचीत के दौरान उस वक्त ठहाका लग गया, जब ट्रंप ने मोदी की अंग्रेजी की तारीफ की। हुआ यूं कि बातचीत के दौरान मोदी ने उपस्थित लोगों से कहा, 'मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने दीजिए। हम दोनों बात करते रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी, आप लोगों तक जरूर जानकारी पहुंचाएंगे।' मोदी के इतना कहते ही ट्रंप ने बात काटते हुए कहा, 'मोदी असल में बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वह बस बात करना नहीं चाहते हैं।'

सोशल मीडिया में छाई रही मुलाकात : मोदी-ट्रंप की यह बेतकल्लुफ मुलाकात कुछ ही देर में मुख्यधारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह छा गई। लोग ट्रंप और इमरान की मुलाकात से भी इसकी तुलना करते देखे गए। एक यूजर ने लिखा, 'मोदी ने चपत तो ट्रंप के हाथ पर लगाई, लेकिन चोट इमरान को लगी होगी।' सोशल मीडिया पर तमाम यूजर इस मुलाकात पर अपनी-अपनी तरह से कमेंट कर लुत्फ उठाते दिखे।

भारत–अमेरिका के बीच आपसी संबंध किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह तस्वीर गहरे रिश्तों को बखूबी बयां करती है। रायटर

> मोदी और ट्रंप की मुलाकात में दोनों की ओर से अपनी सीट पर बैठे–बैठे जो गर्मजोशी दिखाई दी, वह उनके बीच कायम हुए भरोसे के रिश्ते को दर्शाती है।
>
> **– विवेक काटजू, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय**

> खिलखिलाहट के बीच ट्रंप का मोदी की बांह पर मैत्रीपूर्ण तरीके से पंच, आश्चर्य के बीच उन्हें रोकने की भारतीय प्रधानमंत्री की कोशिश (अपने बाएं हाथ को ट्रंप की मुट्ठी के नीचे लाना) और फिर दूसरे हाथ से उस पर हल्के झटके के साथ दबाव डालना उनकी अद्भुत केमेस्ट्री का सुबूत है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह दो दोस्तों के गले मिलने के बराबर है।
>
> **– ख्याति भट्ट, मुंबई की बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट**

मैकबुक प्रो लैपटॉप लेकर विमान यात्रा नहीं करें यात्री : डीजीसीए

नई दिल्ली, प्रेट्र : विमानन नियामक डीजीसीए ने विमान यात्रियों से अपने साथ 15 इंच का मैकबुक प्रो लैपटाप लेकर नहीं चलने को कहा है। एपल ने अपने इस माडल के लैपटॉप में लगी बैटरी के बहुत ज्यादा गर्म हो जाने से आग के खतरे की आशंका जताई है।

एपल ने अपनी वेबसाइट पर मैकबुक प्रो लैपटॉप के माडलों से होने वाले खतरे के बारे में जारी नोटिस में कहा था, 'पुरानी पीढ़ी के 15 इंच के मैकबुक प्रो यूनिट की सीमित संख्या की बैटरी ज्यादा गर्म हो सकती है और आग का खतरा हो सकता है। प्रभावित यूनिटें सितंबर 2015 और फरवरी 2017 के बीच बेची गई थीं। इसकी पहचान सीरियल नंबर से की जा सकती है।' कंपनी ने कहा है कि उसने स्वैच्छिक रूप से प्रभावित बैटरी को कोई शुल्क लिए बगैर बदलने का फैसला लिया है। डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार ने ट्वीट कर सभी विमान यात्रियों से लैपटॉप के प्रभावित माडल के साथ यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है।

35 अध्यापकों को शिक्षक दिवस पर 'सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 13 अध्यापक दिल्ली के हैं। इन्हें योग्यता प्रमाण पत्र, शॉल और 50,000 रुपये नकद दिए जाएंगे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 27 अगस्त 2019

महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए 290 करोड़ का अनुदान पेश

तैयारी ▶ मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर 29 अक्टूबर से डीटीसी की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की थी

डीटीसी बसों में मार्शल की तैनाती के लिए 142 करोड़ रुपये का आवंटन किया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में मेट्रो और बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना के लिए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को विधानसभा में 290 करोड़ रुपये का अनुदान पेश किया। डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए 140 करोड़ और मेट्रो के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा सिसोदिया ने बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी अनुदान पेश किया। वित्त मंत्री ने डीटीसी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल की तैनाती के लिए 142 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर योजना के लिए भी अतिरिक्त 47 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के तहत इस आशय के अनुदान प्रस्ताव को विधानसभा में ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि 29 अक्टूबर से डीटीसी की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। सिसोदिया ने विधानसभा में कहा कि बसों में तो महिलाओं की मुफ्त यात्रा जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन मेट्रो में थोड़ा समय लग सकता है।

दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने जाते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जागरण

सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने वाला दिल्ली दुनिया का पहला शहर : जैन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली दुनिया का पहला शहर है जहां इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे सरकारी तौर पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले लंदन में सरकारी तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, मगर उनकी संख्या बहुत कम है। वह भी कई साल में लगाए गए। जैन दिल्ली विधानसभा में सरकार की सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना पर सत्ता पक्ष द्वारा कराई गई चर्चा पर बोल रहे थे।

जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरी राजधानी में 2.80 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पहले फेज में 1.40 लाख सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और सोमवार को दूसरे फेज में अतिरिक्त 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरों के लिए सरकार ने निविदा जारी कर दी है। निविदा जारी होने के एक साल के भीतर सभी कैमरे लग जाएंगे। इसके बाद पूरी दुनिया में पहली बार किसी शहर पर इतने बड़े पैमाने पर सीसीटीवी से नजर रखी जा सकेगी।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए मंत्री जैन ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में लगने वाली बिजली का खर्च दिल्ली सरकार देगी। फिलहाल जिस तरह के कैमरे लगाए जा रहे हैं, उसमें एक कैमरे में प्रतिमाह 6 यूनिट बिजली खर्च होगी। वहीं, सीसीटीवी के एक पैनल पर 20 यूनिट का खर्चा आएगा। एक पैनल से चार सीसीटीवी कैमरे जुड़े होंगे। इस लिहाज से महीने में कुल 44 यूनिट बिजली का खर्च आएगा। सरकार ने 50 यूनिट तक के लिए डिस्काउंट दिया है।

सत्येंद्र जैन ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक के एचडी कैमरों की रिकार्डिंग एक महीने तक सुरक्षित रखी जा सकेगी। वहीं 50 मीटर के दायरे की तस्वीरें साफ-सुथरी होंगी। वाई-फाई से युक्त सारे कैमरे वायरलेस हैं। अगर किसी कैमरे में कोई खराबी आती है तो तुरंत इसकी सूचना दिल्ली पुलिस के साथ पीडब्ल्यूडी, लगाने वाली कंपनी व आरडब्ल्यूए के पास चली जाएगी। कंपनी पांच साल तक कैमरों को रखरखाव करेगी।

विधायकों ने दिया सरकार को धन्यवाद : अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत करते हुए विधायक जरनैल सिंह ने दिल्ली सरकार को इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए बधाई दी। साथ ही उम्मीद जताई कि कैमरों के लगने से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। दूसरे विधायकों में अखिलेश पति त्रिपाठी, मदन लाल, भावना गौड़, सोमनाथ भारती आदि ने भी अपने विचार रखे।

सिसोदिया ने कहा-छोटे-छोटे अपराधों में आ रही कमी : मनीष सिसोदिया ने सदन में बताया कि सीसीटीवी कैमरों को आम दिल्लीवाले अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर कदम मान रहे हैं। अपना अनुभव साझा करते हुए सिसोदिया ने कहा कि वह जहां-जहां इस बारे में बात करते हैं, वहां के लोगों का मानना है कि बड़े तो नहीं, छोटे-छोटे अपराधों में भी इससे कमी आई है। एक उदाहरण देते हुए सिसोदिया ने बताया कि अभी एक मंदिर कमेटी की तरफ से बताया गया कि कैमरे लगने से ऐसा पहली बार हुआ कि जन्माष्टमी के दौरान उनके मंदिर में चप्पल चोरी नहीं हुई। जिन स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं उनके बच्चे बताते हैं कि अब उनकी पेंसिल गुम नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इलाकों में तैनात पुलिस वाले भी कैमरों को लेकर खुश हैं।

22 अस्पतालों में जुड़ेंगे 11 हजार से ज्यादा बेड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के 19 अस्पतालों के विस्तार की योजना है। इसके अलावा तीन अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इस तरह आने वाले समय में 22 अस्पतालों में कुल 11 हजार 423 बेड बढ़ाए जाएंगे। इससे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दोगुने बेड उपलब्ध होंगे। हालांकि तीन साल में अस्पतालों में करीब 403 बेड बढ़ पाए हैं।

विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने सवाल पूछा था कि सरकार ने अस्पतालों में कितने बेड बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। अस्पतालों में कितने बेड हैं और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितने बेड बढ़े हैं। अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर व एमआरआइ मशीन के संदर्भ में भी जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड क्षमता 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार किया जाएगा। वर्ष 2014-15 में अस्पतालों में 10 हजार 590 बेड स्वीकृत थे। वहीं वर्ष 2017-18 में 11 हजार 353 बेड स्वीकृत थे। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कुल 440 वेंटिलेटर हैं, इनमें से 396 कार्यरत हैं। दिल्ली सरकार के सिर्फ लोकनायक अस्पताल में एमआरआइ मशीन है। इसके अलावा किसी अस्पताल में एमआरआइ मशीन नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने निजी जांच लैबों में मरीजों को नि:शुल्क जांच उपलब्ध कराती है। वहीं सरकार ने बताया कि लोकनायक, जीटीबी सहित 19 अस्पतालों का विस्तार किया जाएगा।

नवंबर में बनकर तैयार होंगे दो अस्पताल : द्वारका, बुराड़ी व आंबेडकर नगर इन तीन जगहों पर नए अस्पताल का निर्माण हो रहा है। इनमें से दो अस्पताल नवंबर में बनकर तैयार होंगे। इनमें अंबेडकर नगर व बुराड़ी के अस्पताल शामिल हैं। इनका कार्य क्रमशः 98 फीसद व 92 फीसद पूरा हो चुका है।

प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की हो रही बिक्री, उच्चस्तरीय जांच के आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली में चाइनीज मांझे से हाल ही में हुई मौत का मुद्दा सोमवार को विधानसभा सत्र में भी उठा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मुख्य सचिव को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर इसकी जांच कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की भी मदद लें और पता लगाएं कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा दिल्ली में बिका कैसे? उन्होंने दोषी विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।

दरअसल, सोमवार को विशेष उल्लेख नियम 280 के तहत सत्तापक्ष के विधायक महेंद्र गोयल ने 15 अगस्त को पश्चिम विहार में चाइनीज मांझे से एक 28 वर्षीय इंजीनियर युवक की मौत का मामला उठाया। यह युवक मोटरसाइकिल पर बहन से राखी बंधवाने जा रहा था, लेकिन मांझे से गर्दन कट जाने के कारण मौत हो गई। सत्तापक्ष के कई अन्य विधायकों ने भी इस पर हैरत जताई कि जब इस मांझे की बिक्री हो ही नहीं सकती, तब इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है?

मालूम हो कि हाई कोर्ट ने दिल्ली में चाइनीज मांझे पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिका। इस मांझे पर कांच की परत होती है जो त्वचा को एकदम काट देती है।

शनिवार को जन्माष्टमी के दिन भी सोनिया विहार पांचवां पुश्ता की रहने वाली एक बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची पिता के साथ पूजा के लिए मंदिर जा रही थी। पुलिस के अनुसार, शनिवार को इशिका ने पिता गिरीश से इच्छा जताई कि उसे हनुमान मंदिर जाकर पूजा करनी है। गिरीश शाम साढ़े छह बजे इशिका को बाइक पर आगे बैठाकर घर से यमुना बाजार हनुमान मंदिर के लिए निकले। जैसे ही वह सोनिया विहार पुश्ता रोड से वजीराबाद रोड पहुंचे, तभी अचानक बाइक के आगे चाइनीज मांझा आ गया। मांझा बच्ची की गर्दन को काटता हुआ निकल गया। बाद में उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका।

> **दिल्ली विधानसभा में भी उठा चाइनीज मांझे से हाल में हुई मौत का मामला**

न्यूज गैलरी

दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया आठवां कटऑफ

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सोमवार रात आठवां कटऑफ जारी किया। डीयू के सभी कॉलेजों में अब भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस पाठ्यक्रम में दाखिले के अवसर हैं। रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज, दौलत राम, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, गार्गी और लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमेन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स में दाखिला ले सकते हैं। डीयू की ओर से कहा गया है कि छात्र मंगलवार को कॉलेजों में दाखिला लेने पहुंचे। दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर जाना होगा। रामजस कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में 95.25 फीसद, हिंदी ऑनर्स में 86.50 फीसद, हिस्ट्री ऑनर्स में 94.75 फीसद और बीकॉम ऑनर्स में 96.75 फीसद तक कटऑफ जारी हुआ। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में बीकॉम ऑनर्स में 98.62 फीसद, हिंदू कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 97.62, बीकॉम ऑनर्स में 97.37 फीसद तक कटऑफ जारी हुआ। हंसराज कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में 97.12 फीसद कटऑफ, दौलत राम कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 95.75 फीसद, फिलॉसफी ऑनर्स में 88.50 फीसद, बीकॉम में 94.75 फीसद और बीकॉम ऑनर्स में 95.50 फीसद कटऑफ जारी हुआ। गार्गी कॉलेज ने बीकॉम में 94 फीसद कटऑफ जारी हुआ। (जासं)

जज साहब, मोटी कहकर प्रताड़ित करता है पति

गाजियाबाद : जज साहब मेरा इंजीनियर पति मुझे मोटी कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ पार्टी में जाने लायक नहीं हो। ऐसे पति से मुझे तलाक चाहिए। अदालत ने महिला की अर्जी स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख लगा दी है। बिजनौर में रहने वाली एक युवती की शादी वर्ष 2014 में मेरठ निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद युवक को नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी मिल गई। इसके बाद वर्ष 2016 से वह पति के साथ इंदिरापुरम क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने लगी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति को मोटी बताकर उत्पीड़न करने लगा। महिला का कहना है कि इंजीनियर पति उसे बात-बात में ताने कसता है। महिला का आरोप है कि पति की इस हरकत से लगातार मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है और डिप्रेशन का शिकार हो रही हूं। (जासं)

पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते लाए जा रहे थे नकली नोट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोटों की तस्करी में नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5.50 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। सभी नोट दो-दो हजार के हैं। आरोपित की पहचान असलम अंसारी के रूप में हुई है। वह पांच साल से तस्करी में लिप्त था और पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते नकली नोट लाकर भारत में खपा रहा था। पिछले एक साल में एक करोड़ के नकली नोट भारत में खपा चुका है। स्पेशल सेल गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।

डीसीपी पीके कुशवाहा ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में नकली नोटों की तस्करी की जा रही है। इसमें अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह सक्रिय हैं। चार महीने की मेहनत के बाद जानकारी मिली कि एक कुख्यात तस्कर 24 अगस्त को दूसरे तस्कर से मिलने नेहरू प्लेस आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने तस्कर असलम अंसारी को धर दबोचा। उसके पास से दो-दो हजार के 275 नकली नोट बरामद किए गए, जो कि देखने में हूबहू असली नोट जैसे हैं। ये नोट इतनी बारीकी से छापे गए हैं कि आम लोग असली और नकली में फर्क नहीं कर सकते। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि नेपाल में अब्दुल रहमान, सज्जाद और शेर मुहम्मद ने नकली नोट मुहैया कराते थे। वह इन्हें लेकर भारत आता था और दिल्ली-एनसीआर के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में खपाता था। बिहार के रक्सौल का एक तस्कर भी इस काम में लगा हुआ है। आरोपित पांच सालों से नकली नोट की तस्करी में लगा हुआ था। असलम ने बताया कि उसने वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद नकली नोटों के काले धंधे पर कुछ दिनों के लिए विराम लगा दिया था, लेकिन एक साल से तस्करी में फिर सक्रिय था।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि नकली नोटों की छपाई पाकिस्तान में होती है और उसे भारत में भेजकर यहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान से दो रास्ते से नकली नोट भारत में लाए जाते हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते मालदा होते हुए नकली नोट भारत में पहुंचते हैं। दूसरा रूट नेपाल के रास्ते रक्सौल बॉर्डर है।

बिना आरएफआइडी टैग के भी मिल रहा प्रवेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश के लिए लागू हुआ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी) टैग लेने के लिए निगम के टोल नाकों पर भीड़ भले ही कम हो गई है, लेकिन लोगों की परेशानी अब भी बरकरार है। अब टैग लेने के लिए दस्तावेजों का जमा कराया जा रहा है। इससे सात दिन बाद टैग लेने के लिए लाइन में लगना होगा। हालांकि, निगम बिना टैग वाली गाड़ियों को बिना जुर्माने के दिल्ली में प्रवेश करने दे रहा है।

दिल्ली के 13 टोल नाकों पर सोमवार को वाहन चालकों और मालिकों को टैग लेने के लिए, दस्तावेज जमा कराने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ा। लोग तीन चार दिन से लाइन में लग रहे थे। जिनका आज नंबर आया है, लेकिन आज भी टैग नहीं मिल पाया। निगम ने केवल दस्तावेज व शुल्क लेकर रसीद दे दी है। इससे इन वाहनों को अब जुर्माना नहीं लगेगा। यह भी देखने में आ रहा है कि निगम ने बिना टैग वाले व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश में ढिलाई दे दी है। बिना टैग वाले मासिक पास धारक वाहन चालकों को बिना रोक टोक के प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। वहीं निगम के मुताबिक अभी तक दो लाख 20 हजार व्यावसायिक वाहन चालकों को टैग जारी कर दिया है। वहीं सोमवार को करीब 150 वाहनों से ही टैग न होने की स्थिति में दोगुना टोल टैक्स जुर्माने के तौर पर वसूल किया। निगम के अनुसार जल्द ही टैग लेने के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।

राशि जब्त का दिखाना होगा सबूत, तब जारी होगा टैग : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ट्रांसपोर्टरों की उस मांग को मान लिया है जिसमें उन वाहनों को टैग जारी कर दिया जाए, जिनका वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र जब्त है। इसमें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय ने कहा कि ऐसे वाहनों को टैग जारी कर दिया जाएगा, जिनकी आरसी या तो चालान में जमा या फिर ऋण देने वाली कंपनी के पास जमा है। इसमें वाहन चालकों को ठोस सबूत देना होगा। इसके आधार पर आरसी की फोटो कॉपी पर आरएफआइडी टैग जारी कर दिया जाएगा।

फल-सब्जी पर असर नहीं, अन्य में देरी की आशंका : दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश के लिए आरएफआइडी टैग लागू होने पर जरूरी वस्तुएं दूध, फल सब्जी की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है लेकिन, अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में देरी हो सकती है। आजादपुर चैंबर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडर्स के महासचिव राजकुमार भाटिया का कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से फल-सब्जी की सप्लाई पर कोई असर नहीं है। क्योंकि इस समय फल और सब्जी का सीजन नहीं है। वह ऑफ सीजन है। हालांकि कूरियर और अन्य सामान लाने वाली कंपनियों के वाहनों को दिक्कत हो रही है।

ट्रांसपोर्टरों ने दी चक्का जाम की चेतावनी : टैग मिलने में हो रही दिक्कतों की वजह से वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर गुस्से में हैं और चक्का जाम करने की चेतावनी दे रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ईपीसीए के चेयरमैन डॉ. भूरेलाल को पत्र लिखकर चक्का जाम की चेतावनी दी है। संगठन से जुड़े हरीश सभरवाल का कहना है हम शनिवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी किया जा सकता है। वहीं अन्य ट्रांसपोर्टर इसके खिलाफ कोर्ट जाने पर भी विचार कर रहे हैं।

गाजीपुर टोल नाके पर बिना आरएफआइडी टैग के दिल्ली में प्रवेश करते व्यावसायिक वाहन। जागरण

डीयू में छात्रसंघ चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में छात्रसंघ चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। छात्र संगठन मतदाताओं के दिलों को जीतने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ) व वामपंथी छात्र संगठन नॉर्थ कैंपस में छात्रों को अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। छात्रों के मुद्दे पर किसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और बीते कुछ सालों में कौन संघर्ष कर रहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं।

कारों में लगे पोस्टर : नॉर्थ कैंपस में निजी कारों के शीशों और दरवाजों पर अपने-अपने प्रत्याशियों के पोस्टर लगाकर छात्र घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में बीते कई वर्षों से यह चलन दिख रहा है। वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर भी प्रत्याशियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं। डीयू प्रशासन ने छात्र संगठनों को पोस्टर लगाने के लिए जगह निर्धारित की है। पोस्टर और पर्चे जहां-तहां न फैलें, इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों का भी पालन किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही चारों तरफ बैनर-पोस्टर देखते ही लग जाता है कि चुनाव होने वाला है। नार्थ कैंपस में वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के पास से निकलती छात्राएं। संजय

एबीवीपी के उम्मीदवार कर रहे छात्रावास में प्रचार : एबीवीपी के दस संभावित प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं ने डीयू के हॉस्टल, पीजी और कॉलेजों में जाकर छात्रों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जाना। उनसे कहा कि संगठन उनकी परेशानी के समाधान के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो वह भी करेंगे। छात्रों ने हॉस्टल की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल की कमी होने से, दूसरे राज्यों से आए विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इसके कारण अन्य प्रदेशों से आ रहे छात्रों को रहने का इंतजाम करने में दिक्कतें आती हैं। एबीवीपी ने नए हॉस्टल के संबंध में अपने प्रयासों की जानकारी दी। उनसे नए हॉस्टल के निर्माण के लिए प्रस्तावित आंदोलनों में भागीदार बनने के लिए समर्थन मांगा।

एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि इस वर्ष हमारे घोषणापत्र के मुख्य एजेंडे में नए छात्रावास के निर्माण की बात प्रमुखता से होगी। छात्रों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त हॉस्टल होने चाहिए। निजी हॉस्टल का किराया भी बहुत बढ़ गया है।

एसएफआइ ने एबीवीपी पर लगाया मारपीट का आरोप, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस संबंध में मॉडल टाउन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

एसएफआइ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय ने आरोप लगाया कि रविवार रात करीब 12 बजे नॉर्थ कैंपस के पास विजयनगर में उनके संगठन के छह कार्यकर्ता नए छात्रों के स्वागत के लिए पोस्टर लगा रहे थे। उसी समय एक गाड़ी से एबीवीपी के आठ कार्यकर्ता हॉकी लेकर आए और उन्हें पीटने लगे। एसएफआइ के दिल्ली के उपाध्यक्ष सुमित कटारिया, कार्यकर्ता हिमांशु और नोएल को चोटें आईं और फ्रैक्चर भी हुआ।

एबीवीपी ने एसएफआइ के आरोपों का खंडन किया है। एबीवीपी की राष्ट्रीय मीडिया को-ऑर्डिनेटर मोनिका चौधरी ने कहा कि एसएफआइ की तरफ से एबीवीपी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और गलत हैं।

इस बार जेएनयू छात्रसंघ में चुने जाएंगे 43 काउंसलर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

> छात्र संघ संविधान में संशोधन कर बढ़ाई गई काउंसलरों की संख्या

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ में इस बार 43 काउंसलर के लिए चुनाव होगा। जेएनयू के स्कूलों में काउंसलर के रूप में छात्र प्रतिनिधियों को चुना जाता है। इस वर्ष इनकी संख्या 12 बढ़ाई गई है। जेएनयू छात्र संघ संविधान में संशोधन करके काउंसलर की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल तक यह संख्या 31 थी, जिसके लिए 100 से ज्यादा प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था।

जेएनयू छात्रसंघ संविधान में यह दूसरा संशोधन है। छात्रसंघ का संविधान 1971 में तैयार किया गया था। पहला संशोधन 1994 में लाया गया, जिसके तहत यौन उत्पीड़न के खिलाफ जेंडर सेंसटाइजेशन कमेटी (जीएसकैश) को शामिल किया गया था। छात्रसंघ के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव हाल ही में जेएनयू की यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग (यूजीबीएम) में सर्वसम्मति से पास हुआ है। इसे शिकायत निवारण समिति की पहल के बाद निर्वाचन महासचिव एजाज अहमद ने प्रस्तावित किया था। शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष ने स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर काउंसलर की संख्या 55 करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यूजीबीएम ने सभी स्कूलों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आधार मानते हुए 43 का प्रस्ताव ही पास किया है।

जेएनयू में नामांकन आज : जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। छात्र संगठनों ने इसकी तैयारी कर ली है। जेएनयू में सभी स्कूलों समेत मुख्य चार पदों - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के पद पर भी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे।

अध्ययन

एम्स सहित विभिन्न संस्थानों की ओर से 2045 लोगों पर किए अध्ययन में सामने आए परिणाम

दिल्ली में 85 फीसद लोगों को दांतों की बीमारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मधुमेह दांतों की बीमारी का भी कारण बन रहा है। सेंटर फॉर क्रोनिक डिजिज कंट्रोल, एम्स, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित कई संस्थानों के डॉक्टरों द्वारा मिलकर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि दिल्ली में 85 फीसद लोग दांत व मसूड़े की बीमारी से पीड़ित हैं। मधुमेह पीड़ितों में दांतों की बीमारी अधिक देखी गई। अध्ययन में पाया गया कि दांतों की बीमारी से पीड़ित ज्यादातर लोग मुख स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं थे। यह अध्ययन 2045 लोगों पर किया गया, जिनमें 53 फीसद पुरुष व 47 फीसद महिलाएं थीं।

अध्ययन में यह पाया गया कि 85 फीसद लोग दांत व मसूड़े से संबंधित कम से कम एक बीमारी से पीड़ित थे। 78.9 फीसद लोग दांतों में कीड़े लगने की बीमारी से पीड़ित पाए गए। वहीं, 35.9 फीसद लोगों को मसूड़े की बीमारी थी। 14.9 फीसद लोगों को फ्लोरोसिस की समस्या थी। खासतौर पर मधुमेह से पीड़ित 42.3 फीसद लोगों में मसूड़े की परेशानी थी। जिन्हें मधुमेह नहीं था, उनमें से 31 फीसद लोगों को ही मसूड़े की परेशानी थी।

इस अध्ययन में शामिल एम्स के इंडोक्राइनोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. निखिल टंडन ने कहा कि अध्ययन के माध्यम से मधुमेह व मुख स्वास्थ्य के बीच संबंध देखने की कोशिश की गई है। हैरानी वाली बात यह सामने आई कि यहां सिर्फ 15 फीसद लोगों को दांत व मसूड़े की कोई बीमारी नहीं है। शोध में पता चला कि 26 फीसद लोग ही सुबह व शाम ब्रश करते हैं। इसके अलावा 31 फीसद लोग दांतों के इलाज के लिए दंत चिकित्सक के पास जाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि 69 लोगों ने दांतों के इलाज के लिए संबंधित डॉक्टरों से संपर्क नहीं किया था। विकसित देशों में फैमिली फिजिशियन की तरह दांतों के डॉक्टर से हर परिवार के लोग संपर्क में रहते हैं। यहां ऐसा कोई चलन नहीं है। जिन लोगों को मधुमेह है, उनमें दांत व मसूड़े की बीमारी होने की आशंका ज्यादा है। ऐसे मरीजों को खासतौर पर दांतों की सफाई व मसूड़ों का ध्यान रखना चाहिए। समय-समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच करानी चाहिए ताकि मुख स्वास्थ्य बेहतर रहे।

केवल 26 फीसद लोग ही सुबह और शाम ब्रश करते हैं। (प्रतीकात्मक)

क्यों जरूरी है मुंह का स्वास्थ्य बेहतर रखना

देश में सात करोड़ से ज्यादा लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। वहीं, दांतों की बीमारी से भी ज्यादा लोग ग्रसित हैं। दांतों व मसूड़े की बीमारी हृदय की बीमारी का कारण बन सकती है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है।

कार किराये पर लगवाने के बहाने 50 लोगों से ठगी, किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

खुद को टूर एंड ट्रैवल कंपनी का मालिक बताकर लोगों की कारों को होटल में किराये पर लगवाने के बहाने ठगी करने के मामले में एक युवक को क्राइम ब्रांच की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले सूरज सिंह के रूप में हुई है। 24 वर्ष का सूरज अब तक 50 से अधिक लोगों से ठगी कर चुका है और सौ से ज्यादा कारों को बेच चुका है। उसके पास से दो लाख रुपये, सौ ग्राम सोने के बिस्कुट सहित आभूषण बरामद किए गए हैं, जो उसने ठगी के पैसों से खरीदे थे।

डीसीपी डॉ. जी राम गोपाल नाइक ने बताया कि 14 अगस्त को गांधी नगर थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि सूरज सिंह ने खुद को टूर एंड ट्रैवल कंपनी का मालिक बताकर उनकी कार को ट्रैवल एजेंसी में लगाकर अच्छा किराया दिलाने के नाम पर ठगी की है। पीड़ित ने कई कार एजेंसी में लगाने के लिए दी थीं। उसने शुरुआत में कुछ पैसे दिए, लेकिन सात-आठ माह से उसने किराये के रूप में पैसे देने बंद कर दिए। पांच अगस्त को वह भाग गया। मामले की जांच करने के लिए एसीपी पंकज सिंह के नेतृत्व में बनी एसटीएफ ने सूरज की जानकारी के आधार पर सूरज को पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी की और रविवार को उसे आनंद विहार से पकड़ लिया। वह उस समय मुंबई भागने की तैयारी में था।

पूछताछ में उसने बताया कि सीमापुरी में उसकी दोस्ती बिलाल और महबूब से हुई। जनवरी 2018 में तीनों ने लोगों को ठगने की साजिश रची और गाजियाबाद के साहिबाबाद में ट्रैवल एजेंसी खोलकर सूरज सिंह को आगे कर दिया गया। वे लोगों की कारों को ट्रैवल कंपनी के जरिये होटल में लगवाकर 60 हजार रुपये से दो लाख रुपये प्रतिमाह किराया देने का झांसा देते थे। शुरुआत में कुछ पैसे कार मालिक को देते, लेकिन बाद में उसके नाम से नई कार खरीदने के नाम पर उस पैसे को वापस ले लेते थे।

नोएडा में स्पाइस मॉल में लगी आग

जासं, नोएडा : सेक्टर-25ए स्थित स्पाइस मॉल की तीसरी मंजिल पर स्थित लेजेंड्स बार्बेक्यू रेस्त्रां की चिमनी में सोमवार दोपहर आग लग गई। प्रबंधन ने मॉल के अंदर मौजूद करीब एक हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

स्पाइस मॉल में तीसरी से पांचवीं मंजिल में बने सिनेमा हाल के आठ स्क्रीन हैं। चार स्क्रीन पर मूवी चल रही थी। मॉल के अंदर धुंआ फैलने लगा, तब सबको जानकारी हुई। दुकानदारों ने बताया कि तीसरी मंजिल पर लेजेंड्स बार्बेक्यू रेस्त्रां है। रेस्त्रां की चिमनी में आग लग गई। चिमनी के अंदर गंदगी थी। इस वजह से आग भड़क गई।

धुएं से मॉल के अंदर लगा अलार्म नहीं बजा। इस वजह से सिनेमा हाल में फिल्म देख रहे दर्शकों को मॉल प्रबंधन के कर्मचारियों ने आग लगने की जानकारी दी। इस पर लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कर्मचारियों ने किसी तरह उन्हें सुरक्षित निकाला। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि अग्निशमन विभाग को पत्र भेज कर मॉल में अग्निशमन व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी।

2009 से 2018 के बीच 1,400 नक्सली मारे गए थे। वहीं इस साल पहले पांच महीनों में नक्सली हिंसा की 310 घटनाएं हुईं, जिसमें 88 लोग मारे गए। यह जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में दी गई है।

अब मनमोहन सिंह को नहीं मिलेगी एसपीजी सुरक्षा

- खतरे का आकलन करने के बाद सरकार ने उठाया कदम
- अब मिलेगी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों वाली जेड प्लस सुरक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुरक्षा एजेंसियों की ओर से खतरे का आकलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की सुरक्षा हटा ली गई है। एसपीजी की जगह उन्हें अर्द्धसैनिक बल की जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां पूर्व प्रधानमंत्री पर खतरे का हर साल आकलन करती हैं और उसी आधार पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। गृह मंत्रालय के अनुसार, मनमोहन सिंह को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय और गृह मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर खतरे का तीन महीने तक आकलन किया जिसमें विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की मदद ली गई। वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार पर खतरे के आकलन के बाद ही उन्हें एसपीजी के बजाय जेड प्लस सुरक्षा देने का फैसला किया गया। एसपीजी देश की सबसे सक्षम सुरक्षा एजेंसी मानी जाती है जो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है। गांधी परिवार के सदस्यों को भी यही सुरक्षा हासिल है।

एसपीजी के सुरक्षा घेरे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फाइल फोटो। आर्काइव

मनमोहन की सुरक्षा से एसपीजी को हटाए जाने के बाद अब यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। दरअसल, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में एसपीजी का गठन किया गया था और 1988 में संसद ने इससे संबंधित कानून पर मुहर लगाई थी। उस समय इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा को शामिल नहीं किया गया था। 1989 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने और 1991 में उनकी हत्या के बाद एसपीजी कानून में संशोधन कर सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को कम से कम 10 साल तक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया। लेकिन 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसमें फिर से संशोधन कर पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा की जरूरत का आकलन 10 साल के बजाय हर साल करने का प्रावधान कर दिया।

इस बीच, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा चुनिंदा तरीके से वापस नहीं ली जानी चाहिए।

हुड्डा, वोरा व एजेएल के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायत

राजेश मलकानियां, पंचकूला

एजेएल प्लॉट आवंटन प्रकरण में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा एवं एजेएल (एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां विशेष अदालत में अभियोजन की शिकायत दाखिल की है। अदालत ने अगली सुनवाई 16 सितंबर को मुकर्रर की है। फिलहाल आरोपित पक्ष को कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर एसके कांतिवाल अदालत में मौजूद थे। आरोप है कि हुड्डा ने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था।

पंचकूला स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर एजेएल को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल ईडी ने कुर्क कर लिया था। एजेएल नेशनल हेरल्ड अखबार का प्रकाशन करता था। ईडी ने जांच में पाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान पद का दुरुपयोग करते हुए यह भूखंड पुनःआवंटन की आड़ में नए सिरे से एजेएल को वर्ष 1982 में तय की गई दर (91 रुपये प्रति वर्ग मीटर) से उसमें ब्याज जोड़ते हुए गैरकानूनी तरीके से आवंटित कर दिया। एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुनः आवंटन से एजेएल को अनुचित फायदा हुआ। पुनः आवंटन के समय इसका बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रुपये था, जबकि इसे 69.39 लाख रुपये में ही दे दिया गया। सीबीआइ के विशेष जज जगदीप सिंह ही ईडी मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा | मोतीलाल वोरा

समान नागरिक संहिता पर एक और याचिका दायर

जासं, नई दिल्ली : देश में समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका में इसका प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायिक आयोग अथवा विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्देश केंद्र सरकार व विधि आयोग को देने की मांग की गई है।

हाई कोर्ट ने इस याचिका को पूर्व में दायर याचिका के साथ जोड़कर मंगलवार के लिए सुनवाई तय की है। अधिवक्ता अभिनव बेरी ने अपनी याचिका में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को लागू किए बिना महिलाओं को लिंग समानता, न्याय और सम्मान नहीं मिल सकता। इस अनुच्छेद का मकसद ही देश में समान नागरिक संहिता लागू करवाना है। इसलिए इस संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए न्यायिक आयोग अथवा विशेषज्ञ कमेटी बनाने का निर्देश विधि आयोग व केंद्र सरकार को दिया जाए।

वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की मूल याचिका के खिलाफ अर्जी दायर कर अपना विरोध जता चुका है।

बोइंग ने वायुसेना को सौंपा 11वां सी–17 ग्लोबमास्टर विमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने सोमवार को भारतीय वायुसेना को 11वां सी-17 ग्लोबमास्टर-3 परिवहन विमान सौंप दिया। इस विमान के मिलने से वायुसेना की सामरिक क्षमताओं में जबर्दस्त इजाफा होगा।

सी-17 ग्लोबमास्टर-3 प्रीमियर परिवहन विमान है। विशालकाय, मजबूत और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकने वाला यह विमान सभी तरह के मौसम में बड़े युद्धक उपकरण और सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। यह विमान वायुसेना की सामरिक और युद्धक क्षमताओं का अहम हिस्सा है। 2013 में वायुसेना की 'स्काई लॉर्ड्स स्क्वाड्रन' में शामिल किए जाने के बाद से सी-17 ने सैन्य अभियानों में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। साथ ही भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति अभियानों में मदद, मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी मददगार साबित हुआ है।

कंपनी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, तकनीक, साजो-सामान और विमान को उड़ाने वाले पायलटों को प्रशिक्षण देने समेत बोइंग भारतीय वायुसेना की सी-17 फ्लीट का रखरखाव कर रहा है। मालूम हो कि बोइंग ने 2016 में सी-17 का सिम्यूलेटर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया था जहां भारतीय वायुसेना को प्रशिक्षण सेवा प्रदान की जाती है। यहां अब तक 5,100 घंटों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इस आपूर्ति के साथ ही दुनियाभर में बोइंग निर्मित 275 सी-17 विमान संचालन में आ गए हैं।

निर्मोही अखाड़े से सवाल, आप रामलला के पक्ष में या विरोध में

अहम मामला ▶ कोर्ट ने मंगलवार को इस पर स्थिति साफ करने को कहा

जब देवता ही नहीं रहेंगे तो उनकी सेवा, पूजा और प्रबंधन का अधिकार कैसे रहेगा

माला दीक्षित, नई दिल्ली

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में राम जन्मभूमि के एक तिहाई हिस्से के मालिक निर्मोही अखाड़ा ने जब सोमवार को रामलला विराजमान की ओर से दाखिल मुकदमे का विरोध जारी रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़ा की पैरवी कर रहे वकील सुशील जैन से पूछा कि वह रामलाल के मुकदमे के समर्थन में हैं या विरोध में। दशकों पुराने मामले में 12वें दिन सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि वह बेवजह देवता (रामलला विराजमान) के मुकदमे का विरोध क्यों कर रहे हैं। दोनों पक्ष साथ हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर देवता ही नहीं रहेंगे तो उनकी सेवा, पूजा और प्रबंधन का अधिकार कैसे रहेगा। वह मस्जिद के तो सेवादार हो नहीं सकते।

हाई कोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था जिसमें एक हिस्सा रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। सभी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। कुल 14 क्रॉस अपीलें दायर की गई हैं जिन पर पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है।

निर्मोही अखाड़ा की ओर से कहा गया कि राम जन्मभूमि मंदिर 1850 से भी पहले से है और हिंदू पूजा करते चले आ रहे हैं। हिंदुओं ने कभी यहां अपना अधिकार नहीं छोड़ा। निर्मोही अखाड़ा शुरू से यहां पूजा सेवा और प्रबंधन करता रहा है। निर्मोही अखाड़ा का ही जन्मभूमि मंदिर पर कब्जा था। जैन ने कहा कि कोर्ट उन्हें पूजा सेवा प्रबंधन और कब्जा दिलाए। जब जैन ने रामलला विराजमान की ओर से निकट मित्र बन मुकदमा दाखिल करने वाले देवकी नंदन अग्रवाल पर सवाल उठाया तो कोर्ट ने कहा कि आप देवता के मुकदमे का विरोध कैसे कर सकते हैं। आप रामलला का मुकदमा खारिज करने की मांग कर रहे हैं।

जैन ने कहा कि वह रामलला और जन्मस्थान का विरोध नहीं कर रहे और न ही जमीन पर मालिकाना हक मांग रहे हैं, वह सिर्फ सेवा पूजा का अधिकार और कब्जा मांग रहे हैं। उनका विरोध निकट मित्र देवकी नंदन अग्रवाल को लेकर है। देवकी नंदन अग्रवाल को निकट मित्र की हैसियत से मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। सेवा पूजा करने वाला प्रबंधक भगवान की ओर से मुकदमा कर सकता है और उसके मुकदमे में जरूरी नहीं है कि वह भगवान को भी पक्षकार बनाए।

जैन ने कहा कि अगर निकट मित्र का मुकदमा नहीं रहेगा तो जन्मभूमि पर सारा कब्जा उन्हें ही मिलेगा। इन दलीलों पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि मंगलवार को नोट दाखिल कर इस मुद्दे पर बहस करें और स्थिति स्पष्ट करें कि वह रामलला के मुकदमे का समर्थन कर रहे हैं या विरोध। रामलला के मुकदमे के विरोध पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह बेवजह खिलाफत क्यों कर रहे हैं। दोनों एक साथ रह सकते हैं। वह अलग से सेवा और पूजा का अधिकार मांग सकते हैं। उन्हें टकराव में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सब तो सुन्नी वक्फ बोर्ड कहेगा। कोर्ट ने कहा कि वह अपने सेवादार होने के साक्ष्य पेश करें। जैन ने कई गवाहों के बयान और दस्तावेज का हवाला दिया। बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एफ. एम. कलीफुल्ला की अध्यक्षता में बनाए गए मध्यस्थता कमेटी के प्रयास के बाद भी इस मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छह अगस्त से सुनवाई शुरू की है।

बैंक लोन घोटाले में रतुल पुरी फिर चार दिन की रिमांड पर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 354 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में पूछताछ के लिए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने फिर से चार दिन की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हवाले कर दिया है। छह दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने सोमवार को पुरी को अदालत में पेश कर पांच दिन की रिमांड मांगी थी।

ईडी ने अदालत को बताया कि रतुल पुरी सवालों के जवाब सही ढंग से नहीं दे रहे हैं। किसी सवाल का जवाब मिलता है कि मुझे नहीं पता और किसी का जवाब मिलता है कि याद नहीं है। मोजर बेयर कंपनी से संबंधित करीब पांच जीबी डाटा जुटाया गया है और इसकी जांच करनी है। एक आरोपित से पुरी का आमना-सामना भी कराना है। इसलिए रिमांड की जरूरत है। रतुल के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि जांच एजेंसी बेवजह फिर से रिमांड मांग रही है। यह नागरिक की स्वतंत्रता है कि वह सवालों का जवाब दे या ना दे। अदालत ने आदेश दिया था कि पुरी अपने वकील से 15 मिनट के लिए रोजाना अकेले में मिल सकते हैं, लेकिन यह आदेश नहीं माना गया। उन्हें फिर से रिमांड पर भेजने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की सलाह पर कुछ दवाइयां पुरी के लिए जरूरी हैं, यदि रिमांड दी जाती है तो ये दवाइयां मुहैया कराई जानी चाहिए। अदालत ने रतुल को चार दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि सीबीआइ ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रतुल के खिलाफ 354 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। मामले में रतुल के पिता दीपक पुरी, मां नीता सहित कई अन्य भी आरोपित हैं।

चिदंबरम की सीबीआइ रिमांड की अवधि चार दिन और बढ़ी

- सॉलिसिटर जनरल ने कहा, पूछताछ नहीं हुई पूरी इसलिए रिमांड जरूरी
- चिदंबरम के वकील और परिवार के सदस्य प्रतिदिन आधे घंटे मिल सकेंगे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया घोटाले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को फिर से चार दिन की रिमांड पर सीबीआइ के हवाले कर दिया। अब 30 अगस्त को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआइ ने 21 अगस्त की देर शाम गिरफ्तार कर अगले दिन उन्हें अदालत में पेश किया था। तब उन्हें 26 अगस्त तक के लिए रिमांड पर भेजा गया था।

सोमवार को सीबीआइ ने चिदंबरम को अदालत में पेश किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछताछ पूरी न होने का हवाला देते हुए फिर से पांच दिन की रिमांड मांगी। कहा कि चिदंबरम का अन्य आरोपितों से आमना-सामना कराना है। अभी तक एक आरोपित से ही सामना कराया जा सका है। कुछ ई-मेल के बारे में भी पूछताछ जरूरी है। वहीं, चिदंबरम की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने कहा कि सीबीआइ के तर्क पर चार दिन की रिमांड मंजूर की जाती है। जांच अधिकारी को कानून के दायरे में रहकर तय समय में जांच पूरी करनी होगी। इस बीच चिदंबरम के वकील और परिवार के सदस्य प्रतिदिन आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकेंगे।

अदालत ने पूछा, चार दिन में क्या किया : अदालत ने सीबीआइ से पूछा कि चार दिन आपने क्या किया? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि जांच से संबंधित कुछ दस्तावेज और साक्ष्य प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआइ को दिए हैं। इन साक्ष्यों पर चिदंबरम से पूछताछ बेहद जरूरी है। ईडी ने इस संबंध में एक शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। पांच देशों को पत्र लिखे गए हैं, जिनमें चिदंबरम के विदेशी बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

सिब्बल ने कहा, एक भी दस्तावेज नहीं आया सामने : सीबीआइ की दलीलों का विरोध करते हुए सिब्बल ने कहा कि पूरी जांच हवा में है। इतनी लंबी पूछताछ में एक भी दस्तावेज सामने नहीं आया। पहले पांच मिलियन डॉलर राशि की जांच का हवाला देकर रिमांड पर लिया गया था, लेकिन चार दिन तक इस बारे में कोई पूछताछ ही नहीं हुई। आखिर सीबीआइ अदालत को सही जानकारी क्यों नहीं दे रही? कम से कम जांच की प्रक्रिया तो साफ-सुथरी होनी चाहिए। उन्होंने चिदंबरम से दो मिनट बात करने की अनुमति भी मांगी, जो दे दी गई।

सीबीआइ की केस डायरी हो गई खत्म

सीबीआइ की तरफ से पेश केस डायरी सही नहीं थी। जब अदालत ने टोका तो बताया कि चलन वाली केस डायरी खत्म हो गई है, क्योंकि प्रिंटर के साथ कुछ समस्या है। केस डायरी का एक प्रारूप होता है, जबकि सीबीआइ ने सामान्य कागजों पर जानकारी दर्ज कर पेश कर दी थी।

प्रज्ञा का विवादित बयान, कहा–विपक्ष की 'मारक शक्ति' से मारे जा रहे भाजपा नेता

- कई भाजपा नेताओं की मौत पर जताई आशंका, कांग्रेस का पलटवार
- भाजपा नेताओं ने साध्वी प्रज्ञा के बयान से किया किनारा

नईदुनिया, भोपाल

भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। सोमवार सुबह मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित शोकसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्ष 'मारक शक्ति' का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस ने इस बयान को मूर्खतापूर्ण करार दिया है, वहीं भाजपा ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह साध्वी की निजी राय है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित शोकसभा में साध्वी ने कहा कि 'एक कठिन समय चल रहा है। मैं जब चुनाव लड़ी, उस समय एक महाराज जी आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना। साधना का समय बढ़ाते रहना, क्योंकि बहुत बुरा समय है। विपक्ष 'मारक शक्ति' का प्रयोग भाजपा पर कर रहा है। यह निश्चित रूप से भाजपा के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो पार्टी को संभालते हैं, उन पर असर करेगा। उनको हानि पहुंचा सकता है। आप निशाने पर हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा और ये होने वाला है। उन महाराजजी की बात को मैं भूल गई, परंतु आज जब मैं देखती हूं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, कभी सुषमा स्वराज जी, बाबूलाल गौर जी, जेटली जी पीड़ा सहते-सहते जाते हैं। मन में एक बार आया, कहीं ये सच तो नहीं। ये आज भी प्रश्नवाचक है, परंतु सच ये है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व निरंतर जा रहा है, असमय जा रहा है।' शोकसभा के बाद मीडिया की ओर से इस बारे में पूछने पर प्रज्ञा ने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जो कह दिया, सो कह दिया।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर फाइल फोटो

भार्गव ने जताई असहमति : प्रज्ञा के बयान पर मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि ये उनके ज्ञान की बात है। मारक शक्ति के बारे में वही बता सकती हैं। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं।

संगठन ने साध्वी को किया तलब : साध्वी प्रज्ञा के विवादास्पद बयान पर भाजपा संगठन ने उनको तलब किया है। उन्हें ऐसे बयान न देने की सख्त हिदायत दी गई है। समझाइश के बाद साध्वी ने भी बयान पर चुप्पी साध ली।

प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर मप्र के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा को प्रज्ञा ठाकुर को संसद नहीं, बल्कि किसी बड़े मंदिर का पुजारी बनाना था, जहां वे पूजा-पाठ करतीं। वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने सांसद की सोच को छोटी और ओछी बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने बयान को मूर्खतापूर्ण व आपत्तिजनक बताया।

शाह का मंत्र, फंडिंग रोकने से खत्म होगा नक्सलवाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को जीतने के लिए उनकी फंडिंग रोकने को मूलमंत्र बताया। वामपंथी उग्रवाद को लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए उन्होंने इसके लिए केंद्र और राज्यों की साझा लड़ाई की जरूरत बताई। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों व केंद्र के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नक्सल इलाकों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के साथ-साथ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की भी समीक्षा की गई।

जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकियों की फंडिंग पर रोक लगाकर स्थिति को काबू करने में सफल रहे शाह नक्सलवाद के खिलाफ भी यही तरीका अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फंडिंग पर लगाम के जरिये नक्सलियों के रहने, खाने-पीने, घूमने, हथियारों की खरीद, ट्रेनिंग आदि व्यवस्थाओं को रोका जा सकता है। उनका कहना था कि वामपंथी उग्रवादी सत्ता हथियाने एवं अपने लाभ के लिए सबसे कम विकसित क्षेत्रों में निर्दोष लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, उसमें वामपंथी उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को नक्सलियों के सफाए के लिए बुलाई गई नक्सल प्रभावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह। साथ में हैं गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी(दाएं) और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। प्रेट्र

बैठक में मौजूद मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम लगाने के लिए किए जा रहे उपायों और जरूरतों के बारे में बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां अधिक केंद्रीय सहायता की जरूरत बताई, वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने नक्सल इलाकों में विकास गतिविधियों को तेज करने व संचार माध्यम की पहुंच बढ़ाने की जरूरत बताई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद थे।

शाह ने पिछले एक दशक में नक्सली हमलों में आ रही कमी का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि पिछले साल केवल 60 जिलों में वामपंथी उग्रवाद की घटना नोट की गई है। उन्होंने इसे राज्य सरकार, राज्य के सुरक्षा बल तथा केंद्रीय बलों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा बताया। उन्होंने आगे भी इस समन्वय को कायम रखने की जरूरत बताई।

नक्सलवाद के खिलाफ 2015 की राष्ट्रीय नीति का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस के आधुनिकीकरण और उन्हें बेहतर हथियार व सुविधाएं मुहैया कराने में राज्यों को केंद्र हरसंभव मदद उपलब्ध कराता रहेगा। नक्सलियों के चंगुल में फंसे लोगों को मुख्यधारा में लाने की कोशिशों को तेज करने के लिए उन्होंने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने की जरूरत बताई।

नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में आ रही दिक्कतों और भविष्य की जरूरत के अनुसार नई योजनाओं को तैयार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी, कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय भी मौजूद थे।

बदली नीति

लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी ने किया साफ कि राजद किसी विशेष जाति या समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि यह सबकी है

माय समीकरण से पीछा छुड़ाने की कोशिश में तेजस्वी

- लोकसभा चुनाव में हार के बाद नया फार्मूला अपना रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष
- पदाधिकारियों से किया साफ, पार्टी में पद पाने के लिए अब प्रदर्शन जरूरी होगा

अरविंद शर्मा, पटना

तीन महीने की राजनीतिक शिथिलता के बाद तेजस्वी यादव 'अति सक्रिय' होकर लौटे हैं तो राजद में सबकुछ बदल कर रख देना चाह रहे हैं। जिन कारणों से लोकसभा चुनाव में पार्टी और गठबंधन की हार हुई थी, उससे भी पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मुस्लिम-यादव (माय) के तुष्टीकरण के लिए बदनाम राजद में अबकी सबको लेकर चलने की नसीहत दी जा रही है।

माय समीकरण की खुलेआम वकालत कर करीब डेढ़ दशक तक बिहार की सत्ता में मजबूती से बने रहने वाले लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी ने पहली बार साफ किया है कि राजद किसी विशेष जाति या समुदाय की पार्टी नहीं है, बल्कि यह सबकी है। राजद के सदस्यता अभियान में तेजस्वी ने पार्टी पदाधिकारियों से सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर नए सदस्यों को जोड़ने की हिदायत दी है। बकौल तेजस्वी, राजद संगठन में सभी समुदायों, वर्गों, जातियों एवं धर्मों के लोगों के चेहरे नजर आने चाहिए।

तेजस्वी के नए फार्मूले को लोकसभा चुनाव में हार से जोड़कर देखा जा रहा है। तब पांच दलों के महागठबंधन में राजद ने सामाजिक समीकरण पर ध्यान नहीं दिया था। अपने हिस्से की 20 सीटों में अधिकतर प्रत्याशी यादव और मुस्लिम समुदाय से ही उतारे थे। टिकट वितरण में ब्राह्मण, भूमिहार एवं कायस्थ जाति की पूरी तरह अनदेखी की गई थी। गरीब सवर्णों के आरक्षण का विरोध भी अकेले राजद ने ही किया था। इसका नतीजा हुआ कि राजद अपने हिस्से की सारी सीटें हार गया था।

तेजस्वी यादव फाइल फोटो

पार्टी पर नियंत्रण की कोशिश : लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राजद की किसी बैठक में शिरकत करते हुए तेजस्वी ने परिक्रमा करने में जुटे पदाधिकारियों को साफ कर दिया कि पार्टी में पद पाने के लिए अब प्रदर्शन जरूरी होगा। अभी तक राजद में पद पाने का कोई पैमाना नहीं था। लालू परिवार की सिफारिश पर कोई भी पद प्राप्त कर लेता था। तेजस्वी ने काम को आधार पर बनाकर पार्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण की कोशिश की है। सभी पदाधिकारियों और विधायकों का लक्ष्य तय कर दिया है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को कम से कम 15 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रखंड और पंचायत स्तर के लिए भी मानक तय कर दिया गया है। तेजस्वी राज्य के सभी 72 हजार बूथों पर राजद की मौजूदगी चाहते हैं।

कांग्रेस में उठी राजद से नाता तोड़ने की मांग : कांग्रेस में एक बार फिर राजद से नाता तोड़ने की बात उठने लगी है। सोमवार को पार्टी की सलाहकार समिति की बैठक में कई नेताओं ने सुझाव दिया कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। पांच विधानसभा सीटों पर शीघ्र ही होने वाले उपचुनाव से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए।

आरटीआइ पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सभी राज्य सरकारों को ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) 'प्रवासी लीगल सेल' द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त नोटिस जारी किए। एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता जोस अब्राहम ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के वास्तविक उद्देश्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाकर सरकारी जानकारियों के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय से जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कानून के सबसे प्रभावी प्रावधानों में से एक धारा-7(1) है जिसके मुताबिक व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली जानकारी आवेदन मिलने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

कह के रहेंगे माधव जोशी

2.3 लाख करोड़ रुपये का बजट जुलाई में पेश किया गया आंध्र प्रदेश में। राज्य का कर्ज 2018–19 में 2.59 लाख करोड़ रुपये था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 27 अगस्त 2019

न्यूज गैलरी

विस में शोक प्रस्ताव के दौरान बजी विधायकों के फोन की घंटी

कोलकाता : मानसून सत्र के 45 दिनों के भीतर सोमवार से एक बार फिर बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन जब शोक प्रस्ताव पेश किया जा रहा था तभी कुछ विधायकों को इधर–उधर टहलते देखा गया। इतना ही नहीं शोक प्रस्ताव के समय ही कुछ विधायकों का मोबाइल फोन बज उठा। इससे विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी नाराज हो गए और विधायकों को फटकार लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि विधानसभा को क्लब नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा तरीका सही नहीं है। सोमवार को सत्र के प्रथम दिन नियमानुसार अजय मुखर्जी, शीला दीक्षित, सुष्मा स्वराज, अरुण जेटली के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान कुछ विधायकों को अधिवेशन कक्ष में घूमते फिरते देखा गया। इसके बाद अध्यक्ष जब शोक प्रस्ताव पढ़ना शुरू किए तभी कुछ विधायकों के फोन की घंटी बज उठी। शोक प्रस्ताव जब समाप्त हुआ तब माकपा विधायक तन्मय भट्टाचार्य ने यह मुद्दा उठाया, जिस पर जवाब देते हुए विधानसभा स्पीकर ने कहा 'विधायक टहल रहे हैं, फोन की घंटी बज रही है, यह सब क्या है? कृपया विधानसभा को क्लब ना बनाया जाए।' (जासं)

आज रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी और प्रियंका

रायबरेली : कांग्रेस का गढ़ रहे रायबरेली में मंगलवार को सियासत का 'स्टारवार' देखने को मिलेगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत कर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे तो वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रेल कोच कारखाने के निगमीकरण के विरोध में केंद्र सरकार को घेरेंगी। प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में सुबह ही पहुंच जाएंगी। पहले लालूपुर में कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के घर जाकर उनके पिता अखिलेश सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। दोपहर 1.45 बजे आधुनिक रेल कोच कारखाना ऐहार पहुंचेंगी। वहीं दूसरी तरफ योगी दोपहर एक बजे पुलिस लाइंस उतरेंगे। वहां से सीधे शहर में राना बेनी माधव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। (जासं)

सिंधिया बोले– भाजपा में शामिल होने की बात अफवाह

उज्जैन : परंपरा के अनुसार उज्जैन के गोपाल मंदिर में महाकाल की सवारी का पूजन करने आए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा में शामिल होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके भाजपा में शामिल होने की बात केवल अफवाह है। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी नेता के संपर्क में नहीं हैं। प्रदेश में लगातार कमजोर हो रही भाजपा बौखलाई हुई है, इसलिए अफवाह फैला रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सिंधिया के भाजपा में जाने की खबर वायरल हो गई थी। (नईदुनिया)

अनुच्छेद 370 पर अब जनता को जागरूक करेगी भाजपा

रणनीति ▸ विपक्ष के दुष्प्रचार को ध्वस्त करने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद के भीतर करारी हार के बाद भी अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले पर सरकार को गलत ठहराने की कोशिश में जुटे विपक्ष को भाजपा अब जनता के बीच बेनकाब करेगी। राहुल गांधी के विपक्षी नेताओं के साथ कश्मीर जाने और एयरपोर्ट से वापस भेजे जाने को घाटी के हालात से जोड़ने की कोशिश के दो दिन बाद ही भाजपा ने इस मुद्दे पर पूरे देश में जनजागरण और जनसंपर्क अभियान का एलान किया है। 370 जनसंपर्क अभियान और 35 बड़ी जनजागरण सभाओं का सांकेतिक अभियान पूरे सितंबर महीने चलेगा। भाजपा ने दो केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में दो टीमों का गठन कर दिया है।

अभियान की जानकारी देते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता कई पीढ़ियों से मांग करते आए हैं कि अनुच्छेद 370 देश के लिए उचित नहीं है और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। यही देश की भी सोच है। मोदी सरकार ने इसे सरकार बनने के दो महीने के अंदर खत्म करने का हौसला दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई विपक्षी दलों ने इसमें सरकार का साथ दिया। इसी कारण भाजपा ने देश की जनता को अनुच्छेद 370 और उसके हटाने की परिस्थितियों से अवगत कराने का फैसला किया है।

धर्मेंद्र प्रधान फाइल

गजेंद्र सिंह शेखावत फाइल

जनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। इसके तहत राज्य, जिला और विधानसभा तीनों स्तरों पर प्रमुख व्यक्तियों की सूची बनाकर उनसे संपर्क कर अनुच्छेद 370 को हटाने की जरूरत के बारे में बताया जाएगा। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि किस तरह यह कश्मीर की जनता के हित में नहीं था और विकास में बड़ी बाधा बना हुआ था। जनता को इस बारे में जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा। वहीं जन जागरण अभियान सभी राज्यों की राजधानियों में बड़े नेताओं की जनसभाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालयों व अन्य अहम स्थानों पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

राहुल अपनी पार्टी में ही अलग-थलग पड़े : समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर राहुल खुद अपनी पार्टी में ही 'अलग-थलग' पड़ गए हैं। भाजपा सिर्फ उनसे हमदर्दी जता सकती है। प्रधान ने राहुल पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 'कुछ ऐसे नेता हैं जो जागते हुए भी सोते हुए दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस मुद्दे पर अलग-थलग पड़ गए हैं। वे अपनी पार्टी में ही अलग-थलग पड़ गए हैं।' भाजपा नेता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव परिसीमन की कवायद पूरी होने के बाद ही होंगे, क्योंकि वहां अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण लागू होगा।

जदयू महाराष्ट्र में भी नहीं कर सकेगा 'तीर' का इस्तेमाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : बिहार में भाजपा के सहयोग से सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र में भी चुनाव के दौरान अपने चुनाव चिह्न 'तीर' का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चुनाव आयोग ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) व शिव सेना के चुनाव चिह्न 'तीर-धनुष' से समानता के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है।

झामुमो की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग को अपनी सहमति वापस लेनी पड़ी। झामुमो ने आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों के चुनाव चिह्नों में समानता होने के कारण मतदाताओं को भ्रम हो सकता है। 16 अगस्त को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने कहा, 'इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार के बाद आयोग चुनाव चिह्न के पैराग्राफ 10 के अंतर्गत जदयू को आवंटित चिह्न तीर पर झारखंड व महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दे रहा है।'

बिहार में पहले ही लगा दी थी रोक : इसी साल मार्च में जदयू की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने आदेश किया था कि झामुमो और शिव सेना बिहार में अपने चिह्न पर चुनाव नहीं लड़ सकते। आयोग ने कहा कि आठ मार्च 2019 को दिया गया आदेश झामुमो के मामले में समान रूप से प्रभावी होता है। यही सिद्धांत महाराष्ट्र में भी लागू होगा, क्योंकि शिव सेना का निशान भी तीर-धनुष है। महाराष्ट्र व झारखंड में जदयू को 'फ्री सिंबल' प्रदान किया जाएगा। ऐसे चुनाव चिह्न गैरमान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को दिए जाते हैं।

झारखंड में कांग्रेस ने आदिवासी चेहरे को सौंपा नेतृत्व

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव को बनाया प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष
- सामाजिक–राजनीतिक समीकरण के लिए पांच कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए, चुनाव समितियों की घोषणा जल्द

विधानसभा चुनाव से पहले नए नेतृत्व का इंतजार कर रहे झारखंड प्रदेश कांग्रेस को आखिरकार नया अध्यक्ष मिल गया। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री वरिष्ठ नेता डॉ. रामेश्वर उरांव को झारखंड प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस में पांच कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन नियुक्तियों के साथ ही झारखंड चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की रुकी गाड़ी को गति दे दी है।

रामेश्वर उरांव को प्रदेश की बागडोर सौंपते हुए कांग्रेस ने झारखंड चुनाव में इस बार आदिवासी समुदाय के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का संदेश देने की कोशिश की है जबकि सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने के लिए पांच कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति में इसका ख्याल रखा गया है। पांच कार्यकारी अध्यक्षों में कमलेश महतो कमलेश, इरफान अंसारी, राजेश ठाकुर, मानस सिन्हा और संजय पासवान शामिल हैं।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से डॉ. अजय कुमार के इस्तीफा देने के बाद से नए अध्यक्ष की नियुक्ति का सूबे के कांग्रेसी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में ढाई महीने तक रही असमंजस की स्थिति के कारण झारखंड समेत कई सूबों के नेतृत्व का फैसला अटका हुआ था। अजय कुमार ने इस्तीफा देने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी को लेकर भी काफी खरी-खरी बातें हाईकमान के सामने रखते हुए कुछ नेताओं पर तो पार्टी को बर्बादी

डॉ. रामेश्वर उरांव जागरण

के कगार तक ले जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर काफी खलबली मची थी। इस वजह से कांग्रेस हाईकमान चुनाव के मौजूदा माहौल में सूबे के नए अध्यक्ष को लेकर ज्यादा प्रयोग करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। रामेश्वर उरांव को इसीलिए कमान सौंपी गई है, क्योंकि वे पार्टी के सभी नेताओं और गुटों को साथ लेकर चल सकते हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रति निष्ठा की उरांव की पुरानी विरासत भी नेतृत्व के लिए उन्हें चुने जाने की एक वजह मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस हाईकमान ने संकेत दिया है कि झारखंड के चुनाव से पार्टी की तमाम संबंधित समितियों का एलान भी जल्द कर दिया जाएगा।

कर्नाटक में पहली बार तीन उप मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने नए मंत्रियों में बांटा प्रभार

बेंगलुरु, प्रेट्र : करीब एक सप्ताह इंतजार के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 17 नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दीं। राज्य में पहली बार तीन उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इनमें गोविंद कारजोल, अश्वथ नारायण व लक्ष्मण सावदी शामिल हैं। चर्चा है कि येदियुरप्पा राज्य में उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर उन्हें ऐसा करना पड़ा।

कारजोल को लोकनिर्माण विभाग व सामाजिक न्याय, नारायण को उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान व तकनीक तथा सावदी को परिवहन विभाग सौंपा गया है। बसवराज बोम्मई गृह मंत्री बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को बड़े और मध्यम उद्योग, पूर्व उपमुख्यमंत्रियों केएस ईश्वरप्पा और आर. अशोक को क्रमशः ग्रामीण विकास व पंचायतीराज तथा राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ आदिवासी नेता बी. श्रीरामुलु को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा ब्राह्मण नेता एस. सुरेश कुमार को प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है। सीसी पाटिल को खान और भूगर्भ, एच. नागेश को आबकारी, प्रभु चव्हाण को पशुपालन और शशिकला जोले को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। अन्य मंत्रियों में वी सोमन्ना (आवास), सीटी रवि (पर्यटन, कन्नड़ और संस्कृति), कोटा श्रीनिवास पुजारी (मत्स्य, बंदरगाह और इनलैंड ट्रांसपोर्ट), जेसी मधुस्वामी (कानून, संसदीय मामले और लघु सिंचाई) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तीन सप्ताह बाद 20 अगस्त को येदियुरप्पा ने 17 मंत्रियों के साथ अपनी कैबिनेट का विस्तार किया था। पार्टी के विधायकों और नेताओं में असंतुष्टि को भांपते हुए येदियुरप्पा पिछले सप्ताह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिले थे और इस स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा की थी।

किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं सावदी, वरिष्ठ विधायकों में असंतोष : दिलचस्प बात यह है कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए सावदी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किए जाने से भाजपा के कई वरिष्ठ विधायकों में असंतोष पैदा हो गया है। इनमें हुक्केरी से आठ बार के विधायक उमेश कट्टी और होन्नली विधायक एमपी रेणुकाचार्य शामिल हैं। माना जा रहा है कि सावदी लिंगायत समुदाय से हैं और पार्टी में दूसरी लाइन तैयार करने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है।

सिद्दरमैया का दावा, एक साल भी नहीं चल पाएगी येदियुरप्पा सरकार : कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया ने दावा किया कि राज्य की येदियुरप्पा सरकार एक साल भी नहीं चल पाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे मध्यावधि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें और पार्टी को मजबूत बनाएं। वह हुबली में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

पीडीपी की कारगिल जिला इकाई भाजपा में शामिल

राज्य ब्यूरो, जम्मू

कश्मीर के बाद अब लद्दाख के कारगिल में भी पीडीपी को बड़ा झटका लगा है। जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन कर लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के अहम फैसले के बाद विधान परिषद के चेयरमैन हाजी इनायत अली व पीडीपी की कारगिल जिला इकाई भाजपा में शामिल हो गई।

सोमवार दोपहर को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीडीपी की कारगिल जिला इकाई का भाजपा में स्वागत किया। इस मौके पर लद्दाख से भाजपा के सांसद जामयांग सेरिंग नांग्याल के साथ प्रदेश भाजपा की कारगिल जिला इकाई के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। नांग्याल ने पीडीपी के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का भाजपा में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। हाजी इनायत अली के नेतृत्व में कारगिल की जिला पीडीपी इकाई ने भाजपा में शामिल होकर स्पष्ट संकेत दिया कि लेह के बाद अब कारगिल में भी भाजपा मजबूत हो गई है। हाजी के साथ कारगिल से पीडीपी के जिला प्रधान काचू गुलजार अहमद भी अपने समर्थकों समेत भाजपा में आ गए। इसके साथ लेह से सेवानिवृत्त एसएसपी टी ग्यालपों व कुछ अन्य लोग भी भाजपा में आए। सूत्रों के अनुसार हाजी इनायत अली के भाजपा में आने के बाद अब कारगिल के कुछ अन्य नेता भी जल्द सत्ताधारी पार्टी में आ सकते हैं।

नई दिल्ली में सोमवार को पीडीपी की कारगिल जिला इकाई भाजपा में शामिल हो गई। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में सभी ने सदस्यता ली। एएनआइ

कश्मीर के बाद अब कारगिल के पीडीपी नेताओं ने भी महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व के प्रति बागी तेवर दिखाए हैं। इससे पहले कश्मीर से पीडीपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़कर महबूबा के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी थी। पीडीपी छोड़ने वाले इन नेताओं में हसीब द्राबू, इमरान रजा अंसारी, अल्ताफ बुखारी, जावेद मुस्तफा मीर सहित अन्य कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

सजायाफ्ता लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए लगाई याचिका

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- वरिष्ठ आइएएस अशोक खेमका के पुत्र गणेश ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका
- वर्तमान में दो साल से कम सजा पर चुनाव लड़ने का है अधिकार

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर किसी भी अपराध के लिए दोषी करार और सजायाफ्ता लोगों को संसदीय या विधानसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मौजूदा समय में दो वर्ष से कम के कारावास की सजा वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति है, जबकि इससे ज्यादा सजा वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाता है।

याचिका दायर करने वाले गणेश खेमका हरियाणा के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अशोक खेमका के पुत्र हैं। याचिका के मुताबिक मौजूदा नियम समानता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि अपराध तो अपराध होता है। चाहे यह छोटा हो या बड़ा। अगर किसी व्यक्ति को दो साल की सजा हुई है और किसी को दो साल से ज्यादा की सजा हुई है तो दोनों के मामलों में असमानता क्यों?

बहस के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु से कानून स्नातक हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 (1) और (2) अपराधी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य मानती है लेकिन धारा 8 (3) के तहत दो साल से कम की सजा वाले व्यक्ति को यह चुनाव लड़ने के योग्य मानती है।

बहस व व्याख्या जरूरी : याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी पर आधारित डिविजन बेंच ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मामला है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) में इस तरह के नियम संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता की बात करता है। इस विषय पर बहस व व्याख्या जरूरी है। बेंच ने अगली सुनवाई पर केंद्र को इस बाबत पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

मप्र में समस्या बतानी शुरू की तो विधायक ने वृद्धा का मुंह किया बंद

नईदुनिया, सागर

मध्य प्रदेश के सागर में रविवार को जलभराव का निरीक्षण करने निकले भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने एक वृद्धा का तब मुंह दबा दिया, जब वह समस्या बताने लगी। बुजुर्ग महिला ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। बोली- आप अपना मुंह बंद करिए, मेरा नहीं। प्रशासनिक अमले के सामने विधायक के इस कारनामे का वीडियो वायरल हो गया है।

शहर में कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश से ज्यादातर सड़कों पर बार-बार जलजमाव की स्थिति बन रही है। नालों पर अतिक्रमण होने के कारण गोपालगंज क्षेत्र के स्नेह नगर में हालत ज्यादा खराब है। निगम का अमला जब यहां का अतिक्रमण हटवा रहा था, इसी दौरान वहां विधायक पहुंचे और लोगों से कहने लगे कि घरों के अतिक्रमण से जाम और जलभराव की स्थिति बनती है। प्रशासन का सहयोग करें, ताकि समस्या से स्थायी मुक्ति मिले। इसी बीच वृद्धा रामवती शर्मा बार-बार कुछ कहने के लिए आगे आ रही थीं। अधिकारियों से बात कर रहे विधायक ने पहले जोर से अम्मा कहकर उन्हें रोका फिर उनके मुंह पर हाथ रख दिया। वृद्धा रामवती शर्मा का कहना है कि मैं विधायक से सिर्फ यह कहना चाह रही थी कि घर के बाहर चबूतरा टूटने के बाद बच्चों के नाले में गिरने का डर है। इसलिए कुछ व्यवस्था कराई जाए। इस पर विधायक ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। यह हमारे लिए अपमानजनक था। ये नेता हमारे ही वोट से जीतते हैं और हमारा ही मुंह बंद कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के सागर में वृद्धा के मुंह पर हाथ रखे विधायक। (वीडिया ग्रैब)

वहीं, विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा, स्नेह नगर में नाले का पानी घरों में घुस गया था। बुजुर्ग महिला ने कहा कि चबूतरा टूटने से उनके घर में छोटे-छोटे बच्चों को खतरा हो सकता है। यहां रैंप जैसा कुछ बन जाए। मैं निगम के अधिकारियों से उन्हीं की समस्या को लेकर बात कर रहा था। बुजुर्ग अम्मा बार-बार टोक रही थीं तो मैंने स्नेहवश उनकी तरफ हाथ करके कहा कि आप चुप हो जाएं, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। मैं किसी को बोलने से कैसे रोक सकता हूं।

'जगन आंध्र प्रदेश की चार राजधानियां बनाना चाहते हैं'

- भाजपा सांसद का दावा, दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री ने की है चर्चा

अमरावती, आइएएनएस : आंध्र प्रदेश के भविष्य पर जारी हंगामे को एक नया मोड़ देते हुए भाजपा सांसद ने कहा है कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी चार राजधानियां बना सकते हैं। राज्यसभा सदस्य टीजी वेंकटेश ने दावा किया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार एक ही जगह हर चीज का विकास नहीं कर सकती है। इसकी जगह राज्य के चार विभिन्न क्षेत्रों में राजधानियों को विकेंद्रित कर सकती है।

वेंकटेश ने कहा कि जगन रेड्डी ने नई दिल्ली में भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने प्रस्ताव पर चर्चा की है। सांसद ने कहा कि उन्हें भाजपा के एक नेता से पता चला है कि मुख्यमंत्री चार राजधानियां बनाएंगे।

हाल ही में तेदेपा से भाजपा में शामिल हुए वेंकटेश ने दावा किया कि जगन रेड्डी सभी क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए उनहोंने प्रस्ताव तैयार किया है। रायलसीमा क्षेत्र के कर्नूल निवासी सांसद ने दावा किया कि एक राजधानी उनके क्षेत्र में होगी।

उन्होंने कहा कि एक समय मंत्रियों और वाईएसआरसीपी नेताओं के परस्पर विरोधी बयान ने भ्रम पैदा कर दिया था कि क्या अमरावती से राजधानी दूसरी जगह ले जाई जाएगी। जबसे वाईएसआरसीपी सत्ता में आई है तब से सभी काम रुके हुए हैं।

अमरावती के किसानों ने राजधानी स्थानांतरण का विरोध किया

वाईएसआरीसपी नेताओं के बयान से आंध्र प्रदेश प्रदेश की राजधानी स्थानांतरित होने का भ्रम पैदा हो गया है। राजधानी के लिए जमीन देने वाले किसानों ने सोमवार को स्थानांतरण के विरोध में प्रदर्शन किया। सचिवालय की ओर जाने वाली सड़क पर किसानों ने जाम लगाया। शहरी विकास मंत्री बोत्सा सत्यनारायण और भाजपा सांसद वेंकटेश के बयान की आलोचना करते हुए गुंटूर जिले के किसानों ने प्रदर्शन किया और राजधानी अमरावती में ही रहने देने की मांग की।

चुनावी दंगल

बस्तर संभाग की एकमात्र इसी सीट पर भाजपा को मिली थी जीत, यहां कांग्रेस के साथ भाजपा की प्रतिष्ठा भी है दांव पर

दंतेवाड़ा उपचुनाव में होगा कड़ा मुकाबला

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। इस उपचुनाव पर कांग्रेस ही नहीं, भाजपा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। विधानसभा 2018 में बस्तर संभाग की एकमात्र सीट दंतेवाड़ा कांग्रेस के हाथ से फिसल गई थी। संभाग की 12 सीटों में से केवल एक दंतेवाड़ा में भाजपा का कब्जा हो पाया था। भाजपा इस सीट को फिर से जीतने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस का दंतेवाड़ा सीट पर सेंध लगाने का प्रयास होगा।

कांग्रेस दंतेवाड़ा सीट से लगातार कर्मा परिवार से प्रत्याशी बनाती रही है। वैसे इस बार भी यही संभावना ज्यादा दिख रही है। संगठन के भीतर पूर्व विधायक देवती कर्मा का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। वहीं, भाजपा इस सीट से दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की पत्नी को मैदान में उतार सकती है।

प्रत्याशी चयन के लिए नौ दिन : चार सितंबर तक नामांकन भरा जा सकेगा। मतलब, राजनीतिक दलों के पास प्रत्याशी का नाम तय करने के लिए नौ दिन ही बचे हैं। तिथि की घोषणा होते ही

कांग्रेस ने चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। पीसीसी अध्यक्ष दो-चार दिन में प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाने वाले हैं, ताकि उनके साथ न केवल प्रत्याशी, बल्कि चुनावी रणनीति पर चर्चा हो सके। इधर, भाजपा भी पूरी तैयारी में है।

छबिंद्र पर रहेगी नजर : महेंद्र कर्मा के पुत्र छबिंद्र कर्मा पर संगठन की नजर रहेगी, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में मां देवती कर्मा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने ताल ठोंक दी थी। छबिंद्र को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाकर समझाया था, तब उन्होंने अपना नाम वापस लिया था। यह चर्चा है कि छबिंद्र यह कहकर दावेदारी ठोंक सकते हैं कि संगठन ने पिछले चुनाव में उनकी मां को मौका दिया था, अब उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए।

पूरे बस्तर में होता कब्जा, अगर दंतेवाड़ा में 2172 वोट कम न मिलते : बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में पूरे बस्तर संभाग में कांग्रेस का कब्जा होता, अगर दंतेवाड़ा में 2172 वोट कम न मिलते। कांग्रेस वोट के इस गड्ढे को पाटने की पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उसका लाभ मिलेगा। आदिवासियों के हित में लिए गए फैसलों की ब्रांडिंग करके चुनाव जीतने की कोशिश होगी।

राकांपा को एक और झटका, शिवसेना में शामिल होंगे विधायक सोपल

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राकांपा को लगातार झटके लग रहे हैं। पार्टी के एक और विधायक दिलीप सोपल ने सोमवार को जल्द ही शिवसेना में शामिल होने और विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है।

सोपल सोलापुर जिले के बारसी से विधायक व राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस-राकांपा (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के एक करीबी ने भी इस राजनीतिक घटनाक्रम की पुष्टि की है। पिछले ही महीने राकांपा के शहापुर विधायक पांडुरंग बरोरा राज्य में सत्तासीन भाजपा गठबंधन की सहयोगी पार्टी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं।

कोंकण के भास्कर जाधव भी जा सकते हैं शिवसेना में : कोंकण में राकांपा के प्रभावशाली नेता व पूर्व मंत्री भास्कर जाधव के शिवसेना में शामिल होने की अटकलें भी रविवार को तैरती रहीं। इस चर्चा को तब आधार मिल गया, जब उन्होंने मुंबई के बांद्रा स्थित शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री में उनसे मुलाकात की। गुहागर से विधायक जाधव पहले भी शिवसेना में रह चुके हैं। हालांकि, जाधव ने इसे सिर्फ अफवाह करार देते हुए राकांपा में बने रहने की बात कही।

सतारा के सांसद भोसले का भी डोल रहा मन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस शनिवार को परोक्ष रूप से सतारा के राकांपा सांसद और मराठा नेता उदयनराजे भोसले को भाजपा में शामिल होने का आमंत्रण दे चुके हैं। भोसले ने शुक्रवार को फड़नवीस सरकार की तारीफ करते हुए पूर्व की कांग्रेस–राकांपा सरकार पर विकास की राह में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया था। राकांपा के चार सांसदों में से एक भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। उनके रिश्तेदार और सतारा से विधायक शिवेंद्र सिंह भोसले अपने साथी विधायक संदीप नायक व वैभव पिचड के साथ पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके हैं।

संजय दत्त ने किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने से किया इन्कार

मुंबई, प्रेट्र : अभिनेता संजय दत्त ने महाराष्ट्र के मंत्री को दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री महादेव जानकर ने रविवार को दावा किया था कि दत्त 25 सितंबर को उनकी पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष (आरएसपी) में शामिल होंगे।

समाजवादी पार्टी के जरिये राजनीति में हाथ आजमा चुके 60 वर्षीय अभिनेता दत्त ने सफाई दी, 'मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं। जानकर मेरे दोस्त और भाई हैं। मैंने उन्हें नम्रतापूर्वक उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।' आरएसपी महाराष्ट्र में भाजपा का सहयोगी दल है। जानकर ने कहा था, 'हमने अपनी पार्टी के विस्तार के लिए फिल्म के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में संजय दत्त 25 सितंबर को हमारी पार्टी में शामिल होंगे।' उल्लेखनीय है कि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले भी दत्त के राजनीति में आने की चर्चा हुई थी। उनकी बहन मुंबई से सांसद हैं और पिता सुनील दत्त मुंबई से सांसद और केंद्र की यूपीए-1 सरकार में मंत्री रहे थे।

1998 में रूस इस संगठन में शामिल हुआ था। बाद में उसने इससे नाता तोड़ लिया। इसके बाद संगठन का नाम जी-7 हो गया। फिलहाल इसमें फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।

एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को खत्म करेंगे : मोदी

बोले पीएम ▸ प्लास्टिक के खिलाफ अपने अभियान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर धार दी

जी-7 के जलवायु पर सत्र में प्रयासों का किया उल्लेख

बायरिट्ज (फ्रांस), प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में सतत भविष्य के लिए 'एक बार इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्लास्टिक' को खत्म करने, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा के दोहन और पेड़-पौधे एवं जीव-जंतुओं के संरक्षण की दिशा में भारत के व्यापक प्रयासों का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के विशेष अनुरोध पर प्रधानमंत्री बायरिट्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सत्र को संबोधित किया जिसमें एक बार इस्तेमाल में लाई जाने वाली (सिंगल यूज) प्लास्टिक को खत्म करने, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा के दोहन और पेड़-पौधे एवं जीव जंतुओं के संरक्षण की दिशा में भारत के व्यापक प्रयासों का जिक्र किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, 'वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'जैवविविधता, सागर, जलवायु' पर जी-7 बायरिट्ज शिखर सम्मेलन के समर्पित सत्र में शरीक हुए। मोदी

फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में एक बैठक में शामिल सभी देशों के प्रमुख। रायटर

ने पिछले हफ्ते पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय को अपने संबोधन में कहा था कि भारत 2030 के लिए लक्षित 'कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज' (सीओपी) 21 जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में अधिकांश को अगले डेढ़ वर्ष में हासिल कर लेगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन सीओपी का 21वां सत्र पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया था। इसमें 195 देशों ने भाग लिया था। देशों ने पेरिस समझौते को मंजूरी दी थी जिसमें भारत ने चार प्रतिबद्धताएं तैयार की थी। भारत ने पेरिस समझौते का 2016 में अनुमोदन किया था और इस समझौते में शामिल होने वाला वह 62 वां राष्ट्र बन गया।

जी-7 जलवायु बैठक में ट्रंप की कुर्सी खाली रही : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी-7 में दुनिया के अन्य नेताओं के साथ जलवायु पर होने वाली चर्चा में शामिल नहीं हुए। विश्व के नेताओं ने अमेजन में लगी आग पर काबू पाने में कैसे मदद की जा सकती है के साथ ही कार्बन उत्सर्जन पर चर्चा की। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी खाली रही। मेजबान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप की जगह उनके सहयोगी थे।

पीएम ने यूएन प्रमुख से आपदा बुनियादी ढांचे पर चर्चा की : प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के साथ आपदा बुनियादी ढांचा के लिए वैश्विक गठबंधन के अपने प्रस्ताव पर चर्चा की। भारत को अगले महीने यूएन महासभा की समाप्ति पर लांच करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री अगले महीने संयुक्त राष्ट्र जलवायु समिट में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने गुतेरस के साथ इस बात पर चर्चा की कि दुनिया प्रशिक्षित स्वयंसेवियों का जत्था तैयार करने पर आगे आ सकती है या नहीं।

ट्रंप बोले-ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता

- अगले कुछ हफ्तों में ईरान के राष्ट्रपति रूहानी से कर सकते हैं मुलाकात
- अमेरिका-ईरान में बातचीत की कोशिश में जुटे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों

बायरिट्ज (फ्रांस), एएफपी : ईरान और अमेरिका के रिश्तों पर जमी धूल हटाने की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की कोशिश रंग लाती दिख रही है। फ्रांस के शहर बायरिट्ज में हुए जी-7 सम्मेलन के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी ईरान के बारे में बदले दिखे। उन्होंने अगले कुछ हफ्तों में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की संभावना पर भी हामी भरी।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चलते अमेरिका से उसका तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों दोनों देशों के बीच बातचीत की पहल में जुटे हुए हैं। उनके विशेष निमंत्रण पर ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ रविवार को अचानक जी-7 सम्मेलन में भी पहुंचे थे। इस दौरान विभिन्न वैश्विक नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि ट्रंप उनसे नहीं मिले थे। सम्मेलन में जरीफ के पहुंचने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, 'मुझे इसकी जानकारी थी। मैक्रों ने इस बारे में मुझसे पूछा था। हालांकि अभी जरीफ से मिलने की मुझे कोई जल्दी नहीं है।' ट्रंप ने यह भी कहा कि

डोनाल्ड ट्रंप फाइल

अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता है। ट्रंप ने मैक्रों की इस बात पर भी हामी भरी की अगले कुछ हफ्तों में रूहानी से मुलाकात की परिस्थितियां बन रही हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने ईरान से बातचीत के बनते माहौल को बड़ा कदम बताते हुए इसकी सराहना की। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है, जिसे ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के प्रमुख रॉबर्ट मेले ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप आज क्या सोचते व कहते हैं और कल क्या सोचेंगे व कहेंगे, इसमें बहुत अंतर होता है।'

रूहानी दे रहे सफाई : विदेश मंत्री जावद जरीफ को अचानक जी-7 सम्मेलन में भेजने को लेकर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी देश के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। विरोधियों का कहना है कि इससे ईरान के कमजोर होने का संकेत गया है। इस पर रूहानी ने कहा, 'मेरा मानना है कि अपने देश के हित के लिए हमें हर तरीका आजमाना चाहिए।'

दबाव में कमजोर नहीं होगा भारत से रिश्ता

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ उसके पुराने संबंध हैं और छोटे-मोटे दबावों से इस रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने कहा, 'भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने मजबूत संबंध हैं। छोटे दबावों (अमेरिकी प्रतिबंध) से इस पर असर नहीं पड़ेगा। यह दौर भी बीत जाएगा।

चीन से वार्ता को तैयार अमेरिका

- सितंबर में अमेरिका जाएगा चीन का डेलिगेशन
- फैसले की घोषणा के बाद दुनियाभर के बाजारों में सुधार

बायरिट्ज (फ्रांस) : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन और अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप को जी-7 देशों की बैठक में ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण दबाव का सामना करना पड़ा। ग्लोबल लीडर्स उन्हें ट्रेड वार खत्म करने के लिए मनाते हुए नजर आए। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें चीन की ओर से कुछ अच्छे संकेत मिले हैं।

शुक्रवार को एक समय ट्रंप यूएस-चीन ट्रेड वार को लेकर अफसोस जताते नजर आए, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उनकी ओर से जारी वक्तव्य में इसका खंडन कर दिया गया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया कि ट्रंप के बयान को गलत समझा गया। उनको चीन पर और टैरिफ नहीं लगा पाने को लेकर अफसोस है। हालांकि ट्रंप ने ट्रेड वार के मुद्दे पर हुई बातचीत में भूमिका निभाने वालों की पहचान बताने से इन्कार कर दिया।

दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए सितंबर में चीन का एक डेलिगेशन अमेरिका जाएगा। अभी यह साफ नहीं हो सका है कि अगले महीने शुरू होने वाली बातचीत पहले से निर्धारित है अथवा यह नए सिरे से होने वाली है। चीन की ओर से इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ट्रंप की ओर से बातचीत का संकेत मिलने के बाद दुनियाभर के स्टॉक मार्केट में सुधार देखा गया।

युआन 11 वर्षों के निचले स्तर पर: चीन की करेंसी युआन 11 वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इस दौरान डॉलर के मुकाबले युआन 7.1487 के स्तर पर जा पहुंचा। चीनी करेंसी की एशियन ट्रेडिंग में 2008 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है।

जानकारों के मुताबिक चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वार और सुस्त होती वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण चीन की करेंसी में तेज गिरावट देखी गई है। इससे पहले दोनों देशों के बीच जारी ट्रेड वार उस वक्त और गहरा गया जब ट्रंप ने चीन की वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा के साथ अमेरिका की कंपनियों को चीन से अपना व्यापार समेटने को कहा।

युआन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पूरी तरह से कन्वर्टिबल नहीं है। चीन ने इसे दो परसेंट के दायरे में सीमित कर रखा है। युआन के सस्ता होने पर चीन के निर्यातकों को लाभ पहुंचता है, जिससे वह अमेरिकी टैरिफ का कुछ हद तक मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। इस महीने की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले युआन 7.0 के स्तर को पार गया था। इसके चलते अमेरिका ने चीन को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित कर दिया था। चीन के केंद्रीय बैंक ने इसका विरोध किया था।

अमेजन वर्षावन की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन ने बढ़ाया हाथ

- फ्रांस में चल रहे जी7 सम्मेलन के दौरान 1.23 करोड़ डॉलर देने का किया वादा
- धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले वर्षावन में दो हफ्ते से ज्यादा समय से लगी है आग

बायरिट्ज, एएफपी : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेजन वर्षावन में लगी आग काबू करने व जंगल संरक्षित करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस के तटीय शहर बायरिट्ज में चल रहे जी7 सम्मेलन के दौरान जॉनसन ने मदद के लिए 1.23 करोड़ डॉलर (करीब 88 करोड़ रुपये) देने का वादा किया। ब्रिटेन सरकार ने बयान जारी कर कहा, 'आग से प्रभावित अमेजन के हिस्सों को फिर से हरा-भरा करने और जीव-जंतुओं के प्राकृतिक आवास के पुनर्निर्माण के लिए यह धनराशि तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।'

मदद की घोषणा के बाद जॉनसन ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता में हो रहे नुकसान का साथ में हल निकलना होगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकृति को बचाए बिना जलवायु परिवर्तन नहीं रोका जा सकता और जलवायु परिवर्तन को रोके बिना प्रकृति को संरक्षित व सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।' इस घोषणा से एक दिन पहले सम्मेलन की मेजबानी कर रहे फ्रांस ने कहा था कि अमेजन वर्षावन की सुरक्षा के लिए सभी देश हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। वायुमंडल को 20 फीसद ऑक्सीजन देने वाले अमेजन के जंगलों में दो हफ्ते से ज्यादा समय से आग लगी है। जैव विविधता से भरपूर इन जंगलों का 60 फीसद हिस्सा ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील के

ब्राजील के अमेजॅन वर्षावन के पोर्टो वेल्हो क्षेत्र में धधकती आग। रायटर

लड़ाकू विमान से बुझाई जा रही आग

ब्राजील के रोंडोनिया राज्य में पड़ने वाले वर्षावन में लगी आग बुझाने के लिए लड़ाकू विमानों से पानी की बौछार की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने आग पर काबू पाने के लिए सैनिक उतारे हैं।

अलावा यह बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरु आदि में भी फैला हुआ है। आग से ब्राजील के अलावा बोलिविया और पेरू के कई शहर भी प्रभावित हुए हैं। कई यूरोपीय देशों ने जंगल में लगी आग को नजरअंदाज करने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो पर आरोप लगाया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि बोल्सोनारो ने जंगल की कटाई और खनन को बढ़ावा दिया है। हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो के पर्यावरण संगठन अर्थ अलायंस ने जंगलों को संरक्षित करने के लिए पचास लाख डॉलर का दान देने की बात कही है।

अमेजॅन वर्षावन के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा आर्थिक मदद करने का एलान किया गया। एपी

मोदी ने दिया एनएसजी की सदस्यता पर जोर

बायरिट्ज (फ्रांस), एएनआइ : भारत परमाणु ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) की सदस्यता भारत के लिए बहुत अहम है। जी-7 सम्मेलन से इतर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही।

इस बातचीत की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर गुतेरस बहुत उत्साहित दिखे। मोदी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेंगे और इस दौरान यूएन महासचिव के जलवायु सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। गोखले ने बताया कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए गुतेरस ने भारत के ताप ऊर्जा (थर्मल पावर) संयंत्रों पर चिंता जताई। इस पर मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत परमाणु ऊर्जा समेत स्वच्छ ऊर्जा के विभिन्न विकल्पों पर काम कर रहा है। उन्होंने इस दिशा में एनएसजी की सदस्यता की जरूरत पर भी जोर दिया। गुतेरस ने भरोसा दिलाया कि इस संबंध में वह भारत की यथासंभव मदद करेंगे।

कश्मीरी पंडित की शवयात्रा में हजारों मुस्लिम हुए शरीक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में जिहादी तत्वों की साजिश के बावजूद हिंदू-मुस्लिम भाईचारा बरकरार है। पुलवामा में वर्षों से रह रहे डॉ. रत्न लाल कौल की जब दो दिन पहले मृत्यु हुई तो पड़ोसियों ने उनके परिजनों को शव जम्मू नहीं ले जाने दिया, बल्कि परिजनों को जम्मू से ले आए और शवयात्रा में करीब छह हजार लोग शामिल हुए।

पुलवामा के मुरन इलाके में रहने वाले रत्न लाल ने आतंकियों की धमकियों के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ा। वह मुरन में ही रहे। जब उनका देहांत हुआ तो उस समय उनका छोटा बेटा ही उनके साथ था। पड़ोसियों को पता चला तो वह तुरंत रत्न लाल के घर पहुंचे। बेटे ने कहा कि वह अपने दिवंगत पिता का अंतिम संस्कार जम्मू में करना चाहता है क्योंकि पूरा परिवार वहीं पर है, लेकिन पड़ोसी नहीं मानें। उन्होंने दिवंगत के बेटे को संभाला और तीन गाड़ियां जम्मू के लिए भेजी ताकि दिवंगत के परिजनों और रिश्तेदारों को पुलवामा लाया जा सके।

मुश्ताक अहमद ने बताया कि रत्न लाल के सभी रिश्तेदार रविवार की सुबह यहां पहुंचे। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलवामा के विभिन्न गांवों के अलावा शोपियां व कुलगाम से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम शवयात्रा में शरीक होने आए।

कश्मीर शांत, धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा जनजीवन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर घाटी में सोमवार को सामान्य जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौटती नजर आई। हालांकि अधिकतर दुकानें बंद रहीं, लेकिन सड़कों पर यातायात पूरी तरह सामान्य रहा। 72 पुलिस थाना क्षेत्रों से दिन की पाबंदियों को पूरी तरह हटा लिया गया है।

सोमवार सुबह दस बजे श्रीनगर समेत वादी के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में ज्यादातर दुकानें खुली गईं। शाम पांच बजे के बाद भी दुकानें खुलीं, लेकिन रेहड़ी, फड़ी और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दिनभर सड़कों पर नजर आए। सड़कों पर निजी और सार्वजनिक वाहन बीते दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा दिखे। अंतर जिला परिवहन सेवा भी बहाल रही। श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर भी आम वाहनों की संख्या रविवार की तुलना में ज्यादा रही। सभी सरकारी कार्यालय निर्धारित समय पर ही खुले और उनमें कर्मचारियों की उपस्थिति लगभग सामान्य रही। प्रमुख कस्बों और जिला मुख्यालयों में बैंक भी खुले। नागरिक सचिवालय में भी कर्मचारियों की उपस्थिति 95 प्रतिशत के करीब दर्ज की गई।

कश्मीर में हायर सेकेंडरी स्कूल भी खुले : कश्मीर घाटी में प्राइमरी और मिडिल के बाद सोमवार को हायर सेकेंडरी स्कूल भी खुल गए

कश्मीर में जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट आया है। अधिकतर थाना क्षेत्रों से दिन की पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। लैंडलाइन फोन की सुविधा भी कई क्षेत्रों में बहाल कर दी गई है। सोमवार को श्रीनगर में सड़कों पर चहल-पहले से लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो रहा है। जागरण

हैं। मंडलायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को पूरी वादी में करीब 2500 प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुले। इनमें छात्रों की संख्या 15 से 80 प्रतिशत तक दर्ज की गई है, जबकि स्कूलों में स्टाफ की उपस्थिति लगभग सामान्य हो चली है। कुछ निजी स्कूल भी खुले। प्रशासनिक पाबंदियों में राहत और सामान्य जिंदगी को बहाल होते देख हताश तत्वों के मंसूबों को भापंते हुए प्रशासन ने सोमवार को भी पूरी वादी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। इसके बावजूद बेमिना, डाउन-टाउन, छन्नपोरा, नौगाम समेत वादी के विभिन्न हिस्सों में शरारती तत्वों ने भड़काऊ नारेबाजी करते हुए पथराव किया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उन्हें खदेड़ स्थिति पर काबू पा लिया।

विपक्ष का जम्मू-कश्मीर जाना उचित नहीं : मायावती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद- 370 हटाए जाने के बाद विपक्ष से अलग राह अपना चुकीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस व अन्य दलों पर निशाना साधा। जम्मू-कश्मीर यात्रा का विरोध करते हुए मायावती ने इसे बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने में कुछ वक्त लगेगा। वहीं दूसरी ओर सीपीआइ नेता डी राजा ने इस बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो दबाव में हैं। उन्हें वहां गए विपक्षी दलों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम वहां एकजुटता का संदेश देने के लिए गए थे। ऐसा कर वह भाजपा को विपक्ष पर हमला करने का मौका दे रही हैं।

बसपा प्रमुख ने सोमवार को ट्वीट किया- 'जैसा कि विदित है कि बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर हमेशा ही समानता, एकता व अखंडता के पक्षधर रहे हैं, इसलिए वे जम्मू-कश्मीर राज्य में अलग से धारा-370 का प्रावधान कराने के पक्ष में कतई नहीं थे। इसी खास वजह से बीएसपी ने संसद में इस धारा को हटाए जाने का समर्थन किया। देश में संविधान लागू होने के लगभग 69 वर्षों के बाद अब वहां हालात सामान्य होने में थोड़ा समय अवश्य ही लगेगा। इसका थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है। इसको माननीय कोर्ट ने भी माना है। ऐसे में अभी हाल ही में बिना अनुमति के कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं का कश्मीर जाना क्या केंद्र व वहां के गवर्नर को राजनीति करने का मौका देने जैसा कदम नहीं है?

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर बसपा प्रमुख का रवैया केंद्र सरकार को राहत देने और कांग्रेस के लिए मायूस करने वाला है। गत शनिवार को राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। जिस पर राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।

मेरे न्योते को बिना वजह मुद्दा बना रहे राहुल : मलिक

- राज्यपाल ने कहा-राहुल की शर्तों को किया था नामंजूर
- अधीर रंजन ने खुद अपनी पार्टी की कब्र खोदी है

राज्य ब्यूरो, जम्मू

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कश्मीर दौरे के समय श्रीनगर हवाई अड्डे पर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ रोके जाने के मामले में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी ने मेरे न्योते को कभी नहीं रुकने वाला मुद्दा बना लिया है। इसे बेवजह लंबा खींचा जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने उनसे (राहुल से) कहा था कि अगर आप हम पर यकीन नहीं करते हैं तो यहां जम्मू कश्मीर में आओ और देखो। बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैं नजरबंद लोगों से मिलना चाहता हूं। सेना से मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कि हमें आपकी यह शर्तें मंजूर नहीं हैं। इसे प्रशासन पर छोड़ दिया जाए।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राज्यपाल को जम्मू कश्मीर भाजपा का अध्यक्ष होना चाहिए संबंधी टिप्पणी पर मलिक ने कहा कि संसद में जो रंजन ने जो कहा, उन्होंने अपनी पार्टी की कब्र खोदी है। मैं अपना काम निष्ठा से कर रहा हूं। मैं आरोपों की परवाह नहीं करता।

सत्यपाल मलिक। फाइल

गुलाम कश्मीर के लोग भी कहेंगे जम्मू कश्मीर बेहतर जगह: राज्यपाल ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। हम इतना काम करेंगे कि गुलाम कश्मीर के लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर कोई जगह रहने लायक है तो वह जम्मू कश्मीर है।

हालात

शांति भंग न करने की गारंटी देने को भी तैयार नहीं, लोगों का सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रहे बड़े नेता

हिरासत से रिहाई नहीं चाहते उमर और महबूबा

नवीन नवाज, श्रीनगर

कश्मीर के आम लोग प्रशासनिक पाबंदियों से जल्द छुटकारा चाहते हैं, लेकिन इसके उलट हिरासत में लिए गए उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद गनी लोन जैसे सियासी दिग्गज बाहर आने को तैयार नहीं हैं। ये नेता शांति भंग नहीं करने की गारंटी देने को तैयार नहीं है और इसलिए बेल बांड भरने को राजी नहीं हैं। माना जा रहा है कि ये नेता लोगों का सामना करने को तैयार नहीं हैं।

5 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद में पेश होने से पूर्व ही एहतियातन नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, माकपा, पीपुल्स कांफ्रेंस समेत तमाम दलों के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया या फिर नजरबंद कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी तब से अलग-अलग स्थान पर हिरासत में हैं। अनुमानित रूप से यह संख्या डेढ़ हजार के करीब हो सकती है।

वादी में हालात सामान्य होते देख प्रशासन सियासी गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए

उमर अब्दुल्ला। फाइल

प्रशासन तैयार है। शर्त यह है कि इनको गारंटी देनी होगी कि कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे। इसके लिए बेल बांड भरना होगा।

केंद्रीय दल के सामने भी उठा था रिहाई का मसला

सूत्रों के अनुसार कई नेताओं को रिहाई के लिए जब बेल बांड भरने के लिए कहा गया तो वे मुकर गए। दरअसल, ये नेता कश्मीरी अवाम का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जिन मुद्दों पर आम लोगों की भावनाओं को भड़काते थे, अब वे पूरी तरह आप्रसंगिक हो गए हैं। कैडर भी इनसे नाराज है, क्योंकि ताजा घटनाक्रम में आम लोगों की आंखों

महबूबा मुफ्ती। फाइल

पर ऑटोनामी, सेल्फ रुल और आजादी के कोरे नारों की धुंध छंट गई है। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की बहन शबनम लोन ने भी अदालत में सज्जाद की रिहाई की याचिका नहीं लगाई। केवल मिलने की याचिका लगाई थी। उन्होंने बताया कि नेकां उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ गत दिनों हुई केंद्र के प्रतिनिधियों की बातचीत में भी यह मुद्दा उठा था। ये नेता चाहते हैं कि इन्हें सियासत की पूरी अनुमति मिले और किसी भी तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए।

राजौरी में बीएसएफ मुख्यालय में धमाका दो जवान घायल

जागरण संवाददाता, राजौरी : जिले की नौशहरा तहसील के बरेरी गांव में सोमवार सुबह सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में हुए जोरदार धमाके में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआइ) और हेड कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल जम्मू रेफर कर दिया गया।

बीएसएफ मुख्यालय में हथियारों की सफाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एंटी मेटेरियल राइफल (एएमआर) का गोला जोरदार धमाका के साथ फट गया। इसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। लोगों को लगा कि आतंकी हमला हुआ है। धमाके में एएसआइ राज दीन और हेड कांस्टेबल जमीदीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उपचार के लिए उप जिला अस्पताल नौशहरा लाया गया। जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जीएमसी रेफर कर दिया गया। एसएसपी जुगल मन्हास ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमाका हथियारों की सफाई के दौरान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

31 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित इनविराड मेडिकेयर के बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को सील कर दिया है। बताया गया कि यह प्लांट नियमों के विरुद्ध चल रहा था।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 27 अगस्त 2019

न्यूज गैलरी

ओडिशा में पार्सल से निकला 5.5 फीट का कोबरा

मयूरभंज (ओडिशा) : ओडिशा में आंध्र प्रदेश से आए एक पार्सल में 5.5 फीट लंबा कोबरा सांप निकला। यह पार्सल ओडिशा के मयूरभंज निवासी मृत्युकुमार ने विजयवाड़ा से मंगवाया था। इसमें राशन का सामान था और यह सोमवार को मिला। हालांकि यह पार्सल पूरी तरह पैक करके भेजा गया था, लेकिन इसमें किसी तरह एक चूहा घुस गया। और उस चूहे के पीछे-पीछे कोबरा सांप भी डिब्बे में घुस गया। जब मृत्युकुमार ने बॉक्स खोला तो वह चौंक गए। उन्होंने खुद को संभालते हुए वन विभाग को फोन किया। कुछ देर बाद विभाग के कर्मचारी पहुंचे और सांप को पकड़कर पास के जंगल में छोड़ दिया। (जासं)

अनंत सिंह की रिमांड के लिए पुलिस ने नहीं दी अर्जी

पटना : एके-47 बरामदगी मामले में मोकामा (पटना, बिहार) विधायक अनंत सिंह को बेउर जेल भेजने के बाद पटना पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लेने की अर्जी सोमवार को नहीं दायर की। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस विधायक को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाह रही थी। माना जा रहा कि 30 अगस्त को बाढ़ कोर्ट में अनंत सिंह की पेशी कराने के साथ ही पुलिस रिमांड के लिए आवेदन देगी। सूत्रों की मानें तो दिल्ली से पटना लाए जाने तक मिली 21 घंटे की मोहलत में पुलिस ने विधायक से कड़ी पूछताछ की। हालांकि वह कोई खास जानकारी नहीं निकाल पाई। (जासं)

भारत में जमात उल मुजाहिदीन का मुखिया गया से गिरफ्तार

मिली सफलता, ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाने की तैयारी

गया व बर्धमान विस्फोट समेत कई आतंकी घटनाओं का मास्टर माइंड है अहमद

जागरण संवाददाता, कोलकाता

भारत में जमात उल मुजाहिदीन (जेएमबी) की जिम्मेदारी संभाल रहे एजाज अहमद को कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बिहार के गया से गिरफ्तार किया है। अहमद बंगाल के बर्धमान और गया विस्फोट कांड समेत अन्य कई आतंकी घटनाओं का मास्टर माइंड है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाने की तैयारी की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार करीब एक माह पहले गिरफ्तार बर्धमान विस्फोट के मुख्य आरोपी कौसर से पूछताछ में एसटीएफ के सामने एजाज अहमद के नाम का लिया था। लेकिन वह कहां छिपा हुआ है, इसकी जानकारी नहीं थी। एसटीएफ को करीब 20 दिन पहले जानकारी मिली थी कि एजाज बिहार के किसी शहर में छिपा है। सूचना पर एसटीएफ की टीम ने करीब चार दिन पहले गया में डेरा डाल लिया था। इसके बाद स्थानीय पुलिस और आइबी की मदद से छापेमारी कर एक मकान से एजाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में एजाज ने खुद का परिचय साफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में दिया। एजाज की कोई पहचान नहीं होने की वजह से एसटीएफ और आइबी संशय में पड़ गई। एजाज की शिनाख्त के लिए गया से ही एनआइए को वीडियो कॉल की गई तो दूसरी ओर से एनआइए की हिरासत में कौसर ने एजाज की शिनाख्त कर ली। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार बर्धमान विस्फोट के मुख्य आरोपी कौसर भारत में जेएमबी का मुखिया था, लेकिन कौसर की गिरफ्तारी के बाद एजाज को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। एसटीएफ ने जिहादी किताबें, सेटेलाइट फोन, लैपटॉप जब्त किए हैं।

गया कोर्ट में आतंकी के पेशी के बाद बंगाल एसटीएफ की पुलिस ले जाती हुई आतंकी एजाज नीले रंग की शर्ट में और मुंह ढके हुए। जागरण

अतीक गिरोह के सभी शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त

अंकुर त्रिपाठी, प्रयागराज

उप्र शासन के फरमान पर प्रयागराज में भी पूर्व सांसद अतीक अहमद गिरोह के सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। एसएसपी ने सभी थानों से अतीक और उनके गुर्गों के लाइसेंसी शस्त्रों की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही जिले के अन्य माफिया के भी लाइसेंसी असलहों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

डीजीपी ओपी सिंह ने दो दिन पहले कहा है कि माफिया के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। दरअसल, माफिया और उनके गुर्गे लाइसेंसी असलहों के बूते सरेआम गुंडागर्दी कर दबदबा बनाते हैं। यहां अतीक गैंग के लोगों के पास तीस से ज्यादा लाइसेंसी असलहे हैं। मौजूदा समय में अहमदाबाद जेल में बंद अतीक के नाम पर फिलहाल अब एक राइफल का लाइसेंस है। वैसे उसके पास पहले तीन शस्त्र लाइसेंस थे, मगर शुआट्स कांड के बाद मार्च 2017 में जिला प्रशासन ने उसके दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। उसी वक्त उसके भाई अशरफ के पिस्टल का लाइसेंस और करीबी गुफरान के भी दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गये थे। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने थाना प्रभारियों से अतीक समेत अन्य माफिया के शस्त्र लाइसेंस का विवरण और उन्हें निरस्त करने की रिपोर्ट मांगी है। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि माफियागीरी खत्म करने का अभियान शुरू किया गया है। अतीक का एक शस्त्र लाइसेंस अभी बचा है, जिसे निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी जाएगी।

मदरसा कांड में अशरफ पर कस सकता शिकंजा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : बहुचर्चित मदरसा कांड में पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर शिकंजा कस सकता है। पुलिस मामले में अशरफ की भूमिका की जांच कर रही है।

खुल्दाबाद क्षेत्र के चकिया निवासी अशरफ के खिलाफ 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद अशरफ फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए ढाई लाख रुपये के इनाम की संस्तुति हुई है। ऐसे में गिरफ्तारी से लेकर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। पुलिस का मानना है कि इससे उसे पूरे मामले की तह में जाने में मदद मिलेगी।

यह था पूरा मामला : 17 जनवरी 2007 को करेली क्षेत्र के महमूदाबाद स्थित एक मदरसे से दो किशोरियों को अगवा करके दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नौशाद अहमद, एखलाक अहमद समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। कुछ लोगों ने अशरफ पर आरोपितों को बचाने को लेकर आरोप लगाए थे। घटना को लेकर बसपा प्रमुख मायावती भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थीं।

हाई कोर्ट में आजम के बेटे अब्दुल्ला ने दर्ज कराया बयान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : रामपुर की स्वार विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक व रामपुर से सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां ने अपनी जन्म की तारीख को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बयान दर्ज कराया। बताया कि एमटेक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने सीबीएसई बोर्ड को हाईस्कूल सहित अन्य प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्मतिथि परिवर्तन की अर्जी दी थी, जो अभी लंबित है। लेकिन पासपोर्ट पर जन्म तारीख संशोधित हो चुकी है। जन्मतिथि को आधार बनाकर याचिका के माध्यम से चुनाव की वैधता को दी गई है।

> **कहा, सीबीएसई बोर्ड को जन्मतिथि परिवर्तन की अर्जी दी है, जो अभी लंबित है**

अब्दुल्ला ने बताया कि उनका जन्म क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में 30 सितंबर 1990 को हुआ। पारिवारिक मित्र साहजेब ने भी कहा कि वह अब्दुल्ला का नर्सरी कक्षा में प्रवेश कराने गये थे, तब विद्यालय के अध्यापक ने स्वयं जन्म की तारीख दर्ज कर ली थी। यह बयान अधिवक्ता एनके पांडेय के माध्यम से दर्ज कराया। इससे पहले अब्दुल्ला की मां, डॉ. उमा व विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज किये जा चुके हैं। नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी सुनवाई कर रहे हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। याचिका में हाईस्कूल की जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देते हुए चुनाव रद करने की मांग की गई है।

बच्चों को नमक-रोटी खिलाने पर एनएचआरसी ने भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, मीरजापुर :

> - मीरजापुर स्थित जमालपुर ब्लॉक के शिउर प्राथमिक स्कूल का मामला
> - एक शिक्षक, एनपीआरसी, बीईओ के निलंबन के साथ बीएसए का तबादला

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उप्र स्थित मीरजापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में बच्चों को नमक-रोटी परोसे जाने का संज्ञान लिया है। आयोग ने इस बाबत मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

इस मामले में हालांकि डीएम की रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार ने एक शिक्षक, न्याय पंचायत रिसोर्स कोऑर्डिनेटर (एनपीआरसी), ब्लाक एजुकेशन आफिसर (बीईओ) का निलंबन करने के साथ ही बीएसए का स्थानांतरण कर दिया है। साथ ही जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की संविदा समाप्त कर दी गई है। जमालपुर ब्लॉक स्थित शिउर प्राथमिक स्कूल में बीते 22 अगस्त को मध्याह्न भोजन में बच्चों को नमक और रोटी परोसे जाने का वीडियो वायरल हुआ तो शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्राथमिक स्कूल के वीडियो में मध्याह्न भोजन के दौरान बच्चों को एक महिला को रोटियां बांटते हुए दिखाया गया है और दूसरी महिला बच्चों को नमक दे रही है। एक शिक्षक व एनपीआरसी का निलंबित कर प्रशासन ने कोरम पूरा कर दिया, लेकिन अगले दिन जब यह मामला मीडिया में सुर्खियां बना तो शासन ने सख्त तेवर दिखाते हुए प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। इसके बाद डीएम अनुराग पटेल, एडीएम यूपी सिंह, सीडीओ प्रियंका निरंजन ने स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल की। जांच के दौरान स्कूली बच्चों ने कहा कि उन्हें दोपहर के भोजन में नमक-रोटी परोसा गया था। इतना ही नहीं, इससे ठीक एक दिन पहले नमक व चावल परोसा गया था। इसी आधार पर जिलाधिकारी, एडीएम, सीडीओ व एसडीएम चुनार की संयुक्त टीम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी। इसके बाद शासन के आदेश पर बीईओ को निलंबित करने के साथ ही जिला समन्वयक एमडीएम की संविदा समाप्त कर दी गई। साथ ही बीएसए को कार्यमुक्त करते हुए प्रयागराज डायट से संबद्ध कर दिया गया। इस प्रकरण के बाद जनपद के सभी प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील को लेकर चौकसी बरती जा रही है।

पाकिस्तान और चीन के युद्धाभ्यास पर भारतीय वायुसेना रख रही पैनी नजर

नई दिल्ली, एएनआइ : कश्मीर को लेकर बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान चीन के साथ हवाई युद्धाभ्यास कर रहा है। दोनों पड़ोसियों की इस गतिविधि को लेकर भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह सकर्त है और इनके युद्धाभ्यास पर पैनी नजर बनाए हुए है। चीन के होटन शहर में हो रहे इस युद्धाभ्यास में दोनों ही देशों के आधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं।

पाकिस्तान ने अपने जेएफ-17 लड़ाकू विमान भेजे हैं। जबकि, चीन की तरफ से जे-10 और जे-11 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं।

भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा, 'लद्दाख के लेह शहर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित होटन शहर में शाहीन कूट नाम से युद्धाभ्यास हो रहा है। युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए चीन जाने से पहले पाकिस्तानी वायुसेना के विमान गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू इलाके में तैनात थे।' यह युद्धाभ्यास दो दिन पहले शुरू हुआ था।

पाकिस्तान को चीन की तरफ से मिसाइल तकनीक, लड़ाकू विमान और युद्धपोत समेत भारी मात्रा में सैन्य सामान मिलता है। अपनी सैन्य जरूरतों के लिए पाकिस्तान बहुत हद तक चीन पर निर्भर है।

कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर पाकिस्तान और चीन ने नाराजगी जताई थी। चीन को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को लेकर आपत्ति है।

'समुद्री रास्ते से हमले की जैश की साजिश नाकाम करने को तैयार'

पुणे, प्रेट्र : कश्मीर पर सरकार के फैसले से तिलमिलाए पाकिस्तान और वहां के आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ हमले की हर स्तर पर साजिश रच रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों को भी उनके मंसूबों की जानकारी है और उनके किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी भी कर रखी है।

यहां एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद की अंडरवाटर विंग समुद्र के रास्ते हमला करने के लिए अपने आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। इस संबंध में खुफिया जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि नौसेना इस तरह के खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि समुद्री सुरक्षा से जुड़े सभी अंग समुद्र के रास्ते किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सजग हैं। 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चौकसी पर उन्होंने कहा कि सभी पक्ष यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समुद्र के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ नहीं हो। बता दें कि मुंबई हमले के लिए आतंकी समुद्र के रास्ते ही आए थे।

उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु 21 फिल्मों को देगा सब्सिडी

जागरण संवाददाता, लखनऊ

उत्तर प्रदेश अब फिल्म इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। फिल्म नीति में बदलाव के बाद प्रदेश में हर भाषा में बनने वाली फिल्मों के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है। फिल्म बंधु सितंबर में करीब 21 फिल्मों को सब्सिडी (अनुदान) देगा। इनमें अवधी, भोजपुरी हिंदी समेत सभी भाषा की फिल्में शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि प्रदेश की फिल्म नीति के चलते शहर में फिल्मों की शूटिंग तेजी से बढ़ी है। बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर और एक्टर प्रदेश में शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए फिल्म निर्माता-निर्देशकों की समस्या और सुविधाओं को देखते हुए हर जिले में फिल्म फेसिलिटेशन कमेटी बनाई गई है। फिल्म बंधु की अधिकारिक वेबसाइट का अपडेशन नियमित तौर पर हो रहा है ताकि कोई असुविधा न हो।

ये फिल्में सब्सिडी की हकदार : बहन होगी तेरी, अलीगढ़, सोनू की टीटू की स्वीटी, दबंग सरकार, चीट इंडिया, बरेली की बर्फी, शादी में जरूर आना, सिपाही, शिव रक्षक, 9 ओ क्लॉक, घप्पा, कैरी ऑन कुत्तों, रब्बा इश्क न होये, सैंया सुपर स्टार, मुकद्दर आदि फिल्मों को सब्सिडी देनी की बात चल रही है।

इन फिल्मों को मिल चुकी है सब्सिडी

इस बार 12 फिल्मों को अनुदान दिया गया है। इनमें टॉयलेट एक प्रेमकथा, मॉम, जॉली एलएलबी 2, निल बट्टे सन्नाटा, 30 मिनट्स, प्रणाम, मैं हूं एकराज, एनएच 8, रोड टू निधिवन, जेडी, भोजपुरी फिल्मों में सांवरिया मोहे रंग दे, ये मोहब्बतें, बबुआ, मोहब्बत, अवधी फिल्म भाग्य न जाने कोई आदि शामिल हैं।

इस तरह मिलती है सब्सिडी

उप्र में शूटिंग जरूरी है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि प्रदेश के कितने कलाकार फिल्म में हैं। उनका किरदार कितना बड़ा है। फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म निर्माण के बजट के साथ खर्च के सभी ऑरिजिनल बिल देने होते हैं। तभी सब्सिडी का चेक दिया जाता है।

उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के चाचा के खिलाफ चार्जशीट

जागरण संवाददाता, उन्नाव : न्यायालय के अभिलेखों में छेड़छाड़ कर सफेदा लगाने के मामले में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के चाचा के खिलाफ सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। विवेचक ने चाचा को आरोपित मानते हुए मामले में और लोगों के नाम सामने आने की भी बात कही है। कोर्ट ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई करने के बाद 30 अगस्त की तारीख नियत की है।

पीड़िता के चाचा पर न्यायालय के अभिलेखों में सफेदा लगाकर नाम बदलने और इसका फायदा उठाने का आरोप लगाकर उन्नाव सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी विवेचना कोतवाली पुलिस कर रही है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सोमवार को मामले में पीड़िता के चाचा की पेशी थी। पेशी के दौरान मामले की विवेचना कर रहे सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज अमर सिंह ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें विवेचक ने चाचा को आरोपित बताया है। वहीं विवेचक के अनुसार इसमें अभी कुछ और नाम भी आ सकते हैं। अभी जांच की जा रही है। पीड़िता के चाचा के वकील ने बताया कि अब सुनवाई में तेजी आएगी।

घोटाले के आरोपित चोकसी ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट जमा करने से किया इन्कार

> - पीएनबी घोटाले के आरोपित ने कहा, एंटीगुआ के डॉक्टर ने इलाज करने से किया मना
> - भारत नहीं लौटने के लिए चोकसी का मुख्य आधार है कि वह यात्रा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट नही है

मुंबई, प्रेट्र : हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपित मेहुल चोकसी ने सोमवार को बांबे हाई कोर्ट को बताया कि पूर्व के निर्देश के मुताबिक वह अपनी मेडिकल रिपोर्ट यहां निगम संचालित जे जे अस्पताल में जमा नहीं करा सकता, क्योंकि एंटीगुआ में उसके डॉक्टर ने कुछ कारणों से उसका उपचार करने से मना कर दिया।

चोकसी ने एक याचिकता में घोटाला में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए निचली अदालत के सामने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू प्रक्रिया को चुनौती दी थी। इस साल जून में हाई कोर्ट ने चोकसी को अपने डॉक्टर के एक पत्र के साथ अपनी नई मेडिकल रिपोर्ट जेजे अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम के पास जमा कराने को कहा था। न्यायमूर्ति आईए महंती की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई के दौरान चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने हाई कोर्ट को बताया कि वे चिकित्सा रिपोर्ट नहीं सौंप पाए। अग्रवाल ने कहा, 'चोकसी का इलाज करने वाले डॉक्टर ने कुछ कारण से उसका उपचार करने से मना कर दिया। यह रिपोर्ट हम बंद लिफाफे में सौंप रहे हैं।' हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन का सामना करने के वास्ते भारत नहीं लौटने के लिए चोकसी का मुख्य आधार यह है कि वह यात्रा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट नही है। न्यायमूर्ति महंती ने कहा, 'लेकिन जब आप (चोकसी) इस दावे का समर्थन करने के लिए दस्तावेज नहीं दे रहे तो इस याचिका को वापस ले लें।' अग्रवाल सहमत हो गए और याचिका वापस ले ली। ईडी और सीबीआई को पंजाब नेशनल बैंक से 13400 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़ा मामले में चोकसी और उसकेभतीजे नीरव मोदी की तलाश है।

मदर टेरेसा को याद किया

समाजसेवा की मिसाल और संत की उपाधि से विभूषित मदर टेरेसा की 110 वीं जयंती पर कोलकाता के मदर हाउस में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर ननों ने शांति प्रार्थना की। 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे (मेसीडोनिया) में जन्मी मदर टेरेसा ने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चेरिटी की स्थापना की थी। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। एएनआइ

मुजफ्फरनगर हिंसा में शाहनवाज हत्याकांड में पांच पर आरोप तय

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : गिरफ्तारी के बाद जमानत पर जेल से रिहा हुए मुजफ्फरनगर दंगे के पांच आरोपितों पर सत्र न्यायालय ने मारपीट के बाद हत्या की धारा में आरोप तय कर दिए हैं। सभी आरोपित सोमवार को न्यायालय में पेश हुए। फिलहाल एक आरोपित फरार चल रहा है। न्यायालय के आदेश पर उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है।

27 अगस्त 2013 को कवाल में शाहनवाज व मलिकपुरा निवासी सचिन व गौरव की हत्या कर दी गई थी। शाहनवाज की हत्या के मामले में उसके पिता मो. सलीम ने मृतक सचिन और गौरव सहित आठ लोगों के विरुद्ध एफआइआर कराई थी। इस मामले में गठित एसआइटी ने जांच कर मृतक सचिन व गौरव के अलावा बाकी छह आरोपितों को क्लीनचिट दे दी थी। इसके बाद सलीम की ओर से दायर निजी परिवाद पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम-2 न्यायालय ने सभी छह आरोपितों को तलब किया था।

आरोपितों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। पांच आरोपितों प्रहलाद, बिशन, तेंदर, जितेंद्र एवं देवेंद्र को चार जून 2019 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

स्कूल के लिए चक्काजाम कर रहे विद्यार्थियों पर टूटा पुलिस का कहर

नईदुनिया, विदिशा

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर चक्काजाम कर रहे विद्यार्थियों पर सोमवार को पुलिस का कहर टूट पड़ा। आठ में से दस शिक्षकों का तबादला किए जाने से नाराज विद्यार्थियों को पुलिस ने जमकर पीटा।

विदिशा जिले के ग्राम सिरनोटा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी सोमवार को प्रदर्शन कर रहे थे। दस में से आठ शिक्षकों का तबादला होने और स्कूल भवन में बारिश का पानी टपकने को लेकर वह खफा थे। पुलिसकर्मियों ने छात्रों को चक्काजाम करने से मना किया। छात्र नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों पर बलप्रयोग करते हुए कुछ छात्रों से मारपीट की। पुलिस द्वारा स्कूली छात्रों के साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही बासौदा विधायक लीना जैन और पूर्व विधायक निशंक जैन भी मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द शिक्षकों की व्यवस्था कराने का आश्वासन छात्रों को दिया। उधर, जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने विद्यार्थियों के साथ मारपीट की है, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

बेल्ट और डंडों से पीटा: छात्र-छात्राओं का कहना है कि स्कूल में करीब 300 विद्यार्थी हैं। स्कूल में 10 शिक्षक नियुक्त थे, लेकिन कुछ दिन पहले आठ शिक्षकों का तबादला कर दिया गया। स्कूल भवन में बारिश का पानी भी टपक रहा है। इस समस्या को लेकर सोमवार दोपहर को हम प्रदर्शन करने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। छात्रों को समझाने की कोशिश की। छात्र नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने कुछ छात्रों को बेल्ट, डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे स्कूल परिसर में भगदड़ मच गई।

गंजबासौदा के एसडीओपी, जीपी अग्रवाल ने बताया कि ग्राम सिरनोट में स्कूली छात्रों के साथ मारपीट की घटना की जानकारी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

हेल्थ साइंस के छात्र ने बोल-बोलकर पढ़ने का बना दिया विश्व रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, कानपुर

छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के छात्र अलाउद्दीन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। बीएससी इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी अंतिम वर्ष के इस छात्र ने बिना रुके बोल-बोलकर 27 घंटे पांच मिनट तक लगातार पढ़ने का विश्व रिकार्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड एशिया के पदाधिकारी डॉ. मनीष विश्नोई ने उसे 'लांगेस्ट रीडिंग अलाउड मैराथन (सिंगल सिटिंग) का प्रमाण पत्र दिया। इससे पहले बोल-बोलकर 25 घंटे चार सेकंड पढ़ने का रिकार्ड लखीमपुर खीरी के यतीश चंद्र शुक्ला के नाम था।

छह माह पूर्व किया आवेदन, कमरे में किया अभ्यास : मूलरूप से जौनपुर के बदलापुर तहसील के बाहरीपुर कलां गांव के रहने वाले अलाउद्दीन पिछले दो वर्ष से यह विश्व रिकार्ड बनाने का प्रयास कर रहे थे। लखीमपुर खीरी के यतीश चंद्र शुक्ला से भी वह मिले। छह माह पूर्व उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में ऑनलाइन आवेदन किया था।

27.05 घंटे तक लगातार बोलकर करते रहे पढ़ाई

उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगातार 27 घंटे पांच मिनट पढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले जौनपुर के अलाउद्दीन। जागरण

रविवार सुबह पढ़ने बैठे, सोमवार को उठे

रविवार सुबह दस बजे से 22 वर्षीय अलाउद्दीन ने डॉ. दिलीप गंगवार इंस्टीट्यूट में जंतु विज्ञान विषय की पढ़ाई शुरू की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड की टीम भी वहां पहुंच गई। सोमवार दोपहर एक बजे तक उन्होंने बिना रुके बोल-बोलकर पढ़ाई की। उनके नाम सबसे ज्यादा देर तक पढ़ने सहित एक ही विषय के साथ इतने लंबे समय तक पढ़ाई करने का रिकार्ड भी दर्ज हो गया। इसके लिए उन्हें 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' का प्रमाण पत्र दिया गया।

जोधपुर जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें और बढ़ेंगी

संवाद सूत्र, जोधपुर

> पोक्सो अधिनियम में सजा याफ्ता है आसाराम

राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश से जोधपुर जेल में बंद कथावाचक आसाराम को झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने लंबित अपीलों की सुनवाई वरीयता के आधार पर करने का आदेश दिया है। इससे आसाराम की मुश्किलें अब और बढ़ जाएंगी। दरअसल इस आदेश को अमली जामा पहनाया गया तो आसाराम की अपील पर सुनवाई का नंबर तीन-चार साल बाद आने की संभावना बनती है। वर्तमान में वरीयता में सात साल से अधिक के लंबित अपराधिक मामलों पर सुनवाई चल रही है।

जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उक्त आदेश दिया है। इसके अनुसार अपील की सुनवाई वरीयता क्रम से निर्धारित करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में अपने स्वास्थ्य को लेकर आसाराम ने सुनवाई को जल्द करवाने के लिए आवेदन किया था। इसमें उसने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। इसके कारण पूर्व में समय-समय पर उसकी सुनवाई की जा रही थी, लेकिन सोमवार को हाई कोर्ट के नए आदेश से आसाराम की मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ेंगी। गौरतलब है कि न्यायालय ने आसाराम को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी माना और उम्रकैद सजा सुनाई है, जिसके बाद से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। न्यायालय ने आसाराम को दुष्कर्म के मामले में पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है।

> हाईकोर्ट का आदेश न्यायपूर्ण है। आसाराम से पूर्व के और इससे इतर भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें विभिन्न आयुवर्ग के लोग जुड़े हैं। नियत प्रकिया के तहत अपील सुनवाई होती है, जिससे सभी को समान रूप से बात रखने का मौका मिलता है।
>
> **– पीसी सोलंकी, आसाराम मामले में पीड़ित बालिका के वकील, हाई कोर्ट, जोधपुर**

65 प्रतिशत सड़क हादसों का शिकार 18 साल से 35 साल तक की उम्र के युवा होते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पांचवी से आठवीं तक के बच्चों को कोर्स की किताबों में ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा।

न्यूज गैलरी

एटा में महिला को बच्चा चोर समझकर पीटा

एटा : साधु के चंगुल से छूट कर रविवार देर रात भागी महिला की लोगों ने बच्चा चोर समझ पिटाई कर दी। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली महिला को एक साधु नशीला पदार्थ खिला ऋषिकेश से यहां ले आया था। पुलिस ने महिला की तहरीर पर अज्ञात साधु समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला निवासी बीना अपनी बहन के यहां ऋषिकेश गई थी। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु उसे नशीला पदार्थ खिला एटा ले आया। महिला ने पुलिस को बताया कि साधु उसे पैदल लेकर जा रहा था। इसी बीच मौका पाकर वह भाग निकली। तभी लोगों ने बच्चा चोर का शोर मचा पिटाई कर दी। (जासं)

अंतागढ़ टेप कांड में अब 28 अगस्त को होगी सुनवाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ के चर्चित अंतागढ़ टेप कांड में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी, मंतूराव पवार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता को अदालत में पेश होना था। मामले की जांच कर रही एसआइटी के वकील सौरभ गुप्ता ने चारों आरोपितों का वॉइस सैंपल लेने के लिए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में आवेदन लगाया था। इस पर आरोपितों की ओर से वकीलों ने पेश करने के लिए वक्त देने का आग्रह किया। (नईदुनिया)

डिप्लोमाधारी डॉक्टर भी बनेंगे मेडिकल कॉलेजों में एसआर

बदले नियम ▸ एमसीआइ ने योग्यता एवं उम्र सीमा में किया बदलाव

एमसीआइ ने नए संशोधन का 16 अगस्त को किया गजट नोटिफिकेशन

जागरण संवाददाता, कानपुर

अब डिप्लोमाधारी चिकित्सक भी देशभर के चिकित्सा विश्वविद्यालयों, चिकित्सकीय संस्थानों राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजीडेंट (एसआर) बन सकेंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस (एमसीआइ बीओजी) ने 16 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन करके चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीमा में बदलाव किया है।

देश के मेडिकल कॉलेजों एवं चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस तथा एमडी में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए चिकित्सा शिक्षकों की कमी है। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए चिकित्सा शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त कि मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ष तक सीनियर रेजीडेंट का अनुभव होने पर ही एमडी, एमएस और डीएनबी डिग्रीधारक डॉक्टर चिकित्सा शिक्षक के लिए आवेदन को पात्र होते थे, वहीं एमबीबीएस के बाद अपने विषय में डिप्लोमा करने वाले छात्र-छात्राएं एसआर बनने के लिए पात्र ही नहीं होते थे। मेडिकल कॉलेजों को सीनियर रेजीडेंट (एसआर) नहीं मिलते थे। ऐसे में आधी से अधिक सीटें खाली रह जाती हैं।

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका: इसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने एमसीआइ को फटकार लगाई। उसके बाद एमसीआइ ने शिक्षक पात्रता की योग्यता यानी टीचर एलिजबिलिटी क्वालीफिकेशन रूल में बदलाव कर एसआर की योग्यता नए सिरे से परिभाषित कर दी। एमसीआइ ने इस नियम को मिनिमम क्वालीफिकेशन फॉर टीचर इन मेडिकल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन-2019 नाम दिया है।

फाइल

इन विषयों में थी डिप्लोमा की पढ़ाई

पैथालॉजी, नाक कान गला (ईएनटी), नेत्र रोग (आप्थेल्मिक), पीडियाट्रिक (बाल रोग), एनस्थीसिया, स्त्री एवं प्रसूति रोग (ऑब्स एवं गॉयनी), अस्थि रोग (आर्थोपेडिक) एवं हृदय रोग (कार्डियोलॉजी)।

उम्र सीमा में भी बदलाव

एमसीआइ ने एसआर की योग्यता के साथ ही उम्र सीमा में भी संशोधन किया है। पहले एसआर बनने की अधिकतम उम्र 40 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है।

डिप्लोमाधारी डॉक्टरों को एसआर बनाने का एमसीआइ का निर्णय सही है। इससे मेडिकल कॉलेजों में एसआर की कमी दूर होगी। साथ ही मरीजों के इलाज, ऑपरेशन तथा पढ़ाई में भी मदद मिलेगी।

– प्रो. आरती लालचंदानी, प्राचार्य, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज।

कानपुर में सीएसए में रैगिंग मारपीट और तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, कानपुर

- छात्रावासों में उपद्रव, जूनियर छात्रों को मुर्गा बनाकर पीटा
- पुलिस के आने से पहले आरोपित फरार होने में हुए कामयाब

उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में बीती रात करीब डेढ़ सौ सीनियर छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। रैगिंग के लिए जूनियर छात्रों के छात्रावास का ताला तोड़कर घुस गए। करीब एक घंटे तक तोड़फोड़ कर जूनियर छात्रों को मुर्गा बनाकर पिटाई की। सूचना पर सीएसए अधिकारी व नवाबगंज पुलिस आने पर आरोपित वहां से भाग गए।

उपद्रवी छात्र राय साहब राम प्रसाद छात्रावास (आरएसआरपी) के गेट का ताला तोड़ जबरन घुस गए, वहां तोड़फोड़ कर जूनियर छात्रों के कमरों का दरवाजा खुलवाने के लिए लाठी-डंडे मारे। वहां कहर बरपाने के बाद उपद्रवी सीनियर छात्र सामने स्थित जीसी बोस छात्रावास पहुंचे। वहां दरवाजे पर अंदर से ताला लगा था, जिसे वह तोड़ नहीं सके। इस पर वह छात्रावास की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए और वहां भी अराजकता की। दरवाजों पर धक्के मार-मारकर कमरे खुलवाने लगे। इस दौरान कुछ कमरों की कुंडी टूट गई जिससे दरवाजे खुल गए। उन्होंने यहां छात्रों को बाहर निकालकर मुर्गा बनाया। जब वह मुर्गा बनने के लिए झुकते तो वे उनकी पीठ पर वार कर रहे थे। हंगामे की सूचना सुरक्षा सुपरवाइजर ने डीन, वार्डन व सुरक्षा विभाग को दी। जानकारी पर थाना नवाबगंज पुलिस सहित कुलसचिव प्रो. कृपाशंकर, सहायक सुरक्षा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र यादव, डॉ. रामजी गुप्ता व डॉ. वाईके सिंह मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही उपद्रवी छात्र भाग निकले। इसके बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों व पुलिस ने वरिष्ठ छात्रों के छात्रावास में पूछताछ की।

मुंह बांधकर पहुंचे छात्र

जूनियर छात्रों के छात्रावास में घुसने वाले कई वरिष्ठ छात्र मुंह बांधकर पहुंचे थे। उन्हें डर था कि कहीं सीसीटीवी कैमरे में चेहरे कैद न हो जाएं। इन छात्रों ने आरएसआरपी छात्रावास के गेट पर पहरा दे रहे दोनों गार्डों से चाबी मांगी। गार्डों ने चाबी पास न होने की बात कही तो छात्रों ने उनका डंडा छीन लिया और शांत खड़े रहने के लिए कहकर ताला तोड़ने लगे। अंदर घुसकर वहां रखा पंखा, कुर्सी-मेज व बल्ब तोड़ दिए।

देर रात कई छात्रों से पूछताछ की गई है। इस प्रकरण में द्वितीय वर्ष के छात्रों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। जांच के लिए टीम बनाई गई है।

– डॉ. एचपी सिंह, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, सीएसए

दूसरी शादी मामले में आइएएस अफसर महिला आयोग में पेश

अहमदाबाद, प्रेट्र : निलंबित आइएएस अधिकारी गौरव दहिया सोमवार को राज्य महिला आयोग के सामने पेश हुए। दहिया के खिलाफ दिल्ली की महिला ने दूसरी शादी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

महिला ने पिछले हफ्ते गांधीनगर में राज्य महिला आयोग के समक्ष दहिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने दहिया को समन जारी किया था। महिला ने आरोप लगाया है कि दहिया ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही उससे शादी की और पहली शादी की बात भी उससे छिपाई। महिला के मुताबिक दहिया ने उसके साथ 2018 में शादी की थी।

आयोग की अध्यक्ष लीलाबेन अंकोलिया ने कहा कि मामले में और स्पष्टता के लिए आयोग दहिया और महिला को एक साथ बुला सकता है। अंकोलिया ने गांधीनगर में पत्रकारों को बताया कि दहिया से विभिन्न शिकायतों को लेकर सवाल जवाब किया गया।

गुजरात कैडर के 2010 बैच के आइएएस अधिकारी दहिया के खिलाफ दूसरी शादी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने उन्हें 14 अगस्त को निलंबित कर दिया था। राज्य महिला आयोग के सामने पिछले हफ्ते पेश महिला ने अपनी आठ महीने की बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने को भी कहा था। उसका कहना था कि दहिया ही उसकी बच्ची के पिता हैं। दहिया ने महिला के साथ शादी से ही इन्कार किया है। उनका कहना है कि महिला पैसे के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रही है।

गंगा में विसर्जित हुई जेटली की अस्थियां

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

- पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के पुत्र रोहन ने हरकी पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर पूर्ण विधि विधान के साथ किया अस्थि विसर्जन
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी मौके पर रहे मौजूद

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की अस्थियां सोमवार दोपहर हरकी पैड़ी में ब्रह्मकुंड पर विसर्जित की गईं। उनके पुत्र रोहन जेटली ने विधि विधान के साथ गंगा में अस्थियां विसर्जित की। तीर्थ पुरोहित पंडित देवेंद्र कुमार शर्मा और पंडित अभिषेक कुमार शर्मा ने कर्मकांड कराया।

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का शनिवार दोपहर निधन हो गया था। रविवार को दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। सोमवार को उनके पुत्र रोहन जेटली कुछ रिश्तेदारों के साथ अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे। अस्थि विसर्जन के उपरांत रोहन ने हरकी पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा का कार्यालय पहुंच तीर्थ पुरोहित की बही में नाम दर्ज कराया। इस दौरान प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद, बाबा रामदेव, रजत शर्मा आदि मौजूद रहे।

हरिद्वार की हरकी पैड़ी पर सोमवार को दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करते उनके पुत्र रोहन जेटली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के सीएमत्रिवेंद्र सिंह रावत व योगगुरु बाबा रामदेव आदि मौजूद रहे। जागरण

बिहार में पुरानी रंजिश में महिला समेत तीन को गोलियों से भूना

सीतामढ़ी, संस : सुप्पी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सोमवार को महिला समेत तीन लोगों की गोलियों से छलनी कर दिया। बदमाशों ने पहले दो युवकों को गोली मारी। इसके बाद अख्ता गांव स्थित घर में घुस कर एक महिला की हत्या कर दी।

मृतकों में अख्ता निवासी असगर खान के पुत्र सलमान खान (30), हसीब खान के पुत्र एजाज खान (32) तथा मुन्ना खान की पत्नी शाहजहां निशा (40) हैं। एजाज और सलमान मामा-भांजा थे। शाहजहां एजाज की भाभी थी। एजाज का भाई रुस्तम खान आठ माह पूर्व अख्ता के सरपंच के देवर नियाज खान की हत्या मामले में जेल में बंद है। मरनेवाले तीनों जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष जियाउद्दीन खान के रिश्तेदार बताए गए। घटना का कारण पूर्व का विवाद बताया जा रहा है।

इसे अख्ता पंचायत के सरपंच के देवर और आरटीआई कार्यकर्ता नियाज खान की हत्या से जोड़ कर देखा जा रहा है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। सुप्पी समेत कई थानों की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। पुलिस ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हरियाणा के गैंगस्टर कौशल को दिल्ली एयरपोर्ट से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

हरियाणा के मोस्टवांटेड गैंगस्टर कौशल को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने सोमवार तड़के 4.30 बजे नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का दावा है कि कौशल नरेश यादव नाम के फर्जी पासपोर्ट से दक्षिणी अफ्रीकी देश जांबिया भागने की फिराक में था। पांच लाख के इनामी कौशल के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने रेडकॉर्नर और लुकआउट नोटिस जारी कराया हुआ था, ऐसे में एयरपोर्ट पर जांच के दौरान उसे इमीग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसकी सूचना हरियाणा एसटीएफ को दी। एसटीएफ के डीआइजी सतीश बालियान ने टीम के साथ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और गुरुग्राम लेकर पहुंचे।

फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त केके राव ने पत्रकारों को बताया कि कौशल के पास से 12 मोबाइल फोन, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा 70 हजार दिरहम (करीब 14 लाख रुपये) और स्पेन का फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुआ है, जो हरीश के नाम से बना हुआ है। एसटीएफ ने मार्च 2017 में गुरुग्राम नाहरपुर रूपा गांव में जॉनी हंस की मां सुदेश की हत्या के मामले में गुरुग्राम अदालत से 2 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। अभी एसटीएफ आरोपित से पूछताछ कर रही है। जॉनी हंस की मां की हत्या के बाद वह भागकर दुबई चला गया था। वहीं से रंगदारी वसूली का अपना गिरोह संचालित कर रहा था। सुदेश की हत्या के मुकदमे में 21 फरवरी 2019 को गुरुग्राम पुलिस ने कौशल के खिलाफ रेडकॉर्नर नोटिस जारी कराया। 27 जून को हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की गोलियों से भूनकर हत्या की साजिश रचने में उसका नाम आया था। पुलिस का दावा है कि यह हत्या एक करोड़ रुपये की रंगदारी नहीं देने पर की गई। इसके बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम में कई कारोबारियों से रंगदारी मांगी गई थी। कौशल पर गुरुग्राम, फरीदाबाद व रेवाड़ी में हत्या, रंगदारी, लूट, हत्या का प्रयास सहित विभिन्न आरोपों में 150 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गुरुग्राम में रिमांड पूरी होने के बाद फरीदाबाद पुलिस विकास चौधरी की हत्या मामले में पूछताछ के लिए गैंगस्टर कौशल को रिमांड पर लेगी। पुलिस आयुक्त के अनुसार पांच लाख रुपये की इनामी राशि एसटीएफ टीम में वितरित की जाएगी।

गैंगस्टर कौशल जागरण

गैंगस्टर कौशल को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत से उसे दो सितंबर तक चार दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपित के ऊपर हरियाणा में 150 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उससे पूछताछ की जा रही है।

–केके राव, पुलिस आयुक्त फरीदाबाद

फीस के लिए दिए मात्र पांच रुपये और पिलाई चाय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- अपने चैनल पर कार्यक्रम में रजत शर्मा ने साझा किए अरुण जेटली से जुड़े संस्मरण

मैं कॉलेज में दाखिले के लिए लाइन में था, काउंटर पर पहुंचा तो फीस में तीन रुपये कम थे। एकाउंटेंट ने डांटा, तभी पीछे से एक आवाज आई... नए छात्र से बात करने का यह क्या तरीका है। यह कहने वाले युवक ने मुझे पांच रुपये दिए और चाय पिलाई। वह कोई और नहीं, अरुण जेटली थे, जो आगे चलकर एक प्रखर अधिवक्ता और देश के वित्त मंत्री बने।

दिवंगत अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये यादें अपने टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के अध्यक्ष और जाने-माने पत्रकार रजत शर्मा ने साझा कीं। जेटली को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपना अभिभावक, अपने घर का बड़ा खो दिया।

अरुण जेटली मेरे लिए सिर्फ नेता नहीं थे, दोस्त थे। दोस्त से ज्यादा मेरे मार्गदर्शक थे। मेरा नाता उनसे तब का है, जब वह नेता नहीं थे और मैं पत्रकार नहीं था।

रजत शर्मा ने कहा कि मैं साधारण परिवार से था। दस भाई-बहनों का बड़ा परिवार था। वर्ष 1973 में कॉलेज की फीस देने के लिए दो-दो, पांच-पांच रुपये के नोट इकट्ठा किए थे। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिले के लिए लाइन में लगा था। जब एकाउंटेंट के सामने दो-दो, पांच-पांच रुपये के नोट गिन रहा था तो उसने डांटते हुए कहा कि ये छोटे-छोटे नोट लेकर आए हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो। जब पूरी फीस गिनकर दी तो उसमें तीन रुपये कम थे तो एकाउंटेंट ने और जोर से डांटा।

मैं परेशान था कि वापस घर से तीन रुपये लाने पड़ेंगे। तभी अरुण जेटली आ गए और अपनी जेब से पांच का नोट निकाला और मुझे दे दिया। बाद में उन्होंने कहा सारे पैसे तुमने दे दिए, अब तो चाय के पैसे भी नहीं होंगे। चलो, तुम्हें चाय पिलाता हूं।

'छात्र राजनीति से जेटली जैसे नेता भी निकलते हैं'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव-2017 के दौरान संपत्ति अवेहलना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का जिक्र करते हुए मौखिक टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि डीयू प्रशासन छात्र नेताओं के साथ कठोर व्यवहार न करे। देश को अरुण जेटली जैसे महान नेता छात्र राजनीति से ही मिले हैं।

हाई कोर्ट ने डीयू प्रशासन से मौखिक कहा कि डूसू उम्मीदवार यदि संपत्ति की अवहेलना के दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का जिक्र करते हुए कहा कि छात्रों पर ज्यादा कठोर न हों और हर मामले में प्रतिबंध न लगाएं। अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा की तरफ से दायर इस जनहित याचिका में डूसू चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा संपत्ति की अवेहलना पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

म्यांमार को दिए 10 वाहन

भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार की सेना को पैट्रोलिंग के लिए 10 टाटा सफारी स्ट्राम वाहन सौंपे। सोमवार को एक समारोह में भारत के राजदूत सौरभ कुमार ने म्यांमार के सैन्य अधिकारियों को वाहनों की सुपुदर्गी दी। एएनआइ

भारत-बांग्लादेश सीमा से 17 पशु तस्कर और पांच घुसपैठिए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने बंगाल में भारत- बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर फिर 254 मवेशियों को जब्त करने के साथ 17 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे पांच बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी पकड़ा है। बीएसएफ ने बताया कि सीमावर्ती मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और नदिया जिले से इनको पकड़ा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार मध्यरात्रि में दो अलग-अलग घटनाओं में जवानों ने नौ बांग्लादेशी और पांच भारतीय पशु तस्करों को 24 मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया। तस्कर मवेशियों को बांग्लादेश में तस्करी की कोशिश कर रहे थे। एक अन्य घटना में 153वीं बटालियन के जवानों ने बीओपी डोबिला क्षेत्र से तीन भारतीय तस्करों को तीन मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया। इसी तरह विभिन्न घटनाओं में मालदा सेक्टर के बीओपी निमतिता एवं सोवापुर क्षेत्र में जवानों ने गंगा से 186 मवेशियों को जब्त किया गया। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से 41 मवेशियों को जब्त किया गया।

सम्मेलन

मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ सम्मेलन, केंद्रीय समिति इन सभी प्रजातियों के गुण-धर्म की जांच-परख करेगी

गेहूं और जौ की 17 नई प्रजातियां चिह्नित की गईं

नईदुनिया, इंदौर

- राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधानकर्ता सम्मेलन में रखा प्रस्ताव, केंद्रीय समिति की अनुमति के बाद होंगी जारी

मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधानकर्ता सम्मेलन के अंतिम दिन सोमवार को देश के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों से प्रस्तावित की गई गेहूं और जौ की 17 नई प्रजातियों को चिह्नित किया गया। इनमें से 15 गेहूं और दो जौ की प्रजातियां हैं। अभी इन्हें किसानों को उगाने और उत्पादन के लिए जारी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की सेंट्रल वैरायटी कमेटी से अनुमति मिलने के बाद ही इन्हें जारी किया जाएगा। अभी केवल इन प्रजातियों को प्रस्तावित किया गया है।

सम्मेलन में चिह्नित प्रजातियों में से नौ प्रजातियां रोटी वाले गेहूं की और छह प्रजातियां मालवी ड्यूरम गेहूं की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर से भी चार नई प्रजातियां प्रस्तावित की गई हैं। इनमें से दो मालवी ड्यूरम गेहूं की हैं, जो मध्यप्रदेश के लिए ही अनुशंसित की गई हैं। दो प्रजातियां चंदौसी/शरबती की हैं जो दूसरे राज्यों के लिए प्रस्तावित हैं। इन प्रजातियों में एचआई-1621 और एचआई-1628 रोटी वाले गेहूं की हैं जबकि एचआई-8802 और एचआई- 8805 मालवी ड्यूरम गेहूं की हैं। बताया जाता है कि मालवी गेहूं की प्रजातियां 60-65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की हैं, जो सामान्य तौर पर चार-पांच पानी में पैदा होने वाली हैं। केंद्रीय समिति इन सभी प्रजातियों के गुण-धर्म की जांच-परख करेगी। इसके बाद तय होगा कि इन प्रजातियों की देश को जरूरत है या नहीं। इसके बाद ही इन्हें जारी किया जा सकेगा। समिति में भारत सरकार के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सहित कृषि वैज्ञानिक भी होते हैं।

भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक डॉ. जीपी सिंह ने बताया कि अभी तो विभिन्न अनुसंधान केंद्रों पर ट्रायल और शोध के बाद सिर्फ इन प्रजातियों को चिह्नित किया गया है। जरूरी नहीं कि यह सभी प्रजातियां जारी कर दी जाएं। प्रजातियों के गुण-धर्म के हिसाब से जरूरी जलवायु, पानी, मिट्टी आदि को देखते हुए केंद्रीय समिति इनमें से कुछ प्रजातियों को जारी करने से रोक भी सकती है।

आयरन व जिंक की गोलियां देने के बजाए 250 ग्राम गेहूं की रोटी खिलाएं : सम्मेलन के आखिरी दिन प्रगतिशील किसानों ने भी सुझाव दिए। मथुरा (उप्र) से आए किसान सुधीर अग्रवाल ने कहा कि गेहूं की हर प्रजाति में आयरन, जिंक व प्रोटीन की मात्रा होती है। एक अध्ययन के मुताबिक आम आदमी प्रतिदिन करीब 250 ग्राम गेहूं का सेवन करता है। यदि सरकार आयरन व जिंक की प्रचुर मात्रा वाले गेहूं का सेवन हर व्यक्ति को करवाए तो आयरन व जिंक की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। सरकार को ऐसी प्रजातियों के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। गेहूं की डब्ल्यूबी-2 प्रजाति में जिंक ज्यादा है और यह काफी फायदेमंद है। जिन प्रजातियों में जिंक की मात्रा कम होती है, यदि गेहूं के पौधों पर फूल आने के दौरान ही जिंक का स्प्रे कर दिया जाए तो उनमें भी यह मात्रा बढ़ जाती है। गेहूं की बीएच-25 प्रजाति में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है।

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के रहने वाले किसान बहादुरसिंह झरिया ने कहा कि वे बहुत पहले दुबई गए थे, वहां उनके दो ट्राले चलते थे। पिताजी ने उन्हें गांव वापस बुलाया और खेती करने की सलाह दी। गांव आकर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सीखी। उन्हें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नई वैरायटी डीबीडब्ल्यू 221 का एक किलो गेहूं दिया गया। उन्होंने उसे एक हेक्टेयर में बेड पद्धति से लगाया और उससे उन्होंने 22 क्विंटल गेहूं के बीज तैयार किए। वर्तमान में गेहूं, धान, मूंग के बीज तैयार कर रहे हैं।

जरूरी नहीं कि सभी प्रजातियां जारी ही की जाएं। प्रतीकात्मक

हनीप्रीत को नहीं मिली राहत जज का सुनवाई से इन्कार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- चार महीने पूर्व नियमित जमानत की मांग को लेकर दायर की थी याचिका

साध्वियों के यौन शोषण में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की दत्तक पुत्री हनीप्रीत को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। हनीप्रीत ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

मामले में जब सोमवार को सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने फाइल देखते ही मामले पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। उन्होंने मामले को अन्य बेंच को देने के लिए चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया। अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि इस याचिका पर कब और कौन जज सुनवाई करेगा। बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने हनीप्रीत को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता पर संगीन आरोप हैं। ऐसे आरोपी को कैसे जमानत दी जा सकती है। हनीप्रीत के वकील का कहना था कि उन्हें पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके बाद आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जज ने सुनवाई से इंकार कर दिया। हनीप्रीत ने मई में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी।

हनीप्रीत ने हाईकोर्ट में दायर अपनी नियमित जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका में कहा है कि 25 अगस्त 2017 को जब पंचकूला में सीबीआइ अदालत ने गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था तो उसके बाद पंचकूला में हुए दंगों की साजिश रचे जाने का उस पर आरोप लगाया गया था। जिस समय दंगे हुए थे, वह उस समय डेरा प्रमुख के साथ थी। डेरा प्रमुख के साथ वह पंचकूला से सीधे रोहतक की सुनारिया जेल चली गई थी। उसे इन दंगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस केस के 52 गवाह बनाए गए हैं। इस केस का ट्रायल काफी लंबा चल सकता है। ऐसे में उसे तब तक जेल में न रखा जाए और उसे जमानत दी जाए।

दैनिक जागरण

ध्यान की दौलत से कार्य करने की क्षमता अपने आप बढ़ती है

ट्रंप से खरी बात

फ्रांस के बायरिट्ज शहर में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष जिस तरह दो टूक ढंग से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सारे मसले द्विपक्षीय हैं और इसीलिए हम किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देना चाहते उससे ट्रंप प्रशासन को यह पता चल जाना चाहिए कि आज के भारत को कश्मीर या फिर किसी अन्य मसले पर झुकाया नहीं जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष खरी बात करने की जरूरत इसलिए थी, क्योंकि हाल में उनकी ओर से दो-तीन बार यह कहा जा चुका है कि वह कश्मीर पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। उनके ऐसे बयानों से ही पाकिस्तान अपनी पीठ ठोकने में लगा हुआ था। अब उसे भी यह अहसास हो जाए तो बेहतर कि अमेरिका या फिर चीन का सहारा लेकर वह भारत को आंखें नहीं दिखा सकता। यह उल्लेखनीय है कि इसके पहले भारत ने चीन के समक्ष भी यह साफ कर दिया था कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से न तो पाकिस्तान से लगती सीमा में कोई बदलाव हुआ है और न ही चीनी सीमा में। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री की खरी बात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भी यह कहने को बाध्य हुए कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन भारत सरकार को केवल इतने से ही संतोष नहीं करना चाहिए। चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी मसले पर कुछ भी कहने और यहां तक कि अपनी ही बातों से मुकर जाने में माहिर हैं इसलिए भारत को चाहिए कि वह अमेरिकी विदेश विभाग से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा वक्तव्य को आधिकारिक रूप देने की मांग करे।

यह आवश्यक है कि भारत सभी आवश्यक मंचों पर यह भी स्पष्ट करे कि वह कश्मीर पर मध्यस्थता का राग सुनने को इसलिए नहीं तैयार, क्योंकि यह उसका अपना आंतरिक मामला है और अगर पाकिस्तान से कोई बात होती है तो वह उसके कब्जे वाले भारतीय भूभाग को लेकर ही होगी। यह सही समय है कि भारत इस बात को भी पूरी दृढ़ता के साथ रेखांकित करे कि पाकिस्तान या फिर अन्य किसी देश को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि भारत जम्मू-कश्मीर या फिर लद्दाख को लेकर किसी से वार्ता करने को राजी हो सकता है। वास्तव में ऐसा करने पर ही दुनिया को यह संदेश जाएगा कि कश्मीर का असल विवाद तो पाकिस्तान के कब्जे वाले उस भारतीय भूभाग को लेकर है जिसे पाकिस्तान ने हथिया रखा है। देश के राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग को भी यह समझने की जरूरत है कि कश्मीर को लेकर रक्षात्मक रवैया अपनाने के कारण ही पाकिस्तान दुनिया में भ्रम फैलाने में कामयाब रहा।

सोनिया की हरी झंडी

बंगाल में कांग्रेस और माकपा समेत वाममोर्चा के अन्य घटक दलों की स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसे में कांग्रेस एवं वामदल एक दूसरे के सहारे भाजपा को रोकने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले ही वामदलों से साथ गठबंधन करने को बंगाल के पार्टी नेताओं को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी। यही नहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में भी वामदलों के साथ लड़ने की सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी है। सोनिया ने बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा के साथ बैठक की जिसमें गठबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद सोमेन मित्रा ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि अगर वाममोर्चा तैयार है तो दोनों पक्षों को राज्य में गठबंधन कर लेना चाहिए। भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा सभी विपक्षी दलों के एक हो जाने के आह्वान के मद्देनजर सोनिया गांधी का यह फैसला काफी अहम है। हालांकि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की मानें तो ममता के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने बंगाल में गठबंधन के लिए वामदलों का चुनाव किया है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि 2021 का विधानसभा चुनाव राज्य की तृणमूल सरकार के खिलाफ होगा। ऐसे में सिर्फ भाजपा विरोध के नाम पर हम तृणमूल के साथ नहीं जा सकते। कांग्रेस एवं माकपा नेतृत्व के बीच तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सहमति बन गई है। उत्तर दिनाजपुर की कालियागंज एवं पश्चिम मेदिनीपुर की खड़गपुर सीट पर कांग्रेस, जबकि माकपा नदिया जिले के करीमपुर सीट से लड़ेगी। कालियागंज सीट कांग्रेस विधायक प्रमथनाथ राय की मौत के बाद खाली हुई है। जबकि खड़गपुर सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष विधायक थे। उनके मेदिनीपुर से सांसद बनने के बाद वह सीट खाली हुई है। इसी तरह करीमपुर से तृणमूल की विधायक रही महुआ मोइत्रा अब कृष्णानगर से सांसद हैं। इसकी वजह से वह सीट खाली हुई है। इससे पहले कांग्रेस एवं वाममोर्चा ने 2016 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था। हालांकि उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उनके बीच सीट बंटवारे पर मामला फंस गया था। इसके बाद दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा। दोनों का ही प्रदर्शन प्रदेश में बदतर रहा। कांग्रेस जहां मात्र दो सीट जीत सकी, जबकि 38 सीटों पर उसके प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। वामो के हिस्से बंगाल से एक भी सीट नहीं आई।

ताशकंद और शिमला समझौते के सबक

सुरेंद्र किशोर

चूंकि शिमला में एक तरह से ताशकंद ही दोहराया गया इसलिए यह जरूरी है कि मौजूदा सरकार इन दोनों समझौतों से सबक सीखे

जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में मोदी सरकार की ओर से लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद से शिमला समझौता की व्यापक चर्चा हो रही है। 3 जुलाई, 1972 को हुए इस समझौते के बारे में यह बात कम लोग ही जानते हैं कि उसकी धज्जियां पाकिस्तान के तत्कालीन शासक जुल्फीकार अली भुट्टो ने उसी जुलाई महीने में ही उड़ानी शुरू कर दी थी। इसीलिए यह कहा जाता है कि भारतीय सेना ने तो युद्ध में फतह हासिल की, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने समझौते की मेज पर सेना द्वारा हासिल लाभ गंवा दिया। ताशकंद समझौते में भी ऐसा ही हुआ था। ताशकंद समझौते के खिलाफ केंद्रीय मंत्री महावीर त्यागी ने अपना इस्तीफा तक दे दिया था। वह ताशकंद समझौते की कुछ शर्तों से असहमत थे। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री मंत्रिमंडल के सारे सदस्य नंदा मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिए गए। जब ताशकंद समझौते पर मुहर लगाने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो बहुत देर तक ताशकंद समझौते पर विवाद होता रहा। महावीर त्यागी ने लिखा है, 'जब इस समझौते को स्वीकार करने का प्रस्ताव आया तो मैं कैबिनेट छोड़कर बाहर आ गया और अपना त्यागपत्र नंदा जी के पास भेज दिया।' अपने इस्तीफे के बाद त्यागी जी ने कहा कि उनकी समझ से पाकिस्तान और भारत तब तक अच्छी तरह उन्नत और संपन्न नहीं बनेंगे जब तक इन दोनों देशों में एकता स्थापित नहीं हो जाती। उन्होंने लिखा कि ताशकंद समझौते के मूल ध्येय से भी मैं सहमत हूं, लेकिन इस समझौते की कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी सरकार और हमारी पार्टी की ओर से की गई घोषणाओं के विपरीत हैं। इस समझौते के कई तत्व बहुत ही गंभीर हैं। केवल भारत के रक्षा मंत्री की हैसियत से ही नहीं, बल्कि विश्व युद्ध के सैनिक की हैसियत से मेरे कुछ निजी अनुभव हैं। उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जीती हुई हाजी पीर की चौकियों को छोड़ना भयंकर भूल होगी, विशेष कर तब जब पाकिस्तान अपने छापामारों, गुप्तचरों और बिना वर्दी के हथियारबंद सैनिकों को वापस बुलाने और भविष्य में ऐसे आक्रमण न करने को कटिबद्ध नहीं होता।

महावीर त्यागी ने यह भी लिखा है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद पाकिस्तानी नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि 'समझौते में हथियारबंद पाकिस्तानियों को वापस बुलाने का जो जिक्र है उसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने हथियारबंद छापमारों को भी कश्मीर से वापस बुलाएंगे। इसी तरह एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का अर्थ यह नहीं है कि हम जम्मू-कश्मीर में कोई दखल न दें, क्योंकि इस क्षेत्र को पाकिस्तान अपना निजी क्षेत्र मानता है।'

ताशकंद समझौते जैसा हश्र शिमला समझौते का भी हुआ। शिमला समझौते पर दस्तखत करके पाकिस्तान लौटने पर पाकिस्तानी संसद में अपने 165 मिनट के भाषण में भुट्टो ने कहा था, 'हम पाकिस्तान की जनता की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि ज्यों ही कश्मीर की जनता अपना मुक्ति आंदोलन शुरू करती है, पाकिस्तान के लोग उनकी हर प्रकार से सहायता करेंगे। वे इस सिलसिले में अपना खून बहाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे।' पाकिस्तान के युद्धबंदियों पर भुट्टो का कहना था कि 'भारत उन्हें अधिक देर तक नहीं रख सकता। हम इस सिलसिले में विश्व जनमत बनाने का प्रयास करेंगे।' भुट्टो ने यह भी कहा, 'इस समझौते से कश्मीर के बारे में हमारे किसी प्रकार के सिद्धांतों का हनन नहीं हुआ है। पाकिस्तान कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने को स्वतंत्र है।'

शिमला समझौते के समय अटल बिहारी वाजपेयी शिमला में ही थे। समझौते के बाद वाजपेयी ने जो कुछ कहा, इतिहास ने उसे सच साबित किया। वाजपेयी ने तभी कह दिया था, 'यह भारत का आत्मसमर्पण है, क्योंकि दोनों देशों के विवादों पर कोई समझौता न होने पर भी भारत पाकिस्तानी इलाकों से भारतीय सेनाओं को हटा लेने पर सहमत हो गया।' याद रहे कि समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 69 वर्ग मील भारतीय इलाका खाली करना था तो भारत को 5139 वर्ग मील पाकिस्तानी इलाका। शिमला समझौते पर तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह का कहना था कि दोनों देशों ने भारतीय उप महाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना के उद्देश्य से बातचीत में भाग लिया, लेकिन सब जानते हैं कि शांति स्थायी रूप नहीं ले सकी। यदि ताशकंद और शिमला में भारत ने पाकिस्तान से कड़ी सौदेबाजी की होती तो स्थायी शांति की जमीन तैयार हो सकती थी। ध्यान रहे ताशकंद समझौते के जरिये भी भारत ने जीती हुई महत्वपूर्ण भूमि पाकिस्तान को लौटा दी थी। उसी जमीन से घुसपैठिये लगातार कश्मीर में प्रवेश करके आतंक फैलाते रहे।

अवधेश राजपूत

पाकिस्तान हर बार गैर भरोसमंद पक्षकार ही साबित हुआ है। वह झूठ बोलने और अपने लोगों समेत दुनिया को भरमाने में माहिर है। यह किसी से छिपा नहीं कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर उसका यही कहना था कि भारत चंद पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ खास नहीं कर सका। अब यह कह रहा है कि भारत बालाकोट से भी बड़े हमले की तैयारी में है। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों ने संकल्प लिया था कि वे अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण उपायों से हल करेंगे और दोनों देशों की सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक-दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार नहीं करेंगी। इसमें यह भी कहा गया था कि आपसी संबंधों में सामान्य स्थिति लाने की दृष्टि से सुविधाओं का आदान-प्रदान होगा और दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमा में लौट जाएंगी। समझौते का एक बिंदु यह भी था कि जम्मू-कश्मीर में 17 दिसंबर, 1971 को हुए युद्ध विराम के तहत नियंत्रण रेखा को मान्य रखेंगे। इस समझौते को लागू करने के लिए किसने क्या प्रयास किए, इसे बयान करने के लिए 1972 के बाद की घटनाएं पर्याप्त हैं। कश्मीर में आतंक फैलाए रखने में पाकिस्तान की मुख्य भूमिका रही है। वह वहां खुले आम जिहाद छेड़ने की बात करता है।

कश्मीर में पाकिस्तान की बेजा हरकतें भारत की ओर से उसके प्रति दिखाई गई उदारता का नतीजा हैं। क्या शिमला समझौते में शामिल भारतीय पक्ष ताशकंद समझौते के बाद के अनुभव से परिचित नहीं था? जरूर परिचित रहा होगा। 90 हजार सैनिकों और करीब 5 हजार वर्ग मील पाकिस्तानी भूभाग पर भारतीय सेना के कब्जे के बावजूद भारत सरकार पाकिस्तान को कोई ठोस सबक नहीं सिखा सकी। शिमला में एक तरह से ताशकंद दोहराया गया। यदि अब ऐसा कोई अवसर आए तो यही उम्मीद की जाती है कि मौजूदा सरकार ताशकंद और शिमला वाली गलती नहीं करेगी। इसी के साथ यह भी उम्मीद की जाती है कि हमारी सरकार उस पुरानी धारणा से भी इस देश को मुक्त करेगी कि भारतीय अपने इतिहास से नहीं सीखते।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

सक्षम नौकरशाही को प्रोत्साहन जरूरी

प्रेमपाल शर्मा

जब कुछ अधिकारियों को उनकी प्रतिभा और मेहनत का फल मिलता है तो पूरी नौकरशाही में नई जान पड़ जाती है

पुरस्कार और दंड देने की प्रक्रिया नौकरशाही के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी जीवन के दूसरे पक्षों में। हाल में कर्मठ, ईमानदार और नवोन्मेषी 16 जिला अधिकारियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके बाद यह खबर आई कि कई टैक्स अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि वे कारोबारियों को अनावश्यक रूप से तंग कर रहे थे। यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। बीते दिनों जिन अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया वे देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर अयाज फकीर भाई ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन को सुलभ बना दिया तो संदीप नंदूरी ने पानी की कमी से जूझते तमिलनाडु के कई गांवों में बर्बाद पानी को इकट्ठा कर फिर उपयोग में लाने की विधि ईजाद कर दी। वहीं राकेश कंवर ने हिमाचल प्रदेश में कूड़े के ढेर को एक खूबसूरत पार्क में बदल दिया। इसी तरह राजकुमार यादव, माधवी खोडे, कार्तिकेय मिश्रा आदि को जब शिक्षा, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा और मेहनत का फल मिला। जब ऐसा होता है तो पूरी नौकरशाही में नई जान पड़ जाती है और अन्य अधिकारी भी कुछ बेहतर करने को प्रेरित होते हैं। पिछले कुछ दिनों में सरकार की कोशिश बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने की रही है। 2006 में शुरू किए गए सिविल सेवा अवार्ड ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिविल सेवा अवॉर्ड हर वर्ष सिविल सेवा दिवस यानी 21 अप्रैल को देश के अलग-अलग क्षेत्रों में शासन-प्रशासन से जुड़े हर स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कामों के लिए दिए जाते हैं। राजस्थान के जिलाधिकारी द्वारा जेनरिक दवाओं की शुरुआत हो या फिर बदायूं के जिलाधिकारी द्वारा मल मुक्ति अभियान, कर्नाटक में भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण करना हो अथवा रेलवे में ई टिकटिंग की व्यवस्था, इसी के चंद उदाहरण हैं।

निःसंदेह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजर कर देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं प्रशासनिक सेवाओं में आती हैं। यदि उन्हें लगातार इसी तरह प्रोत्साहन मिलता रहे तो नौकरशाही का चेहरा बदल सकता है। अभी तक के ज्यादातर अनुभव यही बताते हैं कि आजादी के बाद नौकरशाही की कार्यक्षमता में लगातार गिरावट आती गई है और भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, फिजूलखर्ची में बढ़ावा देखने को मिला है। हम सब के निजी अनुभव भी यही बताते हैं और एनएन वोहरा से लेकर प्रशासनिक सुधार आयोग की तमाम रपटें और दूसरे तमाम सर्वे भी इसी ओर इंगित करते हैं, लेकिन कर्मठ अफसरों को प्रोत्साहन के प्रचार-प्रसार से हालात बदले जा सकते हैं। भारतीय नौकरशाही की बहुत बड़ी कमी यह महसूस की जाती रही है कि आप एक बार उसके हिस्से हो जाएं तो आप कुछ करें या न करें या कितना भी अच्छा करें आपको कोई फल नहीं मिलने वाला और न करने पर भी आपके करियर पर कोई असर नहीं होने वाला। इस धारणा को मूल रूप से समाप्त किए जाने की जरूरत है। इन पुरस्कारों की यही भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल पुरस्कार ही नहीं, सरकार को निकम्मे लोगों से मुक्ति भी पानी होगी।

हाल में जिन अधिकारियों की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है या जो 25 वर्ष की सेवा कर चुके हैं उनके कार्य निष्पादन का आकलन किया जा रहा है। सरकार के ऐसे कदमों और खासकर नाकारा या भ्रष्ट अधिकारियों की छुट्टी करने पर किसी को हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। विशेषकर तब जब एक तरफ तो आप सरकार की, उसकी नौकरशाही की आलोचना करते हैं और उसकी कार्यक्षमता में गिरावट का रोना रोते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधा के अभाव की बात करते हैं और फिर जैसे ही सरकारी दफ्तरों में बैठे निकम्मे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत होती है तो कुछ लोग उनके बचाव में लग जाते हैं। इस क्रम में लोग कई बार सरकार पर निजीकरण करने का आरोप भी लगाते हैं। शासन या सत्ता समाज के कल्याण के लिए होती है। उसे नौकरशाही करे या निजी क्षेत्र करे, अंतिम आदमी को नागरिक हक, न्याय और सुविधाएं चाहिए, ईमानदारी चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। जो भी सरकार इसे निष्पक्षता से करे उसका साथ देने की जरूरत है। यह उल्लेखनीय है कि 16 आइएस अफसरों को पुरस्कृत करने की चयन प्रक्रिया में देश के नामी-गिरामी लोग जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरएम लोढ़ा उस चयन समिति के अध्यक्ष थे और पूर्व नौकरशाह हबीबुल्ला, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, पूर्व कैबिनेट सचिव चंद्रशेखर सदस्य थे। उन्होंने पांच मानदंडों पर देशभर से आई संस्तुतियों पर विचार किया और फिर एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड के लिए उन्हें चुना है। हाल में उठाए गए कई कदम नौकरशाही में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। जैसे इन्हें पुरस्कृत किया गया है वैसे ही कुछ दिनों पहले कस्टम, इनकम टैक्स, पुलिस आदि विभाग के दर्जनों अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। काफी अरसे के बाद उन अधिकारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है जिन्हें सरकार ने विदेश भेजा तो था प्रशिक्षण के लिए, लेकिन वे वर्षों से बिना बताए गायब थे। ऐसे अधिकारियों को राष्ट्रीय हित में बिना किसी रियायत के तुरंत सबक सिखाने और दूसरों को भी संदेश देने की जरूरत है।

ठीक जिस वक्त कुछ कर्मठ अफसरों को पुरस्कृत किया जा रहा था उसी समय नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में क्या-क्या सुधार अपेक्षित हैं, उस पर दिल्ली में विचार मंथन चल रहा था। मेरा मानना है कि न केवल भर्ती प्रक्रिया, बल्कि सेवाकालीन प्रशिक्षण आदि को भी फिर से परिभाषित करने की जरूरत है जिससे नौकरशाह, मालिक के बजाय जनता के सेवक के रूप में प्रतिष्ठित हो सकें। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने भी इसी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि हमारे नौकरशाह अंग्रेजी के दंभ में भारतीय जनता से लगातार दूर रहने की कोशिश करते हैं और गुमान रखते हैं। अब समय आ गया है कि नौकरशाही को जनमुखी बनाया जाए।

(लेखक रेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

सोच

जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़ी सोच जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जो लोग बड़ा नहीं सोचते, वे सोचते ही नहीं। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोचता न हो। मेरा मानना है कि अगर आप सोच ही रहे हैं तो क्यों न बड़ा सोचें। नेपोलियन हिल के अनुसार, 'दुख और गरीबी स्वीकार करने के लिए जितना प्रयास अपेक्षित है, जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए उससे अधिक प्रयास की जरूरत नहीं है।' आपको बस एक संकल्प लेना है कि भव्य विचार रखने हैं। यह एक बर्गर और एक फल के बीच चयन करने जितना आसान है। आप दोनों ही चीजों को खा सकते हैं। आपको बस यह फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए।

जहां जीवन है, वहां भली-बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं का आना-जाना लगा ही रहता है। रात और दिन की भांति सुख-दुख के क्रम को रोका नहीं जा सकता। यदि व्यक्ति प्राप्त अनुकूलताओं की ओर ध्यान दे तो उसे अनुभव होगा कि कुछेक वस्तुओं का अभाव होने पर भी जितना कुछ उपलब्ध है वह कम नहीं है। विश्व में ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं, जिन्हें संभवतः इतना ही प्राप्त नहीं है, जितना अभी मेरे पास है, फिर क्यों मुंह लटकाए फिर रहा हूं। व्यक्ति का ध्यान जब अपनी प्रतिकूलताओं पर ही टिका रहता है तब वह जिधर देखेगा, उधर अभाव ही दिखाई देगा। इससे कुछ लाभ वाली स्थिति का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे में चित खिन्नता का अनुभव करेगा और निराशा ही हस्तगत होगी। अपनी आदतों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जीवन के उजले पक्ष को देखें और उससे कुछ प्रेरणा लें तो जीवन में बहुत कुछ पाया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा सकता है।

'योर बेस्ट लाइफ नाउ' में जोएल ओस्टीन कहते हैं-'आपको अपने दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि आप परम परमात्मा की संतान हैं और महान चीजों के लिए बनाए गए हैं। ऐसा करने के लिए उसने आपको काबिलियत, अंतर्दृष्टि, प्रतिभा, बुद्धि और अलौकिक शक्तियां दी हैं।'

ललित गर्ग

भारतीय भाषाओं की अनदेखी

अनीश कुमार

दुख की बात है कि आज देश का एक वर्ग रोजमर्रा के प्रयोग से अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बनाने पर तुला है

भारत को समझने और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय भाषाएं सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। दरअसल भाषाएं भावी पीढ़ी के लिए केवल साक्षरता के लिए ही जरूरी नहीं हैं, बल्कि भाषाओं में निहित ज्ञानराशि को समझने का सशक्त जरिया भी हैं। यह ज्ञानराशि ही असली भारत है। इसमें आम कामगारों के, किसानों के और आधुनिक पेशवरों के अभ्यासजन्य और अनुभवजन्य ज्ञान संचित हैं। विडंबना है कि यह ज्ञानराशि राशि धीरे-धीरे हमारी शिक्षा की मुख्यधारा में संकुचित हो चुकी है। इसका ही दुष्परिणाम है कि भावी पीढ़ी अपने आनंद और पीड़ा के रंगों का चुनाव गंगा-जमुना के मैदानों, अरावली या दंडाकारण्य आदि की लोकसंस्कृति से, केरल और तमिलनाडु के मृदु-कठोर भावों से कर पाने में सक्षम नहीं है।

दुर्भाग्य यह है कि अपनी इस अक्षमता का उसे भान तक नहीं है, क्योंकि वह अपनी जरूरतों को दूसरों की भाषा से पूरा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इस तरह की एक पूरी पीढ़ी ने देखा है कि अंग्रेजी न आने के कारण उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह पूरी पीढ़ी मां-बाप की भूमिका में अपने बच्चों को उसी अंग्रेजी का संस्कार देना चाह रही है जिसकी कमी से वे जूझते रहे। दुकान से लेकर डाइनिंग टेबल तक बच्चों को अंग्रेजी के शब्दों और 'आदतों' का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस अभ्यास से लगभग हर अभिभावक खुद को आश्वस्त कर रहा है कि उसके बच्चे को आने वाले जीवन में किसी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी दशा में बार-बार यही सवाल उपजता है कि क्या अभिभावक अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी भाषा और माध्यम की शिक्षा के बरक्स मातृभाषा में शिक्षा को स्वीकार करेंगे? यह सवाल केवल अभिभावकों के स्तर तक ही सीमित नहीं है।

इसके समांतर अगला प्रश्न है कि क्या स्कूल नामक संस्था भारतीय भाषाओं में ज्ञान रचना के लिए तैयार है? इन दोनों ही सवालों के लिए अक्सर 'औपनिवेशिक' प्रभाव की दुहाई देते हुए हम पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन हमें अपनी असफलता को भी स्वीकारना होगा कि आजाद भारत में मजबूत भाषा नीतियों के बावजूद पाठ्यचर्या के माध्यम और भाषा के रूप में भारतीय भाषाएं उपेक्षित हैं।

इसका सरलीकृत कारण नीति का कमजोर क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि आर्थिक अवसरों, सामाजिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक बड़प्पन के नाम पर लोक जीवन का अंग्रेजीकरण है। इसके प्रभाव में भारतीय भाषाएं धीरे-धीरे अनौपचारिक कार्य-व्यापार तक सीमित होती जा रही हैं। वर्तमान में भाषा की एक नई समस्या है कि एक वर्ग बोलचाल, रोजमर्रा के व्यवहार और औपचारिक प्रयोग से अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बनाने पर तुला है। इसी वर्ग के जैसा बनने के लिए शेष समाज अपने 'संस्कृतिकरण' के लिए उनकी भाषा को अपना रहा है। उक्त के आलोक में आज इस सवाल का उत्तर खोजा जाना चाहिए कि अंग्रेजी के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय भाषाओं को कैसे समर्थ बनाया जाए?

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

निष्पक्ष होकर कार्य करें जांच एजेंसियां

जांच एजेंसियों की जवाबदेही भी जरूरी शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने सीबीआइ तथा ईडी जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों को निष्पक्ष एवं राजनीतिक दबाव से परे रहकर कार्य करने पर बल दिया है, जो कि वर्तमान परिदृश्य में बेहद जरूरी एवं प्रासंगिक भी है। सरकार बदलने पर पूर्व की सरकारों में रहे मंत्रियों पर स्वतंत्र जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करना शक पैदा करता है, सत्ता में रहते हुए किसी मंत्री पर प्रभावी कार्रवाई ना होना ही शक का कारण भी है। इन्हें सत्तासीन दल के मंत्रियों का भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई देता? जिस दिन सत्ता में रहते हुए भ्रष्ट मंत्रियों तथा भ्रष्ट नेताओं पर उक्त जांच एजेंसियां प्रभावी कार्रवाई करना शुरू कर देंगी, जनता का विश्वास इन जांच एजेंसियों पर बढ़ जाएगा। यह कटु सच्चाई है कि आजकल जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पा रही हैं, बल्कि सत्तासीन दल की कठपुतली की तरह कार्य करती हैं, जो कि जनता के अविश्वास का मुख्य कारण है। सरकारों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे जांच एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने दें, उनका दुरुपयोग ना करें और न होने दें ताकि सरकार और जांच एजेंसियों पर आम जनमानस का विश्वास कायम हो सके।

सर्वजीत आर्या, कन्नौज

भारत और यूएई संबंध

भारतीय प्रधानमंत्री इन दिनों दो खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के दौरे पर थे। यूएई भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। यह उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनसे भारत का व्यापार संतुलन की स्थिति में है। यदि यूएई की तुलना में हम चीन के साथ अपने व्यापारिक

मेलबाक्स

आंकड़ों को देखें तो जितना कुल व्यापार हम यूएई के साथ करते हैं उतना हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा है। भारत-यूएई के द्विपक्षीय संबंध आज के समय में सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, पिछले चार वर्षों में यूएई भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, सामरिक साझेदार बन चुका है। आने वाले समय में भारत और यूएई के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। भारत-यूएई के संबंधों का अंदाजा जम्मू कश्मीर के मामले पर यूएई के वक्तव्य से लगाया जा सकता है, जिसमें यूएई उन चुनिंदा देशों में शामिल पहला देश था जिसने भारत की कश्मीर नीति का समर्थन किया। यूएई कई महत्वपूर्ण इस्लामिक संगठनों का महत्वपूर्ण सदस्य है, जिनमें ओआइसी शामिल है जहां पर पाकिस्तान भारत को संयुक्त राष्ट्र में घेरने के लिए असफल कूटनीतिक चाल चलता रहा है। यूएई का इस तरह जम्मू कश्मीर मुद्दे पर खुलकर सामने आना और भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना उद्दंड पाकिस्तान को करारा तमाचा है। मोदी की यह तीसरी यूएई यात्रा है। बहरीन और यूएई ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित कर इस यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया है।

kulindaryadav5412@gmail.com

कांग्रेस को ऊर्जा चाहिए

लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस आज दोयम दर्जे की पार्टी बन गई है। चुनाव में बार-बार पराजय के बाद आत्मविश्वास खो चुकी इस पार्टी के एक के बाद एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। इससे इसकी साख और खराब हो रही है। हालात यह हैं कि इस समय विपक्ष के नाम पर कोई प्रभावशाली नेता नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। कांग्रेस से लोगों को बड़ी उम्मीद हैं, लेकिन पार्टी इस दिशा में कुछ करती नजर नहीं आ रही है। पार्टी को कम से कम अपना एक स्थायी अध्यक्ष तो चुन ही लेना चाहिए, जो पार्टी में नई ऊर्जा भर सके।

दीपांशु अरोड़ा, दिल्ली

पीवी सिंधू की शानदार जीत

भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधू ने एक बार फिर से देश के सामने चुनौती रख दी है कि किसी भी खेल में हुनर की कमी नहीं। बस जरूरत है उनको पहचानने और निखारने की। बैडमिंटन के ऊंचे आकाश पर चमकते सितारे पर देश को गर्व क्यों न हो। कड़ी मेहनत और लगन से ही सिंधू ने ये ऊंचाई पाई है। अपनी जीत को अपनी मां को समर्पित कर सिंधू ने नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम की है। देश को अपने इस होनहार खिलाड़ी से बार-बार ऐसी जीत की उम्मीद रहेगी।

mkmishra75@yahoo.in

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

60 अरब डॉलर तक पहुंच गया है आपसी कारोबार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। भारत, यूएई से पेट्रोलियम, सोना-चांदी, धातु अयस्क आदि आयात करता है, और उसे कॉटन, रत्न-आभूषण, धागे आदि का निर्यात करता है।

आजकल

भारत-यूएई के बीच प्रगाढ़ होते रिश्ते

अरविंद जयतिलक
स्वतंत्र टिप्पणीकार

यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' से नवाजा जाना भारत के लिए गर्व का क्षण है। क्राउन प्रिंस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को भाई बताया जाना और 'अपने दूसरे घर' आने के लिए आभार जताना दोनों देशों के परवान चढ़ते रिश्ते को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है। साथ ही यूएई ने भारत को अनेक विषयों पर मदद का आश्वासन भी दिया है

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती प्रगाढ़ता कई मायने में महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारणों से अरब देश भारत की विदेश नीति में विशिष्ट महत्व का विषय रहे हैं। यह क्षेत्र भारत के विदेश नीति के रक्षा संबंधी पहलुओं को प्रभावित करता है और इसी को ध्यान में रख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात से निर्णायक संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यूएई के दिल में कितना सम्मान है, वह 2018 में मोदी की यूएई की यात्रा के दौरान देखने को मिला जब यूएई ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा समेत अनेक भवनों को तिरंगे के रंग से रंग दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में भारतीय रुपे कार्ड जारी किया। इस तरह पश्चिम एशिया में यूएई पहला देश बन गया है जहां रुपे कार्ड चलेगा।

गत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान यूएई ने आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भारत में 75 अरब डॉलर के निवेश का फैसला लिया। अगर दोनों देश समझौते के मुताबिक अगले पांच वर्षों में आपसी कारोबार बढ़ाने और ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो निःसंदेह दोनों देशों के सामरिक- आर्थिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। यूएई की पूंजी से रेलवे, बंदरगाहों, सड़कों, हवाई अड्डों आदि के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। महत्वपूर्ण यह भी कि यूएई ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को भी अपना समर्थन दिया है। भारत और यूएई के बीच महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा सहयोग बना हुआ है। अरसे से भारत अपनी संस्थाओं में संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा कार्मिकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित रक्षा कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेता है। याद होगा गत वर्ष पहले संयुक्त अरब अमीरात के प्रदर्शनी निगम द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रदर्शनी में भारत ने शिरकत की थी। इसी तरह फरवरी 2007 में बंगलुरु में आयोजित 'एयरो इंडिया शो' में भाग लेने के लिए यूएई ने भी अपने अधिकारियों को भेजा था। जून 2003 में द्विपक्षीय प्रतिरक्षा आदान-प्रदान के लिए संयुक्त प्रतिरक्षा सहयोग समिति यानी ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी के गठन के लिए एक मसौदे पर हस्ताक्षर भी किए गए। भारतीय नौसेना के पोतों ने संयुक्त अरब अमीरात की अनके सदभावना यात्राएं की।

वर्ष 2008 में बतौर विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की और उसी वर्ष यूएई के विदेशी व्यापार मंत्री शेख लुबना अल कासिमी ने भी भारत की यात्रा की। फिक्की ने उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सफल महिला के खिताब से नवाजकर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक पहलुओं को मजबूती दी। दोनों देशों ने एकदूसरे के हितों को ध्यान में रख ढेरों समझौते किए जो अब फलदायी साबित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए दोनों देशों ने प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक एवं सिविल मामलों में आपसी विधिक सहायता संधि, सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में सहयोग के लिए विधिक एवं न्यायिक समझौता किया जो वर्ष 2000 से ही लागू है। इस संधि के तहत दोनों देश अपराधियों के हस्तांतरण के अलावा आपसी विधिक सहायता को मूर्त रूप दे सकते हैं। चूंकि यह क्षेत्र नशीली दवाओं का अड्डा बनता जा रहा है इसलिए दोनों देशों ने नशीली दवाओं और मस्तिष्क पर खतरनाक असर डालने वाले तत्वों की तस्करी रोकने के लिए 1994 में समझौता किया। इसी तरह 1975 में सांस्कृतिक समझौता और 1989 में नागरिक उड्डयन समझौता हुआ। सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वर्ष 2000 में अमीरात न्यूज एजेंसी तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ। सेबी और अमीरात प्रतिभूति एवं पण्य प्राधिकरण के बीच भी समझौता हुआ। दूरदर्शन के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन महानिदेशालय यानी प्रसार भारती तथा अमीरात केबल टीवी मल्टीमीडिया एलएलसी के बीच चैनल प्रबंधन समझौते को वर्ष 2000 में आकार दिया गया। दोनों देशों के बीच दिसंबर 2006 में मैन पावर सोर्सिंग इनकॉरपोरेशन के एक मसौदे पर भी समझौता हुआ।

इतिहास पर दृष्टि डालें तो इस क्षेत्र से भारत का सामाजिक व व्यापारिक संबंध शताब्दियों का रहा है। इतिहास से जानकारी मिलती है कि भारत से मसाले व कपड़े अमीरात क्षेत्र को और अमीरात क्षेत्र से मोती व खजूर भारत को भेजे जाते रहे हैं। आज संयुक्त अरब अमीरात में तकरीबन 25 लाख से अधिक भारतीय कामगार हैं जो न सिर्फ रोजी-रोटी कमा रहे हैं, बल्कि अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत भेजकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत और सउदी अरब में करीब तीन करोड़ भारतीय विभिन्न तरह के काम कर रहे हैं जो दुनिया भर में पसरे लगभग सवा सात करोड़ भारतीयों का चौथाई हिस्सा है। अकेले यूएई से ही 12 अरब डॉलर भारत आता है।

गौर करें तो अरब देशों में यूएई एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक हब है तथा साथ ही सिंगापुर एवं हांगकांग के बाद विश्व में तीसरा प्रमुख पुनर्निर्यातक केंद्र भी। यही वजह है कि यह इराक, ईरान, सीआइएस देशों तथा अफ्रीका आदि बाजारों के लिए स्रोत केंद्र बना हुआ है। दूसरी ओर लगभग सात प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि दर से भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, इसलिए भी दोनों देशों के बीच बेहतर व्यापारिक संबंध होना आवश्यक है। संयुक्त अरब अमीरात भारतीय उत्पादों के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात को करता है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में निर्मित सामानों के लिए भारत भी एक महत्वपूर्ण निर्यात स्थल बन चुका है। भारत द्वारा यूएई से आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद, सोना, चांदी, धातु अयस्क एवं धातु अपशिष्ट, सल्फर एवं लौह पायराइट्स, मोती तथा बेशकीमती पत्थर इत्यादि शामिल हैं। इसी तरह भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में आरएमजी कॉटन, रत्न, आभूषण, मानव निर्मित धागे, समुद्री उत्पाद तथा प्लास्टिक इत्यादि हैं। वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के आर्थिक व कूटनीतिक संबंधों में और भी मजबूती आएगी और व्यापारिक साझेदारी को एक नया आयाम मिल सकता है।

फ्रांस से भी संबंधों में आ रही मजबूती

फ्रांस के बायरिट्ज में 45वें जी-7 सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा ने भारत और फ्रांस के रिश्तों को मिठास से भर दिया है। दोनों देश नई ऊर्जा के साथ घरेलू और वैश्विक मसलों पर हर चुनौती से मिलकर निपटने के लिए तैयार हैं। उसकी बानगी तब देखने को मिली जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुलवामा हमले की नींदा की, कश्मीर मसले पर भारत का खुलकर समर्थन किया और किसी तीसरे पक्ष की मठाधीशी की चेष्टा को नकारते हुए दो टूक कहा कि कश्मीर मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मसला है और इसे दोनों देशों को मिलकर सुलझाना चाहिए।

नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद के खिलाफ जंग में फ्रांस के सहयोग की प्रशंसा करते हुए दोनों देशों के सभ्यतागत रिश्ते को स्वार्थ से परे बताया। साझा प्रेस कांफ्रेंस के जरिये उन्होंने फ्रांस के उद्यमियों को कहा कि वे भारत में निवेश के सुनहरे मौके का लाभ उठाएं। दोनों देशों ने तकनीकी और सह उत्पादन के क्षेत्र में आपसी सहयोग के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है।

याद होगा कि जब परमाणु परीक्षण (1998) से नाराज दुनिया के ताकतवर देश भारत पर प्रतिबंध थोप रहे थे, तब फ्रांस ने भारत के साथ रणनीतिक समझौते को आयाम दिया। इतिहास में भी जाएं तो दोनों देशों के संबंध लगातार परिवर्तित और मजबूत होते रहे हैं। इंग्लैंड की ही भांति फ्रांस भी भारत में एक औपनिवेशिक ताकत रहा है। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच कभी भी रिश्तों में खटास नहीं देखा गया। फ्रांस द्वारा भारत के साथ आधुनिकीकरण के दौर में व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीकी सहायता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु एवं रक्षा क्षेत्रों में नवीन सहयोग विकसित किया गया। दोनों देशों के बीच आर्थिक व सामरिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का मूल आधार विकसित रणनीतिक-राजनीतिक समझदारी है। विगत दो दशकों में भारत-फ्रांस संबंध को एक नया आयाम मिला है। दोनों देशों ने राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक संबंधों में बेहतरी के लिए गंभीर प्रयास किया है। फ्रांस के नेतृत्व के दृष्टिकोण में बदलाव के साथ कुछ द्विपक्षीय बाध्यताओं ने भी दोनों को एकदूसरे के निकट लाया है। हालांकि दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर कई बार विरोधी रुख भी अपनाए हैं। हिंद-चीन क्षेत्र की स्वतंत्रता मुद्दे पर जहां भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र की आजादी की बात पर बल दिया, वहीं फ्रांस औपनिवेशिक स्थिति बनाए रखने का पक्षधर था।

गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच 10.4 लाख करोड़ रुपये के 14 समझौते हुए जिसके तहत दोनों देशों द्वारा एकदूसरे के सैनिक अड्डे का इस्तेमाल और वहां अपने युद्धपोत रखने पर सहमति जताई गई। इस सामरिक समझौते से दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा मजबूत हुई है और जलपोतों की निगरानी के साथ दोनों देश जल सर्वेक्षण के संबंध में आपसी तालमेल बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, तस्करी, आव्रजन, शिक्षा, रेलवे, पर्यावरण, परमाणु, आतंकवाद और अंतरिक्ष मामलों में भी दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो चुके हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा 20 करोड़ यूरो यानी 1,600 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया जा चुका है जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। आपसी आर्थिक साझेदारी का परिणाम है कि आज भारत में विदेशी निवेश के लिहाज से फ्रांस तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन चुका है। भारत में 400 से अधिक फ्रांस की कंपनियां काम कर रही हैं और सभी कंपनियों का संयुक्त टर्नओवर 30 अरब डॉलर से अधिक है। दोनों देशों के व्यापार में अहम बात यह भी है कि 1994 के बाद व्यापार संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में बना हुआ है।

सामरिक लिहाज से भी दोनों देशों के बीच परंपरागत जुड़ाव रहा है। 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। दशकों तक वह अपने रक्षा उत्पादन में पूर्व सोवियत संघ पर निर्भर रहा। लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में सामरिक सहयोग के क्षेत्र में भारत व फ्रांस की निकटता बढ़ी है। दोनों देशों ने 'भारत महोत्सव' (1985) व 'फ्रांस महोत्सव' (1989) का आयोजन किया। दोनों देशों ने वर्ष 2007-2010 के लिए 'सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम' पर हस्ताक्षर किया और 2016 से 2018 के लिए 'सांस्कृतिक आदान-प्रदान' समझौते को मूर्त रूप देने का संकल्प जाहिर कर चुके हैं। दोनों देशों के नेतृत्व के बीच बढ़ती निकटता साझा हित में है और वैश्विक संतुलन साधने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल भी है।

खरी-खरी

भारतीय रेल में यात्रा का रोमांच!

मनोज लिमये

भारतीय रेल में यात्रा करना अपने आप में एक अभूतपूर्व रोमांच है। अनेकता में एकता का संदेश देने वाली भारतीय रेलें संस्कृति का आईना हैं। इस रोमांच का शुभारंभ प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। डिस्कवरी चैनल में जंगल-जंगल भटकने वाले बेयर ग्रिल को सही एडवेंचर चाहिए तो उसे जनरल डब्बे में जरूर यात्रा करनी चाहिए।

जिस प्रकार हमारा समाज उच्च, मध्यम एवं निम्न वर्ग में असमान रूप से बाकायदा समानता के साथ वितरित है, उसी का प्रतिनिधित्व करती भारतीय रेलें भी विभिन्न श्रेणियों में विभक्त होती हैं। वातानुकूलित, शयनयान और द्वितीय श्रेणी यानी साधारण। यदि आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप टाइप की परेशानियां न हों, तभी द्वितीय श्रेणी सुरक्षित है।

आप यदि अधिकतम रोमांच चाहते हैं तो साधारण श्रेणी (जनरल) में ही यात्रा करें। रेलवे विभाग जनरल डब्बा सबसे आगे या सबसे पीछे लगाता है। जनरल डब्बे का एक अनूठा विज्ञान यह भी है कि इससे उतरने वाले यात्रियों की संख्या चढ़ने वालों के अनुपात में कम ही होती है। विषम परिस्थितियों में इसमें शौचालय तक भी पहुंच पाना सफलता की श्रेणी में गिना जाता है। यदि आप जुगाड़ शब्द की शाब्दिक व्याख्या जानते हैं, तो उचित कुली से अनुचित राशि का लेन-देन कर जगह प्राप्त कर सकते हैं।

भीड़ से ठसाठस ट्रेनें जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचती हैं, तो वहां सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है टीसी। जब आपको टीसी की सर्वाधिक आवश्यकता हो और वो प्लेटफॉर्म पर दिख भी जाए, तो समझिये कि आपकी किस्मत बुलंदी पर है। रानी मधुमक्खी के इर्द-गिर्द जैसे अन्य मधुमक्खियां होती हैं, वैसे ही यात्रियों का गोल घेरा प्लेटफॉर्म पर दिखे, तो समझ जाइए कि टीसी मधुमक्खी इसी घेरे में है।

रेल में लगे पंखे जिद्दी होते हैं। जैसे घोड़ा चाबुक की भाषा जानता है, ये पंखें कंघे की भाषा जानते हैं। कंघे में जाने क्या चुंबकीय तत्व है कि उसके जरिये पंखे को एक गोल चक्कर घुमाते ही ये चल पड़ते हैं। इसमें दो राय, बल्कि तीन राय भी नहीं कि भारतीय रेलवे प्रगतिशील है, परंतु यात्री की प्रगति अब भी विचाराधीन है। प्लेटफॉर्म के सार्वजनिक नल में पानी नहीं आने के कारण वहीं बिक रहे 20 रुपये की बोतल खरीदना क्या दर्शाता है? यह कि पानी अमूल्य पदार्थ है या फिर यह कि रेल का अवमूल्यन जारी है।

ट्वीट-ट्वीट

बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या करने वाली भीड़ का 'हीरो' जेल से जमानत पर बाहर आया तो उसका स्वागत भारत माता की जय व जय श्री राम के नारों से हुआ। राम का नाम बदनाम करना और किसे कहते हैं?
अजित अंजुम@ajitanjum

जिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा व अन्य सुविधाएं वापस लेने के आदेश दिए उन्हें याद रखना चाहिए कि वे भी भूतपूर्व होंगे।
अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

ट्रंप क्या बोलते हैं क्या नहीं, उसे बहुत गंभीरता से लेने में संकोच करता हूं, पर मेरे लिए सबसे अहम प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप के मुंह पर दिया गया यह बयान है कि भारत-पाक के मसले द्विपक्षीय हैं और इसमें हम किसी दूसरे देश को तकलीफ नहीं देते।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

मायावती के पैर छूने वाले तेजस्वी को बताना चाहिए कि वे जम्मू-कश्मीर के गरीबों, दलितों-पिछड़ों को आरक्षण से वंचित रखने वाले अनुच्छेद 370 का समर्थन क्यों कर रहे हैं?
सुशील कुमार मोदी@SushilModi

पंजाब डायरी

धुस्सी बांधों संग डूबती सरकारी कवायद

अमित शर्मा
स्थानीय संपादक, पंजाब

न भाखड़ा बांध की तरह विश्व प्रसिद्ध, न पौंग डैम की तरह विस्थापन की कहानियों को लेकर बदनाम, फिर भी पंजाब में बाढ़ नियंत्रण या आपदा प्रबंधन की कोई भी परियोजना राज्य की तीनों नदियों पर बनाए असंख्य 'धुस्सी बांधों' के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। हो भी कैसे, दशकों से ही आखिर इसी 'धुस्सी बांध' के इर्द-गिर्द घूमता रहा है 'डूबने और डुबोने' का खेल। बाढ़ नियंत्रण के नाम पर हर वर्ष लाखों, करोड़ों डुबोने का घोटाला हो या फिर पानी के कहर को आधार बनाकर सत्ताधारी और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर छींटाकशी कर राजनीतिक लुटिया डुबोने की कोशिशें, इन सबकी एकमात्र धुरी बन कर उभरा है धुस्सी बांध।

1980 के दशक से शुरू हुआ यह खेल आज भी जारी है। हमेशा की तरह इस बार भी बाढ़ग्रस्त जिलों में दरिया के किनारे कमजोर निकले और पानी में बह गए जिन्हें सरकार हर साल भारी भरकम बजट के साथ मजबूत करने का दावा सरकार करती रही है। ऐसे में रूपनगर और जालंधर के कुछ गांवों में बाढ़ से त्रस्त जागरूक लोगों द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया पर उठाए सवाल वाजिब हैं। इन गांवों के बाशिंदे जानना चाहते हैं कि धुस्सी बांध जिन उद्देश्यों के साथ बनाए गए थे, क्या वे कभी पूरे हुए भी या होंगे? शायद नहीं!

दरअसल पंजाब में बाढ़ आने के केवल दो कारण माने जाते हैं। एक तो प्रदेश में अधिक बारिश का होना और दूसरा हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश से भाखड़ा बांध में जल स्तर बढ़ने पर पानी छोड़ा जाना। भाखड़ा बांध से पानी छोड़ते ही यहां नदियों का जलस्तर इस कदर बढ़ जाता है कि दरिया से जुड़े तमाम जिले पानी की चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद हर साल यहां बांधों की मरम्मत और कुछ नए चिन्हित स्थानों पर नवनिर्माण के नाम पर जम कर पैसे की बंदरबांट होती है। मानसून दस्तक दे रही होती है और उधर विभाग फंड्स के एस्टिमेट बना रहा होता है। अबकी बार भी यही हुआ। मानसून ने दस्तक दी और उधर शायद ही कोई जिला प्रशासन था जिसने ऐसा प्रेस नोट जारी नहीं किया कि 'प्रशासन ने संभावित बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। तटबंध क्षेत्रों के तमाम गांवों को खाली करवाने के आदेश दिए जा चुके हैं। सिंचाई और नहर विभाग के अधिकारियों को रेत से भरी बोरियों की ट्रालियां तैयार रखने को कह दिया गया है।'

कहने का भाव है कि पंजाब जैसे विकसित राज्य में भी सालों से आपदा नियंत्रण के नाम पर बस ऐसी ही तैयारी होती आई है और नतीजा फिर वही। इस मानसून भी पानी के कहर में लाखों करोड़ों की राशि (या यूं कहें रेत की बोरियां) पानी में बह गई। सितंबर 1988 में भी जब पानी ने कहर बरपाया तब भी कुछ ऐसा ही कहा गया। यही कहानी अगस्त 1993 और फिर सितंबर 2010 में जब भाखड़ा से पानी छोड़ा गया, दोहराई गई। सौ बोरी रेत डालकर हजार बोरी के एस्टिमेट बनाए गए। अखबारों की सुर्खियां भी बनी, जांच भी बैठी, लेकिन अंततः गलत न कभी साबित हो सका और न ही इस बार भी होगा, क्योंकि विभागीय तर्क है कि जितना पत्थर और रेत डाला उसे बाढ़ के पानी की तेज धार बहा ले गई। हमेशा की तरह मुख्यमंत्री ने इस बार भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत कार्यों के लिए कुछ करोड़ रुपये देने का ऐलान किया और फिर केंद्र सरकार पर बाढ़ को लेकर जारी राहत राशि में राजनीतिक भेदवाव के आरोप जड़े। उधर अकाली-भाजपा नेताओं समेत केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दस ट्रकों में भरी राहत सामग्री बाढ़ग्रस्त जिलों में अपनी मौजूदगी में बंटवाकर भेदभाव के आरोप झुठलाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर यही राजनीतिक खेल पिछले तीन-चार दशकों से तमाम मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री (कांग्रेस से हों या अकाली-भाजपा गठबंधन से) करते रहे हैं।

वहीं अब जिला मुख्यालयों में आपदा प्रबंधन का स्तर देख लें। बाढ़ग्रस्त जालंधर के गांवों ने राज्य सरकार के इस आपदा प्रबंधन की पूरी पोल ही खोल कर रख दी। गांवों में भरा पानी सात दिन बाद भी निकल नहीं पाया, क्योंकि दरिया के दूसरी तरफ ऊंचा हाइवे बनने से पानी की निकासी के लिए रास्ता ही नहीं बचा। ऐसी घटिया योजनाबंदी का नतीजा है कि जहां सरकारी विज्ञप्तियों में दोपहिया वाहनों पर बाढ़ग्रस्त दौरे पर निकले मंत्री, डीसी और एसएसपी की तस्वीरें जारी होती रही, वहीं हफ्तों लोग घरों की छतों पर कैद हो कर रह गए। सेना ने तो हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा दी, लेकिन जिला प्रशासन के पास कश्तियों के अभाव के कारण लोग खुद टबों और बाल्टियों को सिर पर उठा कर राहत सामग्री बांटते दिखे।

हालात वही हैं, हर साल पैसा खूब डूब रहा है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला गया। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री के इस आश्वासन में समाधान है कि विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक की सहायता से राज्य की सभी नदियों के किनारे पक्के किए जाएंगे, लेकिन कहीं धुस्सी बांध के किनारों की तरह ही यह आश्वासन भी दरक न जाए।

जागरण जनमत | कल का परिणाम

कश्मीर गए विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल को एयरपोर्ट से वापस भेज सरकार ने सही किया है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या देश में प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण पर रोक लगा दी जानी चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ताऊ करिए शौक से साथ डिनर या लंच,
पर क्यों बनना चाहते आप बेवजह पंच!
आप बेवजह पंच समझ लो यह दोबारा,
है पूरा कश्मीर हमारा, सिर्फ हमारा।
जी-सेवन में आय बात मत करो पकाऊ,
बस मतलब की बात करो तुम हमसे ताऊ!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

उत्तर भारत में उपेक्षित हिंदी!

डॉ. अरुण कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
दिल्ली विश्वविद्यालय

उत्तर भारत के विद्यालयों में हिंदी को ऐच्छिक बनाया जा रहा है और विश्वविद्यालयों से भी धीरे-धीरे हिंदी का विस्थापन हो रहा है जो हमारे लिए चिंता का विषय है

जब भी हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा और विद्यालयों/ महाविद्यालयों में अनिवार्य भाषा के रूप में मान्यता देने की बात होती है, दक्षिण भारत के राज्य उसके विरोध में झंडा उठा लेते हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्य हिंदी के समर्थन में दिखाई देते हैं। इस तरह की घटनाएं आजादी के पहले भी हुई हैं। वर्ष 1937 में हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास प्रांत में कांग्रेस को विजय मिली और सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। सी राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की घोषणा की। इस घोषणा का न केवल दक्षिण भारत के नेताओं ने, बल्कि तमिल भाषा के विद्वानों ने भी विरोध किया। यहां तक कि वहां के आजादी के आंदोलन से जुड़े नेताओं ने भी विरोध किया।

हिंदी विरोध की यह भावना प्रबल होती गई और इसने आंदोलन का रूप ले लिया। दलगत और जातिगत भावना की दीवारें हिंदी विरोध के आगे ढह गईं। यहां तक कि उस समय के बड़े नेता पेरियार ने कांचीपुरम में हिंदी विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया। हिंदी विरोधी आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि सी राजगोपालचारी को आदेश वापस लेना पड़ा।

मद्रास प्रेसिडेंसी की कांग्रेस सरकार ने मद्रास में हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का दूसरा प्रयास 1946 में किया। इसके खिलाफ तमिलनाडु में एक बार फिर से हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हुए। आंदोलन की उग्रता के कारण सरकार को 1950 में अपनी इस घोषणा को वापस लेना पड़ा। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चली। लेकिन गैर हिंदी भाषियों के विरोध के कारण यह व्यवस्था कर दी गई कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। इस तरह अंग्रेजी 15 वर्षों के लिए आरूढ़ हो गई और 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा बनना था। हम देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने और पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से उसे शामिल करने का उग्र विरोध दक्षिण भारत में हुआ। या यूं कहें कि हिंदी के विरोध में दक्षिण भारत के लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़ा। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में उत्तर भारतीयों ने हिंदी के समर्थन में ही अपनी आवाज बुलंद की। वर्तमान समय में हम यह भी देखते हैं कि उत्तर भारत के स्कूल/ कॉलेज के पाठ्यक्रमों में हिंदी कब अनिवार्य विषय से ऐच्छिक विषय के रूप में बदल गई, किसी को पता भी नहीं चला।

उत्तर भारत के नेताओं ने दक्षिण भारत के स्कूलों/ कॉलेजों में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। उत्तर भारत के स्कूलों/ कॉलेजों में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी को मान्यता भी मिली। लेकिन इधर के कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि स्कूलों/ कॉलेजों से धीरे-धीरे हिंदी विस्थापित होती जा रही है और न तो इसके विरोध में और न ही समर्थन में कोई आंदोलन हो रहा है। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हिंदी को अनिवार्य विषय से हटाकर ऐच्छिक विषय कब बना दिया, पता ही नहीं चला। सीबीएसई में हिंदी पढ़ने वाले तीन तरह के विद्यार्थी मिलते हैं। पहले, जिन्होंने आठवीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है। दूसरे, जिन्होंने दसवीं तक और तीसरे जिन्होंने बारहवीं तक हिंदी पढ़ी है। सीबीएसई ने विद्यार्थियों को यह छूट दे दी है कि वे चाहें तो आठवीं के बाद ही हिंदी पढ़ना छोड़ सकते हैं। सीबीएसई की यह व्यवस्था ऐसा दर्शाती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 351 का पालन नहीं करता हुआ दिखता है। संविधान का अनुच्छेद 351 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यह बात समझ से परे है कि स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य की जगह पर ऐच्छिक विषय बनाकर उसका कितना विकास कर सकेंगे।

भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों के हिंदी विभाग लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं और यहां विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हुई है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सरकार ने कोई अध्यादेश जारी किया है, बल्कि प्रशासनिक पदों पर बैठे हिंदी विरोधी लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। यही स्थिति रही तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज आदि के हिंदी विभागों में शीघ्र ही ताले लग सकते हैं। अन्य कॉलेज में भी स्थिति ठीक नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस तरह से पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसमें स्नातक प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के विद्यार्थियों को ही केवल दो सत्रों में हिंदी पढ़नी पड़ती है। इन विद्यार्थियों में जिन्होंने आठवीं तक हिंदी पढ़ी है, वे हिंदी 'ग' पढ़ते हैं, जिन्होंने दसवीं तक हिंदी पढ़ी हैं वे हिंदी 'ब' और बारहवीं तक हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी को हिंदी 'क' पढ़ना होता है। स्नातक के बाद के पाठ्यक्रमों में तो हिंदी का जिक्र भी नहीं आता। जबकि हिंदी प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सत्र में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होनी चाहिए थी। हिंदी के प्रति उपेक्षा का यह भाव ठीक नहीं है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की यह विडंबना है कि जिस हिंदी को दक्षिण भारत के स्कूलों/ कालेजों में प्रतिस्थापित होने के लिए संघर्ष करना पड़ा और इसमें उसे बार-बार असफल भी होना पड़ा, उसी हिंदी को उत्तर भारत में शुरुआती सफलता भी मिली। उत्तर भारत में उसे कोई विरोध झेलना नहीं पड़ा। लेकिन उत्तर भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रशासनिक पदों पर कुछ हिंदी विरोधी इस तरह से बैठ गए जिन्होंने आसानी से हिंदी को विस्थापित करना शुरू कर दिया है। यदि यही स्थिति रही तो उत्तर और दक्षिण भारत में हिंदी के संदर्भ में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा।

22 करोड़ घरेलू यात्राएं दर्ज की गई थीं वर्ष 2000 में, जो 2018 में करीब नौ गुना बढ़कर 182 करोड़ हो गई। देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। 2000 में यह 60 लाख थी, जो 2016 में 2.47 करोड़ हो गई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 27 अगस्त 2019

डाटागीरी

हर साल 60,000 भारतीयों को मिलता है अमेरिका का ग्रीन कार्ड

अमेरिकी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह ग्रीनकार्ड (स्थाई निवास का दर्जा) के नियमों को और अधिक सख्त बनाएगी। यह एक ऐसा कदम है जो भारत सहित दुनियाभर के आवेदकों को प्रभावित करेगा। 2017 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत चौथा देश है, जहां के नागरिकों ने सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड हासिल किए। 2017 की 'ईयरबुक ऑफ इमिग्रेशन स्टैटिक्स' के अनुसार भारत से आगे मेक्सिको, चीन और क्यूबा हैं।

2017 में भारतीय मूल के 60,394 लोगों ने अमेरिका में स्थाई निवास का दर्जा प्राप्त किया। इसमें से 20,549 अमेरिकी नागरिकों के बेहद करीबी संबंधी (पत्नी, बच्चे, वृद्ध माता-पिता) थे। 23,569 लोग ऐसे थे जो अमेरिका में कार्यरत थे। 14, 962 लोग ऐसे थे जो फैमिली स्पांसर्ड थे, मतलब ऐसे जिनका संबंधी अमेरिका में रहता हो और उसके आग्रह करने पर वीजा मिले। इसके अलावा बचे हुए अन्य शरणार्थी आदि थे।

वहीं, 2017 में 50,802 भारतीय मूल के अमेरिकी निवासियों ने अमेरिकी नागरिकता हासिल की। इसी वर्ष 2,055,480 भारतीय नागरिकों ने अमेरिका का दौरा भी किया। इसमें पर्यटक, व्यापार के सिलसिले में आने वाले यात्री और छात्र आदि थे। कुल मिलाकर बात करें तो हर साल औसतन 60 हजार भारतीयों को अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल होता है, लेकिन अमेरिका के नियमों को सख्त करने की घोषणा के बाद भारतीयों सहित अन्य देश के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

बता दें कि रोजगार के लिए अमेरिका हमेशा से दुनियाभर के लोगों को आकर्षित करता रहा है। यहां की नीतियां न केवल जॉब, बल्कि नया कारोबार शुरू करने के लिए भी बेहतर हैं। इसी के चलते दुनियाभर से यहां लोग आते हैं और बस जाते हैं। इसके लिए ग्रीन कार्ड सबसे अच्छा साधन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से वह हमेशा इस नीति में बदलाव के पक्ष में रहे हैं, ताकि जॉब व कारोबार में अमेरिका के लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

2017 में सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड हासिल करने वाले देशों के नागरिक

देश	संख्या
मेक्सिको	1,70,581
चीन	71,565
क्यूबा	65,028
भारत	60,394
डोमिनियन रिपब्लिक	58,520

भारत में बड़ी उम्र के शेर मुखिया, अफ्रीका में सब बराबर

रोचक जानकारी ▸ भारतीय वन्यजीव संस्थान के अध्ययन में सामने आए चौंकाने वाले कई तथ्य

गिर के संरक्षित वनों में रहने वाली शेरनियों के झुंड पर किया गया अध्ययन

सुमन सेमवाल, देहरादून

भारतीय परंपरा में परिवार और उसमें मुखिया का बड़ा महत्व है। सदियों से हम मुखिया वाली पारिवारिक संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जंगल के राजा शेर भी इस प्रथा से जुड़े हैं। वह भी सिर्फ भारतीय (एशियाई) शेर, क्योंकि अफ्रीकी शेर पारिवारिक मुखिया वाली इस व्यवस्था के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। यह चौंकाने वाली बात भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) के अध्ययन में उजागर हुई है। सोमवार को वार्षिक शोध संगोष्ठी में न सिर्फ इस अध्ययन को साझा किया गया, बल्कि इसके कारणों की पड़ताल भी की गई।

डब्ल्यूआइआइ के अध्ययन में एशियाई और अफ्रीकी शेरों की प्रकृति में अंतर सामने आया है। फाइल

संस्थान की शोधार्थी डॉली बोराह ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2017 से 2019 के बीच गुजरात के गिर संरक्षित वन क्षेत्र में शेरों पर यह अध्ययन किया। उन्होंने मादा शेरों की पारिवारिक स्थिति को केंद्र में रखा। उन्होंने पाया कि जिस झुंड में जो सबसे उम्रदराज मादा शेर है, उसको सबसे अधिक तव्वजो दी जा रही थी। इसके अलावा उससे कम उम्र की शेरनी को उससे कम और फिर इसी क्रम में यह तव्वजो कम होती जा रही थी या उसका काम सिर्फ बड़ों के निर्देशों का अनुपालन करना ही रहा। खास बात यह भी रही कि उम्र की यह हैरारकी (अनुक्रम) वहां अधिक रहीं, जहां शेरनियां एक ही परिवार का हिस्सा थीं। यानी कि दूसरे परिवार की शेरनियों को चाहे वह उम्र में बड़ी ही क्यों न हों, उतनी तव्वजो नहीं मिल रही थी। इसके अलावा एक अन्य अध्ययन में नर शेरों में भी यही स्थिति निकलकर सामने आई। दूसरी तरफ शोधार्थी डॉली बोराह ने बताया कि अफ्रीका में शेर इस प्रथा का बिल्कुल में अनुपालन नहीं करते हैं। वहां उम्र में बड़े शेर व छोटे शेर को एकसमान तव्वजो दी जाती है।

भोजन की कमी को माना जा रहा वजह : शोधार्थी डॉली ने बताया कि भारत में शेरों के लिए भोजन की कमी है। शायद इसीलिए झुंड में बड़े-छोटे का क्रम तय किया गया है, ताकि सभी को समुचित मात्रा में भोजन मिल सके। दूसरी तरफ, अफ्रीका के वनों में शिकार की अधिक संभावना होने के चलते कहीं कोई टकराव की नौबत नहीं आती। लिहाजा, झुंड के सभी शेर मिलजुलकर रहते हैं।

डीएनए सैंपल से की परिवार की पहचान

भारतीय वन्यजीव संस्थान ने शेरों के परिवार की पहचान के लिए करीब 100 डीएनए सैंपल लिए। इससे देखा गया कि जो मादा शेर एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं, वहां हैरारकी का स्तर उम्र के हिसाब से चला आ रहा था। यानी कि झुंड में भी परिवार के सदस्य की उम्र को ही अधिक तव्वजो दी जा रही है।

देश में सबसे पहले पेपरलेस हुई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कागज पर खर्च हो रहे लाखों

राग दरबारी

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में देश की पहली ई-विधान प्रणाली शुरू हुई थी, लेकिन इस पेपरलेस विधानसभा में कागज व प्रिंटिंग पर हर साल लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान सैकड़ों रिम प्रयोग होते हैं। एक रिम में 500 पेज होते हैं। हैरत यह है कि जब सब कार्य ऑनलाइन है तो साल के दो से तीन लाख रुपये कागज पर क्यों खर्च हो रहे हैं? विधानसभा में अधिकारियों को आदेश लिखित में जारी किए जा रहे हैं। अन्य कार्य भी लिखित में हो रहे हैं। विधानसभा के सभी 68 सदस्यों को प्रश्नों का प्रारूप कंप्यूटर में होने के बावजूद लिखित में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

कागजों की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हिमाचल में चार अगस्त, 2014 को ई-विधान प्रणाली शुरू हुई थी। इससे पहले साइकलोस्टाइल प्रक्रिया के तहत प्रिंटिंग होती थी। सभी मंत्रियों, विधायकों व प्रेस सहित अधिकारियों को लिखित प्रश्न के साथ लिखित जवाब दिए जाते थे। इसके लिए लाखों रुपये खर्च होते थे। ई-विधान प्रणाली शुरू होने पर प्रिंटिंग व कागज पर खर्च में बहुत अधिक कमी आई है, लेकिन अभी भी पेपरलैस विधानसभा में कागज का इस्तेमाल हो रहा है।

▸ चार अगस्त, 2014 को यहां शुरू हुई थी ई-विधान प्रणाली

▸ अभी तक पूरी तरह से अपनाई नहीं जा सकी है प्रणाली, कागज इस्तेमाल करने का काम जारी

विधानसभा में कागज व प्रिंटिंग पर हुआ खर्च

वर्ष	पेपर रिम	रिम दाम	टोनर पर खर्च	कुल खर्च
2014	1308	219026	62940	281966
2015	1305	213420	146908	360328
2016	1510	236500	294415	530915
2017	1212	196398	90461	286859
2018	2029	247767	147872	395639
2019	700	126000	60052	186052

(वर्ष 2019 के आंकड़े 21 जून तक के हैं। कुल खर्च में पेपर रिम व टोनर पर खर्च शामिल है।)

विधानसभा को पेपरलेस किए जाने से लाखों रुपये के कागज की बचत हुई है। कागज के कम इस्तेमाल से पर्यावरण संरक्षण हुआ है। हिमाचल की ई-विधान प्रणाली को अन्य राज्य अपना रहे हैं। जो कार्य अभी कागज पर हो रहा है, उसे भी कम किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रणाली पूरी तरह लागू करने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।
- डॉ. राजीव बिंदल, विधानसभा अध्यक्ष

किसान से कोच बने राजेंद्र बदल रहे बेटियों की किस्मत

हरियाणा के जींद जिले के बड़ौदा गांव में राजेंद्र की देखरेख में कबड्डी खेलती लड़कियां। जागरण

सबमें कोई न कोई हुनर जरूर होता है, बस जरूरत होती है तो उसे पहचानने, तराशने और निखारने वाले की। कुछ ऐसा ही इन दिनों कर रहे हैं हरियाणा के जींद जिले के राजेंद्र चहल। वैसे तो वह किसान हैं, लेकिन यहां की बेटियों को कबड्डी के दांव-पेच सिखा कर खेल की दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। अब दूसरे राज्यों से भी बेटियां कबड्डी सीखने के लिए उनके पास आ रही हैं। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ एक किसान से कबड्डी कोच बनने का सफर...

प्रदीप घोघड़ियां, जींद

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी की बात हो और हरियाणा का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं है। यहां की जमीन से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकले हैं और अब बेटियां भी कबड्डी के मैदान में हाथ आजमा रही हैं। राज्य के जींद जिले के गांव बड़ौदा में जहां बेटियों को खेल के मैदान में उतारने से लोग हिचकते थे, वहां भी अब तस्वीर बदलने लगी है और इसमें अहम भूमिका निभाई है राजेंद्र चहल ने। किसान से कोच बने राजेंद्र की वजह से यहां की कई बेटियां कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी हैं और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं।

कोच राजेंद्र चहल।

जींद-नरवाना नेशनल हाईवे पर स्थित बड़ौदा गांव की पहचान यही है कि यहां हर तीसरे घर में एक कबड्डी का खिलाड़ी मौजूद है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुधीर पहलवान को क्षेत्र के लोग कबड्डी खिलाड़ी के तौर पर ही पहचानते हैं। वहीं, कोच राजेंद्र चहल भी कभी कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते थे। अब राजेंद्र के सानिध्य में 75 से ज्यादा लड़कियां कबड्डी के गुर सीख रहीं हैं।

गांव की बेटियों को कबड्डी के लिए प्रेरित करना पेशे से किसान राजेंद्र चहल के लिए इतना आसान भी नहीं रहा। वजह थी ग्रामीण इलाके में लोगों की रूढ़िवादी सोच, जिसकी वजह से वे बेटियों को कबड्डी और कुश्ती जैसे खेलों से दूर रखते थे। राजेंद्र ने हार नहीं मानी और बदलाव लाने की ठानी। महज तीन लड़कियों के साथ कबड्डी सिखाने का सफर शुरू किया। वक्त के साथ उन्होंने लोगों की सोच भी बदली और आज उनके पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से भी कबड्डी के गुर सीखने के लिए लड़कियां पहुंच रही हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रहा बड़ौदा का नाम : बड़ौदा गांव की मिट्टी में कोच राजेंद्र चहल द्वारा कबड्डी के दांव-पेच सीखने वालीं तन्नू, ज्योति, मुकेश, अंजलि जैसी खिलाड़ियों की अब लंबी फेहरिस्त मौजूद है, जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में दमखम दिखा रही हैं। राजेंद्र के मुताबिक, प्रतिदिन दो से तीन घंटे वह लड़कियों को अभ्यास कराते हैं। खास बात यह भी है कि लड़कियों को कोचिंग देने के लिए राजेंद्र किसी से एक पैसा नहीं लेते। बड़ौदा के अलावा उचाना कलां, उचाना खुर्द, करसिंधू, खापड़, घसो, काकड़ौद गांवों की लड़कियां भी राजेंद्र से कबड्डी के दांव-पेच सीख चुकी हैं।

फोटो न्यूज

दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल पार्किंग

वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप एक ओर जहां ईंधन की कमी का संकट पैदा हो रहा है, वहीं प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग भी वैश्विक स्तर की समस्या बनी हुई है। ऐसे में कुछ देश हैं, जहां साइकिल का प्रचलन अभी भी बहुत अधिक है। इसके लिए यहां की सरकारें भी अहम भूमिका निभा रही हैं। वे न केवल अपने नागरिकों को साइकिल चलाने के प्रति जागरूक करती हैं, बल्कि साइकिल के रख-रखाव के लिए उचित स्थान भी उपलब्ध करवाती हैं। इन्हीं में से एक देश है नीदरलैंड, जहां साइकिलों की संख्या लगभग यहां की आबादी के बराबर है। नीदरलैंड के उट्रेच शहर में पिछले दो साल से दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल पार्किंग बन रही थी, जो अब तैयार हो गई है। तीन मंजिला पार्किंग में 12,500 साइकिलें एक साथ खड़ी की जा सकती हैं।

विशेष बनावट

इस पार्किंग को इस तरह से तैयार किया गया है कि साइकिलों को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। यहां डिजिटल साइकिल स्पेस इंडिकेशन सिस्टम लगे हैं। इससे यात्रियों को पार्किंग के लिए खाली जगह ढूंढ़ने में आसानी होती है। रेलवे स्टेशन के पास बनी यह पार्किंग 24 घंटे खुली रहती है और यहां कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है।

साइकिल रखने वाले शीर्ष देश

देश	आबादी	साइकिल
नीदरलैंड	1.71 करोड़	1.60 करोड़
डेनमार्क	57 लाख	45 लाख
जर्मनी	8.35 करोड़	62 लाख
स्वीडन	90.41 लाख	60 लाख
नार्वे	54 लाख	34 लाख

साइकिल रखने और चलाने के मामले में फिनलैंड 6वें, जापान 7वें, स्विट्जरलैंड 8वें, बेल्जियम 9वें और चीन 10वें स्थान पर है।

बीएचयू में विकसित धान की दो प्रजातियों को हरी झंडी

जागरण संवाददाता, वाराणसी

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के कृषि विज्ञान संस्थान में विकसित सुगंधित धान की दो प्रजातियों (मालवीय सुगंधित धान-एचयूबीआर-1202 व एचयूबीआर-158) को कृषि निदेशालय, लखनऊ ने हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से संस्तुति होने के बाद बाजार में इसके बीज उपलब्ध होंगे। कई मायनों में ये प्रजातियां खास हैं। इसकी उपज अधिक है। पकने पर सुगंधित और खाने में स्वादिष्ट होते हैं।

संस्थान के आनुवंशिकी व पादप प्रजनन विभाग के वरिष्ठ धान प्रजनक प्रो. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि निदेशालय, लखनऊ में पिछले दिनों प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें देश के कई संस्थानों में विकसित मूंग, उर्द, धान, अरहर, सरसों, अलसी, मक्का आदि की कई प्रजातियों को भारत सरकार को नोटिफिकेशन के लिए संस्तुति की गई। वहां से नोटिफाई होने पर इसके बीज किसानों को बाजार में आसानी से उपलब्ध होंगे। इसमें बीएचयू में विकसित सुगंधित धान की दो प्रजातियां भी शामिल हैं। ये धान की अन्य प्रजातियों की अपेक्षा अधिक उपज वाली हैं। इसका चावल सुगंधित होने से बाजार में इसकी कीमत साधारण चावल की अपेक्षा अधिक होगी।

बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान में विकसित धान की नई प्रजाति एचयूबीआर-158।

एचयूबीआर 158 (मालवीय सुगंधित धान-158) : यह प्रजाति 132 दिन में तैयार होती है। इसकी बोआई जून के तृतीय सप्ताह में की जाती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह से रोपाई शुरू कर सकते हैं। 20 से 25 दिन के पौधों की रोपाई होती है। इसका चावल महीन व सुगंधित होता है। चावल का बाजार भाव प्रति किलोग्राम 50 रुपये से अधिक मिलेगा। इसकी उपज प्रति हेक्टेयर लगभग 50 से 55 क्विंटल होगी।

एचयूबीआर 1208 (मालवीय सुगंधित धान-1208) : धान के इस प्रजाति की अवधि लगभग 130 दिनों की है। इसकी बोआई भी जून के तीसरे सप्ताह में की जाती है। 20 से 22 दिन के पौधे होने पर रोपाई की जाती है। इसकी उपज प्रति हेक्टेयर लगभग 48 से 52 क्विंटल होता है। इसका चावल पतला बेलनाकार और सुगंधित होता है। इसका भाव भी बाजार में 50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक मिलेगा।

चाय के बागानों से गुलजार हो रहा छत्तीसगढ़

नईदुनिया, अंबिकापुर

▸ जशपुर में सफल प्रयोग के बाद सरगुजा के मैनपाट में तैयार होगा बागान

▸ बलरामपुर जिले के सामरी में भी चाय के खेती की संभावना

पांच साल पहले प्रयोग के तौर पर छत्तीसगढ़ के जशपुर में चाय की खेती शुरू की गई थी। अब दायरा बढ़ता जा रहा है। पूरे उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में चाय के बागान नजर आने लगे हैं। जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर जिले में चाय की खेती शुरू हुई है। सरगुजा के मैनपाट में नए बागान बड़े भू-भाग पर स्थापित किए जा रहे हैं। यहां के एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने भी पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ की जलवायु को चाय की खेती के अनुकूल पाया है। कृषि विज्ञान केंद्र जशपुर, सरगुजा जिले के बाद बलरामपुर जिले के सामरी पाठ क्षेत्र में भी चाय की खेती की संभावनाएं तलाश रहा है। किसानों की समृद्धि को देखते राज्य सरकार भी इसमें विशेष पहल कर रही है।

उत्तरी छत्तीसगढ़ को चाय के बागान से गुलजार करने के लिए मैनपाट का चयन किया गया। यहां 30 प्रगतिशील किसानों को साथ लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जशपुर जिले के सारडीह स्थित चाय बागान प हुंचे, जहां वन विभाग के अधिकारियों व चाय की खेती में लगी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चाय की खेती से बदली आर्थिक स्थिति को लेकर खुशी जाहिर किया। कृषि वैज्ञानिकों मौसम की अनुकूलता को देखते हुए जशपुर की तरह मैनपाट में भी बेहतर खेती की बात कही है।

समान जलवायु से बढ़ी उम्मीदें : जशपुर, मैनपाट और सामरीपाट की जलवायु एक समान है। मैनपाट में तिब्बती के साथ ही स्थानीय किसान बड़े पैमाने पर टाउ की खेती करते हैं। वर्तमान में सामरी व जशपुर के किसान भी बड़े पैमाने पर फसल ले रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यहां की अनुकूल जलवायु है। वहीं अब चाय की खेती से इन किसानों को उत्साह बढ़ रहा है।

छत्तीसगढ़ के जशपुर में शुरू की गई चाय की खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। प्रतीकात्मक

जशपुर रोड सरगुजा के पाट क्षेत्रों की जलवायु लगभग एक समान है। यहां मैंने चाय की खेती देखी। इसे देखते हुए सरगुजा के मैनपाट में चाय की खेती के लिए प्रयास शुरू किया गया है। इन्हें जल्द ही विकसित किए जाएंगे। खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन भी सहयोग करेगा।
- अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़

मैनपाट के 30 प्रगतिशील किसानों ने जशपुर जिले में चाय की खेती का अवलोकन किया है। जशपुर जिले के चाय बागान में भ्रमण के दौरान भूमि चयन से लेकर बेहतर बीज और उत्पादन के साथ पैकेजिंग की तकनीक भी सीखी है।
- डॉ. पीएस राठिया, प्रभारी, कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट

अंग्रेजी अक्षर सीखने का आसान तरीका तलाशा

डीडी गोयल, डबवाली (सिरसा)

तलाशी राह

हरियाणा के सिरसा निवासी राहुल धमीजा ने ऐसा तरीका तैयार किया है, जिसकी मदद से बच्चे खेल-खेल में अंग्रेजी वर्णमाला सीख रहे हैं। उनके द्वारा तैयार प्रारूप से अब बच्चे एक अक्षर से एक बार में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई शब्द जान पा रहे हैं। यही वजह है कि उनका यह तरीका बच्चों में तेजी से अपनाया जा रहा है। राहुल का कहना है कि उनके द्वारा तैयार प्रारूप को सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि कई देशों से सराहना मिल रही है। नेपाल के एक प्रकाशन ने उनसे संपर्क साधा है। प्रकाशक इस वर्णमाला से एक पुस्तक तैयार करना चाहता है, जिसके लिए उसे मूल प्रारूप की आवश्यकता है।

राहुल बताते हैं कि उन्होंने सितंबर 2016 में अंग्रेजी वर्णमाला के खास प्रारूप को तैयार करना शुरू किया था। उनका उद्देश्य था कि बच्चे शुरू में सिर्फ ए फॉर एपल ही नहीं, बल्कि एक अक्षर से बहुत कुछ सीख सकें। उन्होंने सभी अक्षरों को कहानी का रूप दे दिया। उन्होंने अब तक वर्णमाला के 22 अक्षर तैयार कर लिए हैं। चार अक्षरों पर अभी काम चल रहा है। बकौल राहुल, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में उनके द्वारा तैयार की गई वर्णमाला पढ़ाई जा रही है। पंजाब के शिक्षा विभाग ने पढ़ो पंजाब अभियान चलाया हुआ है। पंजाब ने मोबाइल एप पर यह वर्णमाला अपलोड कर रखी है।

अंग्रेजी वर्णमाला दिखाते राहुल धमीजा। जागरण

नया प्रारूप प्रचलित वर्णमाला से बिल्कुल भिन्न है। उदाहरण के तौर पर वर्णमाला का अक्षर वी लेते हैं। आमतौर पर बच्चे वी फॉर वैन पढ़ते हैं, लेकिन रचनात्मक तरीके से बनाए गए नए प्रारूप में वी फॉर पढ़ना रोचक है। कलरफुल वी अक्षर में तस्वीरें डिजाइन करके वी फॉर के 10 अर्थ बताए गए हैं। इस वजह से बच्चों को वर्णमाला आसानी से समझ आ रही है।

21.61 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट प्रचलन में थे इस साल 19 जुलाई को। आरबीआइ के मुताबिक, 20 जुलाई, 2018 को 19.1 लाख करोड़ रुपये और नोटबंदी से पहले चार नवंबर, 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपये प्रचलन में थे।

उत्तर प्रदेश में गढ़ी जा रही 'सबसे ऊंची' गणेश प्रतिमा

जागरण विशेष ▶ चंदौसी में 135 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का काम जारी, 2020 तक होगी तैयार

चंदौसी में सीता रोड स्थित गजानन परिसर में बन रही 135 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा। जागरण

सचिन चौधरी, चंदौसी

उत्तर प्रदेश के चंदौसी में 135 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनाने का काम बीते 12 वर्षों से चल रहा है। गणेशोत्सव दो सितंबर से प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन भक्तों को इस प्रतिमा के दर्शन के फिलहाल एक वर्ष और इंतजार करना होगा, क्योंकि कंक्रीट की यह प्रतिमा 2020 तक बनकर तैयार होगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कीर्तिमान दर्ज कराने के लिए दावा भेजा जा चुका है। आयोजकों का दावा है कि वर्तमान में सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है, जो 85 फीट ऊंची है।

हड्डी और सींग के कारोबार के लिए विश्वविख्यात सम्भल जनपद की चंदौसी तहसील को मिनी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यहां के हर गली और मोहल्ले में मंदिरों का होना है। यहां का गणेश चौथ मेला भी विख्यात है। अब चंदौसी के लोगों को सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा के बनकर तैयार होने का इंतजार है। नृत्य मुद्रा वाली इस प्रतिमा को गढ़ने में दिल्ली और ओडिशा से बुलाए गए 10 कारीगर जीजान से जुटे हुए हैं।

गणेश मेले के संस्थापक डॉ. गिरीराज किशोर ने बताया कि चंदौसी में 58 साल से गणेश चौथ मेले का आयोजन होता आ रहा है। यहां के लोगों में भगवान गणेश के प्रति विशेष आस्था है। गणेश चुतर्थी पर हर घर में गणेश विराजते हैं। अनेक पंडाल लगते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे में हमने तय किया कि भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाए। भारत और एशिया सहित विभिन्न जगहों पर स्थापित गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई के बारे में जानकारी जुटाई और तय किया कि 135 फीट ऊंची प्रतिमा का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। वर्ष 2007 में चंदौसी में सीता रोड स्थित गजानन परिसर में प्रतिमा बनाने काम शुरू किया गया, जो अब तक जारी है।

डॉ. गिरीराज किशोर।

▶ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कीर्तिमान दर्ज कराने के लिए दावा भेज चुके हैं गणेश मेले के आयोजक

▶ ओडिशा और दिल्ली के 10 कारीगर लगातार कर रहे हैं काम

दस किमी दूर से भी दिखाई देती है निर्माणाधीन प्रतिमा

प्रतिमा लगभग बन कर तैयार हो गई है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले साल तय यह पूरी तरह तैयार हो जाएगी। भगवान गणेश की इस प्रतिमा की ऊंचाई 135 फीट होने के चलते शहर से दस किलोमीटर दूर से भी यह दिखाई देती है। आसपास के अनेक गांवों से भी प्रतिमा को आसानी से देखा जा सकता है।

डॉ. गिरीराज बताते हैं कि प्रतिमा का निर्माण वह स्वयं अपने खर्चे और देखरेख में करा रहे हैं। इस प्रतिमा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कराने के लिए दो साल पहले आवेदन किया जा चुका है। आवेदन के जवाब में वहां से संदेश आया कि प्रतिमा के पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसका सर्वे करके प्रमाण पत्र दिया जाएगा। डॉ. गिरीराज का कहना है कि कोल्हापुर में मौजूद 85 फीट की गणेश प्रतिमा के बाद दूसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में है, जिसकी ऊंचाई 57 फीट है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

गोबर के श्रीगणेश हरेंगे क्लेश

दीपक अवस्थी, रायपुर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस बार गोबर निर्मित गणेश प्रतिमाएं भक्तों को बेहतर पर्यावरण का संदेश देंगी। बेहद सकारात्मक सोच के साथ इन प्रतिमाओं के सृजन में लगे नौजवानों और मूर्तिकारों का उद्देश्य पर्यावरण के साथ गोवंश के संरक्षण का संदेश देना भी है। रायपुर के नजदीक स्थित छोटे से गांव डूंडा में 'एक पहल सेवा समिति' के मूर्तिकारों ने लोगों को निःशुल्क प्रतिमाएं उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। यह पहल यहां के लोगों को काफी पसंद आ रही है।

संस्था के अध्यक्ष राजकुमार साहू ने बताया कि क्षेत्र की सभी गोशालाओं और अन्य जगहों से कुछ दिनों पूर्व ही गोबर को एकत्र करने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने इसे तैयार करने के तरीके के बारे में बताया कि गोबर को हल्का पानी मिलाकर उसे मिट्टी के एक सांचे में डाल दिया जाता है। सांचे में भगवान गणेश की आकृति बनी हुई है। सूखने के बाद मूर्ति को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब पांच दिन लगते हैं। करीब 300 मूर्तियां तैयार की गई हैं।

गोबर से निर्मित श्रीगणेश की प्रतिमा। नई दुनिया
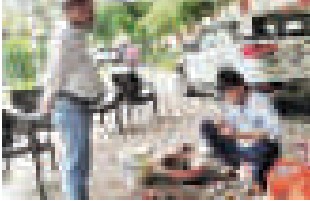
रायपुर के डूंडा गांव में गोबर से श्रीगणेश की प्रतिमा को आकार देता कलाकार। नई दुनिया

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में बढ़ी खानदानी दरार

अश्विनी रघुवंशी, धनबाद

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' का नाम पढ़ते ही अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी और मनोज वाजपेयी एवं नवाजुद्दीन सिद्दकी अभिनीत फिल्म की यादें ताजा हो जाती हैं। यहां एक और कहानी है। दोनों कहानी धनबाद की हैं, मगर यह 'रील' नहीं, 'रियल' लाइफ की कहानी है। धनबाद के 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में अब खानदानी दरार बढ़ चुकी है। वासेपुर के 'बॉस' मामा फहीम खान के खानदान में एलान ए जंग हो चुका है। एक माह पहले फहीम खान का भांजा गोडविन जेल से बाहर आया था तो उसने पुलिस विभाग के शीर्ष अफसर से मिल कर शिकायत की थी कि बॉस का बेटा इकबाल खान उसे मरवा देगा। अब भांजे ने ममेरे भाई इकबाल खान पर केस भी करवा दिया है। इकबाल खान तड़ीपार है। कोलकाता में रह रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस इकबाल खान की तलाश में है। ऐसे में फहीम के भाई सानू खान और शेर खान ने कहा कि अब उनका भांजों से कोई रिश्ता नहीं है।

दरअसल, नया बाजार के सगीर हत्याकांड में फहीम खान को आजीवन कारावास हो चुकी है। 11 साल से वह जेल में है। जेल में रहने पर भी फहीम का खौफ दस साल तक कायम रहा। दरअसल, फहीम के हुक्म पर भांजे कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, लेकिन पिछले एक साल से फहीम जेल के भीतर व्हील चेयर पर है। एंजियोग्राफी हो चुकी है। इस अवधि में चार भांजे कई मुकदमे दर्ज हो गए। ऐसे में मामा फहीम के गिरते स्वास्थ्य को देख भांजों की बॉस बनने की ख्वाहिश जाग गई। जहां से फहीम या उनका बेटा इकबाल उगाही करता है, वहां से उनके भांजे भी अपना हिस्सा चाह रहे हैं। इसी के साथ शुरू हुए झगड़े में खानदानी दरार बढ़ती जा रही है।

पहले करते थे हुक्म की तामील : जेल में बंद बड़ा भांजा गोपी 'वासेपुर का बॉस' बनना चाहता है। फहीम की बहन नसीमा बेगम के बच्चे जियाउर रहमान उर्फ गोपी, हैदर अली उर्फ प्रिंस, जियाउल हक उर्फ बंटी व शौकत उर्फ गोडविन लंबे समय तक मामा फहीम खान, सानू खान, ममेरे भाई इकबाल खान, रज्जन खान के हुक्म की तामील करते आए हैं। अब भांजों के साथ गुर्गों की बड़ी फौज है। आर्थिक तौर पर भी सबल हो चुके हैं।

रंगदारी के लिए दोनों गैंग बना रहे दबाव : पुलिस में दर्ज केसों के मुताबिक धनबाद के वासेपुर, भूली से पांडरपाला तक कोई भी जमीन खरीदता या बेचता है तो गैंग के डोरेमोन (कार्टून कैरेक्टर का उपनाम), मिट्ठू पागल जैसे गुर्गे सामने आ जाते हैं। जमीन की खरीद-फरोख्त के साथ ही, धनबाद नगर निगम और पूर्व-मध्य रेल मंडल से गैंग की ओर से रंगदारी वसूली जाती है। अब पुलिस को पता चला है कि गैंग दो फाड़ हो गया है। फहीम खान और उनके बेटे एक गिरोह व भांजे की टोली दूसरे गिरोह को संभाल रही है। दोनों रंगदारी की रकम के लिए लोगों पर दबाव बना रहे हैं।

पुलिस मददगारों पर नकेल कसने की तैयारी में : पुलिस ने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के प्रमुख लोगों के अलावा उनकी मदद से ठेकेदारी, कारोबार या जमीन का लेन-देन करने वालों की लंबी सूची बना ली है। एक-एक कर सभी लोगों को नोटिस देकर बुलाया जाएगा। गैंग से किसी तरह का ताल्लुक रखने वालों के फिंगर प्रिंट लिए जाएंगे। उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार होगा। आय का वर्तमान स्त्रोत दर्ज किया जाएगा।

शेर खान बोला-दुश्मनों से मिल गए भांजे, एनकाउंटर कर दो : 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के बॉस फहीम खान के भाई शेर खान ने कहा कि भांजे दुश्मनों से मिल गए हैं। उन्होंने बगावत की है। भांजों ने फहीम और भतीजे इकबाल खान के नाम का दुरुपयोग कर कमाई की है। एसएसपी किशोर कौशल अपराध करने वालों की फाइल तैयार करने के साथ उनका एनकाउंटर भी कर दें।

फहीम का भाई शेर खान। जागरण

गैंग्स ऑफ वासेपुर में दरार आ चुकी है। फहीम और उनके भांजे अलग हो चुके हैं। जल्द गैंग्स पर बड़ा एक्शन होगा।
– किशोर कौशल, एसएसपी, धनबाद

सदियों पुरानी कुरीति पर दो वर्षों में लगाई लगाम

यशवंतसिंह पंवार, झाबुआ

नारी सशक्तीकरण

मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ क्षेत्र में वधूमूल्य प्रथा का चलन जोरों पर था। वर पक्ष लड़की के पिता को नियत राशि देता और लड़की का पिता राशि के लालच में कम उम्र में ही बेटी की शादी कर देता। 2016 से दिसंबर 2018 तक झाबुआ कलेक्टर रहे आशीष सक्सेना को सदियों पुरानी इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने का श्रेय दिया जा रहा है।

सक्सेना वर्तमान में बतौर अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन व विकास संचालनालय, भोपाल में पदस्थ हैं, लेकिन झाबुआ में अपने 28 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने दहेज दापा के कलंक से हजारों बालिकाओं को मुक्ति दिलाने का सराहनीय काम कर दिखाया। आशीष बताते हैं कि झाबुआ की 13 वर्षीय एक आदिवासी लड़की रेखा की पीड़ा ने उन्हें स्थिति की विकरालता से रूबरू कराया। तलावली इलाके की 13 वर्षीय रेखा भूरिया जब तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटी और अपने प्रशिक्षक के साथ वह कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंची तो आशीष ने उससे उसके भविष्य के बारे में कुछ बातें कीं। आशीष ने पूछा कि बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, इस पर उसकी आंख नम हो गईं। तब प्रशिक्षक जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि रेखा की शादी तय कर दी गई है, इसलिए वह दुखी है। आशीष ने तब दहेज दापा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। रेखा के मामले में वह उसके परिजनों से मिले और उसकी शादी के शगुन के रूप में पिता ने जो राशि वर पक्ष से ली थी, वह लौटाने के लिए उन्हें राजी किया। इतना ही नहीं, रेखा को छात्रावास में भर्ती करवाया गया। रेखा ने आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। बस यहीं से कलेक्टर सक्सेना ने दहेज दापा के खिलाफ कमर कस ली। इसके लिए उन्हें न केवल प्रशासनिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी कई तरह के प्रयास करना पड़े। आशीष ने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज दापे के मामले में सर्वे करवाया। सर्वे में दहेज दापे को लेकर वास्तविक स्थिति सामने आई तब इसकी रोकथाम के लिए योजना बनाई। तड़वी (मार्गदर्शक) सम्मेलन करवाए गए। समाज के बुजुर्गों को समझाया गया। किशोरी संसद के रूप में बालिकाओं के सम्मेलन आयोजित कराए गए। इसमें 39 हजार बालिकाओं ने भाग लिया। 18 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं करने को लेकर बालिकाओं को शपथ दिलवाई गई। अधिक से अधिक बालिकाओं को छात्रावासों में प्रवेश दिलवाया गया। आशीष सक्सेना ने बताया कि उन्होंने ग्रामसभा में दहेज दापा के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवा दिया था, हालांकि उसका लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां तो भील पंचायत चलती है। ऐसे में उन्होंने समाज के सम्मानित लोगों (तड़वियों) से सीधा संपर्क करना शुरू किया। मुख्य समस्या यह थी कि भांजगड़िये यानी दलाल शादियां करवाने में दोनों पक्ष से पैसा लेते थे। कानूनी कार्रवाई से ज्यादा बात नहीं बनती थी। ऐसे में पुलिस के साथ मिलकर ऐसे सभी लोगों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया। काउंसलिंग भी की गई। नतीजा यह निकला कि लिए हुए पैसे भी उन्होंने बालिकाओं के बैंक खातों में वापस जमा करवाए। गांव-गांव में जाकर दहेज दापे की राशि को नहीं लेने या एकदम ही कम करने पर जोर दिया गया। इससे सकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

झाबुआ में दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने वाले तत्कालीन कलेक्टर आशीष सक्सेना। नईदुनिया

खत्म की वधूमूल्य की कुप्रथा

दहेज दापा की राशि 5–7 लाख रुपये तक भी रहती। दोनों पक्षों के इस आर्थिक व्यवहार में बालिकाएं पिस जातीं। शादी के बाद वर पक्ष अपना कर्ज उतारने के लिए बालिका से मजदूरी तक करवाता। कमजोर कोख में बच्चा पलता है तो कुपोषित पैदा होता। कम उम्र में शादी होने से लड़कियों को भी कई तरह की स्वास्थ्यगत समस्याओं से जूझना पड़ता। शिक्षा या अन्य सपने तो उनके वधूमूल्य का लेन–देन होते ही चकनाचूर हो जाते। कलेक्टर आशीष सक्सेना के दो साल के कार्यकाल में जिले में 3580 शादियां हुईं। उनके ही प्रयासों से 324 शादियां बगैर दहेज और 2302 शादियां न्यूनतम दहेज दापे की राशि पर हुईं।

खाद्य पदार्थों में विषैलेपन का आकलन करेगा आइआइटीआर

रूमा सिन्हा, लखनऊ : मिलावटखोरी के जरिये लोगों की जान खतरे में डालने वालों की निगहबानी के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एफएसएसएआइ) ने एक और पहल की है। लखनऊ स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) और भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आइआइटीआर) को खाद्य पदार्थों में विषैलेपन के आकलन की जिम्मेदारी सौंपी है। आइआइटीआर ही नहीं, एफएसएसएआइ ने सरकारी व गैर सरकारी लगभग एक दर्जन प्रयोगशालाओं का नेटवर्क तैयार किया है। नेशनल रिसर्च लेबोरेट्री के तौर पर नामित इन प्रयोगशालाओं को न केवल खाद्य पदार्थों की जांच, बल्कि जांच विधि व मानक तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल, अथॉरिटी इसके जरिये अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहती है, जिससे आने वाले समय में मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा सके। आइआइटीआर के निदेशक प्रो. आलोक धावन बताते हैं कि संस्थान को न केवल रेफरेंस, बल्कि रेफरल लैबोरेट्री बनाया गया है। यानी संस्थान देशभर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की विषाक्तता जांच करने के साथ मानक भी तैयार करेगा।

आंखों में सपने, पांव के नीचे जोखिम...

बांस के कच्चे झूलते पुल के सहारे नदी पार कर रहे इन बच्चों की आंखों में भविष्य को लेकर कई सपने हैं और कदम उन सपनों को साकार करने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन पुल के नीचे बह रही नदी बार–बार इनका रास्ता रोकती है। यह नजारा झारखंड की राजधानी रांची के शहरी इलाके से सटे वार्ड 50 के गांव बड़ा घाघरा के नदी ढीपा का है। अरसे से यहां के लोग नदी पर पुल बनाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। किसी तरह बांस की खपच्ची बांधकर गांव के लोग बार–बार यह कच्चा पुल बनाते हैं। इससे किसी तरह आवागमन तो हो जाता है, लेकिन बताने की जरूरत नहीं कि बांस के इस पुल से नदी पार करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। फिर भी क्या करें, मजबूरी है। **फोटो :** करुण

'गार्ड ऑफ ऑनर' ले महाकाल निकले नगर भ्रमण पर

उज्जैन में राजाधिराज की एक झलक को आतुर श्रद्धालु। नईदुनिया

नईदुनिया, उज्जैन

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार को भगवान महाकाल 'गार्ड ऑफ ऑनर' लेने के बाद नगर भ्रमण पर निकले। उनकी शाही सवारी में जमकर भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर से शाम चार बजे शाही ठाठ के साथ देशी-विदेशी फूलों से सजी रजत पालकी में सवार होकर अवंतिकानाथ नगर भ्रमण करने निकले। भक्तों को छह रूपों में भगवान महाकाल के दर्शन हुए। त्रिलोकीनाथ चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरुड़ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा-महेश और रथ पर होलकर व सप्तधान स्वरूप में वह सवार थे। राजा के इन दिव्य रूपों के दर्शन को देशभर से भक्त जुटे थे।

दोपहर को सभामंडप में पुजारियों ने भगवान चंद्रमौलेश्वर का पूजन किया। इसके बाद पालकी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। शाम 5.15 बजे सवारी रामघाट पहुंची। यहां शिप्रा नदी के जल से महाकाल का अभिषेक किया गया। गोपाल मंदिर पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवारी का पूजन किया। इसके बाद तय मार्ग से होती हुई पालकी पुनः महाकाल मंदिर पहुंची।

भगवान महाकाल यूं तो तीनों लोकों के नाथ कहे जाते हैं, लेकिन लौकिक जगत में इन्हें अवंतिका का राजाधिराज माना जाता है। ऐसे में वह जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो उन्हें सशस्त्र बल की टुकड़ी तीन स्थानों पर सलामी देती है। पहली बार जब बाबा की पालकी मंदिर से रवाना होती है तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद रामघाट पर पूजन के समय तथा पालकी के मंदिर लौटने पर। यह परंपरा करीब 300 साल पुरानी है।

▶ देशी–विदेशी फूलों से सजी पालकी में सवार हुए अवंतिकानाथ

भगवान महाकाल का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप।

सवारी एक नजर में

- **6** किमी लंबा था सवारी मार्ग
- **6** घंटे तक छाया रहा भक्ति का उल्लास
- **2100** पुलिस जवानों ने संभाली व्यवस्था
- **88** दल शामिल (भजन मंडली, झांझ–डमरू आदि)

जज्बा

प्रधानाध्यापिका ने नहीं किया बजट का इंतजार, अपने वेतन से खरीदा फर्नीचर और कराया एक कक्ष के फर्श का निर्माण, अब अन्य कक्षों का फर्श पक्का कराने की तैयारी

गीता ने बदल दी सरकारी स्कूल की तस्वीर

दीपक मिश्रा, रुड़की

बदलाव लाने के लिए भीड़ की नहीं, बस नेक इरादे और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। कुछ इसी इरादे और इच्छाशक्ति के बल पर उत्तराखंड के रुड़की जिले के एक सरकारी स्कूल की तस्वीर बदलने का काम किया है यहां की प्रधानाध्यापिका गीता ने। रुड़की के गणेशपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर-पांच की प्रभारी प्रधानाध्यापिका गीता रानी ने विद्यालय में सुधार कार्य कराने के लिए विभाग से बजट मिलने का इंतजार नहीं किया। अपने वेतन से जरूरी काम पूरे करवाए और अब यह सरकारी विद्यालय किसी निजी स्कूल सा प्रतीत होता है।

गीता रानी विद्यालय में सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं और किसी भी जरूरी कार्य को पूर्ण कराना अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं था। गीता ने एक विद्यालय का पुराना फर्नीचर खरीदकर उसे ठीक कराया। अब बच्चे जमीन पर नहीं, कुर्सी पर बैठ कर पढ़ाई करती हैं। बच्चों को हिंदी-अंग्रेजी के स्वर-व्यंजन और पहाड़े कंठस्थ रहें, इसके लिए उन्होंने कक्षा-कक्ष की दीवार पर इन्हें खूबसूरत ढंग से अंकित करवाया। इसके अलावा दीवारों पर राष्ट्र और राज्य से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां भी अंकित कराईं। गीता बताती हैं, इससे दो फायदे हुए। एक तो दीवारें सुंदर दिखने लगीं और दूसरा बच्चे अब इन्हें देकर जरूरी चीजें आसानी से याद कर सकते हैं।

गीता ने विद्यालय परिसर में तरह-तरह के पौधे भी लगाए हैं। यही नहीं, विद्यालय के एक कक्ष में फर्श भी पक्का करवा चुकी हैं और अब अन्य कक्षों में इसकी तैयारी चल रही है। सभी छात्र-छात्राएं साफ-सुधरी यूनिफार्म में विद्यालय आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो वे किसी निजी स्कूल के विद्यार्थी हैं। वर्तमान में विद्यालय में 61 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जबकि प्रधानाध्यापिका समेत तीन शिक्षक कार्यरत हैं।

रुड़की के गणेशपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती गीता रानी। जागरण

विद्यालय में तैयार कराया किचन गार्डन

गीता ने विद्यालय परिसर में ही किचन गार्डन भी तैयार कराया है। यहां पर मौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। इन दिनों बरसात के चलते फिलहाल कुछ मौसमी सब्जियां समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए अब नए सिरे से मौसमी सब्जियों को तैयार किया जा रहा है। किचन गार्डन में तैयार होने वाली सब्जियों का इस्तेमाल मिड–डे मील में किया जाता है। सर्दियों के मौसम में ज्यादा सब्जियां तैयार होती हैं।

राष्ट्रीय संस्करण
मंगलवार 27 अगस्त 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

रुपया नौ महीने के निचले स्तर पर

मुंबई : सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 36 पैसे कमजोर हुआ। इस दौरान यह एक डॉलर के मुकाबले 72.02 के स्तर पर आ गया। यह बीते नौ महीने में सबसे निचला स्तर है। हालांकि सरकारी सुधारात्मक प्रयासों के चलते इक्विटी मार्केट में 700 से अधिक अंकों का सुधार हुआ, लेकिन दिन के कारोबार में रुपया 14 नवंबर 2018 के बाद सबसे निचले स्तर पर क्लोज हुआ। सोमवार को भारतीय रुपये के अलावा चीनी युआन, तुर्किश लीरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। (प्रेट्र)

ऑटो सेक्टर की मंदी बाहरी कारणों से नहीं, इसकी खुद की खामियों की वजह से है। सेक्टर को सरकार से मदद मांगने से पहले इन खामियों को दूर करना चाहिए।
— राजीव बजाज
एमडी, बजाज ऑटो

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
37,494.12	11,057.85	₹39,670	₹46,550	₹72.02	$59.04
▲ 792.96	▲ 228.50	▲ ₹675	▲ ₹1,450	▲ ₹0.36	

कारपोरेट हलचल

सोबती ने संभाला डीजी स्कोप का पद

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पूर्व सीएमडी अतुल सोबती ने सार्वजनिक उपक्रमों की शीर्ष संस्था स्कोप यानी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर जनरल पद का कार्यभार संभाल लिया है। सोबती ने डॉ. यूडी चौबे का स्थान लिया है जिनका डीजी स्कोप का कार्यकाल समाप्त हो गया। सोबती ने विभिन्न पदों पर करीब चार दशकों तक बीएचईएल में काम किया जिनमें छह साल बोर्ड में बतौर डायरेक्टर का कार्यभार भी शामिल है।

आइओसी में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) ने नोएडा स्थित पाइपलाइन मुख्यालय में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इंडियन ऑयल के डायरेक्टर (पाइपलाइन) अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि इंडियन ऑयल के लिए यह गर्व की बात है कि वह देश सेवा में कार्यरत है और सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। इस मौके पर आइओसी के कर्मचारियों को लंबी अवधि तक सेवा के लिए पुरस्कृत भी किया गया।

एनएसआइसी में मना स्वतंत्रता दिवस

नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (एनएसआइसी) में 73वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पौधारोपण का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एनएसआइसी के डायरेक्टर (पीएंडएम) पी उदयकुमार ने कहा कि जीवन के लिए वृक्ष बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनसे न केवल हमें स्वच्छ हवा मिलती है बल्कि स्वच्छ जल, छाया और भोजन में भी इनकी अहम भूमिका है।

सोखी बनीं एनबीसीसी में डायरेक्टर

श्रीमती बीके सोखी को एनबीसीसी में डायरेक्टर (फाइनेंस) पद पर नियुक्त किया गया है। शहरी आवास मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। सोखी ने 1990 में एकाउंट ऑफिसर की हैसियत से एनबीसीसी ज्वाइन किया था। उन्हें फाइनेंस के क्षेत्र का 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है।

पीडीआइएल में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआइएल) के नोएडा स्थित कॉरपोरेट ऑफिस में 73वां स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ डायरेक्टर (फाइनेंस) डीएस सुधाकर रमैया के राष्ट्रीय ध्वज फहराने से हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों के लिए पीडीआइएल के चेयरमैन व एमडी पार्थ सारथी सेन शर्मा का संबोधन पढ़ा।

बाजार ने मनाया सरकार के प्रयासों का जश्न

- तीन महीनों का **सबसे बड़ा दैनिक उछाल** दर्ज हुआ सेंसेक्स में
- निफ्टी 228 अंक उछलकर 11,000 अंक के पार

मुंबई, प्रेट्र : पिछले सप्ताह शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित सुधार के कदमों का सोमवार को निवेशकों ने शेयर बाजार में जमकर जश्न मनाया। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 792.96 अंक यानी 2.16 परसेंट की छलांग के साथ 37,494.12 अंक पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 228.50 अंक यानी 2.11 परसेंट के उछाल के साथ 11,057.85 पर बंद हुआ।

एफपीआइ से सरचार्ज वापस लेने के सरकार के फैसले का बैंकिंग स्टॉक पर सीधा प्रभाव देखा गया। पिछले कई सत्रों से लगातार दवाब में रहे कई बैंकिंग शेयरों में सोमवार को जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही 20 मई के बाद एक दिन के कारोबार में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

हालांकि इस दौरान घरेलू मोर्चे पर बाजार की अपनी चुनौतियां रहीं। लेकिन यूएस और चीन में चल रहे ट्रेड वार के चलते दुनियाभर के बाजार जिस खराब दौर से गुजर रहे हैं, भारतीय शेयर बाजारों में अभी उस तरह की निराशा नहीं दिखी है। दिन के कारोबार में यस बैंक के शेयरों ने सेंसेक्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरे नंबर पर एचडीएफसी और इसके बाद बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एलएंडटी, एसबीआइ, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक रहे। इन कंपनियों के शेयरों ने 5.24 परसेंट से अधिक की उछाल दर्ज की। दूसरी ओर टाटा स्टील, सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, आरआइएल, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान इन कंपनियों के शेयर 2.01 परसेंट तक लुढ़क गए। एवीपी इक्विटी रिसर्च के प्रमुख नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि शुक्रवार को वित्त मंत्री की सुधारवादी घोषणाओं के कारण सोमवार को बाजार तेजी के साथ खुले। जबकि दूसरे एशियाई बाजारों में सुस्ती देखी गई।
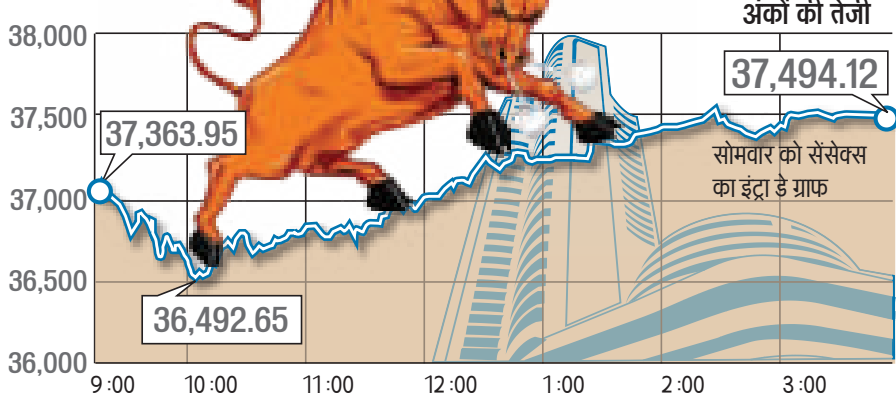
इस दौरान शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, हैंगसेंग, कोस्पी और निक्केई गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि ट्रंप द्वारा चीन के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू करने की घोषणा के कारण दोपहर के बाद से एशियाई और यूरोपीय बाजारों में कुछ सुधार हुआ। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपये में 36 पैसे की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 72.02 के स्तर पर बंद हुआ।

बीएसई ने शुरू किया इंटरेस्ट रेट आधारित ट्रेडिंग का विकल्प

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीएसई ने सरकारी बांड आधारित ब्याज दरों पर ट्रेडिंग का विकल्प पेश किया है। बीएसई ने 2014 में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर शुरू किया था, जिसके पास 40 परसेंट का औसतन मार्केट शेयर था। अब यह अपने इंटरेस्ट रेट को विस्तार देने जा रहा है। बीएसई एकमात्र ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो ट्रेडिंग पर इंटरेस्ट रेट का विकल्प दे रहा है।

792.96 अंकों की तेजी
37,494.12
37,363.95
36,492.65
सोमवार को सेंसेक्स का इंट्रा डे ग्राफ
38,000 / 37,500 / 37,000 / 36,500 / 36,000
9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00

निवेशकों ने कमाए 2.4 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : इकोनॉमी की सुस्ती को दूर करने के सरकारी प्रयासों के कारण सोमवार को शेयर मार्केट में तेजी का रुख रहा। इस दौरान निवेशकों की वेल्थ में 2.41 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। दिन के कारोबार में बीएसई का सेंसेक्स 792.96 अंकों की बढ़त के साथ 37,494.12 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,41,975.59 करोड़ रुपये की उछाल के साथ 1,40,34,462.19 रुपये पर जा पहुंचा।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा कहते हैं कि बाजार में तेजी की मुख्य वजह सरकार की सुधारवादी घोषणाएं हैं। इसके अलावा वैश्विक संकेत भी बाजार के पक्ष में ही रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की चीन के साथ बातचीत की घोषणा का निवेशकों के बीच अच्छा संकेत गया।

दिन के कारोबार में बैंकिंग सेक्टर के शेयर ने यस बैंक की अगुआई में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। बीएसई के 1,705 स्टॉक में तेजी देखी गई। वहीं 811 स्टॉक में गिरावट दर्ज की गई और 123 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

फिक्की ने लगाया करीब सात परसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इकोनॉमिक ग्रोथ के कई अनुमान आने के बाद अब इंडस्ट्री चैंबर फिक्की ने भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए कम से कम 6.9 परसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान लगाया है। लेकिन पहले आए कई अनुमानों से फिक्की के अनुमान में अंतर यह है कि इसमें माना गया है कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन ही जीडीपी को इस ऊंचाई तक पहुंचेगा। वैसे पहली तिमाही को लेकर फिक्की का अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ रेट छह परसेंट रहेगा। सरकार 31 अगस्त को वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के आंकड़े जारी करेगी।

फिक्की ने देश के इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में देश के अलग अलग इकोनॉमिस्ट से राय ली गई है। इस साल जून-जुलाई में कराए गए इस सर्वे में पूरे साल के जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए न्यूनतम 6.7 परसेंट और अधिकतम 7.2 परसेंट का अनुमान लगाया गया है। फिक्की का मानना है कि पूरे वर्ष के लिए जीडीपी में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का योगदान अहम होगा। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष में इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 6.9 परसेंट और सर्विस सेक्टर का आठ परसेंट रहने का अनुमान है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले अधिकांश इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि आरबीआइ फिलहाल नरम दरों की अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगा। आरबीआइ वित्त वर्ष 2019-20 की शेष अवधि में रेपो रेट में अभी और कमी कर सकता है। हालांकि सर्वे में चालू वित्त वर्ष में रोजगार की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की गई है। लेकिन इस स्थिति में सुधार के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर इकोनॉमिस्ट्स ने जोर दिया है जिनसे रोजगार के मोर्चे पर स्थितियां बदल सकती हैं। इनमें बिजनेस करने की लागत, रेगुलेटरी और लेबर रिफॉर्म्स तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा शामिल है। देश की जीडीपी की संभावनाओं का पूरा फायदा उठाने का रोडमैप भी सर्वे में हिस्सा लेने वाले इकोनॉमिस्ट्स ने दिया है। इनका मानना है कि तेज रफ्तार इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कृषि को बढ़ावा देना होगा, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करनी होगी, मार्केट से संबंधित सुधारों को तेज करना होगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के नए सोर्स तलाशने होंगे। चालू वित्त वर्ष में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 2.2 परसेंट के ग्रोथ रेट का अनुमान सर्वे में लगाया गया है।

फिक्की के मुताबिक इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रतीकात्मक

केंद्र के बफर स्टॉक से प्याज उठाएं राज्य : पासवान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सेंट्रल बफर स्टॉक में 50 हजार टन से अधिक प्याज
- दिल्ली, चंडीगढ़ व बनारस में 40-45 रुपये प्रति किलो बिक रहा प्याज

प्याज के बढ़ते भाव पर काबू पाने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों से सेंट्रल बफर स्टॉक से प्याज उठाने को कहा है। दिल्ली, चंडीगढ़ और बनारस समेत देश के विभिन्न हिस्सों में प्याज के मूल्य में तेजी का रुख है। केंद्र के बफर में 50 हजार टन से अधिक प्याज का स्टॉक है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि फिलहाल किसी राज्य सरकार ने प्याज उठाने की पहल नहीं की है।

बाजार के जानकारों के मुताबिक प्याज के उत्पादक राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात में बाढ़ की वजह से फसल को काफी नुकसान होने की आशंका है। इसे देखते हुए बाजार में जमाखोर सक्रिय हो गए हैं। उन पर काबू पाने के लिए सरकार ने प्याज की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के मूल्य निगरानी प्रणाली के मुताबिक सोमवार को विभिन्न खुदरा बाजारों में प्याज का मूल्य 40 से 45 रुपये प्रति किलो तक रहा है। सोमवार को चंडीगढ़ में 45 रुपये, राजधानी दिल्ली में 42 रुपये और बनारस समेत आधा दर्जन शहरों में 40 रुपये किलो बिका है।

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए अंतर मंत्रालयी बैठक बुलाई थी, जिसमें खाद्य, उपभोक्ता के साथ कृषि और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पासवान ने बताया कि समीक्षा के दौरान दाल, खाद्य तेल और प्याज की कीमतों के साथ आपूर्ति का ब्योरा लिया। राजधानी दिल्ली में मदर डेयरी और नैफेड के मार्फत प्याज 23.90 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचने का फैसला लिया गया है। हालांकि मदर डेयरी पहले से ही इस भाव पर प्याज बेच रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र विभिन्न जिंसों की मांग व आपूर्ति की स्थितियों पर नजर बनाए हुए है।

फाइल

राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में मिलेगी मदद

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

चालू वित्त वर्ष में आरबीआइ से रिकॉर्ड सरप्लस मिलने से सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाये रखने में मदद मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने भारी भरकम 19,77,693 करोड़ रुपये रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य रखा है लेकिन अप्रैल से जून तक पहली तिमाही में इसमें से मात्र 2,84,886 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं जो लक्ष्य का मात्र 14.4 परसेंट है। खास बात यह है कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में लक्ष्य के मुकाबले 15.5 परसेंट रेवेन्यू का लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 3.3 परसेंट पर रखने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इकोनॉमी के कई क्षेत्रों में सुस्ती के चलते टैक्स रेवेन्यू में अपेक्षित वृद्धि न होने के चलते इस लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था ऐसे में अब आरबीआइ से रिकॉर्ड सरप्लस मिलने से सरकार के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि आरबीआइ ने सरकार से परामर्श के बाद इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा करने को पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था।

सोना 40 हजारी होने के करीब, चांदी 1,450 रुपये उछलकर 46,500 रुपये के पार

- 675 रुपये चढ़कर 39,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोने का भाव
- 1,450 रुपये के उछाल के साथ 46,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : संकेत घरेलू बाजार से मिल रहे हों या विदेशी बाजारों से, पिछले कुछ कारोबारी सत्रों के दौरान निवेशकों ने सोना-चांदी पर खूब दांव खेला है। दोनों बहुमूल्य धातुओं में सोमवार को जमकर खरीदारी हुई, जिसके चलते दिन के कारोबार में सोना 675 रुपये चढ़कर 39,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर जा पहुंचा। चांदी में भी 1,450 रुपये का उछाल दर्ज किया गया और कारोबार के आखिर में यह 46,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी रिसर्च हैड हरीश वी. ने कहा कि ग्लोबल मार्केट में सोना छह वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले सप्ताह अमेरिका और चीन में ट्रेड वार जिस तरह से आगे बढ़ा, उसे देखते हुए भी निवेशकों ने सोने को निवेश के सुरक्षित ठिकाने के रूप में चुना। घरेलू बाजार में चांदी को सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाइयों का भरपूर साथ मिला।

न्यूयॉर्क में सोने का भाव जबर्दस्त उछाल के साथ 1,529 डॉलर, जबकि चांदी का भाव 17.68 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर पहुंच गया। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 39,670 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 39,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी का भाव 700 रुपये की मजबूती के साथ 29,500 रुपये पर जा पहुंचा। चांदी हाजिर 46,550 रुपये प्रति किलोग्राम के पिछले भाव पर स्थिर रही। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव 1,625 रुपये चढ़कर 45,291 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। चांदी के सिक्कों का भाव प्रति सैकड़ा 3,000 रुपये चढ़कर 94,000 रुपये खरीद और 95,000 रुपये बिक्री के स्तर जा पहुंचा।

विदेशी बाजारों में भी सोमवार को सोना दमकता रहा। फाइल

एलएनजी इंपोर्ट कांट्रैक्ट पर दोबारा हो सकता है मोलभाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सही समय पर एलएनजी इंपोर्ट से संबंधित समझौतों पर दोबारा मोलभाव कर सकता है। एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए प्रधान ने कहा कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं।

भारत हर साल कतर से 85 लाख टन एलएनजी इंपोर्ट करता है। यूएस से भी 58 लाख टन एलएनजी इंपोर्ट किया जाता है। फिलहाल भारत जिस दर पर एलएनजी खरीद रहा है, स्पॉट मार्केट में वही गैस आधे दामों पर उपलब्ध है। भारत कतर के साथ पहले भी लांग-टर्म इंपोर्ट कांट्रैक्ट पर दोबारा मोलभाव कर चुका है। 75 लाख टन एलएनजी के लिए हुए समझौते में भारत ने 8,000 करोड़ रुपये बचाए थे। इसके अलावा 2017 में एक्सॉन मोबील कॉर्प और गोरगोन एलएनजी के साथ हुए सौदों में भी दोबारा मोलभाव हो चुका है।

नजरिया

प्रगतिशील किसानों के सम्मेलन में तोमर ने उठाए सवाल, यह भी कहा – कृषि क्षेत्र में निवेश और सब्सिडी देने को सरकार प्रतिबद्ध

सब्सिडी की बैसाखी छोड़ें किसान : तोमर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि क्षेत्र में निवेश और किसानों को लगातार दी जा रही सब्सिडी को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रगतिशील किसानों के बीच यह मुद्दा उछालते हुए पूछा, 'क्या बगैर सरकारी मदद के आप जैसे किसान अपने बूते खड़े नहीं हो सकते हैं।' किसानों की यह प्रवृत्ति बनती जा रही है कि सब्सिडी तो उन्हें मिलेगी ही। तोमर सोमवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसानों के एक सम्मेलन में बोल रहे थे।

तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का जितना बड़ा निवेश खेती में है, किसी दूसरे क्षेत्र में इतना निवेश नहीं है। लेकिन इसका अपेक्षित नतीजा नहीं मिल पाता है। इतनी सब्सिडी देने के बावजूद उसका परिणाम खेती में नहीं दिख रहा है। विकास दर बढ़ाए नहीं बढ़ रही है। इन मुद्दों पर प्रगतिशील किसानों को गांव में अपने लोगों के बीच बैठकर विचार करने की जरूरत है।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा 'देश के छोटे किसान के लिए तो खेती जीवन-यापन का साधन है। लेकिन प्रगतिशील किसानों को एक बिना सब्सिडी वाली आत्मनिर्भर खेती का मॉडल पेश करना चाहिए।' हालांकि उन्होंने तुरंत जोर देकर कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से बातचीत करने के अंदाज में कहा 'खेती में इतना परिश्रम, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उत्पादन और किसान कर्मण पुरस्कार मिलने के बावजूद भी सरकार के सहयोग के बगैर किसान खड़े नहीं रह पाते।' फिर तो कुछ और करने की जरूरत है ताकि वे सरकार की मदद के बगैर खड़ा रह सकें। उन्होंने वैज्ञानिकों के सुझाए कुछ उपाय बताए, जिनमें फिशरीज, एनिमल हस्बैंडरी व हॉर्टिकल्चर प्रमुख हैं। किसान इन पर फोकस करें, तभी उनकी आमदनी भी दोगुनी हो सकती है।

कृषि मंत्री तोमर ने प्रगतिशील किसानों से आग्रह किया कि वे कृषि दूत बनकर खेती को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के एक हाथ के साथ किसान का दूसरा हाथ जुड़ना जरूरी है। इससे पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने एग्रीकल्चर लोन देने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने की जानकारी किसानों को दी। आइसीएआर के डायरेक्टर जनरल डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने किसानों की आमदनी बढ़ाने की रणनीति का ब्योरा दिया।

फिशरीज को किसानों की आमदनी बढ़ाने का बड़ा जरिया मान रही सरकार। फाइल

एमनेस्टी स्कीम के तहत 60 दिनों में होगा फैसला

- स्कीम अगले महीने शुरू होकर दिसंबर के अंत तक चलेगी
- छोटे करदाताओं को मुकदमों के बोझ से राहत देना है लक्ष्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा है कि इंपावर्ड कमेटी एमनेस्टी स्कीम के तहत टैक्स में राहत देने की घोषणा पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लेगी। सबका विश्वास-लिगेसी डिस्प्यूट स्कीम 2019, सितंबर से अगले चार महीनों के लिए लागू होगी। इस स्कीम के तहत लिगेसी सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज से संबंधित मामलों का निपटान किया जाएगा।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) ने बताया कि स्कीम इंटरेस्ट, पेनाल्टी और फाइन में पूरी तरह से छूट देगी। इसके अलावा यह स्कीम मुकदमे से बचाव भी करेगी। आवेदक को उसके मामले में फैसले की सूचना के सवाल पर सीबीआइसी ने बताया कि इंपावर्ड कमेटी 60 दिनों के भीतर किसी मामले में फैसला लेगी और आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फैसले के बारे में अवगत कराया जाएगा। यह स्कीम टैक्स देने वालों को बाकी पड़े टैक्स को चुकाने और इससे संबंधित विवादों से निपटने का अवसर देगी। इस समय 3.75 लाख करोड़ से अधिक रुपये सर्विस टैक्स और एक्साइज से संबंधित मुकदमों में फंसे हुए हैं। इस स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान की थी। इसका मुख्य मकसद छोटे टैक्स दाताओं को टैक्स से संबंधित मुकदमों के बोझ से मुक्ति दिलाना है।

प्रतीकात्मक

इसलिए बदलनी पड़ रही देशों को राजधानी

इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है। यह शहर धीरे-धीरे पानी में डूबता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि कुछ सालों में यह शहर डूब जाएगा। इसके अलावा यातायात की गंभीर समस्या भी दिन ब दिन और विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। इन चीजों को देखते हुए इंडोनेशिया बोर्नियो द्वीप को अपनी नई राजधानी बनाने की योजना बना रहा है। इंडोनेशिया इकलौता ऐसा देश नहीं है, जो अपनी राजधानी बदलने की योजना बना रहा है। इससे पहले भी कई देशों ने अपनी राजधानी बदली है। आइए आज उन देशों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी बदली...

कजाखस्तान

कजाखस्तान को 1991 में सोवियत संघ से आजादी मिली। उस समय देश की राजधानी अलमाटी थी। लेकिन इस शहर के साथ कई समस्याएं थीं। एक तो इसका विस्तार नहीं किया जा सकता था। दूसरी समस्या यह थी कि यह भूकंप के लिए संवेदनशील इलाका था और चीन की सीमा के करीब भी था। इसलिए कजाख सरकार अपनी राजधानी को 1997 में अलमाटी से 1,200 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित अस्ताना शहर ले गई। बाद में अस्ताना का नाम यहां सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव के नाम पर नूर सुल्तान रख दिया गया।

नाइजीरिया

नाइजीरिया का तटीय शहर लागोस साल 1914 में देश की राजधानी बना था। लेकिन यहां सब अनियोजित तरीके से चल रहा था। फिर साल 1976 में राष्ट्राध्यक्ष जनरल मुरतला आर मोहम्मद ने घोषणा की, कि अबुजा को देश की राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस स्थान को देश की राजधानी के तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि यहां हर धार्मिक और जातीय समूह के लोग रहते हैं। इसके अलावा ये शहर देश के केंद्र में भी पड़ता है। यहां निर्माण कार्य 1980 में शुरू हुआ और 12 दिसंबर, 1991 को अबुजा देश की नई राजधानी बनी।

म्यांमार

यांगून को रंगून भी कहा जाता है, जो 1948 से 6 नवंबर, 2005 तक म्यांमार की राजधानी रहा। देश के सैन्य शासकों ने राजधानी बदलने का फैसला लिया, जिसके बाद नेपीडॉ शहर को यहां की नई राजधानी बनाया गया। नई राजधानी केंद्रित और रणनीतिक रूप से अधिक सक्षम थी। लेकिन राजधानी बदलने का कोई औपचारिक कारण नहीं बताया गया।

बोलीविया

बोलीविया की दो राजधानी हैं सुक्रे और ला पाज। 1899 तक सुक्रे एकमात्र राजधानी थी। लेकिन गृह युद्ध के बाद संसद और सिविल सेवा बोलीविया के सबसे बड़े शहर ला पाज में स्थानांतरित हो गई, जबकि न्यायपालिका सुक्रे में बनी रही। सुक्रे शहर देश का केंद्र बिंदु है। ला पाज की दस लाख आबादी की तुलना में इसकी आबादी महज ढाई लाख ही है।

ब्राजील

रियो डी जेनेरो सालों तक ब्राजील की राजधानी रही है। लेकिन ये शहर बहुत भीड़भाड़ वाला है, यहां सरकारी भवन भी काफी दूरी पर थे और ट्रैफिक भी काफी रहता था। जिसके बाद सरकार ने नए शहर को राजधानी बनाने का फैसला लिया। ब्रासीलिया शहर आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सिटी प्लानर के चार साल के कड़े परिश्रम के बाद 21 अप्रैल, 1960 में बनकर तैयार हुआ और ब्राजील की नई राजधानी कहलाया।

पाकिस्तान को काली सूची से बचाने में जुटे इमरान

उठाया कदम ▶ एफएटीएफ के बिंदुओं पर अमल करने को बनाई समिति

इस्लामाबाद, आइएएनएस : आतंकी फंडिंग पर पाकिस्तान को काली सूची में डाले जाने के मंडरा रहे खतरे ने प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वह इस खतरे से बचने के प्रयास में जुट गए हैं। इसी कोशिश के तहत उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के सभी 27 बिंदुओं पर अमल करने के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है। अगर पाकिस्तान इन बिंदुओं पर खरा नहीं उतर पाता है तो एफएटीएफ की ओर से उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। ऐसे में पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी।

डॉन अखबार ने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के हवाले से बताया कि इस समिति को एफएटीएफ मसले पर राष्ट्रीय प्रयास को पटरी पर लाने का जिम्मा सौंपा गया है। आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अजहर के नेतृत्व में गठित की गई समिति में वित्त, विदेश और आतंरिक मामलों के सचिवों के साथ ही मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग से निपटने वाली सभी एजेंसियों के प्रमुखों को भी शामिल किया गया है। हालांकि एफएटीएफ की ओर से निर्धारित किए गए सभी बिंदुओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के पास अक्टूबर तक का ही वक्त है, लेकिन वह कुछ महीने की और मोहलत पाने का भी प्रयास कर रहा है।

निगरानी सूची में है पाकिस्तान : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून, 2018 में अपनी निगरानी यानी ग्रे सूची में डाला था और उसे इस साल अक्टूबर तक 27 बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा था। इन बिंदुओं पर अगर वह खरा नहीं उतर पाया तो उसे काली सूची में डाला जा सकता है। इस संबंध में एफएटीएफ की 13 से 18 अक्टूबर तक पेरिस में होने वाली बैठक में अंतिम फैसला होगा।

इमरान खान का फाइल फोटो। एपी

एपीजी ने काली सूची में डाला

इमरान ने यह उच्च स्तरीय समिति ऐसे समय गठित की है, जब हाल ही में एफएटीएफ से संबद्ध क्षेत्रीय एशिया-प्रशांत समूह (एपीजी) ने पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया। आस्ट्रेलिया में गत शुक्रवार को खत्म हुई इस समूह की बैठक में यह माना गया कि पाकिस्तान 40 मानकों में से 32 का पालन करने में विफल रहा है।

क्या है एफएटीएफ-एपीजी

जी-7 देशों की पहल पर 1989 में गठित एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है। गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 16 थी। 2016 में ये संख्या बढ़कर 37 हो गई। भारत भी इस संस्था का सदस्य देश है। शुरुआत में इसका मकसद मनी लॉड्रिंग पर रोक लगाना था, लेकिन 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों के बाद आतंकी संगठनों का वित्त पोषण भी इसकी निगरानी के दायरे में आ गया। एपीजी यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप इसकी क्षेत्रीय इकाई है। सुविधा के लिए इस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कई क्षेत्रीय इकाइयां भी गठित कर रखी है। इनमें आठ अन्य संस्थाएं प्रमुख हैं।

किन पर होती है कार्रवाई : एफएटीएफ दुनिया के उन देशों की दो सूची बनाती है जो मनी लॉड्रिंग और आतंकी संगठनों को मिलने वाले धन को रोकने या उसके खिलाफ कदम उठाने में पीछे रहते हैं। इस आशय की पहली सूची ग्रे और दूसरी ब्लैक होती है।

कैसे होगा पाक को नुकसान : अंतरराष्टीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक सहित वैश्विक वित्तीय संस्थाएं पाकिस्तान की साख को गिरा सकती हैं। इससे इसे कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। मूडी, एस एंड पी और फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां देश की रेटिंग गिरा सकती हैं।

कश्मीर पर पोस्ट के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति को ट्विटर का नोटिस

इस्लामाबाद, आइएएनएस : कश्मीर को लेकर दुनिया भर में दुष्प्रचार कर रहे पाकिस्तान की हालत वास्तव में बहुत दयनीय हो गई है। कश्मीर मुद्दे पर दुनिया के तमाम देशों से पाकिस्तान को दुत्कार तो मिली ही है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने तो कश्मीर पर पोस्ट को लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को ही नोटिस थमा दिया है। सोशल मीडिया कंपनी द्वारा किसी देश के राष्ट्रपति को नोटिस भेजने का शायद यह पहला मामला है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के मंत्री ने इसके लिए भी भारत सरकार को दोषी ठहराने की कोशिश की है।

आरिफ अल्वी ने शनिवार को विदेशी मीडिया के एक वीडियो को शेयर किया था। इसमें भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद कश्मीर के कथित हालात को दिखाया गया था। इस पर ट्विटर ने अल्वी को नोटिस भेज दिया, जिसमें सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि उनके अकाउंट पर कश्मीर के हालात को दर्शाने के संबंध में शिकायत मिली है।

राष्ट्रपति अल्वी को ट्विटर द्वारा भेजे नोटिस के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने कहा, 'ट्विटर ने मोदी सरकार का मुखपत्र बनने के लिए सारी हदें पार कर दी है! उसने हमारे राष्ट्रपति को नोटिस भेजा है! यह बहुत ही बुरा और हास्यास्पद है।' हालांकि, ट्विटर ने यह भी कहा है कि वह यह नहीं तय कर सका कि राष्ट्रपति के पोस्ट से किस कानून का उल्लंघन हुआ, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। वहीं, न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान के संचार मंत्री मुराद सईद ने कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने उन्हें भी नोटिस भेजकर कहा था कि उनके एक ट्वीट से भारतीय कानून का उल्लंघन हुआ। हाल के दिनों में सैकड़ों पाकिस्तानी यूजर यह शिकायत कर चुके हैं कि कश्मीरियों के समर्थन संबंधी पोस्ट करने पर उनके अकाउंट को निलंबित कर दिया गया।

हांगकांग के हालात हैं खतरनाक : पुलिस

हांगकांग में प्रत्यर्पण बिल का विरोध कर रहे उग्र प्रदर्शनकारियों पर पिस्टल ताने पुलिस अफसर। रायटर

- रविवार को देर रात तक जारी हिंसा में पहली गोली चली
- प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट, लाठीचार्ज और पानी की बौछार का इस्तेमाल

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में तीन महीने से चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया है और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। रविवार को अभी तक का सबसे भीषण टकराव हुआ और पहली बार पानी की बौछार छोड़ने के साथ ही एक हवाई फायर भी करना पड़ा। रविवार की हिंसा के सिलसिले में 86 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनमें सबसे कम उम्र का प्रदर्शनकारी 12 साल का है। यह जानकारी हांगकांग की पुलिस ने दी है। सोमवार को भी महानगर के कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प होने की खबर है।

हांगकांग के उपनगर सुएन वान में रविवार को लोकतंत्र के लिए आंदोलन चला रहे प्रदर्शनकारियों का पुलिस से टकराव हुआ था। पुलिस के अनुसार कई तरह के हथियारों से लैस भीड़ पथराव कर रही थी। इसी दौरान छह पिस्टलधारी अधिकारी भीड़ में फंस गए। इसके बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए हवा में एक गोली चलाई। इस गोली से कोई घायल नहीं हुआ। तीन महीने के आंदोलन में पुलिस की ओर से यह पहली गोली चली थी। यहां पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए 74 रबर बुलेट और आंसू गैस के 215 गोले चलाने पड़े। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देर रात तक जारी रहा था। पुलिस के अनुसार हिंसक प्रदर्शनकारी हांगकांग का माहौल खराब कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है।

लगातार 12 हफ्तों से जारी आंदोलन चीन सरकार के लिए हांगकांग में बीते 22 सालों की सबसे बड़ी चुनौती है। यह पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश 1997 में चीन के पास आया था। उसके बाद से कई बार ज्यादा अधिकारों के लिए आंदोलन हो चुके हैं लेकिन ताजा आंदोलन सबसे ज्यादा समय से जारी है।

इमरान ने कहा, हर मंच पर उठाएंगे कश्मीर मसला

- मोदी-ट्रंप मुलाकात के बाद राष्ट्र को किया संबोधित, परमाणु युद्ध की भी दी गीदड़ भभकी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : कश्मीर मसले पर दुनियाभर में अलग-थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देने पर उतर आया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा, 'क्या ये बड़े देश सिर्फ अपने आर्थिक हित ही देखते रहेंगे। उन्हें याद रखना चाहिए, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा। ये न सिर्फ इस क्षेत्र में कहर बरपाएगा बल्कि पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अब यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर निर्भर है।' हताशा में इमरान खान ने यहां तक कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत हर अंतरराष्ट्रीय फोरम पर कश्मीर मसले को उठाएंगे।

फ्रांस में जी-7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में इमरान खान ने पाकिस्तानी आवाम को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार तब तक कश्मीरियों के साथ खड़ी रहेगी जब तक भारत घाटी में से पाबंदियां नहीं हटा लेता। कश्मीर पर अपनी सरकार की रणनीति को रेखांकित करते हुए इमरान ने कहा, 'सबसे पहले तो मेरा यह मानना है कि पूरा देश कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने कहा है कि मैं कश्मीर के दूत के रूप में काम करूंगा।'

अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने प्रस्तावित संबोधन का जिक्र करते हुए इमरान ने कहा, 'मैं दुनिया को इस बारे में बताऊंगा। जिन राष्ट्राध्यक्षों के साथ मैं संपर्क में हूं उनके साथ मैंने यह विचार साझा किया है। मैं यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाऊंगा।' उन्होंने कहा, 'मैंने अखबारों में पढ़ा है कि लोग इस बात से निराश हैं कि मुस्लिम देश कश्मीर के साथ नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि निराश न हों। अगर कुछ देश अपने आर्थिक हितों के कारण इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, आखिर में वे भी इस मुद्दे को उठाएंगे। समय के साथ उन्हें यह करना ही होगा।' इमरान ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर 'ऐतिहासिक भूल' की है।'

युद्ध के लिए तैयार : कुरैशी : वहीं एएनआइ के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनका देश हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच लड़ाई से पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। जम्मू-कश्मीर से गैरकानूनी तरीके से अनुच्छेद 370 हटाकर भारत ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है।

ब्रिटिश एयरवेज की गलती से कई उड़ानें रद, यात्रियों में मचा हड़कंप

न्यूयॉर्क टाइम्स से

लंदन : ब्रिटिश एयरवेज की एक गलती ना सिर्फ हजारों यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी बल्कि खुद उसके लिए भी आफत बन गई। हुआ यह कि ब्रिटेन की इस विमानन कंपनी ने गत शुक्रवार को अपने यात्रियों को सूचित किया कि पायलटों की प्रस्तावित हड़ताल के चलते उनकी सितंबर की उड़ानें रद कर दी गई हैं। इस खबर से यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि कंपनी ने कुछ घंटे के अंदर ही यह साफकर दिया कि परवाह नहीं करें। कोई उड़ान रद नहीं हुई है। गलती से ऐसा हुआ है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एयरवेज के पास हजारों फोन कॉल और ट्वीट की बाढ़ गई। इससे निपटने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाना पड़ा।

महज 24 घंटे के अंदर ही करीब 38 हजार फोन कॉल और 33 हजार ट्वीट किए गए। इससे निपटने के लिए ब्रिटिश एयरवेज को जहां अपनी ट्विटर सर्विस टीम में 20 फीसद स्टाफ बढ़ाना पड़ा तो वहीं फोन पर लोगों से बात करने के लिए अतिरिक्त 70 कर्मचारी लगाने पड़े। कई यात्रियों ने गुस्से में कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा के लिए दूसरा विकल्प चुन लिया है। जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने जब स्थिति जानने के लिए फोन किया तो बात नहीं हो पाई। इसलिए उन्हें ट्विटर का सहारा लेना पड़ा। डीन वाल्टन नाम के एक यात्री ने ट्वीट में कहा, 'ब्रिटिश एयरवेज की शर्मनाक सेवा। अब वे ईमेल में कह रहे हैं कि फ्लाइट रद नहीं हुई है।' एयरलाइंस ने रविवार को एक बयान में कहा, 'हमें इसके लिए माफ कीजिए कि कुछ ग्राहकों को गलती से ऐसे ईमेल चले गए, जिसमें कहा था कि उनकी उड़ानें रद कर दी गई हैं। हमने महज कुछ घंटे के अंदर सभी ग्राहकों को ईमेल के जरिये स्पष्ट कर दिया कि उनकी उड़ानें पूर्व योजना अनुसार रवाना होंगी।'

अगस्त में दूसरी बार जूझे यात्री : ब्रिटिश एयरवेज के साथ अगस्त में यह दूसरा वाकया है, जब उसके यात्रियों को किसी गड़बड़ी के चलते जूझना पड़ा। इस माह के शुरू में कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया था, जिसके चलते हीथ्रो, गेटविक और लंदन सिटी एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा उड़ानें रद हुई थीं या विलंब से रवाना हुई थीं।

ट्विटर पर उड़ा ब्रिटिश एयरवेज का मजाक। फाइल

24 घंटे के अंदर किए गए 38 हजार फोन कॉल और 33 हजार ट्वीट

- एयरलाइंस ने बाद में कहा, कोई उड़ान रद नहीं हुई, गलती से हुआ ऐसा

अफगानिस्तान में तालिबान के नहीं रुकेंगे हमले

- लड़ाके बोले, समझौता अमेरिका से-अफगान सरकार से नहीं
- अफगानिस्तान में पिछले 18 साल से सक्रिय है तालिबान

काबुल, रायटर : अमेरिका और तालिबान अफगानिस्तान से विदेशी सुरक्षा बलों की सुरक्षित वापसी के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देने के करीब हैं लेकिन अफगान सुरक्षा बलों पर तालिबान के हमले रोकने पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही। सूत्रों के अनुसार अमेरिका समेत सभी विदेशी फौजों की सुरक्षित वापसी के लिए इसी हफ्ते समझौता हो सकता है। इसी के साथ अफगानिस्तान में पिछले 18 साल से युद्धरत अमेरिका का अभियान खत्म हो जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों और तालिबान के बीच कतर में एक साल से वार्ता चल रही है।

समझौते के तहत तालिबान जाती हुई विदेशी फौजों पर हमला नहीं करेगा। अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो की सेनाओं के अफगानिस्तान से जाने की तालिबान शुरू से मांग करता रहा है। अमेरिका की ओर से शामिल हो रहे वार्ताकार अफगानिस्तान की सरकार को भी वार्ता प्रक्रिया में शामिल करने के लिए तालिबान को मनाते रहे लेकिन चरमपंथी संगठन नहीं माना। तालिबान ने साफ कर दिया है कि अफगान सरकार के खिलाफ उसका संघर्ष जारी रहेगा और लड़कर हम अपना हक लेंगे। तालिबान के इस रुख के बाद अफगान अधिकारियों और अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों को अफगानिस्तान में फिर से गृहयुद्ध जैसी स्थितियां लौटने की आशंका सताने लगी है। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा के हमले के बाद अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था और वहां की तालिबान सत्ता को उखाड़ फेंका था। इसके बाद से अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार है।

तालिबान कमांडर ने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए बताया कि समझौते के अनुसार अमेरिकी फौज अफगानिस्तान की सरकारी सेना की कार्रवाई में मदद बंद कर देगी। तालिबान पर सीधे हमले बंद कर देगी। बदले में तालिबान मिलिटेंट भी अमेरिकी फौजों पर हमलों को विराम दे देंगे। समझौते के तहत अमेरिका अफगान सरकार को मदद देना भी बंद कर देगा। अमेरिकी वार्ताकार दल के नेता जलमे खलीलजाद ने इस तरह के दावों पर टिप्पणी करने से इन्कार किया है। उन्होंने ट्वीट कर साफ कर दिया है- अमेरिका तालिबान से समझौते के पहले अफगान सुरक्षा बलों का समर्थन कर रहा था, बाद में भी करेगा। अफगानिस्तान का भविष्य सभी संबद्ध पक्षों की आपसी वार्ता से तय होगा।

चीन को भरोसा

द्विपक्षीय वार्ता से ही हल होगा कश्मीर मसला

बीजिंग के प्रमुख थिंक टैंक की राय, भारत और पाकिस्तान को आपसी समझबूझ से निकालना होगा कश्मीर का समाधान

जयप्रकाश रंजन, बीजिंग

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से चीन अचंभित तो है, लेकिन वह अपने अभिन्न मित्र देश पाकिस्तान की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने को भी तैयार नहीं है। चीन की कूटनीति में अहम भूमिका निभाने वाले बीजिंग के प्रमुख थिंक टैंक मानते हैं कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान को आपसी समझबूझ से ही कश्मीर का समाधान निकालना होगा। हालांकि विदेश मंत्रालय से जुड़े ये थिंक टैंक अभी भी यह स्वीकार करने में हिचक रहे हैं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है।

चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डिप्टी डायरेक्टर लान जियांशू के मुताबिक, अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के कदम को हम हतप्रभ करने वाला इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके कारण यथास्थिति बदल गई। जब भी स्थिति बदलती है तो उसका असर होता है। यह स्थानीय लोगों की इच्छा का मामला है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र से भी जुड़ा है और भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय भी है। इसके बावजूद हम मानते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका गंभीर बातचीत से समाधान नहीं हो सके। चीन यह भी मानता है कि एक बड़े और संभावित सुपर पावर होने की वजह से भारत की विशेष जिम्मेदारी है कि वह उलझे हुए मुद्दों पर बातचीत कभी बंद न करे। उक्त सलाहकार के मुताबिक आतंकवाद पर भारत का पक्ष मजबूत है लिहाजा उसे वार्ता की मेज पर अपनी बात मनवाने का ज्यादा मौका मिलेगा। चीन पहले भी कहता रहा है कि कश्मीर मसले को भारत और पाकिस्तान मिलकर सुलझाएं।

सनद रहे कि इस महीने की शुरुआत में भारत सरकार ने जब अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया तो पाकिस्तान और चीन की पहल पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कश्मीर पर एक बंद कमरे में बैठक हुई थी। लेकिन इस पर कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। बैठक में अमेरिका, रूस और फ्रांस का रुख भारत के प्रति सकारात्मक था।

- पुलवामा हमले के बाद बिगड़ गए थे दोनों देशों के रिश्ते
- जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पाक यूएन जाने की कर रहा तैयारी

चीनी विशेषज्ञों को उम्मीद है कि यह मामला जल्द सुलझेगा। प्रतीकात्मक

चक्रवातों पर परमाणु बम गिराने का विचार नहीं : ट्रंप

- एक्सिअस की रिपोर्ट को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया हास्यास्पद

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सिअस की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि वह देश में आने वाले चक्रवातों पर देश के तट तक पहुंचने से पहले ही परमाणु बम गिराना चाहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट को 'हास्यास्पद' बताया है।

एक्सिअस नाम की समाचार वेबसाइट ने रविवार को कहा था कि एक बैठक में ट्रंप ने जानना चाहा कि क्या अफ्रीका के तट पर चक्रवात बनने की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए तूफान पर ही परमाणु बम गिराया जा सकता है। एक अज्ञात सूत्र ने बताया कि बैठक में शामिल हुए सदस्य यह कहते हुए बाहर निकले, 'हम इसका क्या करें?' वेबसाइट में हालांकि यह नहीं बताया गया है कि यह बातचीत कब हुई।

इस रिपोर्ट को लेकर ट्रंप ने मीडिया पर निशाना साधा और इसे 'फेक न्यूज (फर्जी खबर)' बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि एक्सिअस की यह खबर हास्यास्पद है कि राष्ट्रपति ट्रंप भीषण चक्रवातों के तट तक पहुंचने के पहले ही उस पर परमाणु बम गिराना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। खबर के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया लेकिन एक्सिअस ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि ट्रंप का 'मकसद बुरा नहीं है।' वेबसाइट ने कहा है कि राष्ट्रपति ने 2017 में भी इस प्रकार का सुझाव दिया था।

चक्रवातों पर बम गिराने का विचार नया नहीं है। इससे पहले 1950 के दशक में राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहोवर के कार्यकाल में एक सरकारी वैज्ञानिक ने यह सलाह दी थी। हालांकि इस विचार पर वैज्ञानिक पहले भी असहमति जता चुके हैं। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी-7 सम्मेलन में भाग लेने फ्रांस पहुंचे थे। जहां विश्व के कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की।

मलेशिया के गृह मंत्री ने कहा, कानून से ऊपर नहीं है जाकिर नाईक

कुआलालंपुर, एएनआइ : विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक को मलेशिया में सार्वजनिक भाषण देने से प्रतिबंधित किए जाने के बाद गृह मंत्री तान श्री मुहयिद्दीन ने कहा है कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि इस्लामिक प्रचारक के बयान से असुविधा पैदा हुई है। यही कारण है कि न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है। मलय टाइम्स में छपी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

हाल ही में खुद की वापसी के आह्वान के जवाब में नाईक ने 'बेरसामा डॉ. जाकिर नाईक से विशेष वार्ता' के दौरान मलेशिया के चीनी नागरिकों से वापस जाने को कहा था। उसने कहा था कि सबसे पहले तो वे ही इस देश के पुराने अतिथि हैं। मलेशिया में हिंदुओं की तुलना भारतीय मुस्लिमों से करने की कई पार्टियों ने निंदा की थी। उसने कहा था कि यहां के हिंदूओं को भारत के मुस्लिमों की तुलना में 100 फीसद से ज्यादा अधिकार हासिल हैं। भारत में वांछित नाईक को मलेशिया की पूर्व सरकार द्वारा स्थायी निवास दिया गया है।

रहाणे के शतक के बाद बुमराह ने कहर बरपाया

भारत 318 रन से जीता, कैरेबियाई टीम पर दर्ज की सबसे बड़ी जीत, वेस्टइंडीज 100 रन पर ढेर

नॉर्थ साउंड (एंटीगा), प्रेट्र : जसप्रीत बुमराह की अगुआई में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और अजिंक्य रहाणे के करीब दो साल बाद पहले टेस्ट शतक की मदद से भारत ने मेजबान वेस्टइंडीज को एंटीगा के नॉर्थ साउंड में सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में 318 रन से हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जीत के साथ शुरुआत की। यह भारत की वेस्टइंडीज के खिलाफ रन अंतर से सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ भारत को 60 अंक मिले, जबकि वेस्टइंडीज को कोई अंक नहीं मिला।

रहाणे ने धैर्य भरी पारी खेलते हुए 102 रन बनाए, लेकिन युवा बल्लेबाज हनुमा विहारी (93) अपने पहले टेस्ट शतक से सिर्फ सात रन से चूक गए। उनके आउट होने के साथ ही भारत ने अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 343 रन बनाकर घोषित कर दी, जिससे वेस्टइंडीज को जीत के लिए 419 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आठ ओवर में चार मेडन रखते हुए सात रन देकर पांच विकेट झटके, जिसके चलते कैरेबियाई टीम दूसरी पारी में 26.5 ओवर के खेल में सिर्फ 100 रन पर ढेर हो गई। यह वेस्टइंडीज का भारत के खिलाफ न्यूनतम टेस्ट स्कोर है। उनके अलावा इशांत शर्मा ने तीन और मुहम्मद शमी ने दो विकेट हासिल किए। वेस्टइंडीज की ओर से नौवें नंबर के बल्लेबाज केमार रोच ने सर्वाधिक 38 रन बनाए।

मुश्किल लक्ष्य के सामने वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही, उसने चायकाल तक 15 रन तक ही अपने शुरुआती पांच विकेट गंवा दिए थे। बुमराह और इशांत के घातक गेंदबाजी स्पैल के सामने वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम की पोल खुल गई। बुमराह ने दोनों सलामी बल्लेबाजों क्रेग ब्रेथवेट (01) और जॉन कैंपबेल (07) को चलता किया और फिर डेरेन ब्रावो (02) का विकेट भी झटका। इस दौरान इशांत ने भी बुमराह का पूरा साथ निभाते हुए शमराह ब्रूक्स (02) और शिमरोन हेटमायर (01) को पवेलियन की राह दिखाई।

अजिंक्य रहाणे • एएफपी

चायकाल के बाद भी भारतीय गेंदबाजों का कहर जारी रहा। बुमराह ने शाई होप (02) और जेसन होल्डर (02) को बोल्ड कर पारी में अपने पांच विकेट पूरे किए, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर सात विकेट पर 37 रन हो गया। शमी ने एक ही ओवर में रोस्टन चेज (12) और शेनॉन गेब्रियल (00) को चलता कर स्कोर नौ विकेट पर 50 कर दिया। यहां से रोच और मिगुएल कमिंस (नाबाद 19) ने 10वें विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी कर वेस्टइंडीज के स्कोर को तीन अंकों में पहुंचा दिया। 100 रन के टीम स्कोर पर रोच को इशांत ने विकेट के पीछे रिषभ पंत के हाथों कैच कराकर भारत को शानदार जीत दिलाई।

इससे पहले चौथे दिन के खेल की शुरुआत में भारत ने कप्तान विराट कोहली (51) का विकेट जल्दी गंवा दिया। कोहली ने रहाणे के साथ तीसरे विकेट के लिए 106 रन जोड़े। इसके बाद रहाणे एवं विहारी ने पांचवें विकेट के लिए 135 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान रहाणे ने अपना टेस्ट शतक पूरा किया। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2017 में श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ते हुए 132 रन की पारी खेली थी। रहाणे ने 242 गेंदों का सामना किया और पांच चौके लगाए। गेब्रियल ने रहाणे को होल्डर के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। इसके बाद भारत ने रिषभ पंत (07) का विकेट सस्ते में गंवाया, जबकि विहारी ने अपने पांचवें टेस्ट में शतक जड़ने का सुनहरा मौका गंवा दिया। विहारी कप्तान होल्डर की गेंद पर पुल शॉट ठीक से नहीं खेल पाए और विकेट के पीछे शाई होप ने उनका कैच लपक लिया। उन्होंने 128 गेंदें खेलीं और 10 चौके व एक छक्का जड़ा।

इससे पहले मयंक अग्रवाल (16) भारत की दूसरी पारी में आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। उन्हें 14वें ओवर में चेज ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। टीवी रीप्ले में साफ नजर आ रहा था कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही है, लेकिन मयंक ने रिव्यू नहीं लिया। चेज ने केएल राहुल (38) को बोल्ड कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। वह स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में विकेट गंवा बैठे। राहुल ने दूसरे विकेट के लिए चेतेश्वर पुजारा (25) के साथ 43 रन जोड़े। एक ओवर बाद रोच ने पुजारा को चलता कर भारत का स्कोर तीन विकेट पर 81 रन कर दिया।

इससे पहले भारत ने इशांत शर्मा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज को पहली पारी में 74.2 में 222 रन पर समेट दिया था। इशांत ने 43 रन देकर पांच विकेट झटके, जबकि उनके अलावा मुहम्मद शमी और बायें हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा ने दो-दो विकेट हासिल किए।

50 से ज्यादा रन रहाणे ने दोनों पारियों में अपने टेस्ट करियर में चौथी बार बनाए। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन, इंग्लैंड के खिलाफ साउथैंप्टन और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिल्ली में ऐसा कर चुके हैं

93 रन पर हनुमा आउट हुए। वह 2002 में राहुल द्रविड़ के 91 रनों पर आउट होने के बाद कैरेबियाई सरजमीं पर नर्वस नाइंटीज में आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने

100 वीं अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की भारत ने कोहली की कप्तानी में। भारतीय कप्तानों में सिर्फ धौनी और मुहम्मद अजहरुद्दीन ही इस मामले में उनसे आगे हैं

08 शतकीय साझेदारी भारतीय कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट क्रिकेट में की हैं। ये किसी भी भारतीय जोड़ी की टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियां हैं

100 रन वेस्टइंडीज का भारतीय टीम के खिलाफ न्यूनतम टेस्ट स्कोर है। इससे पहले वह 2006 में किंगस्टन में 103 रन पर ढेर हुई थी

स्कोर बोर्ड

टॉस : वेस्टइंडीज (गेंदबाजी)/ **भारत पहली पारी :** 297 (96.4 ओवर)/ **वेस्टइंडीज पहली पारी :** 222 (74.2 ओवर)/ **भारत दूसरी पारी :** 343/7 घोषित (112.3 ओवर)
परिणाम : भारत 318 रनों से जीता **मैन ऑफ द मैच :** अजिंक्य रहाणे

वेस्टइंडीज दूसरी पारी 100 (26.5 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
क्रेग ब्रेथवेट का. पंत बो. बुमराह	01	04	00	00
जॉन कैंपबेल बो. बुमराह	07	15	01	00
शमराह ब्रूक्स एलबीडब्ल्यू बो. इशांत	02	05	00	00
डेरेन ब्रावो बो. बुमराह	02	10	00	00
हेटमायर का. रहाणे बो. इशांत	01	12	00	00
रोस्टन चेज बो. शमी	12	29	01	00
शाई होप बो. बुमराह	02	11	00	00
जेसन होल्डर बो. बुमराह	08	19	01	00
केमार रोच का. पंत बो. इशांत	38	31	01	05
शेनॉन गेब्रियल का. पंत बो. शमी	00	04	00	00
मिगुएल कमिंस नाबाद	19	22	02	01

अतिरिक्त : (लेबा-7, नोबॉ-1) 8, **कुल :** 26.5 ओवर में

100 रनों पर सभी आउट
विकेट पतन : 1-7 (ब्रेथवेट, 1.4), 2-10 (कैंपबेल, 3.5), 3-10 (ब्रूक्स, 4.1), 4-13 (हेटमायर, 6.6), 5-15 (ब्रावो, 7.3), 6-27 (होप, 11.1), 7-37 (होल्डर, 15.2), 8-50 (रोस्टन, 19.2), 9-50 (गेब्रियल, 19.6)
गेंदबाजी :
इशांत शर्मा 9.5-1-31-3
जसप्रीत बुमराह 8-4-7-5
रवींद्र जडेजा 4-0-42-0
मुहम्मद शमी 5-3-13-2

भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत

रन	बनाम	जगह	वर्ष	कप्तान
337	द. अफ्रीका	दिल्ली	2015	कोहली
321	न्यूजीलैंड	इंदौर	2016	कोहली
320	ऑस्ट्रेलिया	मोहाली	2008	धौनी
318	वेस्टइंडीज	एंटीगा	2019	कोहली
304	श्रीलंका	गॉल	2017	कोहली

12 वीं जीत घर के बाहर दर्ज की बतौर कप्तान विराट ने। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को पछाड़ा। इसके अलावा 27 टेस्ट कोहली ने बतौर कप्तान जीते। उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान धौनी की बराबरी की। धौनी ने 60 मैचों में तो कोहली ने मात्र 47 मैच में यह उपलब्धि हासिल की

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका

टीम	मैच	जीत	हार	ड्रॉ	अंक
भारत	1	1	0	0	60
न्यूजीलैंड	2	1	1	0	60
श्रीलंका	2	1	1	0	60
ऑस्ट्रेलिया	3	1	1	1	32
इंग्लैंड	3	1	1	1	32
वेस्टइंडीज	1	0	1	0	00

जसप्रीत जैसा कोई नहीं

एंटीगा, प्रेट्र : भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो उनसे पहले कोई एशियाई गेंदबाज हासिल नहीं कर सका था। वह दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज में टेस्ट की एक पारी में पांच विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने इन चार देशों का पहली बार दौरा किया और अपने पहले दौरे पर ही वहां उन्होंने टेस्ट में एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट ले लिए। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट का विश्व रिकॉर्ड रखने वाले श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन हों या भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले लेग स्पिनर अनिल कुंबले या फिर दिग्गज पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वसीम अकरम और वकार युनूस हों या फिर कोई और गेंदबाज, कोई भी बुमराह से पहले हासिल नहीं कर सका है।

जसप्रीत बुमराह • एएफपी

बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में मात्र सात रन देकर पांच विकेट चटकाए। बुमराह ने मैच के बाद कहा कि अच्छा लग रहा है और हमने एक गेंदबाजी इकाई के रूप में दबाव बनाया जो अच्छा था। हमने अपने फायदे के लिए हवा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ड्यूक की गेंद से इंग्लैंड में खेलने से मुझे काफी मदद मिली थी। इससे मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। मैं हमेशा एक गेंदबाज के रूप में विकसित होने और नई चीजें करने की कोशिश करता हूं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच शुक्रवार से किंग्सटन के सबीना पार्क में खेला जाएगा।

उपलब्धि
- द. अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, विंडीज में लिए पारी में पांच विकेट
- इन चार देशों में पांच विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने

> बुमराह, इशांत और शमी बढ़िया गेंदबाजी ग्रुप के तौर पर सामने आए हैं। हम अपने गेंदबाजी संयोजन से खुश हैं। यह संयोजन इसी आधार पर है कि कौन से खिलाड़ी एक से ज्यादा कौशल दिखा सकते हैं। यह सब टीम चयन पर हमेशा ही विचार में रखे जाते रहेंगे।
> **विराट कोहली,** भारतीय कप्तान

> बुमराह पहली पारी में अपने प्रदर्शन से निराश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने स्तर के मुताबिक गेंदबाजी नहीं की। दूसरी पारी में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। वह चैंपियन गेंदबाज हैं। हमने बीते छह महीनों से टेस्ट नहीं खेला है, इसलिए वह पहली पारी में लय हासिल नहीं कर पाए थे।
> **हनुमा विहारी,** भारतीय बल्लेबाज

बुमराह एंड कंपनी ने भारत को बनाया विश्व विजयी : सहवाग

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को लगता है कि जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ने भारत को विश्व पटल पर विजयी रथ पर सवार करने और टेस्ट में नंबर-एक टीम बनाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 318 रनों से हरा दिया। इस मैच की पहली पारी में जहां इशांत शर्मा ने पांच विकेट अपने नाम किए तो दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने सात रन देकर पांच विकेट लिए। सहवाग ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले अच्छे गेंदबाज नहीं थे। जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, आशीष नेहरा जैसे गेंदबाज मेरे समय में थे। जसप्रीत बुमराह, मुहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव जैसे गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करते देख खुशी होती है। यह लोग जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं वो शानदार है। इनके रहने से हमारे पास एक बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण है। एक ओर जहां भारत ने विंडीज को बड़ी हार सौंपी तो दूसरी तरफ लीड्स में एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीन इंग्लैंड को दे दी। अपने समय में तूफानी बल्लेबाजों में शुमार सहवाग के दिल में टेस्ट क्रिकेट के लिए खास जगह है। उनका मानना है कि स्टोक्स जैसे प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट चैंपियनशिप का सही प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप सही समय पर आई है, ऐसा मुझे लगता है। जब इस तरह के शानदार मैच होते हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप का होना अच्छा है। यह टेस्ट खेलने वालों के लिए बेहतरीन चीज है और इससे प्रारूप और ज्यादा रोचक तथा प्रतिस्पर्धी बन गया है।

न्यूजीलैंड ने बराबर की सीरीज

कोलंबो, एएफपी : न्यूजीलैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मेजबान श्रीलंका को यहां बारिश और खराब रोशनी से प्रभावित दूसरे टेस्ट मैच में हराकर दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर करने में सफलता हासिल की।

पांचवें दिन ट्रेंट बोल्ट की एक शॉर्ट गेंद पर केन विलियमसन ने गली में जैसे ही लसिथ एमबुलडेनिया का कैच लपका तो कीवी टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। जिस समय न्यूजीलैंड की टीम ने जीत दर्ज की तब सिर्फ मैच में एक घंटे का समय बचा था।

न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी छह विकेट पर 431 रन बनाकर घोषित करते हुए पहली पारी के आधार पर 185 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद पहली पारी 244 रन आउट होने वाली श्रीलंकाई टीम को दूसरी पारी में सिर्फ 122 रन पर ढेर कर यह टेस्ट एक पारी और 65 रन से अपने नाम कर लिया। जब आखिरी विकेट के रूप में एमबुलडेनिया आउट हुए तो उस समय करीब 19.4 ओवर बाकी बचे थे। पहले चार दिन खेल बुरी तरह से बारिश, नम मैदान और खराब रोशनी से प्रभावित रहा था, लेकिन आखिरी दिन 30 मिनट देर से खेल शुरू होने के बावजूद मौसम साफ रहा। भोजनकाल से पहले श्रीलंका ने 32 रन पर पांच विकेट गंवा दिए इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला ने जबर्दस्त संघर्ष करते हुए मैच को ड्रॉ कराने की उम्मीद जगाए रखी। डिकवेला बायें हाथ की अंगुली में कट लगने की वजह से विकेटकीपिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने करीब साढ़े तीन घंटे तक बल्लेबाजी करते हुए 51 रन की पारी खेली। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 13वां अर्धशतक है। कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने 21 रन की पारी खेली, जो इस पारी में किसी भी दूसरा सर्वाधिक स्कोर रहा। सुरंगा लकमल और डिकवेला ने करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी की, लेकिन यह साझेदारी तब टूट गई जब चाय के बाद विलियम समरविले की गेंद पर लकमल करीब में फील्डिंग कर रहे टॉम लाथम को विकेट के पास कैच दे बैठे। जल्द ही श्रीलंका ने डिकवेला का विकेट गंवा दिया, जो स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में एजाज पटेल की गेंद पर लाथम को कैच दे बैठे।

मुकाबला
- दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को पारी व 65 रन से हराया
- दूसरी पारी में 122 रन पर ढेर हुई श्रीलंकाई टीम

जीत के बाद कोहली ने टीम को सराहा

एंटीगा, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज पर मिली 318 रनों की विशाल जीत के बाद पूरी टीम की जमकर सराहना की।

कोहली ने इस रिकॉर्ड जीत के बाद कहा कि जिंक्स (अजिंक्य रहाणे), लोकेश राहुल दोनों ने दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी की। हनुमा विहारी ने भी अच्छा साथ दिया। हमें मैच में तीन-चार बार वापसी करनी पड़ी। खिलाड़ियों का भार प्रबंध करना हमारे लिए बहुत अहम है, इसीलिए बुमराह विश्व कप के बाद सफेद गेंद क्रिकेट नहीं खेले। हम चाहते थे कि वह इस टेस्ट सीरीज में तरोताजा होकर मैदान पर आएं, वह हमारे लिए टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खास खिलाड़ी हैं। यह एक जिम्मेदारी है जिसे मैं पूरी कर रहा हूं और यह खुशकिस्मती है कि मैं टीम में एक से ज्यादा जिम्मेदारी में योगदान दे पा रहा हूं।

उन्होंने कहा कि टीम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं फैसले लेता हूं लेकिन उन्हें लागू करना होता है। हम पर दबाव रहेगा और हमें और मजबूत होने की जरूरत है। हम एक दूसरे की सफलता का आनंद ले रहे हैं और यही अहम है। हमें इस मैच में हुई कमियों को दूर कर और मजबूत होने की जरूरत है।

बल्लेबाजों को आइना देखने की जरूरत : होल्डर

एंटीगा, एएफपी : भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने कहा है कि टीम के बल्लेबाजों को आइना देखने की जरूरत है। कप्तान टीम के बल्लेबाजों से काफी निराश हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बल्लेबाजों को इस तरह के प्रदर्शन के बाद गंभीरता से आइना देखने की जरूरत है। विंडीज के बल्लेबाज भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। बुमराह ने सात रन देकर पांच विकेट लिए। होल्डर ने बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि आज उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह खतरनाक हैं। उन्होंने कुछ शानदार गेंदें फेंकी। कुछ बेहतरीन गेंदों पर उन्होंने हमारे बल्लेबाजों को आउट किया। वे बेशक दमदार गेंदबाज हैं लेकिन निश्चित तौर पर हमें उनका तोड़ ढूंढ़ने की जरूरत है। होल्डर ने कहा कि हमारे बल्लेबाज इस मैच में अच्छा नहीं कर सके। मुझे लगता है कि विकेट बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी थी। नई गेंद से शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। एक बल्लेबाज के तौर पर उस समय आपको परेशानी हो सकती थी, लेकिन बाद में इस पर बल्लेबाजी करना आसान हो गया था।

शतक लगाकर अच्छा लग रहा है : रहाणे

एंटीगा, प्रेट्र : वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले भारतीय टीम के उप कप्तान अंजिक्य रहाणे ने अपने इस सैंकड़े को विशेष बताया है। रहाणे ने 17 टेस्ट मैच के बाद खेल के सबसे लंबे प्रारुप में शतक जमाया है। अपनी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए रहाणे ने कहा कि मैं काफी विशेष महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारे लिए पहली पारी काफी अहम थी। मेरे और लोकेश राहुल के बीच में हुई साझेदारी ने अच्छा काम किया। इससे पहले मैं हैंपशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहा था जिससे मुझे मदद मिली। रहाणे ने अपने पुरस्कार को अपने समर्थकों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पिछले तकरीबन दो साल में जिन लोगों ने मेरा समर्थन किया मैं यह पुरस्कार उन्हें समर्पित करता हूं। विकेट काफी अच्छी थी। हम जानते थे कि अगर हम विकेट पर टिके रहे तो रन अपने आप आएंगे।

विहारी बोले, गेंदबाजी बेहतर करने पर ध्यान दे रहा हूं : वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 93 रनों की बेहतरीन पारी खेलने वाले हरफनमौला खिलाड़ी हनुमा विहारी ने कहा है कि वह अपने गेंदबाजी को बेहतर करने पर ध्यान दे रहे हैं। मैच के बाद विहारी ने कहा कि यह जरूरी है कि मेरी ऑफ स्पिन में सुधार हो। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि टीम के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि मैं इसी संयोजन के साथ टीम में फिट बैठता हूं। मैं लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुझे ज्यादा ओवर फेंकने को मिलें और मैं भविष्य में टीम के काम आ सकूं। विहारी ने 102 रन बनाने वाले रहाणे के साथ 135 रनों की साझेदारी की थी। इस साझेदारी के दम पर भारत ने विंडीज के सामने 419 रनों की चुनौती रखी। विहारी ने अपनी पारी के लिए रहाणे को भी श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही थी, उसे देखते हुए रहाणे ने मेरी मदद की, क्योंकि वह काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे।

द्रविड़ को 26 सितंबर को मुंबई में पेश होने को कहा गया

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीसीसीआइ के लोकपाल डीके जैन ने एनसीए प्रमुख राहुल द्रविड़ को उनके खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के आरोपों के संदर्भ में 26 सितंबर को मुंबई में पेश होने के लिए कहा है।

इस महीने के शुरू में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जैन ने मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की शिकायत मिलने पर द्रविड़ को लिखित में जवाब देने के लिए कहा था। गुप्ता की शिकायत के अनुसार द्रविड़ कथित तौर पर हितों के टकराव के दायरे में आते हैं क्योंकि वह राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के निदेशक होने के साथ इंडिया सीमेंट ग्रुप के उपाध्यक्ष भी हैं जो कि आइपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स की मालिक है। बीसीसीआइ संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक समय पर दो पदों पर नहीं रह सकता है। जैन ने पुष्टि की कि द्रविड़ को 26 सितंबर को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। बीसीसीआइ कर्मचारी मयंक पारिख भी हितों के टकराव के मामले का सामना कर रहे हैं और वह भी उसी दिन अपना पक्ष रखेंगे। पता चला है कि द्रविड़ ने अपने जवाब में खुद का बचाव किया है और कहा कि वह अपने नियोक्ता इंडिया सीमेंट से बिना वेतन के अवकाश पर हैं और उनका महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी वाली आइपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स से कोई लेना देना नहीं है।

द्रविड़ को नोटिस भेजा जाना सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों को पसंद नहीं आया था। इस पर गांगुली ने यह तक कह दिया था कि भगवान भारतीय क्रिकेट की मदद करे। अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने भी गांगुली का समर्थन किया था। गांगुली ने ट्वीट किया था, 'भारतीय क्रिकेट में एक नया चलन आया है, हितों का टकराव, खबरों में रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, भगवान भारतीय क्रिकेट की मदद करे, द्रविड़ को हितों के टकराव के मामले में बीसीसीआइ लोकपाल से नोटिस मिला है।'

हितों का टकराव
- बीसीसीआइ लोकपाल जैन ने राहुल को अपना पक्ष रखने को कहा
- एनसीए निदेशक व इंडिया सीमेंट ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं द्रविड़

ना हारना जरूरी, ना जीतना जरूरी, जिंदगी खेल है, खेलना जरूरी है : रिजिजू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल दिवस (29 अगस्त) पर फिट इंडिया मूवमेंट लांच करेंगे। प्रधानमंत्री का लक्ष्य देश को फिट करना है और इसके लिए वह स्कूल, कॉलेज सभी वर्गों के लोगों को फिट रहने की शपथ भी दिलाएंगे। मोदी के इस मूवमेंट को लेकर खेल मंत्री किरण रिजिजू खुश हैं। उन्होंने कहा कि ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है, जिंदगी खेल है, खेलना जरूरी है। रिजिजू ने कहा कि यह मेरा फलसफा है। अभिषेक त्रिपाठी ने किरण रिजिजू से फिट इंडिया, एनडीटीएल पर प्रतिबंध सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। पेश हैं मुख्य अंश :

साक्षात्कार

- **फिट इंडिया मूवमेंट कितना महत्वपूर्ण है। इसका बजट क्या है?**

-देखिये फिट इंडिया कैंपेन हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मूवमेंट रहेगा। फिट इंडिया मूवमेंट यूनिवर्सल है। बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग, पुरुष, महिला, पैरा या नॉर्मल सभी को फिट रहना है। आदमी जब तक जीवित है सभी को फिट रहना चाहिए इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट एक यूनिवर्सल है। हर भारतीय को इसमें जुड़ना है। कभी-कभी हम अच्छा काम करते हैं और बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह हमारी फिटनेस के लिए कितना लाभदायक है। फिट रहना अनिवार्य है। यह कोई विकल्प नहीं है। हर इंसान को फिट होना ही चाहिए। दूसरी बात, हम भारत को महाशक्ति देश के रूप में देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक नए भारत के रूप में ले जाना चाहते हैं। तो एक मजबूत सशक्त भारत बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि हर भारतीय को फिट रहना होगा। जब आप शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं रहोगे तो देश कैसे फिट रहेगा इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री 29 अगस्त को हमारे खेल दिवस पर लांच करने जा रहे हैं। भारत के करोड़ों लोग इसमें जुड़ेंगे। इसके बाद पूरे देश में एक माहौल बनेगा। आम लोग, कॉर्पोरेट, दूर दराज गांव के लोग, स्कूल, कॉलेज, सरकारी, प्राइवेट दफ्तर हर जगह फिटनेस का माहौल बनना चाहिए। जब हर भारतीय फिट होगा तो इंडिया अपने आप फिट हो जाएगा।

- **इसके पीछे किसकी प्रेरणा थी? इसका भविष्य क्या है?**

-मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरा भारत फिट रहे। बजट कोई समस्या नहीं है। हर किसी को अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए। आरामदायक जिंदगी के साथ फिटनेस भी जरूरी है। फिटनेस के लिए नए आधारभूत ढांचे आपके लिए हैं। आप जिम जाकर अपनी फिटनेस पर काम कर सकते हैं। आप बिना किसी ढांचे के भी फिट हो सकते हैं। पैदल चलकर, सीढ़ियों पर ऊपर-नीचे उतरकर-चढ़कर भी फिट हो रहा जा सकता है। आप किसी खेल में हिस्सा लेकर, प्रतिदिन 30 मिनट योगा करके भी फिट हो सकते हैं। इसके लिए बजट की जरूरत नहीं है।

- **आप खुद फिट रहने के लिए क्या करते हैं?**

-मैं दिन में 16-17 घंटे मंत्रालय और अन्य गतिविधियों से जुड़ा रहता हूं। इस बीच जब भी 30 या 40 मिनट का समय मिल जाता है तो जॉगिंग या योगा कर लेता हूं। कहीं कोई खेलता हुआ मिल गया तो खेल लेता हूं। मैं जब स्कूल में रहा तो एथलीट था। जब गृहराज्य मंत्री था तो सिपाहियों के बीच में रहकर कुछ न कुछ गतिविधि करता रहता हूं। अब मैं देश का खेल मंत्री बन गया तो खिलाड़ियों से मिलता हूं। मेरा मंत्र है 'ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है, जिंदगी खेल है, खेलना जरूरी है। कुछ भी हारो, जीतो, आगे बढ़ो, कुछ भी करो जिंदगी एक खेल है और खेलना जरूरी है।'

- **खेलो इंडिया का तीसरा सत्र कहां होगा। यह पहले के मुकाबले कितना अलग होगा?**

-खेलो इंडिया गुवाहाटी में कराएंगे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत भी हो गई है। इस बार भी अच्छा होगा। यह बड़ा यूथ गेम होगा। पिछले दो सत्र भी खेलो इंडिया के अच्छे रहे थे। उन दोनों सत्रों से निकले बहुत सारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं।

- **अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों में अगर राष्ट्रीय खेल महासंघ का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो क्या खेल मंत्रालय भी उसका समर्थन करेगा?**

- मुझे नहीं पता है कि खेल महासंघों में क्या राजनीति चल रही है। अगर कोई भारतीय अंतरराष्ट्रीय खेल समितियों के लिए चुनाव लड़ता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। हमने भारतीय टेनिस संघ के लाइफ प्रेसिडेंट अनिल खन्ना को समर्थन देने का वादा किया है। हमारा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को अंतरराष्ट्रीय महासंघों में जाना चाहिए।

- **बीसीसीआइ सीईओ राहुल जौहरी ने खेल सचिव और नाडा को पत्र लिखकर पूछा है कि क्रिकेटरों के डोप टेस्ट का क्या होगा? क्या एनडीटीएल पर प्रतिबंध के बाद भी क्रिकेटरों के डोप टेस्ट किए जाएंगे?**

-जी बिलकुल नाडा तो है ही। वह डोप टेस्ट करेगी। क्रिकेट भी हमारा खेल है। नाडा क्रिकेटरों के सैंपल लेगी। हर किसी को नियमों का पालन करना है।

- **बीसीसीआइ ने आरटीआइ में आने से मना करते हुए कहा था कि वह राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) नहीं है। वह सरकार से पैसे नहीं लेती है?**

-सरकार का पैसा जनता का पैसा है, तो उनके बयान मायने नहीं रखता। बीसीसीआइ के पास धन कहां से आ रहा है। बीसीसीआइ का तर्क बिना किसी आधार के है। पैसा देश का है। खेल में पैसा सिर्फ लोगों के जरिये आता है। लोग टीवी देखते हैं, लोग टिकट और विज्ञापनों के लिए पैसा देते हैं तो यह लोगों का पैसा है। उन्हें सिर्फ लोगों से पैसा मिलता है। सभी महासंघों का पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्य करना महत्वपूर्ण है।

- **अंतरराष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने भारत की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। क्या आपको लगता है कि एनडीटीएल को पूरा बदलने की जरूरत है?**

-जी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अतिरिक्त फंड के लिए पत्र लिखा है जिससे एनडीटीएल को और बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। यह बहुत बड़ा फंड नहीं हैं। हमने तीन से चार करोड़ रुपये उनसे मांगे हैं जो जल्दी ही हमें मिल जाने चाहिए। हम फिर से लैब को तैयार करेंगे। जहां तक वाडा की बात है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल विवाद हैं। मैंने पहले भी कहा कि वाडा एनडीटीएल के स्तर को लेकर कुछ चिंतित है। हमने इसको लेकर कम समय में भी समाधान निकाल लिया था लेकिन उन्होंने उसे उस मसले पर प्रतिबंधित किया जिसका हम लगभग निकाल चुके थे।

- **पिछले साल इसको लेकर बहुत बातचीत हुई। खेल सचिव राधे श्याम जुलानिया ने एनडीटीएल की कुछ पदों की नियुक्तियों को रोक दिया था। यह भी वाडा के प्रतिबंध की एक बड़ी वजह थी। इस पर क्या कहेंगे?**

-यह हमारा आंतरिक मामला है। यह कोई विवाद नहीं है। इसको लेकर कदम उठाएंगे।

विजय अंतिम तीन काउंटी मैचों के लिए समरसेट से जुड़ेंगे

चेन्नई, प्रेट्र : भारतीय टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज मुरली विजय सत्र में अंतिम तीन काउंटी चैंपियनशिप मैचों में इंग्लैंड की काउंटी टीम समरसेट का हिस्सा होंगे। तमिलनाडु का यह सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान के अजहर अली की जगह लेगा। समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब ने कहा कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मुरली विजय सत्र के अंतिम तीन स्पेकसेवर्स काउंटी चैंपियनशिप मैचों के लिए विदेशी खिलाड़ी के रूप में क्लब से जुड़ रहे हैं।

बार्सिलोना की जीत में ग्रीजमैन ने दागे दो गोल

फुटबॉल डायरी ▶ बार्सिलोना ने ला लीगा के मैच में रीयल बेटिस को 5–2 से शिकस्त दी

ग्रीजमैन के अलावा पेरेज, अल्बा और विडाल ने एक-एक गोल दागे

मैड्रिड, एएफपी : बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग 'ला लीगा' में रीयल बेटिस की टीम को 5-2 से शिकस्त दी। टीम की इस जीत में उसके स्ट्राइकर एंटोनी ग्रीजमैन ने दो गोल दागे। ग्रीजमैन पर टीम के मुख्य स्ट्राइकर लियोन मेसी और लुइस सुआरेज की अनुपस्थित में गोल करने की जिम्मेदारी थी जिन्होंने इसे अच्छी तरह से निभाया। हालांकि, मेसी दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच देख रहे थे। मेसी पिंडली में चोट के चलते मैदान से बाहर हैं। ग्रीजमैन के अलावा बार्सिलोना के लिए कार्ल्स पेरेज, जोर्डी अल्बा, अर्तुरो विडाल ने भी एक-एक गोल किए। वहीं, रीयल बेटिस के नाबिल फेकिर और लोरेन मोरोन ने गोल किए, लेकिन वह सिर्फ हार का अंतर ही कम कर पाए।

बार्सिलोना के स्ट्राइकर एंटोनी ग्रीजमैन। (फाइल फोटो)

बराबरी पर रहा पहला हाफ : पिछले सप्ताह बार्सिलोना की टीम को एथलेटिक बिलबाओ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन, रीयल बेटिस के खिलाफ मैच में टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया। हालांकि, बार्सिलोना के मैनेजर ईर्नेस्टो वाल्वेर्ड की टीम के लिए शुरुआत खराब रही, क्योंकि 15वें मिनट में नाबिल ने गोल करके रीयल बेटिस का मैच में खाता खोला। इसके बाद 41वें मिनट में रोबर्टो ने एक अच्छा पास ग्रीजमैन को पेनाल्टी एरिया की तरफ दिया और फिर ग्रीजमैन ने गेंद को अपने बायें पैर से सीधे गोल पोस्ट में भेज दिया। इस तरह बार्सिलोना ने मैच में वापसी की। पहला हाफ 1-1 से बराबर रहा। दूसरे हाफ की शुरुआत के पांचवें मिनट में ग्रीजमैन ने बॉक्स के बायीं ओर से गेंद पर बायें पैर से किक लगाई और गेंद सीधा गोल पोस्ट पर चली गई जिन्हें गोलकीपर मार्टिन रोक नहीं पाए। बार्सिलोना मैच में 2-1 से आगे हो गया। इसके चार मिनट बाद ही पेरेज ने गोल कर अपनी टीम की बढ़त 3-1 से मजबूत कर दी। 60वें मिनट में अल्बा पीछे नहीं रहे और उन्होंने दो खिलाड़ियों को छकाकर टीम की बढ़त 4-1 कर दी। इसके 10 मिनट बाद ही विडाल ने बॉक्स के अंदर से गोल किया और टीम को 5-1 बढ़त दिला दी। यहां से बार्सिलोना का मैच गंवाना मुश्किल था लेकिन टीम 79वें मिनट में एक गोल खा बैठी। मोरोना ने बार्सिलोना के डिफेंस में सेंध लगाकर मैच का स्कोर 5-2 जरूर कर दिया लेकिन उनकी टीम जीत हासिल नहीं कर पाई। इस जीत के बाद बार्सिलोना तालिका में नौवें और रीयल बेटिस अंतिम 20वें स्थान पर हैं। बार्सिलोना की टीम को उम्मीद है कि मेसी अगले सप्ताह तक फिट हो जाएंगे, लेकिन सुआरेज व ओस्माने डेंबेले लंबे समय के लिए बाहर हैं।

दूसरे सबसे युवा फाटी : मैच के दौरान 21 वर्षीय पेरेज के गोल का आनंद दर्शकों ने खूब लिया। मैच में ईर्नेस्टो वाल्वेर्ड ने उनकी जगह स्थानापन्न खिलाड़ी 16 वर्षीय अनसुमाने फाटी को मैदान पर भेजा। फाटी 16 वर्ष की उम्र में क्लब की ओर से ली लीगा में खेलने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वाल्लेर्ड ने इस मैच में जोआओ फेलिक्स की जगह ग्रीजमैन को टीम में शामिल किया था।

ग्रीजमैन ने स्वीकार किया कि उन्होंने मैच में मेसी की तरह गोल करने, जबकि गोल का जश्न बनाने अमेरिकी बॉस्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स की तरह करने की कोशिश की। लेब्रोन हवा में उड़ने के अंदाज में जश्न मनाते हैं। ग्रीजमैन ने कहा, 'मैंने जैसे गोल किए हैं, मेसी इनका अभ्यास में करने की कोशिश करते हैं। मैं उनके तहर गोल करने की कोशिश की। मुझे लेब्रोन का जश्न मनाने का तरीका पसंद है इसलिए मैंने ऐसा करने की कोशिश की। पिछले मैच में हारने के बाद हम बड़ी जीत चाहते थे जो हमने रीयल बेटिस के खिलाफ किया।'

नवारो ने छीनी रीयल मैड्रिड से जीत : ला लीगा के अन्य मैचों में वलाडोलिड क्लब के सर्जिओ गॉर्डियोना नवारो ने रीयल मैड्रिड से जीत छीनते हुए मैच 1-1 से ड्रॉ करा दिया। पहला हाफ गोलरहित रहा।

भारत के मैच के टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के ओमान के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालीफायर के शुरुआती मैच के टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यह मैच चार सितंबर को गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेला जाएगा। टिकटों की कीमत 50, 100 और 200 रुपये रखी गई है। गुवाहाटी भारत के लिए भाग्यशाली मैदान रहा है। उसने यहां मार्च 2015 में नेपाल को 2–0 से और जून 2016 में लाओस को 6–1 से हराया था। भारतीय फुटबॉल टीम पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

स्टोक्स ने फ्राइड चिकन और चॉकलेट खाकर रचा इतिहास

एशेज डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : खेल जगत के लिए रविवार का दिन बेहद खास था। बैडमिंटन हो या फिर क्रिकेट का मैदान। रविवार को यहां जो भी होता दिख रहा था वह हैरतअंगेज और किसी क्लासिक सपने से कम नहीं था। एशेज में रोमांचित करने के लिए बेन स्टोक्स का क्लासिक शो रहा। इंग्लैंड को विश्व कप में ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले स्टोक्स ने रविवार को लीड्स के मैदान में हैरतअंगेज पारी खेलकर इंग्लैंड को ना सिर्फ हार के मुंह से बाहर निकाला, बल्कि एशेज सीरीज को भी 1-1 की बराबरी पर ला दिया।

स्टोक्स ने इस ऐतिहासिक पारी से पहले ऐसा क्या खा लिया, जिससे उन्हें इतनी ऊर्जा मिल गई कि उन्होंने हारी हुई बाजी को किसी फिल्मी अंदाज में जीत में बदल दिया। स्टोक्स ने इस ऐतिहासिक लम्हे से पहले जो खाया उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली तो शायद सपने में यह नहीं खाएंगे जो स्टोक्स ने इस पारी को खेलने से पहले वाली रात को खाया। इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत के बाद स्टोक्स से जब यह सवाल पूछा गया था यह सुनकर क्रिकेट खिलाड़ियों को ही नहीं इंग्लैंड टीम के डायटिशन भी हैरत में रह गए होंगे। क्रिकेटर इन दिनों फिटनेस के प्रति कुछ ज्यादा ही सावधान रहते हैं और वे फ्राइड और हाई कैलोरी फूड खाने से दूर ही रहते हैं। लेकिन स्टोक्स ने शनिवार की रात फ्राइड चिकन और चॉकलेट ही उड़ाई। स्टोक्स ने कहा कि बीती रात मैंने फ्राइड चिकन और चॉकलेट बार और कुछ किशमिश खाए थे। सुबह उठ कर एक-दो कॉफी पी ली। इसके बाद मैदान पर उतरकर स्टोक्स ने जो कमाल किया वह अब इतिहास है। स्टोक्स ने कहा कि पारी के दौरान मैं बस इतना जानता था कि अगर आज हार गए तो एशेज चली जाएगी।

बेन स्टोक्स (फाइल फोटो)

नायर ने जड़ा शतक, इंडिया रेड और इंडिया ब्लू का मैच ड्रॉ

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय टीम में वापसी की कोशिश कर रहे करुण नायर ने दूसरी पारी में नाबाद 166 रन बनाए, जिससे इंडिया रेड ने सोमवार को इंडिया ब्लू के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी के चार दिवसीय मैच को ड्रॉ कराया। इंडिया रेड ने चौथे और दिन छह विकेट पर 297 रन पर पारी घोषित की, जिसके बाद मैच को ड्रॉ करने पर सहमति बनी।

इस ड्रॉ मुकाबले के पहली पारी में बढ़त के आधार पर इंडिया रेड को तीन अंक मिले, जबकि इंडिया ब्लू को एक अंक से संतोष करना पड़ा। इंडिया रेड ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंडिया ब्लू ने 255 रन बनाए थे। इंडिया रेड ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 93 रन से की। पहली पारी में एक रन से शतक बनाने से चूकने वाले नायर ने दूसरी पारी में 223 गेंद में नाबाद रहते हुए 19 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 166 रन बनाए। नायर को पहली पारी में शतक लगाने वाले अंकित कलसी का अच्छा साथ मिला और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 157 रन की साझेदारी की। कलसी 160 गेंद में 64 रन बनाकर जलज सक्सेना (4/105) की गेंद पर बोल्ड हुए। सक्सेना इंडिया ब्लू के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उनके अलावा दिवेश पठानिया को दो सफलता मिलीं। इंडिया रेड का अगले मुकाबले में इंडिया ग्रीन से सामना होगा। इंडिया ग्रीन और इंडिया ब्लू के बीच खेला गया पहला मैच बारिश से धुल गया था।

करुण नायर। (फाइल फोटो)

'रोहित से सहानुभूति, लेकिन रहाणे खरे उतरे'

क्रिकेट डायरी

मुंबई, प्रेट्र : पूर्व क्रिकेटर प्रवीण आमरे की रोहित शर्मा के प्रति सहानुभूति है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें खुशी है कि उनका शिष्य अजिंक्य रहाणे वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा में पहले टेस्ट मैच में टीम प्रबंधन की उम्मीदों पर खरा उतरा। भारतीय टेस्ट उप कप्तान रहाणे ने इस टेस्ट में 81 और 102 रन बनाए। यह उनका पिछले दो साल में पहला शतक है।

टीम प्रबंधन इस मैच से पहले रोहित और रहाणे में किसी एक को चुनने को लेकर असमंजस में था, लेकिन बाद में उसने टेस्ट उप कप्तान पर भरोसा दिखाया। आमरे ने कहा कि मुझे रोहित से सहानुभूति है। मेरी निजी राय है कि रोहित को विश्व कप में पांच शतक बनाने के बाद मौका दिया जाना चाहिए था। हम सभी जानते हैं कि वह क्षमतावान खिलाड़ी हैं लेकिन टीम प्रबंधन ने अंजिक्य पर भरोसा दिखाया और वह उस पर खरा उतरे जो अजिंक्य के लिहाज से अहम है।

हांगकांग के खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध

दुबई, प्रेट्र : हांगकांग के खिलाड़ियों इरफान अहमद और नदीम अहमद पर मैच फिक्सिंग के आरोप में क्रिकेट से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि उनके साथी खिलाड़ी हसीब अमजद पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया है। सुनवाई के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की भ्रष्टाचार रोधी ट्रिब्यूनल ने साक्ष्य सुने जिनमें बताया गया कि तीनों खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किए या मैच फिक्स करने की साजिश की। इसके अलावा दो साल की अवधि में फिक्सरों द्वारा संपर्क किए जाने की सूचना भी नहीं दी। आइसीसी महाप्रबंधक (एसीयू) एलेक्स मार्शा ने कहा कि लंबी और पेचीदा जांच के बाद पाया गया कि इस दौरान अनुभवी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों ने मैच को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रयास किया।

मिस्बाह ने किया मुख्य कोच पद के लिए आवेदन

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के लिए आवेदन किया। मिस्बाह करीब पांच महीने पहले तक पेशेवर क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब वह टीम का मार्गदर्शन करते नजर आ सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, हितों के टकराव से बचने के लिए मिस्बाह ने बोर्ड क्रिकेट समिति से भी इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के सबसे सफल और लंबे समय तक टेस्ट कप्तान रहे मिस्बाह ने 2017 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। वह इसी साल मार्च में पाकिस्तान सुपर लीग टी–20 टूर्नामेंट में पेशावर जालमी के लिए खेले। 45 वर्षीय मिस्बाह ने कहा कि यह अच्छा लगा कि मेरा नाम टीम के भावी मुख्य कोच के तौर पर लिखा जा रहा था लेकिन मैंने यह फैसला सोमवार को लिया।

यह उनको जवाब है जिन्होंने मुझ पर सवाल उठाया : सिंधू

बासेल (स्विट्जरलैंड), प्रेट्र : पीवी सिंधू ने कहा कि पिछले दो विश्व चैंपियनशिप फाइनल में खिताब नहीं जीतने के कारण हो रही आलोचना से वह 'नाराज और दुखी' थीं और हाल में संपन्न विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उन आलोचकों को जवाब है जिन्होंने उन पर सवाल उठाया था। दो बार की रजत पदक विजेता सिंधू ने रविवार को पहली बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता।

जापान की नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ खिताबी जीत के बाद विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) की आधिकारिक वेबसाइट ने सिंधू के हवाले से कहा, 'यह मेरा उन लोगों को जवाब है जो बार-बार सवाल पूछ रहे थे। मैं सिर्फ अपने रैकेट से जवाब देना चाहती थी और इस जीत के साथ मैं ऐसा करने में सफल रही। पहले विश्व चैंपियनशिप फाइनल के बाद मुझे काफी बुरा लग रहा था और पिछले साल मैं नाराज थी, दुखी थी। मैं भावनाओं से गुजर रही थी, खुद से पूछ रही थी, सिंधू तुम यह एक मैच क्यों नहीं जीत पा रही हो? लेकिन, आज मैंने खुद से अपना स्वाभाविक खेल दिखाने और चिंता नहीं करने को कहा और यह काम कर गया।' हैदराबाद की 24 साल की सिंधू बेहद एकतरफा फाइनल में ओकुहारा को 21-7 21-7 से हराकर खिताब जीतने में सफल रहीं। सिंधू ने फाइनल में तीसरी बार खेलते हुए खिताब जीता। इससे पहले 2017 में उन्हें ओकुहारा और 2016 में ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन के खिलाफ हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। यह विश्व चैंपियनशिप में सिंधू का पांचवां पदक है। इससे पहले 2013 और 2014 में उन्होंने कांस्य पदक जीते थे। सिंधू विश्व चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में सर्वाधिक पदक जीतने के मामले में चीन की झेंग निंग के साथ शीर्ष पर हैं। निंग ने 2001 से 2007 के बीच एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक जीते थे।

विविध

एकेटीयू ने पांच हजार छात्रों का प्रवेश किया निरस्त

मनीष तिवारी, ग्रेटर नोएडा

▶ सत्र 2016–17 से लेकर 2018–19 तक प्रवेश किए गए निरस्त

▶ झारखंड स्टेट ओपन स्कूल की वैधानिक मान्यता न होने के कारण उठाया कदम

डा. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि ने झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर दाखिले लेने वाले छात्रों का प्रवेश निरस्त कर दिया है। प्रवेश सत्र 2016-17 से लेकर 2018-19 तक निरस्त किए गए हैं। झारखंड स्टेट ओपन स्कूल की वैधानिक मान्यता न होने के कारण विवि ने यह कदम उठाया है। निर्णय से विवि से संबद्ध प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले लगभग पांच हजार छात्रों का भविष्य अंधेरे में डूब गया है। छात्रों ने विवि के खिलाफ कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।

विवि से संबद्ध कॉलेजों में संचालित कोर्स में प्रदेश के साथ ही देश के दूसरे राज्यों के छात्र भी प्रवेश लेते हैं। विवि अपनी वेबसाइट पर उन शिक्षा बोर्डों की सूची देता है जिनकी वैधानिक मान्यता है। प्रवेश के वक्त कॉलेज प्रबंधन विवि की वेबसाइट पर उन बोर्डों की सूची देखकर ही छात्रों को प्रवेश देते हैं। विवि ने बिना जांचे-परखे झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची का नाम भी वेबसाइट पर अपनी सूची में डाल दिया था। जिसके आधार पर कॉलेजों ने वहां के छात्रों को प्रवेश दे दिया। जांच के बाद विवि को अब पता चला है कि झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची की वैधानिक मान्यता नहीं है। इसकी भनक विवि को इस सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व लग गई थी। इस कारण विवि ने कॉलेजों को निर्देश दिया था कि चालू सत्र में झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची के छात्रों को प्रवेश न दें। अब विवि ने आदेश जारी कर दिया है कि जिन-जिन कॉलेजों में झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाता है। विवि के इस आदेश से छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आदेश के बाद कॉलेजों ने छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो अंतिम वर्ष में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विवि के आदेश से छात्रों की वर्षों की मेहनत पर पानी फिरने के साथ ही लाखों रुपया भी बर्बाद हो गया है। अब सभी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। ऐसे में छात्र दूसरे कॉलेजों में प्रवेश भी नहीं ले सकते हैं।

विवि के खिलाफ संगठित होकर छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। विवि के वीसी विनय कुमार पाठक का कहना है कॉलेजों ने कहा था कि झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची के छात्र बड़ी संख्या में प्रवेश के लिए आ रहे हैं। उनकी मांग पर वेबसाइट पर झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची का नाम भी दर्ज कर दिया गया था। लंबे समय से चल रही जांच के बाद पाया गया है कि झारखंड स्टेट ओपन स्कूल रांची की वैधानिक मान्यता नहीं है। इस कारण प्रवेश निरस्त कर दिए हैं। इस सत्र में जिन छात्रों ने कॉलेज में फीस जमा की है, उनकी फीस वापस कराई जाएगी।

प्रवेश निरस्त किए जाने के बाद विवि के खिलाफ नाराजगी जताते छात्र। जागरण

गुजरात में भी योग बोर्ड गठित, बाबा रामदेव के करीबी बनाए गए अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : छत्तीसगढ़ व हरियाणा के बाद गुजरात की भाजपा सरकार ने भी योग बोर्ड का गठन कर दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी व भारत स्वाभिमान अभियान के गुजरात प्रभारी रहे शीशपाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

शीशपाल ने गांधीनगर में पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि बाबा ने योग को लेकर देश व दुनिया में अलख जगाई। सीएम विजय रूपाणी का आभार जताते हुए कहा कि वह योग के माध्यम से राज्य के युवाओं को नशा से मुक्त कर स्वस्थ, बलवान व चरित्रवान बनाएंगे। राजस्थान के अलवर में जन्मे शीशपाल लंबे समय से गुजरात में पतंजलि संस्था से जुड़े रहे हैं। उनका दावा है कि वह राज्य में 20 लाख युवाओं को योग प्रशिक्षण देते हुए हजारों को योग शिक्षक बना चुके हैं। राज्य में केंद्र के फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 29 अगस्त से होगी। युवा एवं खेल मंत्रालय के सचिव आरसी मीणा ने बताया कि गत शुक्रवार को पीए प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये फिट इंडिया अभियान के बारे में चर्चा कर चुके हैं।

फर्रुखाबाद में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला जीरो डिस्चार्ज ईटीपी

जीरो डिस्चार्ज ईटीपी पर 42 करोड़ की लागत का है अनुमान। (प्रतीकात्मक)

श्रीनारायण मिश्र, कानपुर

फर्रुखाबाद के टेक्सटाइल्स पार्क का गंदा पानी अब गंगा में नहीं जाएगा। यहां 42 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) बनाया जाएगा।

गंगा में प्रदूषित पानी जाने से रोकने के लिए फर्रुखाबाद में 34.11 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल्स पार्क बनाया जा रहा है। जहां शहर के सारे उद्योग शिफ्ट होंगे, जिनका पानी गंगा में जाता है। पहले चरण में पार्क में 50 उद्योगों को शिफ्ट करने की तैयारी है। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण परियोजना में सबसे खास है यहां बनने वाला ईटीपी। 1.6 एकड़ जमीन में बनने वाला यह ईटीपी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाला होगा। यह प्रतिदिन 1.5 मिलियन पानी का शोधन करेगा। यह पानी दोबारा उद्योगों को इस्तेमाल के लिए मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 42 करोड़ रुपये है। 32 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा से मिल रहा है जबकि दस करोड़ टेक्सटाइल पार्क के लिए बनी एसपीवी को वहन करना होगा। फर्रुखाबाद टेक्सटाइल्स पार्क की एसपीवी में प्रबंध निदेशक रोहित गोयल कहते हैं कि फिलहाल यहां जो उद्योग लगने वाले हैं, उनमें पानी का डिस्चार्ज 1.25 एमएलडी है। इसलिए यह ईटीपी पर्याप्त है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी क्षमता एक एमएलडी बढ़ाई जा सकती है।

कॉमन फैसिलिटी सेंटर का खर्च ओडीओपी से : फर्रुखाबाद में टेक्सटाइल ही एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में भी शामिल है। इसलिए इस पार्क में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने का 90 फीसद खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। ओडीओपी योजना के तहत इस सेंटर में 15 करोड़ रुपये की लागत से लैब, पैकेजिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, टेक्सटाइल्स के लिए प्लांट व मशीनरी लगाई जाएगी। इसमें राज्य सरकार 90 फीसद और दस फीसद खर्च एसपीवी उठाएगी।

फूलों से महकेगी गुरु नानक देव की नगरी

जागरण संवाददाता, कपूरथला

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर देश-विदेश से पहुंचने वाली लाखों की संगत को एक खुशनुमा माहौल देने के लिए सोमवार से सुल्तानपुर लोधी व इसके आसपास के क्षेत्र में फूल लगाने के अभियान की शुरुआत हुई। पंजाब सरकार के इस प्रोजेक्ट को समाज सेवी संगठन व संत बलबीर सिंह सीचेवाल की मदद से पूरा किया जाएगा। यह फूल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में खिलेंगे और जनवरी तक खिले रहेंगे। फूलों की विभिन्न किस्मों की पनीरी के लिए सुल्तानपुर लोधी में डेढ़ से दो एकड़ क्षेत्रफल में नर्सरी बनाई गई है। कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर डीपीएस खरबंदा ने सोमवार को औपचारिक रूप से इस मुहिम की शुरुआत की।

पंजाब सरकार ने बागवानी विभाग को सौंपे गए इस प्रोजेक्ट के तहत नवंबर तक काली बेईं व गुरुद्वारा श्री बेर साहब के आसपास 550 फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। इस पवित्र मौके की याद में ऊंचे मिट्टी के प्लेटफॉर्म पर मैरीगोल्ड फूलों के साथ 550 लिखने का भी फैसला लिया गया है। इस अहम काम को पूरा करने के लिए एक प्रसिद्ध फूल विज्ञानी अवतार सिंह ढींडसा, एडवोकेट हरप्रीत सिंह संधू, बागवानी, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल से भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सहयोग मांगा गया है। बागबानी विभाग के डायरेक्टर को अभियान की निगरानी करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

सड़क के दोनों ओर बनेंगी फूलों की क्यारियां : पवित्र शहर और 'पिंड बाबे नानक दा' को जाने वाली सड़कों के दोनों तरफ फूलों की क्यारियां बनाई जाएंगी। कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर डीपीएस खरबंदा ने बताया कि 1100 मनरेगा मजदूर ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहब के सामने पवित्र बेईं नदी के किनारे चार लाख फूलों के पौधे लगाने का काम पूरा करेंगे।

इसके अलावा चार एकड़ में गांव बूसोवाल के बाहरी हिस्से में बनाए जा रहे वीवीआइपी हेलीपैड के आसआसपास सेलोशिया, किस्टाटा, फ्रेंच मैरीगोल्ड लेमन, फ्रेंच मैरीगोल्ड ओरेंज, सेलोसिया पलूमोसा, गोमफ्रेना पर्पल और कौसमस बिपिनेटस जैसी विभिन्न किस्मों के फूल लगाए जाएंगे।

सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को लेकर पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत करते डिप्टी कमिश्नर डीपीएस खरबंदा और अन्य। जागरण

युवक की हत्या में आइटीबीपी के तीन जवान गिरफ्तार

संवाद सूत्र, लालकुआं (हल्द्वानी) : आइटीबीपी की हल्दूचौड़ स्थित 34वीं वाहिनी में 16 अगस्त को भर्ती के दौरान सूरज हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए तीन जवानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित जवान उप्र, हरियाणा व राजस्थान के रहने वाले हैं।

नानकमत्ता निवासी सूरज सक्सेना हत्याकांड में रविवार को पुलिस ने बहुद्देश्यीय भवन हल्द्वानी में आइटीबीपी की भर्ती बोर्ड के 18 जवानों को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान भर्ती में सूरज के साथ आए उसके दोस्तों की शिनाख्त पर आइटीबीपी के तीन जवानों हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र शेर सिंह, राजस्थान के जिला सीकर निवासी संतोष यादव पुत्र राम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी चंद्रेश्वर पुत्र ओमप्रकाश को हत्या व साक्ष्य छिपाने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। इनमें दो कांस्टेबल व एक हेड कांस्टेबल है। तीनों आरोपितों को सोमवार को नैनीताल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

वहीं दोपहर बाद नानकमत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा आइटीबीपी परिसर के बाहर परिजनों व ग्रामीणों द्वारा दिए जा रहे धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी प्रत्यूष कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव व कोतवाल योगेश उपाध्याय धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मामले में तीन आइटीबीपी के जवानों को जेल भेजे जाने की सूचना देते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त करने की बात कही। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया।

16 अगस्त को नानकमत्ता निवासी सूरज सक्सेना अपने साथियों के साथ हल्दूचौड़ स्थित आइटीबीपी की भर्ती में शामिल होने आया था। दौड़ क्वालिफाई करने के बाद सूरज का आइटीबीपी जवानों के साथ विवाद हो गया। आरोप है कि भर्ती कर रहे जवानों द्वारा उसकी लाठी डंडों से पिटाई की गई। इसके बाद सूरज कच्छा बनियान व घड़ी पहने ही रहस्मय तरीके से गायब हो गया।

मौसम विशेष

च. ह – चक्रवाती हवा का क्षेत्र; मॉनसून की अक्षिय रेखा

श्रीनगर 29/18, चंडीगढ़ 34/26, दिल्ली 36/26, जयपुर 31/25, लखनऊ 34/25, पटना 35/28, गुवाहाटी 36/27, अहमदाबाद 30/25, भोपाल 28/23, रांची 30/22, कोलकाता 34/27, नागपुर 28/24, मुम्बई 31/25, भुवनेश्वर 32/25, हैदराबाद 32/24, विशाखापत्तनम 33/27, पणजी 31/24, बंगलूरू 27/20, चेन्नई 36/28, पोर्ट ब्लेयर 28/22, अंडमान निकोबार 27/23, कोचीन 28/23, तिरुवनंतपुरम 32/24

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रहेगी। भूस्खलन की संभावना भी रहेगी। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क और गर्म बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/24/व	अहमदाबाद	33/25/आंबा
कोलकाता	34/27/व	बड़ौदा	31/23/व
चेन्नई	34/27/आंबा	नागपुर	30/23/व
हैदराबाद	33/24/व	इन्दौर	27/23/आंबा
बंगलूरू	28/19/व	राँची	34/25/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/24/व	पटना	36/28/व
गुवाहाटी	34/28/आंबा	जमशेदपुर	34/25/आंबा
गंगटोक	17/08/व	पुणे	23/22/व

उत्तर कोरिया को लेकर पहली बार छह पक्षीय वार्ता हुई

2003 में आज ही उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम की चिंताओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बीजिंग में द. कोरिया, उ. कोरिया, अमेरिका, चीन, जापान और रूस को शामिल करते हुए पहली छह पक्षीय वार्ता बुलाई गई।

विश्व इतिहास का सबसे छोटा युद्ध लड़ा गया

1896 में आज ही विश्व इतिहास का सबसे छोटा युद्ध ब्रिटेन और जांजीबार के बीच हुआ था जो सिर्फ 38 मिनट चला। जांजीबार के सुल्तान द्वारा अपनी गद्दी छोड़ने से इन्कार करने के बाद यह शुरू हुआ था। करीब 500 जांजीबारियों को मारकर ब्रिटेन ने यह युद्ध जीता था।

दोराबजी टाटा ने भारत में रखी थी स्टील उद्योग की नींव

स्टील उद्योग की नींव रखने वाले और टाटा समूह के पहले चेयरमैन दोराबजी टाटा का जन्म 1859 में आज ही मुंबई में हुआ था। 1907 में टाटा स्टील और 1911 में टाटा पॉवर की स्थापना की। 1919 में भारत की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस बनाई। वहीं जमशेदपुर के रूप में एक आदर्श शहर बसाया। 1910 में ब्रिटेन ने नाइटहुड से सम्मानित किया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहते हुए साल 1924 में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल की वित्तीय मदद भी की। दुनिया उन्हें स्टीलमैन के नाम से जानती है। 3 जून, 1932 को वह दुनिया को अलविदा कह गए।

इधर-उधर की

जाम से बचने को एंबुलेंस का सहारा

तेहरान, एजेंसी : एंबुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जाता है, लेकिन इन दिनों ईरान में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। ईरान में कुछ अमीर लोग अपने पैसे से सुविधा के नए आयाम गढ़ रहे हैं। ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए गैर कानूनी तरीके से वो एंबुलेंस को टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तेहरान, ईरान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहां की आबादी करीब एक करोड़ 40 लाख है। हाल ही में एक फुटबॉलर ने प्राइवेट एंबुलेंस कंपनी को फोन कर उनके घर एंबुलेंस भेजने को कहा। फोन पर बातचीत के दौरान ही फुटबॉलर ने साफ कर दिया था कि उन्हें एंबुलेंस बतौर टैक्सी इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। उनके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है।

महिलाओं को डिप्रेशन से निजात दिला सकता है नियमित व्यायाम

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : यह तो सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज यानी व्यायाम से शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता है और कई प्रकार की बीमारियां भी दूर रहती हैं। अब एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि व्यायाम करने से गंभीर डिप्रेशन यानी अवसाद से जूझ रहीं महिलाओं को इससे निजात मिल सकती है। हालांकि व्यायाम से होने वाले फायदे इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कौन-सा व्यायाम कब और कैसे कर रहे हैं। क्या हम घर पर स्वतः एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी कोच के नेतृत्व में।

हाल में हुए ध्ययन यह बताते हैं कि व्यायाम हमारे मूड को ठीक रखता है और कई अध्ययनों में यह दावा भी किया गया है कि शारीरिक रूप से सक्रिय लोग सुस्त रहने वाले या व्यायाम नहीं करने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं। कुछ परीक्षणों में इस बात का दावा भी किया गया है कि नियमित व्यायाम से चिंता और अवसाद को कम किया जा सकता है। यह अवसादरोधी दवाओं जितना ही प्रभावी हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं बता पाए हैं कि शारीरिक व्यायाम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकता है।

- एक्सरसाइज से शरीर में होता है एंडोकैनाबिनोइड्स नामक पदार्थ का स्राव
- मस्तिष्क में पहुंच कर तंत्रिका की कार्यप्रणाली को करता है प्रभावित

व्यायाम से होता है रासायनिक पदार्थों का स्राव : वैज्ञानिकों के मुताबिक, वर्कआउट करने से हमारे पूरे शरीर में कई तरह के प्रोटीन और अन्य जैव रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है। ये पदार्थ रक्त में प्रवेश कर हमारे मस्तिष्क तक पहुंच कर तंत्रिका संबंधी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इससे हमारी भावनाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि व्यायाम के दौरान निकलने वाले पदार्थों में से कितने तत्व मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसका पता लगाने के लिए आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जैकब मेयर ने एंडोकैनाबिनोइड्स और रनर्स हाई नामक पदार्थों के बारे पड़ताल शुरू की है।

क्या है एंडोकैनाबिनोइड्स : एंडोकैनाबिनोइड्स शरीर में स्वतः ही उत्पन्न होने वाले साइकोएक्टिव पदार्थ है। इसके यौगिक भांग में भी पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं। एंडोकैनाबिनोइड्स हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में विशेष रिसेप्टर्स को बांधते हैं। साथ ही हमारे मूड को शांत और बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

मस्तिष्क को रखता है शांत : अध्ययन से पता चलता है कि व्यायाम अक्सर रक्तप्रवाह में एंडोकेनाबिनोइड के स्तर को बढ़ाता है, जिसके कारण कुछ लोग को वर्कआउट के बाद खुद को शांत और हल्का महसूस करते हैं। नया अध्ययन हाल ही 'मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज' में प्रकाशित हुआ है। जिसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि नियमित व्यायाम से गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहीं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन देखा गया। एंडोकेनाबिनोइड के स्राव ज्यादा होने से यह सीधा मस्तिष्क पर पहुंचकर तंत्रिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। जिसके कारण सुप्त कोशिकाएं जाग्रत हो जाती हैं। अवसाद के दौरान भी मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं सुप्तावस्था में चली जाती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसे में नियमित व्यायाम डिप्रेशन से जूझ रहीं महिलाओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं हो सकता।

चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढों की भेजी नई तस्वीरें

उपलब्धि ▸ उपग्रह ने 23 अगस्त को 4,375 किलोमीटर की ऊंचाई से ली थी तस्वीरें

अभी चंद्रमा की दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है चंद्रयान-2

बेंगलुरु, प्रेट्र : चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढों की नई तस्वीरें भेजी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को नई तस्वीरें साझा करते हुए यह जानकारी दी। चंद्रयान-2 अभी चंद्रमा की दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है।

इसरो के बयान में कहा गया है कि चंद्रयान-2 के टेरैन मैपिंग कैमरा-2 ने लगभग 4,375 किलोमीटर की ऊंचाई से 23 अगस्त को ये तस्वीरें ली थी। इसरो ने 22 अगस्त को चंद्रयान-2 द्वारा ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीर जारी की थी।

बयान के मुताबिक चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की सतह पर मौजूद जिन गड्ढों की तस्वीरें ली है उनमें सोमरफेल्ड, किर्कवुड, जैक्सन, मच, कोरोलेव, मित्रा, प्लास्केट, रोच्देस्टेवेन्स्की और हरमिट शामिल हैं। इन गड्ढों के नाम महान वैज्ञानिकों, अंतरिक्षयात्रियों और भौतिकविदों के नाम पर रखे गए हैं। मित्रा गड्ढे का नाम प्रसिद्ध भारतीय भौतिकविद और पद्मभूषण से सम्मानित प्रोफेसर एस कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है। उन्हें आयनमंडल और रेडियोफिजिक्स के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए जाना जाता है। चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई को किया गया था। सात सितंबर को यह उपग्रह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जहां अभी किसी देश का उपग्रह नहीं उतरा है। इस उपग्रह के तीन हिस्से हैं। ऑर्बिटर, लैंडर 'विक्रम' और रोवर 'प्रज्ञान'। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-2 के सभी उपकरण अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। 21 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान-2 को चंद्रमा की अगली कक्षा में भेजा था। अभी इसकी तीन बार कक्षा बदली जाएगी। इसके बाद दो सितंबर को ऑर्बिटर से लैंडर अलग होकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ जाएगा। जहां सात सितंबर को उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडिंग के कुछ देर बाद लैंडर से रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और एक दिन में विभिन्न तरह के प्रयोग करेगा। बता दें कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। रोवर को वहां पानी का पता लगाने के साथ ही खनिजों के बारे में भी शोध करना है।

चंद्रयान-2 द्वारा ली गई तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढे साफ देखे जा सकते हैं। एएनआइ

क्विज के टॉपर पीएम के साथ देखेंगे चंद्रयान-2 की लैंडिंग

नई दिल्ली, प्रेट्र : अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने केलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने स्कूली बच्चों के लिए एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। यह प्रतियोगिता आठवीं से दसवीं तक के छात्रों के लिए है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले दो छात्रों को बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में सात सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंडिंग देखने का मौका मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस क्विज में शामिल होने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने को लेकर पत्र लिखा है। क्विज में 10 मिनट में 20 सवालों के जवाब देने हैं।

शोध अनुसंधान

पैच की मदद से दी जा सकेगी त्वचा कैंसर की दवा

अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) के शोधकर्ताओं ने त्वचा पर लगाया जा सकने वाला ऐसा पैच तैयार किया है, जो बिना दर्द के कैंसर की दवा को सही जगह पर पहुंचा सकेगा। यह तरीका घातक त्वचा कैंसर मेलानोमा के इलाज में कारगर हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि त्वचा कैंसर में कुछ दवाएं लोशन की तरह ऊपर से लगाई जा सकती हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में दवा बहुत अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। इसी तरह इंजेक्शन के जरिये दवा को त्वचा की अंदरूनी सतह तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया दर्दभरी हो सकती है। हर मरीज को इंजेक्शन लगाना भी संभव नहीं होता। वहीं, यह पैच आसानी से त्वचा पर लगाया और हटाया जा सकता है। थोड़ी ही देर में यह दवा को त्वचा के अंदर तक पहुंचाने में सक्षम होता है। इस प्रक्रिया से दवा को त्वचा में पहुंचाने से डेढ़ सौ गुना तक ज्यादा असर देखा गया। - आइएएनएस

एआर ग्लासेज से कमजोर नजर वालों को मिलेगी मदद

ऑग्मेंटेड रियलिटी (एआर) ग्लासेज की मदद से कमजोर नजर वालों को आसपास की वस्तुएं स्पष्टता से देखने में मदद मिल सकती है। एआर ग्लासेज के जरिये कंप्यूटर की मदद से सामने दिख रही वस्तुओं की ज्यादा स्पष्ट छवि दिखाई देती है। कम रोशनी में नहीं देख पाने वालों के मामले में यह तरीका कारगर हो सकता है। शोधकर्ता मार्क हुमायूं ने कहा, 'अभी कमजोर नजर वालों के लिए वर्चुअल रियलिटी (आभासी वास्तविकता) आधारित कुछ डिवाइस उपलब्ध हैं। हालांकि इनके प्रयोग के लिए मरीज को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना पड़ता है। वहीं एआर तकनीक में कुछ भी आभासी नहीं होता। इसमें जो सामने दिख रहा है, उसी को और बेहतर करते हुए मरीज की रेटिना तक पहुंचाया जाता है।' इसकी मदद से मरीज 50 फीसद तक ज्यादा बेहतर तरीके से चलने में सक्षम हो पाते हैं। - आइएएनएस

प्रथम महिलाओं का समूह

दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के राष्ट्र प्रमुख इन दिनों फ्रांस के बायरिट्ज में चल रहे शिखर सम्मेलन में बेहतर नतीजों के लिए माथापच्ची कर रहे हैं, किंतु प्रथम महिलाएं पर्यटन का खूब आनंद उठा रही हैं। फ्रांस की फर्स्टलेडी ब्रिगिट मैक्रों (बाएं से चौथी) के साथ अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप, जापान की फर्स्ट लेडी एबी, चिली की सेसिलिया मोरेल, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की पत्नी जेनी मॉरिसन, यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष माल्गोरजाता टस्क और वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष डेविड मालपास की पत्नी एडेल मैलपास ने समुद्र के किनारे सैर-सपाटा किया। रायटर

स्कूल का पहला दिन

हिंसाग्रस्त फलस्तीन में जिंदगी का पटरी पर लौटना काफी मुश्किल काम माना जाता है। फलस्तीन और इजरायल के बीच जारी जंग का असर छोटे-छोटे मासूमों पर पड़ा है। हजारों लोग विस्थापितों को जीवन जी रहे हैं। इजरायल अधिकृत वेस्ट बैंक में स्थित शरणार्थी शिविर में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा देने के लिए स्कूलों का संचालन कर रहा है। ऐसे ही एक स्कूल में पहले दिन बच्चे प्रात:काल परेड में एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच टकराव लगभग एक सदी से ज्यादा पुराना है। रायटर

खुजली को ऐसे भांपता है मस्तिष्क

- मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ बॉयोमेडिकल मैटेरीयल्स में प्रकाशित हुआ अध्ययन
- रीढ़ की हड्डी में मौजूद न्यूरॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोपेप्टाइड वाई का उत्पादन होने पर महसूस होती है खुजली

कुछ मामलों में खुजली कैंसर का कारण भी बनती है। प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, आइएसडब्ल्यू : गंदगी, एलर्जी या फिर किन्हीं अन्य कारणों से होने वाली खुजली, आपकी त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाती है। कई बार शरीर में छोटी-छोटी फुंसियां होने और उसे खुजलाने पर खून निकलने जैसी समस्या भी सामने आती है, जो त्वचा के लिए खतरनाक है। कई बार यह मधुमेह और कुछ मामलों में कैंसर का कारण भी बनती है। क्या आपने कभी गौर किया है आखिर कैसे हमारा मन शरीर को खुजलाने का करता है। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि रीढ़ की हड्डी में मौजूद न्यूरॉन्स मस्तिष्क को खुजली संकेतों को कैसे प्रसारित करने में मदद करते हैं।

दरअसल, हमारा तंत्रिका तंत्र दिमाग तक खुजली के संकेतों को पहुंचता है। जर्नल ऑफ द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ बॉयोमेडिकल मैटेरीयल्स में प्रकाशित शोधपत्र में खुजली के बारे में विस्तार से बताया गया है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इससे पुरानी खुजली के इलाज की नई दवाइयां भी खोजी जा सकती हैं। कैलिफोर्निया के साल्क इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर मार्टिन गाउल्डिंग ने बताया, कि खुजली की संवेदना का मस्तिष्क तक सफर रीढ़ की हड्डी से गुजरता है, जो एक विशिष्ट मार्ग है। शोधकर्ताओं ने पहले रीढ़ की हड्डी में निरोधात्मक न्यूरॉन्स का एक सेट खोजा था, जो कोशिकाओं के लिए ब्रेक की तरह काम करते हैं, जो खुजली की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले रीढ़ की हड्डी को अधिकांश समय बंद रखते हैं। ये न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोपेप्टाइड वाई (एनपीवाई) का उत्पादन करते हैं। यह खुजली की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाने के मार्ग का निर्माण करते हैं, जो पुरानी खुजली के मामले में रास्ते को हमेशा खुला रखते हैं।

चूहों पर किए गए परीक्षण में शोधकर्ताओं ने पाया कि इन न्यूरॉन्स की गैर मौजूदगी में उन्हें खुजली की संवेदना प्राप्त नहीं होती है, लेकिन प्रयोग के दौरान जब दवाइयों के डोज से इन न्यूरॉन्स की संख्या को दोबारा बढ़ाया गया तो वे लगातार खुजली की संवेदना हासिल करने लगी। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसका मतलब यह है कि रीढ़ की हड्डी में मौजूद न्यूरॉन्स मस्तिष्क तक खुजली के संकेतों को भेजते हैं।

स्क्रीन शॉट

कश्मीर की अंतिम हिंदू शासक कोटा रानी पर बनेगी फिल्म

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब फिल्मकारों की निगाहें कश्मीर पर टिकी हैं। इस दिशा में कश्मीर पर फिल्म बनाने को लेकर रिलायंस एंटरटेनमेंट और फैंटम फिल्म्स ने संयुक्त रूप से पहल की है। हालांकि यह फिल्म अनुच्छेद 370 पर नहीं, बल्कि कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी कोटा रानी पर आधारित होगी। कोटा रानी ने 13 शताब्दी के दौरान राज किया था। उन्होंने अंतिम समय तक कश्मीर में हिंदू शासन बनाए रखने का जीतोड़ प्रयास किया था। कोटा रानी बेहद खूबसूरत होने के साथ कुशल प्रशासक और सैन्य रणनीतिकार थीं। उन्होंने कई एशियाई आक्रमणकारियों से कश्मीर को बचाया। हालांकि उन्हें अपने शासन के दौरान धोखे और साजिशों का भी सामना करना पड़ा। इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मुस्लिम आधिपत्य को काफी हद तक रोका। फिल्म के संदर्भ में सहनिर्माता मधु मंटेना का कहना है, 'यह शर्म की बात हैं कि भारतीय होने के बावजूद हम कोटा रानी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। वह देश की सक्षम शासकों में शुमार थीं। हमारा लक्ष्य उनकी कहानी को पर्दे पर लाने का है।'

सालगिरह मुबारक किरण...

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर अपनी शादी की 34वीं सालगिरह मना रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पर शादी का ब्लैक ऐंड व्हाइट फोटो शेयर करते हुए अनुपम ने पत्नी किरण खेर को प्यारा-सा कमेंट लिखा है। अनुपम ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'डियरेस्ट किरण... शादी की 34वीं सालगिरह मुबारक। बहुत लंबा वक्त जिंदगी का साथ में तय किया है हमने। 34 साल गुजर गए, लेकिन लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। साथ में बिताए पलों से मुझे बेहद प्यार है। सालगिरह मुबारक।' इस फोटो में अनुपम और किरण दूल्हा-दुल्हन बने हैं। उनके साथ भाई राजू खेर और मां दुलारी खेर भी नजर आ रही हैं। किरण खेर ने भी दोनों की क्लासिक फोटो शेयर कर अनुपम खेर को शादी की सालगिरह की बधाई दी है।

बिग बी को मिलती थी दो रुपये पॉकेट मनी

गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में ज्ञान की परीक्षा लेने के साथ-साथ प्रतिभागियों की जिंदगी और उनसे जुड़े कई पहलुओं से भी महानायक अमिताभ बच्चन रूबरू होते हैं। कई बार प्रतिभागी उनके प्रति अपनी दीवानगी का इजहार करने से नहीं चूकते हैं। उनकी फिल्मों के किस्सों को जानने की कोशिश भी होती है। कुछ सवालों के जवाब पाने की जिज्ञासा होती है। बिग बी भी उन्हें निराश नहीं करते हैं। उनके सवालों के जवाब देते हैं। बीच-बीच में प्रतिभागी से बातचीत के दौरान अपनी पुरानी यादों को भी साझा कर लेते हैं। अपने इसी बातचीत के क्रम में उन्होंने अपने बचपन को याद किया है। शो से जूड़े सूत्र के मुताबिक, अमिताभ ने बताया कि जब वह बोर्डिंग स्कूल में थे, तब उन्हें हर महीने दो रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। स्कूल के बाकी खर्चे फीस में शामिल कर लिए जाते थे। लिहाजा यह पॉकेटमनी उनके लिए काफी होती थी।

तारा को उम्मीद - फिल्मों में मिलेगा गाने का भी मौका

अपनी पहली ही फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से पहचान बना चुकीं अभिनेत्री तारा सुतारिया की दूसरी फिल्म 'मरजावां' रिलीज को तैयार है। वह धीरे-धीरे एक्टिंग में अपने कदम जमाती जा रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें सिंगिंग का भी शौक है। गौरतलब है कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले तारा संगीत की ओर ज्यादा ध्यान देती थीं। वह एक म्यूजिकल थियेटर का हिस्सा रही हैं। तारा ने कहा, 'म्यूजिकल थियेटर ने मुझे वे सभी मौके दिए, जिनकी मुझे चाहत थी। उम्मीद है कि अब फिल्मों में भी गाने का मौका मिलेगा'

दर्शकों के दबाव में स्क्रिप्ट तलाशते हैं आयुष्मान

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आयुष्मान खुराना फिल्मों के लिए नए और अनूठे विषय चुन रहे हैं। 'आर्टिकल 15' में वह गंभीर पुलिस अफसर के किरदार में दिखे तो वहीं आगामी फिल्म 'ड्रीमगर्ल' में वह लड़कियों की आवाज में डायलॉग बोलते नजर आएंगे। आयुष्मान का मानना है कि यह फिल्म महिलाओं की दुनिया में पुरुष को शामिल कर दकियानूसी परंपरा को तोड़ेगी। आयुष्मान लैंगिग समानता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। बदलाव लाने का हमें प्रयास करना होगा। आज लड़कियों को अपनी पसंद का काम करने में सहज महसूस करना चाहिए। अपने किरदार को लेकर उनका कहना है कि फिल्म में वह वैसे ही पेश आ रहे हैं, जैसे एक लड़की पेश आती है। इस किरदार को करने में उन्होंने तनिक भी असहज महसूस नहीं किया। उनका मानना है कि दर्शक उनसे बेहतर कंटेंट की उम्मीद कर रहे हैं। यही दबाव उन्हें हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट्स की तलाश करवाता है। राज शांडिल्य निर्देशित 'ड्रीमगर्ल' में आयुष्मान खुराना के साथ नुसरत भरूचा और अन्नू कपूर भी हैं।

अध्ययन

...तो ऐसे मस्तिष्क में बनती और मिटती हैं यादें

किसी घटना के संकेतों को लेकर न्यूरॉन्स का झुंड जब मस्तिष्क से लगातार टकराता है तो उसकी यादें लंबे समय तक मस्तिष्क में बने रहती हैं

वाशिंगटन डीसी, एएनआई : मनुष्य अपने जीवनकाल में कई ऐसी यादों को अपने मस्तिष्क में संजोए रहता है जो आखरी समय तक बनी रहती हैं, जबकि कई घटनाएं उसकी स्मृति से कुछ समय बात मिट जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि कैसे इस तंत्रिका संबंधी प्रक्रिया में यादें क्षीण होने लगती हैं, जबकि कुछ यादें लम्बे समय तक मस्तिष्क में बने रहती हैं।

कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने चूहों पर परीक्षण कर यह पता लगाया कि जब किसी घटना के संकेतों को लेकर न्यूरॉन्स का झुंड मस्तिष्क पर लगातार फायर करता है या टकराता है तो उस घटना की यादें लंबे समय तक मस्तिष्क में बने रहती हैं, जबकि जब मस्तिष्क से कम न्यूरॉन्स टकराते हैं तो एक निश्चित समय बात घटना की यादें क्षीण होने लगती हैं।

यह अध्ययन साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इस शोध से यह पता लगाने में भी मदद मिल सकती है कि स्ट्रोक और अल्जाइमर जैसी बीमारी होने पर यादें कैसे प्रभावित होती हैं। पोस्टडॉक्टरल स्कॉलर वाल्टर गोंजालेज के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने चूहों की तंत्रिका गतिविधि की जांच करने के लिए एक परीक्षण किया। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक मॉडल बनाकर चूहे को एक सफेद दीवार के साथ पांच फीट लंबे बाड़े में रख दिया और उसके दोनों छोरों पर एक खास निशान बनाकर एक छोर में चूहे के खाने के लिए भोजन रख दिया और उस तक पहुंचने के लिए एक उलझा हुआ गलियारा भी बना दिया। अब जब चूहे को भूख लगी तो पहले दिन चूहा सूंघते हुए भोजन तक पहुंचा और 20 दिनों तक यह प्रक्रिया जारी रही। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि पहले दिन एक न्यूरॉन ने चूहे के हिप्पोकैंपस (मस्तिष्क का वह क्षेत्र जहां यादें बनती हैं) से टकराया था और समय बीतने के साथ-साथ भूख लगने पर चूहे के हिप्पोकैंपस से लगातार न्यूरॉन टकराते थे और वह सही रास्ते से चल कर भोजन तक पहुंच जाता था। इस तरह उसे वह रास्ता याद हो गया और वह कुछ दिनों बाद भूख लगते ही तुरंत भोजन तक पहुंच जाता था।

- कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने चूहों पर परीक्षण कर लगाया पता

न्यूरॉन मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं घटनाओं के संकेत।

शोधकर्ताओं ने कहा कि परीक्षण से पता चलता है कि चूहे को शुरुआती कुछ दिनों तक अपने भोजन तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। समय बीतने के साथ-साथ उसे भोजत तक पहुंचने का रास्ता याद हो गया जो उसकी स्मृति में लम्बे समय तक बना रहा। गोंजालेज के कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि किसी घटना के होने पर यदि हमारे मस्तिष्क के हिप्पोकैंपस में न्यूरॉन्स के झुंड लगातार टकराते हैं तो उस घटना की याद लंबे समय तक मस्तिष्क में बनी रहती हैं। वहीं दूसरी ओर यदि कुछ एक ही न्यूरॉन्स हिप्पोकैंपस के टकराते हैं तो ऐसी संभावना रहती है कि हम कुछ समय बाद उस घटना को भूल जाते हैं।